राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 252

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, मंगलवार, 18 फरवरी 2020

www.jagran.com

पृष्ठ 16

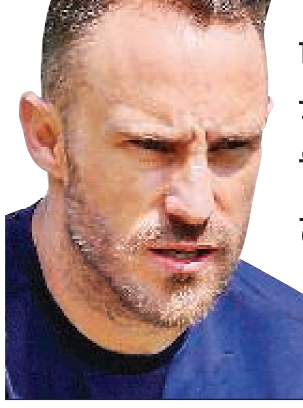

फाफ डुप्लेसिस ने दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट टीम की कप्तानी छोड़ी >>14

सेना में महिलाओं को मिलेगा स्थायी कमीशन

सुप्रीम आदेश ▶ सरकार को मिली तीन माह की मोहलत, कमांड नियुक्ति पर भी होगा विचार

महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने के लिए मानसिकता बदलने की जरूरत : कोर्ट

माला दीक्षित, नई दिल्ली

नारी सशक्तीकरण की दिशा में 17 फरवरी की तारीख इतिहास में दर्ज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सेना में लैंगिक भेदभाव दूर करने के लिए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने सरकार से तीन महीने के भीतर शॉर्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) की सभी महिला अधिकारियों को स्थायी (परमानेंट) कमीशन देने को कहा है। स्थायी कमीशन का विकल्प देते समय महिला अधिकारियों की नौकरी की अवधि मायने नहीं रखेगी। अदालत ने स्पष्ट किया कि 14 साल की नौकरी पूरी कर चुकी या 20 साल की नौकरी पूरी कर चुकी सभी महिला अफसर फैसले के दायरे में आएंगी।

ऐतिहासिक आदेश में कोर्ट ने महिलाओं के लिए कमांड पोस्टिंग के भी दरवाजे खोले हैं। कोर्ट ने कहा है कि वैसे तो यह नीतिगत मसला है और सक्षम अथॉरिटी प्रत्येक मामले के आधार पर निर्णय लेगी लेकिन महिलाओं को कमांड पोस्ट देने पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई जा सकती। अतार्किक भेदभाव बराबरी के मौलिक अधिकार के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सेवारत 1,653 महिला सैन्य अधिकारियों को फायदा होगा।

कोर्ट ने महिला सैन्य अधिकारियों की क्षमता को लेकर सवाल उठाने वाली सरकार की दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि सेना में वास्तविक समानता लाने के लिए सोच बदलने की जरूरत है। कोर्ट ने अपने आदेश में 11 महिला सैन्य अधिकारियों की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि महिला होने के आधार पर उनकी क्षमता पर सवाल उठाना न सिर्फ उनकी महिला होने की गरिमा का निरादर है, बल्कि भारतीय सेना के सदस्य का भी निरादर है।

सेना में महिला अधिकारियों के लिए आगे का रास्ता खोलने वाला यह अहम फैसला न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की पीठ ने दिया। कोर्ट ने आदेश दिया है कि जिन एसएससी महिला अधिकारियों को इस आदेश के अनुपालन में स्थायी कमीशन मिलेगा वे सभी संबंधित लाभों को पाने की अधिकारी होंगी। कोर्ट ने साफ किया है कि ये लाभ उन सभी महिला अधिकारियों को मिलेंगे जो अभी सेवा में हैं या जिन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में रिट याचिका दाखिल की थी।

हाई कोर्ट के आदेश को दी थी चुनौती पेज>>6
रंग लाया अनुपमा का संघर्ष पेज>>7
कांग्रेस और भाजपा ने किया स्वागत पेज>>7

"गर्भावस्था, प्रसव और परिवार की जिम्मेदारियों के लिए लंबी छुट्टी का तर्क देकर महिलाओं को बराबरी से दूर रखना इस घोर रूढ़िवादी सोच का प्रतीक है कि घर की जिम्मेदारी केवल महिलाओं की है। इसमें यह सोच भी झलकती है कि महिलाएं कमजोर होती हैं और मुश्किल काम नहीं कर सकती हैं। – जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़

नई दिल्ली में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारतीय सेना की कमीशन अधिकारी (बाएं से) अंजली बिष्ट, सीमा सिंह और संध्या यादव ने विक्ट्री का निशान बनाकर खुशी जाहिर की। एएनआइ

परमानेंट कमीशन (पीसी)

- परमानेंट कमीशन (पीसी) का अर्थ है सेवानिवृत्त तक सेना में नौकरी।
- सेवानिवृत्ति की आयु संबंधित व्यक्ति के पद पर निर्भर होती है।
- पीसी से भर्ती व्यक्ति को शॉर्ट सर्विस कमीशन में जाने की अनुमति नहीं होती।
- वैध कारण बताते हुए समयपूर्व सेवानिवृत्ति का आवेदन किया जा सकता है।
- पेंशन पाने के लिए न्यूनतम 20 साल की नौकरी करनी होती है।

शॉर्ट सर्विस कमीशन (एसएससी)

- एसएससी के तहत 10 साल के लिए सेना में नियुक्ति होती है।
- इसके बाद चार साल के अतिरिक्त कार्यकाल का भी विकल्प मिलता है।
- इस चार साल की अवधि में जरूरत पड़ने पर कभी भी त्यागपत्र दे सकते हैं।
- कुछ मामलों में 14 साल के बाद भी नौकरी में रहने का विकल्प मिलता है।
- विभिन्न मानकों के आधार पर परमानेंट कमीशन का भी रास्ता खुलता है।

अदालत ने यह भी कहा

- शारीरिक क्षमता की दलील के आधार पर महिलाओं को स्थायी कमीशन नहीं देना बेतुका
- कई शौर्य व सेना पदक जीत अपनी क्षमता साबित कर चुकी हैं महिलाएं

फैसले की अहम बातें

- स्थायी कमीशन का विकल्प नौकरी कर रही सभी एसएससी महिला अधिकारियों को दिया जाएगा।
- 14 साल से ज्यादा समय से नौकरी कर रही और स्थायी कमीशन का विकल्प नहीं लेने वाली महिला अधिकारी 20 साल तक नौकरी में रह सकेंगी, ताकि पेंशन की पात्रता मिल जाए।
- वन टाइम मेजर के तहत पेंशनेबल सर्विस होने तक नौकरी में बने रहने का विकल्प उन सभी एसएससी महिला अफसरों को मिलेगा जिनकी 14 साल से ज्यादा की नौकरी हो गई है और जिन्हें स्थायी कमीशन में नहीं नियुक्ति दी गई।
- एसएससी महिला अफसर जिनकी नौकरी 20 साल से ज्यादा हो गई है और स्थायी कमीशन नहीं मिला, वे नीति के मुताबिक पेंशन पर रिटायर होंगी।
- स्थायी कमीशन का विकल्प चुनते समय महिला अधिकारी के लिए भी चॉइस ऑफ स्पेशलाइजेशन और शर्तें रहेंगी।

वोडाफोन सिर्फ 3,500 करोड़ रुपये एजीआर बकाया चुकाने में समर्थ

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : देश की प्रमुख दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी वोडाफोन ने एक तरह से यह साफ कर दिया है कि मौजूदा हालात में उसके लिए एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) मामले में 50 हजार करोड़ रुपये की बकाया राशि का भुगतान करना संभव नहीं है। कंपनी की तरफ से सोमवार को महज 2,500 करोड़ रुपये तत्काल और कुछ दिन बाद 1,000 करोड़ रुपये के भुगतान की अर्जी दी गई जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।

भारती एयरटेल ने 10 हजार करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है। टाटा समूह की टाटा टेलीसर्विसेज ने भी 2197 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। इस तरह से देखा जाए तो दूरसंचार कंपनियों पर एजीआर के तौर पर बकाये 1.47 लाख करोड़ रुपये की राशि में से महज 14,700 करोड़ रुपये सरकार के पास आए हैं। इस बीच, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि बैंक टेलीकॉम कंपनियों के इस संकट पर पैनी नजर रखे हुए हैं। दूसरी तरफ, दूरसंचार विभाग (डीओटी) के सूत्रों का कहना है कि अगर कंपनियों ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की 17 मार्च को होने वाली सुनवाई तक पूरा भुगतान नहीं किया, तो उनकी बैंक गारंटी जब्त करने के कानूनी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है।

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपनाया था सख्त रुख पेज>>6

सरोकार

एयर वेंट्स तकनीक से सींच रहे धरती की कोख

प्रयागराज : मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, प्रयागराज ने भूगर्भ जल स्तर को बढ़ाने की दिशा में सफल प्रयोग किया है। 'रिचार्ज वेल विद एयर वेंट्स' नामक इस युक्ति से रेन वाटर हार्वेस्टिंग की पुरानी पद्धति के मुकाबले डेढ़ गुना अधिक वाटर रिचार्ज होता है। (पेज-11)

जागरण विशेष

करियर पर निशाना लगा रहीं बीहड़ की बेटियां

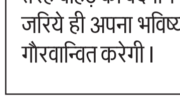

भिंड : मध्य प्रदेश के चंबल के बीहड़ अब बदल रहे हैं। ये बीहड़ अब ऐसी युवा पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं, जो बंदूक के शौक से पहले की तरह बीहड़ को बदनाम नहीं, बल्कि इसके जरिये ही अपना भविष्य संवार देश को गौरवान्वित करेगी। (पेज-11)

न्यूज गैलरी

नेशनल कैपिटल ▶ पृष्ठ 2

केजरीवाल ने अपने पास नहीं रखा कोई विभाग

नई दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया है। केजरीवाल ने कोई भी विभाग अपने पास नहीं रखा है। जल बोर्ड को अब तक मुख्यमंत्री संभाल रहे थे, लेकिन इस बार उन्होंने इसे सत्येंद्र जैन को सौंप दिया है। गोपाल राय को पर्यावरण विभाग का जिम्मा सौंपा गया है।

राज-नीति ▶ पृष्ठ 4

14 साल बाद बाबूलाल मरांडी की घर वापसी

रांची : झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी सोमवार को भाजपा में वापस लौट आए। 2006 में उन्होंने भाजपा छोड़कर झारखंड विकास मोर्चा का गठन किया था। हालिया विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार के बाद बाबूलाल मरांडी की वापसी की कवायद शुरू हुई थी।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 5

यूपीपीएससी 2019 की प्रारंभिक परीक्षा में 6320 अभ्यर्थी सफल

प्रयागराज : उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2019 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। इसमें 6320 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए सफल हुए हैं। आयोग की ओर से कहा गया है कि प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट सात अलग-अलग ग्रुपों में जारी किया है। इसी के साथ एसीएफ व आरएफओ प्रारंभिक परीक्षा का भी परिणाम जारी किया गया है।

अंतरराष्ट्रीय ▶ पृष्ठ 13

कोरोना का साया चीन के संसद सत्र पर भी, 105 और मरे

बीजिंग : कोरोना वायरस की महामारी की छाया चीन के संसदीय सत्र पर पड़ती दिख रही है। सरकारी मीडिया की मानें तो पांच मार्च को होने वाले संसदीय सत्र को स्थगित किया जा सकता है। उधर, चीन में सोमवार को 105 और लोगों की वायरस संक्रमण के चलते मौत हो गई।

प्रदर्शन का हक, लेकिन यह सड़क पर न हो : सुप्रीम कोर्ट

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोहराया है कि सार्वजनिक स्थल या सड़क को बाधित करके विरोध-प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। लोगों को विरोध-प्रदर्शन का मौलिक अधिकार है, लेकिन ये सड़क या सार्वजनिक स्थल पर कैसे हो सकता है। इससे अव्यवस्था पनपती है। प्रदर्शन के अधिकार और सड़क प्रयोग करने वाले आम आदमी के अधिकार के बीच संतुलन कायम करने की जरूरत है।

जस्टिस संजय किशन कौल और केएम जोसेफ की खंडपीठ ने सोमवार को यह टिप्पणियां दिल्ली के शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में जारी धरना-प्रदर्शन को लेकर कीं। अदालत शाहीन बाग में 60 दिन से ज्यादा समय से चल रहे धरना-प्रदर्शन को हटाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने कहा कि इसका हल निकालने की जरूरत है। प्रदर्शन एक निश्चित स्थान पर हो सकता है। इसके लिए वैकल्पिक जगह चिह्नित की जा सकती है। कोर्ट ने वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े से कहा है कि वह शाहीन बाग जाकर प्रदर्शनकारियों से मिलें और बातचीत कर हल निकालें। कोर्ट ने वकील संजय हेगड़े को वकील साधना रामचंद्रन और पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला का सहयोग लेते हुए शाहीन बाग जाकर लोगों से बातचीत कर हल निकालने का समय देते हुए सुनवाई 24 फरवरी तक के लिए टाल दी।

इससे पहले अदालत ने कहा कि सड़क को कैसे बंद किया जा सकता है। यह उनकी सबसे बड़ी चिंता है। जस्टिस कौल ने कहा कि आज एक समूह सीएए के विरोध में प्रदर्शन कर रहा है और सड़क बाधित है। कल को हो सकता है कि कोई दूसरा वर्ग किसी दूसरी चीज को लेकर विरोध जताते हुए दूसरी सड़क या गली बंद कर दे। कहीं तो इसका अंत होगा। कोर्ट की यही सबसे बड़ी चिंता है। प्रदर्शन करने का मौलिक अधिकार है, लेकिन लोगों के आने-जाने और परिवहन के भी अधिकार हैं। ऐसे में दोनों के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है। कोर्ट ने साफ किया कि इस मामले में वह बहुत सीमित दायरे में यानी सिर्फ सड़क बाधित करने के पहलू पर ही विचार कर रहा है।

दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ऐसा नहीं है कि प्रशासन ने प्रयास नहीं किए, लेकिन प्रदर्शनकारी महिलाओं और बच्चों की आड़ लिए हैं जिसके कारण कड़ी कार्रवाई करने से अधिकारी कतरा रहे हैं। जबकि अधिकारियों ने रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन और शाहीन बाग की मस्जिदों के मौलवियों से बातचीत कर हल निकालने की कोशिश की थी। वहां पूरी तरह रास्ता बंद है। पूरे शहर को बंधक बना रखा है।

मेहरा ने कहा-ऐसा संदेश न जाए कि उनके आगे हम घुटनों पर आ गए हैं : मेहता ने खंडपीठ से कहा, 'मैं नहीं चाहता कि यह संदेश जाए कि हम उनको हटाने के लिए उनके आगे गिड़गिड़ा रहे हैं। उन्हें मनाने के लिए हर संस्था उनके सामने घुटनों के बल आ गई है।' इस पर खंडपीठ ने मेहता से प्रदर्शन करने के लिए वैकल्पिक स्थान देने के बारे में पूछा। तभी भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर और दो अन्य याचिका कर्ताओं की ओर से पेश वकील ने कहा कि वहां सब बंद नहीं है। इसका विरोध करते हुए मेहता ने कहा, नहीं सब पूरी तरह बंद है।

मध्यस्थों से बातचीत के लिए शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी तैयार पेज>>5

शाहीन बाग मामला

- प्रदर्शन स्थल बदलने को तीन मध्यस्थों संजय हेगड़े, साधना रामचंद्रन और वजाहत हबीबुल्लाह को किया नियुक्त
- अगली सुनवाई 24 को, खंडपीठ ने सरकारी वकील से पूछा, क्या प्रदर्शन को वैकल्पिक जगह मिलेगी

सुप्रीम कोर्ट फाइल

"लोकतंत्र विचारों की अभिव्यक्ति पर काम करता है। लेकिन इसकी कुछ सीमाएं और बाध्यताएं हैं। हमें चिंता इस बात की है कि अगर सभी ने सार्वजनिक क्षेत्रों को बाधित करना शुरू कर दिया तो यह कहां पर जाकर खत्म होगा।

-जस्टिस एसके कौल और जस्टिस केएम जोसेफ की खंडपीठ

हमने अपनी राय दे दी और उम्मीद करते हैं कि इसका हल निकलेगा। अगर कुछ नहीं हो पाता तो हम इसे संबंधित प्रशासन पर छोड़ देंगे।

-जस्टिस केएम जोसेफ की टिप्पणी"

भारत से लौटाई गईं ब्रिटिश सांसद डेबी अब्राहम्स

नई दिल्ली, एजेंसियां : जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का विरोध कर चुकी ब्रिटेन की विपक्षी सांसद डेबी अब्राहम्स (डेबोराह एंजेला एल्सपेथ मेरी अब्राहम्स) को सोमवार की सुबह नई दिल्ली स्थित आइजीआइ एयरपोर्ट पहुंचने पर तत्काल वापस लौटा दिया गया। लेबर पार्टी की डेबी ने दावा किया है कि उनके पास वैध वीजा होने के बावजूद उन्हें वापस दुबई प्रत्यर्पित किया गया। जबकि भारत के गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि उन्हें समय रहते ही उनका ई-वीजा रद किए जाने की जानकारी दे दी गई थी। इसके बावजूद उन्होंने भारत आने की जहमत उठाई।

डेबी अब्राहम्स (59) ब्रिटेन में कश्मीर पर सर्वदलीय संसदीय समूह की अध्यक्ष हैं। उनकी दलील है कि वह भारत में अपने परिवार और मित्रों से मिलने वैध ई-वीजा पर भारत आई थीं। लेकिन एक साल के लिए जारी किया गया उनका वीजा, आगामी अक्टूबर तक वैध होने के बावजूद बिना किसी स्पष्टीकरण के रद कर दिया गया। इस सिलसिले में ब्रिटिश उच्चायोग की प्रवक्ता ने बताया कि वह सांसद डेबोराह पर भारत में प्रवेश पर मनाही के संबंध में भारतीय प्रशासन के संपर्क में हैं। उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट पर काउंसलर एक्सेस भी दिया गया था। इस विवाद पर गृह मंत्रालय की प्रवक्ता ने बताया कि ब्रिटिश सांसद का वीजा रद किए जाने के बाद उन्हें इस बात की जानकारी दी गई थी और वह यह सब जानते हुए भी दिल्ली पहुंच गईं।

- अब्राहम्स का आरोप-वैध वीजा होने पर भी दिल्ली से दुबई किया डिपोर्ट
- जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का सांसद ने किया था विरोध

सोमवार को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पहुंची ब्रिटिश सांसद डेबी अब्राहम्स को तत्काल वापस लौटा दिया गया। एपी

13 फरवरी से पहले इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली थी : डेबी पेज>> 6

राकांपा ने किया भीमा-कोरेगांव मामले की समानांतर जांच का एलान

मुंबई : महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार में दरार दिखने लगी है। सरकार में शामिल राकांपा ने सोमवार को कहा कि पार्टी नेता और गृह मंत्री अनिल देशमुख यलगार परिषद भीमा-कोरेगांव मामले की विशेष जांच दल (एसआइटी) के जरिये समानांतर जांच के तौर-तरीके तय करेंगे। पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में सरकार ने इसकी जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) को सौंपने को मंजूरी प्रदान कर दी थी। अगर समानांतर जांच हुई तो अलग-अलग निष्कर्षों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच भी तनाव बढ़ सकता है। (पेज-3)

साप्ताहिक अवकाश के लिए हाई कोर्ट पहुंचे हरियाणा के पुलिसकर्मी

चंडीगढ़ : साप्ताहिक अवकाश के लिए हरियाणा के पुलिसकर्मियों ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन सोमवार को हाई कोर्ट ने इसे प्रशासनिक विषय करार देते हुए इस मामले में किसी भी तरह का आदेश जारी करने से इन्कार कर दिया। साथ ही याची को इस विषय को सरकार के सामने उठाने का निर्देश दिया। बता दें हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने 2017 में पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने की घोषणा कर दी थी, लेकिन इसे आज तक अमलीजामा नहीं पहनाया जा सका है। (पेज-4)

निर्भया के दोषियों के लिए फिर डेथ वारंट जारी, तीन मार्च को होगी फांसी

नई दिल्ली : निर्भया कांड के दोषियों के खिलाफ तीसरी बार डेथ वारंट जारी हुआ है। सोमवार को निर्भया के परिजनों और दिल्ली सरकार की अर्जी पर पटियाला हाउस की एक अदालत ने चारों दोषियों को तीन मार्च की सुबह छह बजे फांसी देने का आदेश जारी किया है। अतिरिक्त सत्र न्यायालय में सुनवाई के दौरान दोषी मुकेश की तरफ से बताया गया कि वह नहीं चाहता है कि अब अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर उसका प्रतिनिधित्व करें। इस पर वृंदा ग्रोवर ने अदालत से अपील की कि उन्हें इस केस से मुक्त किया जाए। (पेज-5)

तैयारी

सेना के तीनों अंगों को मिलाकर थिएटर कमान बनाने की योजना, अगले साल के मध्य तक अस्तित्व में आ जाएगा एयर डिफेंस कमान, युद्ध के हालत में तीनों सेनाओं के बीच होगा बेहतर समन्वयन

सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए बड़े सुधार की ओर सेनाएं

नई दिल्ली, एजेंसियां : देश की सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए कई स्तरों पर सैन्य सुधार की प्रक्रिया चल रही है। दुश्मन के किसी भी हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जहां सैन्य बलों के लिए अत्याधुनिक हथियारों का अधिग्रहण किया जा रहा है। वहीं, युद्ध की स्थिति में तीनों सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय के लिए देश के सैन्य ढांचे को पुनर्गठित भी किया जा रहा है। इसके तहत तीनों सेनाओं को मिलाकर दो से पांच थिएटर कमान बनाने की योजना है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जम्मू-कश्मीर के लिए एक अलग थिएटर कमान बनाने की भी योजना है, जिसमें खुफिया ब्यूरो को भी शामिल किया जाएगा। सेना के लिए गेम चेंजर साबित होने वाले इन सुधारों की जानकारी खुद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल बिपिन रावत ने सोमवार को दी।

जनरल रावत ने यहां पत्रकारों से कहा कि 2022 तक थिएटर कमान के गठन की संभावना है। उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि एयर डिफेंस कमान के तो अगले साल के मध्य तक ही अस्तित्व में आ जाने की उम्मीद है। इस कमान के तहत सेना के मिसाइल प्रणाली के साथ ही नौसेना की कुछ इकाइयों को भी रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा की चुनौतियों के लिए सेना के अलग थिएटर कमान का गठन किया जाएगा।

2021 के अंत तक पेनिनसुला कमान : जनरल रावत ने कहा कि नौसेना के पूर्वी और पश्चिमी कमान को मिलाकर 2021 के आखिर तक पेनिनसुला कमान का गठन कर दिया जाएगा। इसका हेड नौसेना का कमांडर होगा। इसके जिम्मे सर क्रीक से लेकर बंगाल की खाड़ी में सुदरबन तक भारतीय समुद्री सीमा की सुरक्षा होगी। युद्धपोतों की तैनाती व संचालन संबंधी मामलों में कमांडर को सैन्य मुख्यालय से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। जनरल रावत ने बताया कि चीन से लगती देश की पूर्वी सीमा की सुरक्षा के लिए एक से दो कमान का गठन किया जा सकता है। इसी तरह पाकिस्तान से लगती पश्चिमी सीमा के लिए जम्मू-कश्मीर में अगल थिएटर कमान तो होगा ही, जम्मू के दक्षिणी भाग में अंतरराष्ट्रीय सीमा के लिए एक अलग कमान का भी गठन किया जाएगा।

ट्रेनिंग-लाजिस्टिक्स थिएटर कमान : सीडीएस ने बताया कि तीनों सेनाओं के लिए ट्रेनिंग व लॉजिस्टिक के लिए भी अलग से थिएटर कमान का गठन किया जाएगा। ट्रेनिंग कमान जहां सेना के तीनों अंगों के जवानों को एक समान और बहुआयामी ट्रेनिंग देगा, वहीं लाजिस्टिक थिएटर कमान सभी थिएटर कमान के बीच साजो-सामान पहुंचाने का काम करेगा। इसके अलावा विदेशों के थिएटर कमान के साथ तालमेल भी बिठाएगा।

बिपिन रावत फाइल फोटो

अभी देश में कुल 17 कमान पेज>>3

31 मार्च से पहले बकाया बिजली बिल भरकर पुरस्कार जीत सकते हैं टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड के उपभोक्ता। योजना में 11 किलोवाट या इससे कम बिजली लोड वाले उपभोक्ताओं को शामिल किया जाएगा।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
मंगलवार 18 फरवरी 2020

नई पारी शुरू ▶ केजरीवाल ने मंत्रियों को बांटे विभाग, फिर उप मुख्यमंत्री बने सिसोदिया, सत्येंद्र जैन को मिला जल बोर्ड, तीन मंत्रियों के बदले विभाग

मुख्यमंत्री ने नहीं रखा कोई विभाग, और ताकतवर बने जैन व राय

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को तीसरी बार सत्ता संभालने के बाद मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कोई भी विभाग अपने पास नहीं रखा है, जबकि विभागों के बंटवारे में सत्येंद्र जैन और गोपाल राय इस कार्यकाल में और ताकतवर हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने खुद संभाल रहे जल बोर्ड को सत्येंद्र जैन को सौंप दिया है। गोपाल राय को पर्यावरण विभाग दे दिया है। पर्यावरण विभाग पिछले साल से कैलाश गहलोत संभाल रहे थे। मुख्यमंत्री अब सभी मंत्रियों के काम पर नजर रखेंगे। इसके साथ ही जनता से सीधा संवाद स्थापित करेंगे।

केजरीवाल ने सरकार के तीन मंत्रियों के विभाग बदले हैं। मनीष सिसोदिया को फिर से उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। उनके पास पहले की तरह ही महत्वपूर्ण विभाग रहेंगे। मगर महिला एवं बाल विकास विभाग उनसे लेकर राजेंद्र पाल गौतम को दे दिया है। बताया जा रहा है कि सिसोदिया ने ही यह विभाग किसी अन्य मंत्री को दिए जाने का आग्रह किया था। केजरीवाल ने खुद संभाल रहे महत्वपूर्ण विभाग दिल्ली जल बोर्ड को सत्येंद्र जैन को दे दिया है। कपिल मिश्रा को जल मंत्री के पद से हटाए जाने के बाद केजरीवाल ने यह विभाग राजेंद्र पाल गौतम को दिया था। मगर इस विभाग की चुनौतियों को देखते हुए उन्होंने इसे स्वयं ले लिया था। तभी से यह विभाग मुख्यमंत्री के पास था। कहा जा रहा है कि दो सौ यूनिट बिजली मुफ्त कर एक बड़ी योजना पर काम किया। इसका बड़ा लाभ इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिला है। गोपाल राय को पर्यावरण विभाग दिया गया है। राय के पास मुख्यरूप से अभी तक श्रम विभाग ही था। उन्होंने इस विभाग में शानदार काम किया है। पर्यावरण विभाग अभी तक कैलाश गहलोत के पास था। बता दें कि बाकी अन्य मंत्रियों के विभागों में कोई फेरबदल नहीं किया गया है।

अरविंद केजरीवाल ने तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाल लिया। इसके लिए सचिवालय पहुंचने पर अधिकारियों व कर्मचारियों ने उनका उत्साहपूर्वक स्वागत किया। इस दौरान एक सिक्योरिटी गॉर्ड लाल चंद क्षत्रिय से हाथ मिलाते केजरीवाल। एएनआइ

कैबिनेट मंत्री और विभाग

- **उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया** : शिक्षा, वित्त, भूमि एवं बिल्डिंग सतर्कता, सेवा, पर्यटन, कला, संस्कृति एवं भाषा और अन्य वे सभी विभाग जो किसी मंत्री को अभी तक आवंटित नहीं किए गए हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है।
- **गोपाल राय** : रोजगार, विकास, श्रम एवं सामान्य प्रशासन विभाग, पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग
- **सत्येंद्र जैन** : जल, स्वास्थ्य, उद्योग, लोक निर्माण विभाग, ऊर्जा, गृह, शहरी विकास और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण
- **इमरान हुसैन** : खाद्य एवं आपूर्ति और चुनाव।
- **राजेंद्र पाल गौतम** : गुरुद्वारा चुनाव, एससी/एसटी, समाज कल्याण, कोआपरेटिव, महिला एवं बाल विकास विभाग
- **कैलाश गहलोत** : विधि, न्याय एवं विधि निर्मकन संबंधी मामले, परिवहन, प्रशासनिक सुधार, सूचना एवं प्रौद्योगिकी और राजस्व विभाग

पहले ही दिन से रफ्तार में सरकार

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

- चुनाव घोषणापत्र और मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड पर काम करना पार्टी की सर्वोच्च प्राथमिकता
- आम आदमी की जरूरतों को पूरा करने पर सरकार का होगा जोर

दिल्ली की नई सरकार पहले ही दिन से रफ्तार में है। सरकार ने रफ्तार के साथ काम करना शुरू कर दिया है। सरकार ने आम आदमी पार्टी (आप) के चुनाव घोषणापत्र और मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड पर काम करने के लिए अधिकारियों से रूपरेखा तैयार करने को कहा है क्योंकि अगले पांच साल में चुनाव घोषणापत्र और मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड पर काम करना ही पार्टी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके साथ ही आम आदमी की जरूरतों को किस तरह तेजी से पूरा किया जा सके, इस पर सरकार का जोर होगा।

दिल्ली वालों को 24 घंटे मिलेगा स्वच्छ पानी : सत्येंद्र जैन : कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि घोषणापत्र में दिल्ली की जनता से जुड़ी सारी मूलभूत आवश्यकताओं को रखा गया है। इन्हें पूरा करना नई सरकार का प्रमुख एजेंडा होगा। साथ ही मोहल्ला क्लीनिक को पूरे दिल्ली में एक किलोमीटर के दायरे में लाया जाना सरकार का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि दिल्ली वालों को 24 घंटे पानी उपलब्ध करवाया जाएगा।

दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करना अहम मुद्दा : गोपाल राय : पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि नई सरकार के लिए दिल्ली का प्रदूषण दूर करना बहुत अहम मुद्दा है। दिल्ली से प्रदूषण का सफाया किया जाएगा। इसके लिए तमाम योजनाओं पर काम होगा। सरकार समाज के सबसे निचले स्तर तक पहुंचेगी। समाज के सबसे वंचित वर्ग की जरूरतों को ध्यान में रखकर काम किया जाएगा। लोग आज दिल्ली के विकास मॉडल को देख रहे हैं। इस मॉडल की पूरे देश में चर्चा है। इस कारण नई सरकार दिल्ली मॉडल को और विस्तार देगी। दिल्ली से प्रदूषण का सफाया किया जाएगा।

परिवहन व्यवस्था पर होगा काम : कैलाश गहलोत : कामकाज संभालने के बाद कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड उनकी प्राथमिकता में रहेगा। साथ ही सरकार दिल्ली के परिवहन व्यवस्था को और मजबूत करने पर काम करेगी। उन्होंने कहा कि परिवहन व्यवस्था सुधारने के लिए तमाम योजनाएं जमीन पर आने वाली हैं। दिल्ली में आने वाले कुछ समय में ही परिवहन के क्षेत्र में बदलाव दिखेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि अब केंद्र सरकार को मेट्रो में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की अनुमति दे देनी चाहिए।

दिल्ली का विकास करना लक्ष्य : राजेंद्र पाल गौतम : कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल ने भी दिल्ली के विकास को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जताई। गौतम का कहना है कि दिल्ली का विकास करना हमारा लक्ष्य है। दिल्ली की नई सरकार से हर वर्ग को अपेक्षा है। आम आदमी पार्टी ने जिस तरह की जीत दोबारा प्राप्त की है, उसके पीछे समाज के हर एक व्यक्ति का सहयोग है। इस बात का ध्यान नई सरकार के कामकाज में भी रखा जाएगा। जो वंचित हो, उसे भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके, इसकी पूरी व्यवस्था की जाएगी।

दिल्ली को बनाया जाएगा विश्व स्तर का शहर : इमरान हुसैन : कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन ने कहा कि नई सरकार दिल्ली को विश्व स्तर का शहर बनाना चाहती है। इसी को ध्यान में रखकर चुनाव घोषणापत्र और मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड को तैयार किया गया था। अब इसे तेजी से लागू करने पर जोर होगा। जिससे जनता ने जिस उम्मीद से अरविंद केजरीवाल को फिर से मुख्यमंत्री चुना है, उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके।

होली के बाद आएगा दिल्ली का बजट : सिसोदिया

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : दिल्ली का बजट होली के बाद आएगा। पदभार संभालने के बाद उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने वित्त विभाग के अधिकारियों की बैठक बुलाई। उन्होंने अधिकारियों से बजट तैयार करने के लिए तेजी से काम करने के लिए कहा। साथ ही वित्त विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के उन्मूलन की जरूरत पर बल दिया। कहा कि विभागीय भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए सख्त कदम उठाने जरूरी हैं। राजस्व संबंधी प्रभावी लक्ष्यों की स्थापना हमारा अगला कार्य होना चाहिए।

सिसोदिया ने शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे स्कूलों के बुनियादी ढांचे में सुधार लाने और नई कक्षाएं बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने पर ध्यान दें। उन्होंने कहा कि हमें अपने स्कूलों के बुनियादी ढांचे में सुधार लाने पर काम करना जारी रखना होगा। इसके अलावा स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने में तेजी लाने और छात्रों के लिए और अधिक नई कक्षाएं सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। सिसोदिया ने एसएमसी (स्कूल प्रबंधन समिति) के प्रभावी उपयोग पर भी बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्कूलों की बाहरी दीवारों और साइन बोर्डों की दीवारों को भी ठीक कराने के लिए कहा।

न्यूज गैलरी

सार्वजनिक स्थानों से अवैध होर्डिंग हटाएं : हाई कोर्ट

नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) को सार्वजनिक सुरक्षा और संपत्तियों के लिए खतरा पैदा करने वाले सार्वजनिक स्थानों पर लगे सभी अवैध होर्डिंग को हटाने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने सार्वजनिक स्थानों पर अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। मुख्य पीठ ने कहा कि नागरिक निकाय 2017 की आउटडोर विज्ञापन नीति की शर्तों का पालन करते हुए अवैध होर्डिंग को हटाया जाए। मुख्य पीठ ने कहा कि ऐसे में अब आगे अवैध होर्डिंग को हटाने और नीति के उल्लंघन के मामले की निगरानी की जरूरत नहीं है। (जासं)

सफदरजंग में सामने आए डेंगू व चिकनगुनिया के मामले

नई दिल्ली : कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच स्वाइन फ्लू के मामले भी देखे जा रहे हैं। साथ ही अब तो डेंगू, चिकनगुनिया व मलेरिया के मामले भी सामने आ रहे हैं। सफदरजंग अस्पताल में डेंगू के नौ मामलों की पुष्टि हुई है। 30 मरीजों के चिकनगुनिया से पीड़ित होने की बात सामने आई है। अस्पताल के अनुसार चिकनगुनिया के 130 संदिग्ध मरीज भी भर्ती हैं। सफदरजंग अस्पताल में डेंगू के अभी जो मामले आए हैं, उनमें दिल्ली के अलावा बिहार, उत्तराखंड व हरियाणा से आए मरीज भी शामिल हैं। अस्पताल का कहना है कि 130 संदिग्ध मरीजों की जांच की जा रही है। (जासं)

इग्नू के दीक्षा समारोह में छात्रों को डिग्री व डिप्लोमा दिया

नई दिल्ली : इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विवि (इग्नू) के मुख्यालय में 33वें दीक्षा समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में सफल दो लाख 31 हजार 622 विद्यार्थियों को डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण पत्र दिए गए। मुख्य अतिथि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 50 से अधिक मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए। निशंक ने कहा कि आपके द्वारा अर्जित उपलब्धियां आपके शिक्षकों और आपके माता-पिता के आशीर्वाद के कारण हैं जिन्होंने आपका मार्गदर्शन किया और आपको सुविधाएं प्रदान की। (जासं)

दिल्ली में युवा चेहरे पर दांव लगा सकती है कांग्रेस

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली

- अंतरिम प्रभारी समझ रहे अभी दिल्ली का मिजाज, 20 या 21 को पदभार संभालने के बाद करेंगे नेताओं से चर्चा

20 या 21 को दिल्ली का प्रभार संभाल लूंगा। प्रभार संभालने के बाद दिल्ली के नेताओं से यहां की स्थिति पर चर्चा भी करेंगे और देखेंगे कि यहां संगठन को मजबूत करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है।
-शक्ति सिंह गोहिल, अंतरिम प्रभारी, दिल्ली कांग्रेस

विधानसभा चुनाव में शिकस्त के बाद से नेतृत्वविहीन चल रही दिल्ली कांग्रेस की कमान इस बार किसी युवा चेहरे के हाथ आ सकती है। पार्टी ऐसा नेतृत्व चाह रही है जो उत्साही हो और संगठन को फिर से खड़ा करने के लिए मेहनत करने का दम-खम रखता हो।

पार्टी सूत्र बताते हैं कि शीर्ष नेतृत्व दिल्ली के लिए युवा नेतृत्व तलाश रहा है। इस बार कांग्रेस किसी ऐसे नेता पर दांव नहीं लगाना चाह रही जो खुद कुछ न कर सके। पार्टी का मानना है कि अनुभवी नेताओं का अहम भी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहा है। हालांकि नए अध्यक्ष के रूप में पार्टी एक खूबी यह भी चाह रही है कि वह दिल्ली की नब्ज पकड़ना जानता हो।

बहरहाल, दिल्ली कांग्रेस को नया सेनापति मिलने में अभी थोड़ा वक्त लगने की संभावना है। कारण, पार्टी ने जिन शक्ति सिंह गोहिल को राजधानी का अंतरिम प्रभारी बनाया है, अभी वह दिल्ली का सियासी मिजाज समझ रहे हैं। गुरुवार को पूर्व प्रभारी पीसी चाको केरल से दिल्ली आएंगे तो उसी दिन या फिर शुक्रवार को वह उनसे दिल्ली प्रभारी का कार्यभार लेंगे। इसके बाद वह चाको से फीडबैक लेकर अगले कुछ दिनों में दिल्ली के नेताओं से मिलना शुरू करेंगे। इसी के आधार पर वह अपनी रिपोर्ट बनाएंगे, जो बाद में पार्टी अध्यक्ष को सौंपेंगे।

इस बीच दिल्ली के विभिन्न नेता न केवल अपने लिए लॉबिंग कर रहे हैं, बल्कि अपने-अपने आका के यहां हाजिरी लगाते हुए अपना नाम आगे बढ़ाने के लिए अनुनय-विनय भी कर रहे हैं। कुछ नेता सीधे सोनिया गांधी से भी मुलाकात कर रहे हैं।

मसलन, पूर्व विधायक अलका लांबा ने भी दो दिन पूर्व सोनिया से मुलाकात कर दिल्ली में पार्टी की हार और संगठन की स्थिति पर चर्चा की। उनकी इसी मुलाकात के आधार पर सोमवार को अलका के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के कयास भी लगाए जाते रहे। दूसरी तरफ दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में कांग्रेस दल के नेता अभिषेक दत्त के भी सोनिया गांधी से मिलने की चर्चा है।

फेज चार में यमुना पर बनेगा 560 मीटर लंबा मेट्रो का पुल

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : फेज-चार की मेट्रो परियोजनाओं को अब रफ्तार मिलने की उम्मीद है। खास बात यह है कि फेज-चार के मजलिस पार्क-मौजपुर कॉरिडोर पर मेट्रो का पांचवा पुल बनेगा। इसकी लंबाई 560 मीटर होगी। यह पुल सिग्नेचर ब्रिज से महज 213 मीटर की दूरी पर होगा। यह कॉरिडोर बनकर तैयार होने और इस पर परिचालन शुरू होने पर मेट्रो से सिग्नेचर ब्रिज की खूबसूरती यात्रियों को आकर्षित करेगी। मजलिस पार्क-मौजपुर कॉरिडोर के निर्माण के लिए टेंडर जारी हो चुका है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) के अनुसार यह पुल यमुना पर मौजूद ओल्ड वजीराबाद व सिग्नचेर ब्रिज के बीच बनेगा जो सिग्नेचर ब्रिच से 213 मीटर आगे और ओल्ड वजीराबाद पुल से 385 मीटर पहले स्थित होगा।

मेट्रो का यह पुल मजलिस पार्क-मौजपुर कॉरिडोर के सूरघाट व सोनिया विहार मेट्रो स्टेशन को जोड़ेगा। इसका निर्माण होने पर रिंग रोड की तरह मेट्रो का पिंक रिंग कॉरिडोर बन जाएगा। मौजूदा समय में यमुना पर चार मेट्रो पुल है।

भाजपा प्रत्याशी भेज रहे बंद लिफाफे में शिकायत

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

भाजपा में हार पर मंथन चल रहा है। विधानसभा चुनाव में जिम्मेदारी संभाल रहे नेताओं के साथ बात करने के बाद अब कार्यकर्ताओं के साथ मंथन होगा। विधानसभा स्तर पर वरिष्ठ नेता कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। इन बैठकों में प्रत्याशी को भी शामिल किया जाएगा। कई प्रत्याशी हार के कारण व अपनी शिकायत लिखकर प्रदेश नेतृत्व को भेज रहे हैं।

विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के असली कारण जानने के लिए तीन दिनों तक प्रदेश कार्यालय में मंथन चला। विस विस्तारक, प्रभारी व संयोजक के साथ ही पार्षदों और चुनाव प्रबंधन समितियों के सदस्यों के साथ राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने बैठक की। अधिकांश लोगों ने गुटबाजी, प्रत्याशियों के चयन में देरी, घोषणा पत्र में देरी और कुछ नेताओं की नफरत वाले बयान को हार का कारण बताया है। सोशल मीडिया टीम के कार्यकर्ताओं के साथ भी चर्चा की गई है। उनसे सोशल मीडिया पर भाजपा के साथ ही दूसरी पार्टियों के चुनाव अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल की गई। प्रत्याशियों के साथ बैठक होनी है, लेकिन इससे पहले ही उन्होंने अपना संदेश बंद लिफाफे में भेजना शुरू कर दिया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि जल्द ही वरिष्ठ नेता प्रत्याशियों के साथ बैठक करेंगे। इसके साथ ही 19 फरवरी से विधानसभा स्तर पर वहां के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की जाएगी। ज्यादातर विधानसभाओं में 19 व 20 फरवरी को बैठक हो जाएगी। प्रत्येक बैठक में राष्ट्रीय स्तर का और प्रदेश का कोई नेता शामिल होगा। इन बैठकों में बूथ कार्यकर्ताओं को भी बुलाया जाएगा। इस बार पार्टी ने बूथ प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया था। प्रत्येक दस घरों की जिम्मेदारी एक कार्यकर्ता को सौंपी गई थी। बावजूद इसके भाजपा उम्मीदवारों को समर्थन नहीं मिला।

दिल्ली सरकार से डीएसजीपीसी भंग कर चुनाव कराने की मांग

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

शिरोमणि अकाली दल दिल्ली (सरना) ने दिल्ली सरकार से दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डीएसजीपीसी) को भंग करने और फिर से चुनाव कराने की मांग की है। पार्टी के अध्यक्ष परमजीत सिंह सरना ने कहा कि कमेटी के पदाधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। पूर्व अध्यक्ष मनजीत सिंह जीके के खिलाफ अदालत में मामला चल रहा है और मौजूदा अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा व अन्य पदाधिकारी खुद को बचाने में लगे हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले दिनों कमेटी की जनरल हाउस की बैठक में फर्जी दस्तावेज पेश किए गए। उन्होंने जनरल हाउस की बैठक में जीके की सदस्यता खत्म किए जाने से संबंधित फैसले पर भी प्रश्न उठाया। उन्होंने कहा कि वह भ्रष्टाचार के किसी आरोपित के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन कमेटी को यह बताना चाहिए कि किस नियम के तहत सदस्यता समाप्त करने का फैसला किया गया है। जीके जब अध्यक्ष थे, उस समय सिरसा महासचिव थे, इसलिए अनियमितता के लिए दोनों दोषी हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि हरिनगर स्थिति गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अवतार सिंह हित के हवाले करने की साजिश चल रही है। वर्षों पहले अकाल तख्त ने हित को यह स्कूल डीएसजीपीसी को वापस करने का निर्देश दिया था। उन्होंने कमेटी के खातों की जांच कराने की भी मांग की। इस मौके पर पार्टी के महासचिव हरजिंदर सिंह सरना सहित अन्य नेता मौजूद थे।

सिरसा ने आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल का मालिकाना अधिकार डीएसजीपीसी के पास है और रहेगा। इसे लेकर दुष्प्रचार किया जा रहा है। स्कूल की इमारत कमेटी के पैसे से तैयार की गई है। स्कूल के कर्मचारियों को वेतन व अन्य सुविधाएं भी कमेटी अपने फंड से देती है। विरोधी इस स्कूल को बेचने का दुष्प्रचार कर रहे हैं जिसमें कोई सच्चाई नहीं है।

गार्गी कॉलेज मामले में केंद्र और सीबीआइ को नोटिस

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : गार्गी कॉलेज में छात्राओं के साथ हुई छेड़छाड़ के मामले की जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार व सीबीआइ को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने दोनों से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी को इस पर सुनवाई करने से इन्कार करते हुए याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कुछ घंटे बाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। याचिकाकर्ता ने मांग की कि घटना से जुड़े सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को संरक्षित रखा जाए और इस सुनियोजित आपराधिक साजिश के पीछे छिपे लोगों को गिरफ्तार किया जाए। आरोप लगाया कि दिल्ली चुनाव के दौरान राजनीतिक व आपराधिक साजिश रची गई और इस घटना के बाद कोई कार्रवाई भी नहीं की गई।

6 फरवरी को गार्गी कॉलेज में सांस्कृतिक उत्सव के दौरान बाहर से आए लोगों ने छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की। छात्राओं का आरोप था कि जब घटना हुई तो पुलिस और कॉलेज प्रशासन मूकदर्शक बना सब देख रहा था।

जामिया के वीडियो पर भाजपा-कांग्रेस में संग्राम

नई दिल्ली, प्रेट्र : जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छात्रों के खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई के कुछ वीडियो क्लिप सामने आने के बाद भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी संग्राम छिड़ गया है। भाजपा ने कांग्रेस पर जामिया की घटना को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाते हुए कहा कि वह हमेशा देशविरोधी तत्वों का समर्थन करती है। वहीं, कांग्रेस ने सरकार पर पुलिस बल का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है।

जामिया के पूर्व व मौजूदा छात्रों के संगठन जामिया समन्वय समिति (जेसीसी) ने रविवार को एक सीसीटीवी फूटेज जारी किया था, जिसमें नकाब पहने सुरक्षाकर्मी लाइब्रेरी में छात्रों पर लाठियां बरसाते नजर आ रहे हैं। इसके कुछ देर बाद एक अन्य वीडियो सामने आ गया, जिसमें हाथों में पत्थर लिए और नकाब पहने उपद्रवी छिपने के लिए लाइब्रेरी में घुसते नजर आ रहे हैं। ये दोनों ही वीडियो 15 दिसंबर के बताए गए हैं। दूसरा वीडियो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच का है जो लीक हो गया है। हालांकि इन वीडियो की सत्यता का पता नहीं चल सका है।

भाजपा प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव ने सोमवार को प्रेस कांफ्रेंस में कहा, 'कांग्रेस पार्टी लगातार समाज विरोधी तत्वों और हिंसा फैलाने वालों का समर्थन कर रही है। उसने देश के सुरक्षा बलों और पुलिस के जवानों के खिलाफ आवाज उठाई है।' राव ने कहा कि छात्र नकाब क्यों लगाए हैं और हाथों में पत्थर लेकर वे कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने पूछा कि किस संस्था में छात्र नकाब पहनते हैं और हाथों में पत्थर लेकर जाते हैं। कांग्रेस हमेशा से देश के दुश्मनों के साथ खड़ी होती है और सुरक्षा बलों पर सवाल उठाती है।

भाजपा पर पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने कहा कि सत्तारूढ़ दल रंगे हाथों पकड़ा गया है। उसने पुलिस बल का दुरुपयोग किया है। वह निर्दोष छात्रों पर हमले की दोषी है। अदालत की निगरानी में जामिया हिंसा की जांच कराई जानी चाहिए। कपिल सिब्बल ने भी सरकार पर निशाना साधा है। रविवार को प्रियंका गांधी ने भी सरकार पर हमला किया था और कहा था कि अगर सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो उसकी नीयत देश के सामने आ जाएगी।

घायल छात्र ने मांगा दो करोड़ का मुआवजा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान जामिया मिल्लिया इस्लामिया में हुई हिंसा में घायल हुए छात्र ने याचिका दायर कर दो करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की है। याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र व दिल्ली सरकार के साथ दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने तीनों को नोटिस जारी किया है। छात्र का आरोप है कि 15 दिसंबर 2019 को हुई हिंसा के दौरान वह पुस्तकालय में पढ़ रहा था और लाइब्रेरी में पुलिस द्वारा की गई बर्बर पिटाई में उसके दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए थे। अधिवक्ता नबीला हसन के माध्यम से दायर याचिका में याचिकाकर्ता छात्र शायान मुजीब ने दलील दी है कि उसने अब तक इलाज में दो लाख रुपये खर्च किए हैं। मुआवजे के अलावा याचिकाकर्ता ने पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के मामले में रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की है।

उपलब्धि

एयरपोर्ट पर प्रयोग किए जाने वाले 45 प्लास्टिक उत्पादों को पर्यावरण अनुकूल विकल्पों से बदला गया

आइजीआइ देश का पहला प्लास्टिक मुक्त एयरपोर्ट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आइजीआइ) एयरपोर्ट अब एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त एयरपोर्ट बन गया है। इस बदलाव के लिए वहां लंबे समय से अभियान चलाया जा रहा था। एयरपोर्ट पर प्रयोग किए जाने वाले 45 प्लास्टिक उत्पादों को पर्यावरण अनुकूल विकल्पों से बदला गया है। इस संबंध में एयरपोर्ट संचालक कंपनी को सोमवार को प्रमाण पत्र दिया गया। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के मुताबिक आइजीआइ एकल उपयोग प्लास्टिक का उपयोग न करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट बन गया है।

दरअसल, देश के सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट आइजीआइ को प्लास्टिक से मुक्त कराने की मुहिम छेड़ी गई थी। प्लास्टिक से पर्यावरण और मनुष्य को हो रहे नुकसान के मद्देनजर एयरपोर्ट पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा था। एयरपोर्ट में बड़े स्तर पर प्लास्टिक का प्रयोग हो रहा था। खाने-पीने के बर्तन सहित अन्य चीजों में एजेंसियां प्लास्टिक के पैकेट अथवा पैकिंग का प्रयोग करती थीं, जबकि प्लास्टिक से पर्यावरण को भारी नुकसान होने के साथ ही इसका मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। नुकसान के मद्देनजर एयरपोर्ट पर प्लास्टिक की जगह पूरी तरह पर्यावरण अनुकूल टिकाऊ विकल्पों का प्रयोग शुरू किया गया था। इसके तहत वहां प्लास्टिक की जगह कागज और मिट्टी के बर्तनों में खाने-पीने के सामान परोसे जा रहे हैं। इसके मद्देनजर आइटीसी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ने आइजीआइ एयरपोर्ट को सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री एयरपोर्ट घोषित किया।

दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के प्रवक्ता ने बताया कि वर्तमान में करीब 45 विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक उत्पादों को अन्य विकल्पों के साथ बदल दिया गया है। यही नहीं विकल्पों के प्रयोग से एयरपोर्ट से निकलने वाले प्लास्टिक कचरे की मात्रा भी काफी कम हो गई है। इन कचरे के प्रभावी संग्रह और अलग करने के लिए एयरपोर्ट पर अलग-अलग चार तरह के कूड़ेदान की व्यवस्था की गई है। उसमें कागज, प्लास्टिक, कांच और धातु के अलावा खाद्य अपशिष्ट कचरे को अलग-अलग रखे जाने की व्यवस्था की गई है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के सीइओ विदेह जयपुरिया ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण के तहत प्रधानमंत्री की सोच के अनुरूप एयरपोर्ट पर प्लास्टिक के प्रयोग को हतोत्साहित करने के लिए तमाम कदम उठाए गए। ज्ञातव्य है कि आइजीआइ एयरपोर्ट में यात्रियों की सुविधा के लिए भी समय-समय पर नवाचार किए जाते हैं। यह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट में एक है।

सीइओ विदेह जयपुरिया प्रमाण पत्र के साथ। सौजन्य : डायल

अब आपात स्थिति में बटन दबाते ही पहुंचेगी पुलिस

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- दिल्ली पुलिस ने उबर कैब के साथ मिलकर हिम्मत प्लस क्यूआर कोड योजना की शुरुआत की

दिल्ली पुलिस ने उबर कैब के साथ मिलकर हिम्मत प्लस क्यूआर कोड योजना की शुरुआत उबर टैक्सियों के लिए की है। दिल्ली पुलिस के आयुक्त अमूल्य पटनायक ने इसे लांच किया। इस योजना के तहत उबर इमरजेंसी की एसओएस फीचर को दिल्ली पुलिस के हिम्मत प्लस से जोड़ा गया है। यह एप उबर टैक्सी में क्यूआर कोड से साथ लगा होगा। आपात स्थिति में इसकी मदद से दिल्ली पुलिस मुख्यालय को चालक या सवारी की वास्तविक स्थिति मिल जाएगी। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच कर मुसीबत में फंसे शख्स की जान बचाने में कारगर साबित होगी।

इस योजना को लागू करने के लिए हर उबर चालक को क्यूआर वेरिफिकेशन कार्ड का वितरण किया जाएगा। पुलिस ने अब तक 1000 चालक को हिम्मत क्यूआर कार्ड वितरित कर दिए है। दिल्ली में उबर के चालकों व सवारियों दोनों के लिए उबर एप में इमरजेंसी बटन की सुविधा होती है। इस बटन के इस्तेमाल से अब तक उबर से मदद मिलती थी, लेकिन हिम्मत प्लस के साथ जुड़ने पर पुलिस भी फौरन मदद के लिए पहुंचेगी। अमूल्य पटनायक ने कहा कि इस नई सुविधा से जरूरतमंदों तक मदद फौरन पहुंचाई जा सकेगी। इस अवसर पर उबर के दक्षिण एशिया प्रमुख प्रभजीत सिंह भी उपस्थित थे।

2197 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है छत्तीसगढ़ को जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में सितंबर 2019 तक। इस अवधि तक ओडिशा को 2586 और झारखंड को 1112 करोड़ रुपये मिले हैं।

कांग्रेस में हार पर घमासान सिर फुटव्वल की ओर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली की हार पर कांग्रेस में मचा घमासान अब नेताओं के सिर फुटव्वल की ओर बढ़ने लगा है। हार के कारणों पर चिंतन के बजाय कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेता अजय माकन और मिलिंद देवड़ा की तकरार यहां तक पहुंच गई कि एक ने दूसरे को पार्टी छोड़ने तक की नसीहत दे डाली। दिलचस्प यह भी है कि दिल्ली में हुई दुर्गति पर बेचैन पार्टी नेताओं की चिंता आपसी भिड़ंत की दहलीज तक पहुंच रही है, मगर कांग्रेस नेतृत्व का मौन नहीं टूट रहा।

दिल्ली में पांच साल में कांग्रेस के शून्य से शून्य तक के सफर पर वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम के बयान पर शर्मिष्ठा मुखर्जी सरीखी नई पीढ़ी के नेता के तीखे प्रहार का मामला थमा भी नहीं था कि मिलिंद देवड़ा और अजय माकन आपस में भिड़ गए। इसकी शुरुआत रविवार रात मिलिंद देवड़ा के एक ट्वीट से हुई। अपने ट्वीट में देवड़ा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक विडियो टैग किया। इसमें केजरीवाल अपनी सरकार के वित्तीय प्रबंधन मॉडल के अनुशासन की चर्चा करते हुए पांच साल में राजस्व को दोगुना करने की बात कह रहे हैं। इस पर अपनी राय देते हुए देवड़ा ने कहा कि दिल्ली में यह हो सकता है तो अन्य राज्यों में क्यों नहीं?

अजय माकन

- केजरीवाल मॉडल की मिलिंद देवड़ा ने प्रशंसा की तो ट्विटर पर ही भिड़ गए माकन
- माकन ने देवड़ा को आधे सच की पैरोकारी के बजाय कांग्रेस छोड़ने की दे डाली नसीहत

मिलिंद देवड़ा सभी फाइल

महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता देवड़ा के इस बयान पर बिफरते हुए अजय माकन ने कहा कि देवड़ा कांग्रेस छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ दें, लेकिन दूसरे के आधे-अधूरे सच के बखान से बचें। इसके साथ ही माकन ने देवड़ा को आईना दिखाते हुए दिल्ली में शीला दीक्षित के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के समय बेहतर वित्तीय प्रबंधन के आंकड़ों का हवाला भी दिया। बाद में देवड़ा ने जवाबी वार करते हुए माकन पर तंज कसा कि वह शीला दीक्षित के शानदार प्रदर्शन की माकन की तरह अनदेखी नहीं कर सकते। देर से ही सही, बदलाव हो तो अच्छी बात है। माकन पर दूसरा कटाक्ष करते हुए देवड़ा ने कहा कि अपनी सियासत के लिए आप के साथ चुनावी गठबंधन का प्रयास करने के बजाय अगर शीला दीक्षित के कामों को लेकर मैदान में जाते तो कांग्रेस आज सत्ता में होती। गौरतलब है कि दिल्ली में शीला दीक्षित सरकार में मंत्री रहे माकन की उनसे हमेशा ही खटपट रही।

राकांपा ने किया भीमा-कोरेगांव मामले की समानांतर जांच का एलान

मुंबई, प्रेट्र : महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार में दरार दिखने लगी है। सरकार में शामिल राकांपा ने सोमवार को कहा कि पार्टी नेता और गृह मंत्री अनिल देशमुख यलगार परिषद भीमा-कोरेगांव मामले की विशेष जांच दल (एसआइटी) के जरिये समानांतर जांच के तौर-तरीके तय करेंगे। पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में सरकार ने इसकी जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) को सौंपने को मंजूरी प्रदान कर दी थी। अगर समानांतर जांच हुई तो अलग-अलग निष्कर्षों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच भी तनाव बढ़ सकता है।

मामले की एनआइए जांच की अनुमति देने के उद्धव के फैसले पर सार्वजनिक तौर पर नाखुशी जता चुके राकांपा प्रमुख शरद पवार ने सोमवार को पार्टी के कैबिनेट मंत्रियों की एक बैठक की अध्यक्षता की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता और राज्य के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक ने कहा, 'राकांपा के कैबिनेट मंत्रियों की बैठक में फैसला किया गया कि गृह मंत्री सभी जरूरी प्रक्रियाओं की जांच करेंगे और यलगार परिषद मामले के लिए एसआइटी का गठन करेंगे।' मलिक ने इस संवेदनशील मामले में अलग जांच के फैसले को न्यायोचित बताते हुए कहा, 'कानून के अनुसार किसी एक घटना पर कोई भी राज्य सरकार समानांतर जांच दल का गठन कर सकती है। एनआइए एक्ट की धारा-10 के तहत एक अलग समिति का गठन किया जा सकता है।'

- इस मामले में केंद्र सरकार के साथ भी बढ़ सकता है तनाव

नवाब मलिक फाइल फोटो

पवार ने रविवार को आरोप लगाया था कि केंद्र ने यलगार परिषद मामले की जांच एनआइए को इसलिए सौंपी है क्योंकि पूर्ववर्ती देवेंद्र फड़नवीस सरकार कुछ छिपाना चाहती थी। पवार ने इससे पहले भी मामले की जांच एसआइटी से कराने की मांग की थी। उनका कहना था कि केंद्र को जांच एनआइए को सौंपने से पहले महाराष्ट्र सरकार को विश्वास में लेना चाहिए था।

अभी देश में कुल 17 कमान

प्रथम पृष्ठ से आगे

देश में अभी सेना, नौसेना और वायुसेना के अलग-अलग कुल 17 कमान हैं। इनमें सेना और वायुसेना की सात-सात और नौसेना की तीन कमान शामिल है। इनके अलावा दो थिएटर कमान- अंडमान एवं निकोबार कमान और स्ट्रेटीजिक फोर्सेज कमान, जिसके तहत परमाणु हथियार हैं।

थिएटर कमान के फायदे : सेना के तीनों अंगों के 17 कमान मिलाकर दो से पांच थिएटर कमान के गठन से जहां खर्च में कटौती होगी, वहीं सैन्य बलों के बीच समन्वय बढ़ेगा और उनकी क्षमता मजबूत होगी। थिएटर कमान में सेना, वायुसेना और नौसेना एक इकाई के रूप में काम करेंगे, इसलिए युद्ध की स्थिति में उनके बीच बेहतर तालमेल रहेगा और वो दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई के लिए ठोस रणनीति बना पाएंगे। अभी चीन और अमेरिका के पास इस तरह की व्यवस्था है।

बड़ी खरीद के लिए नीति बनाने की वकालत : जनरल रावत ने सैन्य बलों के लिए बड़ी खरीद के लिए एक नीति बनाने की भी वकालत की। इसमें 114 लड़ाकू विमानों का अधिग्रहण भी शामिल है।

सीडीएस ने कहा कि नौसेना के लिए : विमानवाहक पोत की जगह पनडुब्बी हासिल करना ज्यादा जरूरी है। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता पनडुब्बी हासिल करना है।

पर्यावरण से कोई समझौता नहीं : मोदी

रखी बात ▶ कॉप सम्मेलन में बोले पीएम, भारत में दोगुनी हुई बाघों की संख्या

तीन साल के लिए भारत बना सीएमएस-कॉप का अध्यक्ष

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को जोर देकर कहा कि उनकी सरकार सतत विकास के मार्ग पर दृढ़ता से भरोसा करती है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बगैर इसे हासिल करने की कोशिश कर रही है। भारत उन चुनिंदा देशों में शुमार है जिसके कार्य पेरिस समझौते के लक्ष्यों के अनुरूप हैं।

प्रधानमंत्री वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये गांधीनगर में आयोजित 'वन्य प्राणियों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण' (सीएमएस) पर कांफ्रेंस ऑफ पार्टीज (कॉप) के 13वें सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले भारत ने तीन साल के लिए इस सम्मेलन की अध्यक्षता संभाली। 2017 से फिलीपींस इसका अध्यक्ष था। सम्मेलन में 110 देशों के करीब 1,200 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2010 में भारत में बाघों की संख्या 1,411 थी जो 2022 से काफी पहले ही बढ़कर करीब दोगुनी 2,967 हो गई है। भारत में 60 प्रतिशत एशियाई हाथी हैं, देश में 30 हाथी संरक्षण वन हैं। गुजरात एशियाई शेरों का घर है, आज इनकी आबादी सर्वाधिक 523 तक पहुंच गई है। मोदी ने कहा कि प्रवासी प्राणी इस पृथ्वी को आपस में जोड़ते हैं। भारत में हिम प्रदेश के तेंदुओं, एशियाई शेर, गेंडे, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण पर बल दिया जा रहा है। एशियाई देशों के संगठनों में भारत एक नेतृत्वकर्ता की भूमिका में है और प्रवासी पक्षी व वन्य जीवों के संरक्षण पर जोर देता आया है।

नरेंद्र मोदी फाइल

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विविधता से भरा देश है, भारत का क्षेत्रफल दुनिया का 2.4 है, लेकिन जैव विविधता में हमारा हिस्सा आठ फीसद है। भारत के भौगोलिक विस्तार में 21.67 प्रतिशत भूभाग हरियाली से आच्छादित है। देश का 1.7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वनों से ढका है। भारत की जीवन शैली और संस्कृति पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी है। देश हरित विकास मॉडल के माध्यम से क्लाइमेट एक्शन का समर्थन करता है। इसके लिए इलेक्ट्रिक वाहन, स्मार्ट सिटी, जल संरक्षण पर जोर देने के साथ ही ग्रीन इकोनॉमी को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। मोदी ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक दुनिया के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है, इससे निपटने के लिए मिशन शुरू किया गया है। देश में माइक्रो प्लास्टिक के कचरे से मुक्ति के लिए समुद्री कछुआ नीति पर अमल किया जाएगा।

भारत कई प्रवासी प्राणियों का घर : जावड़ेकर : केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया कि भारत कई प्रवासी पशु-पक्षियों का घर है जिनमें हिम तेंदुएं, समुद्री कछुए, हम्पबेक्ड व्हेल, बार हेड गीज आदि शामिल हैं। भारत ने साइबेरियन क्रेंस, मरीन टर्टल्स, डुगोंस और रेप्टबर्स के संरक्षण के लिए कांफ्रेंस में प्रतिबद्ध देश के रूप में एमओयू पर हस्ताक्षर भी किए हैं। पर्यावरण राज्यमंत्री बाबुल सुप्रियो ने कहा कि दुनिया में 173 प्रजातियां विलुप्तप्राय हैं, इनमें से 10 भारत की हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि पशु पक्षियों का संरक्षण महज नियम-कानूनों से नहीं बल्कि लोक जागृति से होगा।

पाकिस्तान ने नहीं लिया हिस्सा : सम्मेलन के पहले दिन पाकिस्तान सम्मेलन से अनुपस्थित रहा। इस बारे में पूछे जाने पर सूत्रों ने बताया, 'इस समय हमें कुछ नहीं पता है। आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि वे यहां आए हैं। हालांकि उन्होंने पंजीकरण कराया था, लेकिन वे नहीं आए।' कोरोना वायरस के चलते भारत की ओर से लगाए गए यात्रा प्रतिबंधों के चलते चीन ने भी हिस्सा नहीं लिया, लेकिन उसने औपचारिक तौर पर क्षमायाचना की है।

असम के मूल निवासियों को परिभाषित करने के लिए 1951 हो कट-आफ वर्ष

नई दिल्ली, प्रेट्र : गृह मंत्रालय द्वारा नियुक्त एक समिति ने सुझाव दिया है कि असम के मूल निवासियों को परिभाषित करने तथा राज्य के बाहर के लोगों की आवाजाही पर नियंत्रण के लिए इनर लाइन परमिट (आइएलपी) जारी करने का कट-आफ वर्ष 1951 होना चहिए। सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी। समिति ने असम के विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों में मूल निवासियों के लिए सीटों के आरक्षण के लिए भी दो फार्मूले सुझाए हैं। इसमें उनके लिए 67 फीसद आरक्षण का सुझाव शामिल है।

मंत्रालय ने असम के मूल निवासियों को संविधान के तहत सुरक्षा मानक प्रदान करने के उपाय सुझाने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था। सूत्रों ने बताया कि जस्टिस (सेवानिवृत्त) विप्लव कुमार शर्मा की अध्यक्षता वाली 13 सदस्यीय समिति ने पिछले हफ्ते रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया। समिति ने मंत्रालय को बताया कि वह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को रिपोर्ट सौंपने के लिए तैयार है तथा उनसे मिलने के लिए समय भी मांगा। रिपोर्ट इसी सप्ताह गृह मंत्रालय को दी जा सकती है।

सूत्रों के अनुसार, कमेटी ने निर्विरोध सिफारिश की है कि जो लोग 1951 में असम के निवासी थे और उनके वंशजों को राज्य का मूल निवासी माना जाएगा, चाहे उनका समुदाय, जाति, भाषा या धर्म कुछ भी हो। समिति ने यह भी सुझाया कि असम में आइएलपी लानी चाहिए ताकि राज्य के बाहर से लोगों की आवाजाही नियंत्रित की जा सके। नियमों के अनुसार, बाहरी लोगों को उन क्षेत्रों में प्रवेश के लिए निर्दिष्ट अधिकारियों से अनुमति लेनी होती है जहां आइएलपी लागू है। वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड और मिजोरम में आइएलपी लागू है।

- गृह मंत्रालय की समिति ने दिया सुझाव
- असम के विस और लोस क्षेत्रों में मूल निवासियों के लिए सीटों के आरक्षण के लिए भी दो फार्मूले सुझाए

गृह मंत्रालय के कार्यालय की फाइल फोटो।

राज्य इकाइयां करें एनजीटी के ऑनलाइन पोर्टल का प्रचार-प्रसार : नाल्सा

नई दिल्ली, प्रेट्र : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नाल्सा) ने अपनी राज्य इकाइयों को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के ऑनलाइन पोर्टल का प्रचार-प्रसार करने को कहा है। नाल्सा का कहना है कि इससे लोगों के बीच एनजीटी के फैसलों का पता चलेगा और लोग इससे जुड़ी अपनी समस्याओं को लेकर आगे भी आएंगे।

सभी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को संबोधित पत्र में नाल्सा ने कहा है कि भौगोलिक कारणों से दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए एनजीटी और उसकी पीठों तक पहुंचना कठिन होता है। पत्राचार के अनुसार, 'प्रदूषण और पर्यावरण को होने वाले नुकसान के सिलसिले में पीड़ितों की एनजीटी तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इसके अभियानों, शिविरों व ऑनलाइन सुविधाओं के बारे में सूचनाओं का प्रचार-प्रसार करें।' इसके लिए सभी जरूरी उपाय करने को भी कहा गया है।

एनजीटी ने मौजूदा ई-फाइलिंग प्रक्रिया के अतिरिक्त एक नई प्रणाली की शुरुआत की है। हाल ही में एनजीटी चेयरमैन आदर्श कुमार गोयल ने नाल्सा से एनजीटी की नई ऑनलाइन सेवा के बारे में लोगों तक जानकारियां पहुंचाने का आग्रह किया था। उन्होंने इस सेवा के जरिये जरूरतमंद और योग्य लोगों के सहयोग करने का भी आग्रह किया था।

सामुदायिक रसोई पर जवाब नहीं देने वाले राज्यों पर जुर्माना

नई दिल्ली, एजेंसियां : सुप्रीम कोर्ट ने सामुदायिक रसोई को लेकर अपनी योजना की जानकारी नहीं देने वाले पांच राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों पर 10-10 लाख रुपये का जुर्माना ठोका है। इनमें दिल्ली, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा और गोवा शामिल हैं। मामले पर अगली सुनवाई आठ अप्रैल को होगी।

देश भर में खाद्य सुरक्षा योजना लागू करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने पिछले इन राज्यों पर पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना ठोका था। लेकिन इन राज्यों ने न जुर्माना भरा और न ही अदालत के आदेशों का पालन करते हुए हलफनामा ही दायर करना उचित समझा।

इस पर जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने जुर्माने की रकम जमा नहीं कराने पर इन राज्यों के खिलाफ अतिरिक्त पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना ठोक दिया। इस तरह अब इन राज्यों को जुर्माने के रूप में 10-10 लाख रुपये जमा कराने होंगे। कई राज्यों ने जुर्माने को माफ करने की अपील की थी, जिसे पीठ ने ठुकरा दिया। केंद्र सरकार ने कहा है कि वह देश भर में इस योजना को लागू करने को लेकर एक अतिरिक्त हलफनामा दायर करेगी।

याचिका पर पिछले हफ्ते सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पाया था कि सिर्फ सात राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने खाद्य सुरक्षा और सामुदायिक रसोई पर हलफनामा दायर किया है। इन राज्यों में अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, कर्नाटक, पंजाब, उत्तराखंड, झारखंड, नगालैंड और जम्मू-कश्मीर शामिल हैं। पिछली सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि जो राज्य 24 घंटे के भीतर हलफनामा दायर कर देंगे, उन्हे एक लाख रुपये और जो जवाब नहीं दाखिल करेंगे उन्हें पांच लाख रुपये जुर्माना भरना होगा।

- सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते ठोका था पांच-पांच लाख जुर्माना
- सामुदायिक रसोई की स्थापना को लेकर नहीं बताई थी अपनी योजना

प्रतीकात्मक फोटो

याचिका में कहा गया है कि भूख और कुपोषण के चलते प्रतिदिन पांच साल तक की उम्र वाले कई बच्चों की मौत हो रही है। यह स्थिति सही नहीं है क्योंकि यह नागरिकों के खाद्य एवं जीवन के अधिकारों समेत विभिन्न मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। याचिका में केंद्र सरकार को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि वह उन लोगों के लिए एक राष्ट्रीय खाद्य ग्रिड बनाए जो जनवितरण प्रणाली के दायरे से बाहर हैं।

पीडब्ल्यूडी घोटाले में त्रिपुरा के पूर्व मुख्य सचिव गिरफ्तार

अगरतला, आइएएनएस : त्रिपुरा के पूर्व मुख्य सचिव यशपाल सिंह को करोड़ों रुपये के लोकनिर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) घोटाले में सोमवार को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। त्रिपुरा के कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह ने बताया कि उनको दोनों राज्यों की पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि उनका ट्रांजिट रिमांड लेने के लिए पहले उन्हें उत्तर प्रदेश के एक कोर्ट में पेश किया जाएगा। फिर अदालत की इजाजत से उन्हें आगे की कानूनी औपचारिकताओं के लिए अगरतला लाया जाएगा।

यशपाल 2008-09 के दौरान त्रिपुरा में पीडब्ल्यूडी के प्रधान सचिव थे। त्रिपुरा पुलिस की अपराध शाखा 638 करोड़ रुपये की परियोजनाओं के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार के मामले में उनकी तलाश कर रही थी। जांच अधिकारी अजय दास के नेतृत्व में पुलिस दल दिल्ली और उत्तरी त्रिपुरा में कई अन्य स्थानों पर यशपाल की तलाश में गया। अंततः उनको गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया। त्रिपुरा सरकार के सतर्कता विभाग ने पिछले साल 13 अक्टूबर को माकपा नेता और पूर्व पीडब्ल्यूडी और वित्त मंत्री बादल चौधरी, पूर्व मुख्य सचिव यशपाल सिंह और इसी विभाग के मुख्य अभियंता सुनील भौमिक के खिलाफ इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी। चौधरी और भौमिक को पिछले साल 14 और 21 अक्टूबर को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। त्रिपुरा हाई कोर्ट ने दोनों को कुछ सप्ताह पहले जमानत दे दी।

नियुक्ति के लिए जजों के नाम को सरकार 127 दिन में देती है मंजूरी

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया के दौरान सरकार को भेजी गई सिफारिश को मंजूरी देने में उसे औसतन 127 दिन लगते हैं, जबकि शीर्ष अदालत कोलेजियम को इसके लिए 119 दिन का वक्त लगता है।

अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने जस्टिस एसके कौल और जस्टिस केएम जोसेफ की पीठ को बताया कि देश भर के हाई कोर्ट ने 396 खाली पदों में से 199 के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति के वास्ते नामों की सिफारिश तक नहीं की गई है। वेणुगोपाल की दलीलों को ध्यान में रखते हुए, शीर्ष अदालत ने सभी हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से रिक्तियों की आज तक की मौजूदा स्थिति और भविष्य में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों के बारे में जानकारी मांगी है।

वेणुगोपाल ने कहा, 'आइबी (खुफिया ब्यूरो) सूचनाएं प्राप्त करने के बाद सरकार द्वारा लिए गए दिनों की संख्या 127 है। कोलेजियम द्वारा लिए जाने वाले दिनों की संख्या 119 हैं।' जब पीठ ने आइबी की रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद सरकार द्वारा लिए गए दिनों की संख्या का उल्लेख किया, तो वेणुगोपाल ने कहा, 'मान लीजिए कि एक प्रतिकूल आइबी रिपोर्ट है, तो हमें इसे सत्यापित करना होगा। हम इसे आंख बंद करके आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। सिफारिश किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम द्वारा लिए गए दिनों की संख्या देखें।'

- केंद्र ने कहा, कोलेजियम नामों को मंजूरी देने में लगाता है 119 दिन
- कई हाई कोर्ट ने 199 जजों की नियुक्ति के लिए नाम तक नहीं भेजे

सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत की पीठ ने कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के पहलू पर दो सुझाव हैं। पीठ ने कहा, 'पहला यह देखना है कि यह समय अवधि सभी चरणों में कैसे कम हो और दूसरा यह है कि यदि इसमें बहुत अधिक समय लग रहा है, तो छह महीने पहले नामों की सिफारिश करने के बजाय इस अवधि को एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।' पीठ ने कहा, 'जब सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम किसी नाम को दोबारा भेजता है, तो आप इसे कैसे लंबित रख सकते हैं? क्योंकि कानून के तहत आप इससे बंधे हुए हैं।'

वेणुगोपाल ने कहा कि बांबे, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे कुछ उच्च न्यायालय हैं जिन्हें रिक्तियों की जानकारी देने में लगभग पांच साल लगते हैं। उन्होंने कहा, 'सभी उच्च न्यायालयों को नोटिस जारी करें और उनसे पूछें कि यह देरी क्यों हुई तभी सभी चीजें व्यवस्थित होंगी। इसमें सरकार के कुछ नहीं करने का सवाल ही कहां है?'

पीठ ने टिप्पणी की कि ऐसा देखा गया है कि जब एक बार किसी व्यक्ति की न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति की सिफारिश की जाती है तो उसके खिलाफ शिकायतें दायर होने लगती हैं। इस मामले में शीर्ष अदालत अगली सुनवाई 21 मार्च को करेगी।

नशे के खिलाफ जंग में राज्यों के सुस्त रवैये से केंद्र खफा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : नशे की गिरफ्त में गंभीर रूप से फंसे देश के करीब साढ़े सात करोड़ लोगों को भले ही इससे निकालने की तत्काल जरूरत है, लेकिन राज्य फिक्रमंद नहीं हैं। यह स्थिति तब है, जब केंद्र सभी राज्यों को एक्शन प्लान और पैसा दोनों दे चुका है। दक्षिण के दो राज्यों को छोड़ दें, तो किसी भी राज्य ने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। ऐसे में केंद्र ने अब पूरे मामले को मुख्यमंत्रियों और मुख्य सचिवों के सामने उठाने का निर्णय लिया है।

जल्द ही राज्यों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई जा सकती है। हालांकि राज्यों के इस रुख को लेकर केंद्र की ओर से इस तरह की आपत्ति पहली बार दर्ज नहीं कराई गई है, बल्कि इससे पहले भी अक्टूबर 2019 में की गई समीक्षा में ये मुद्दे उठाए गए थे। उस समय भी राज्यों से एक्शन प्लान के मुताबिक, तेजी से काम शुरू करने को कहा गया था।

केंद्र अब तक राज्यों को दो किश्तों में 57 करोड़ रुपये दे भी चुका है। हालांकि पूरे एक्शन प्लान के तहत केंद्र ने करीब 450 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनाई है। वित्त वर्ष 2020- 21 के बजट में भी इसे लेकर 260 करोड़ का प्रावधान किया गया है। एक्शन प्लान के तहत नशे की गिरफ्त में गंभीर रूप से फंसे लोगों के तत्काल उपचार की जरूरत बताई गई है। इसके तहत नशा मुक्ति केंद्रों को बेहतर बनाने और उन्हें स्वास्थ्य केंद्रों से जोड़ने जैसे कदम उठाए गए हैं।

एम्स दिल्ली की मदद से कराए गए सैंपल सर्वे के मुताबिक, देश में मौजूदा समय में करीब 28 करोड़ लोग नशे की गिरफ्त में हैं। इनमें करीब साढ़े सात करोड़ लोग गंभीर रूप से गिरफ्त में हैं जिन्हें तत्काल उपचार की जरूरत है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने इस रिपोर्ट के बाद ही नशे से निपटने के लिए नेशनल एक्शन प्लान को अंतिम रूप दिया था।

कह के रहेंगे माधव जोशी

सख्त रुख

सुप्रीम कोर्ट ने धर्म और विभिन्न पंथों से संबंधित मौलिक अधिकारों के सात सवाल तैयार किए हैं, इन मुद्दों से निबटने के लिए न्यायिक नीति भी तैयार करेगी नौ जजों की संविधान पीठ

चढ़ावे का दुरुपयोग हो, तो नियंत्रित कर सकता है कानून

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मंदिरों में चढ़ावा देना धार्मिक गतिविधि हो सकती है। लेकिन अगर इस धन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए और कैसिनो चलाने के लिए होता है, तो कानून इसे नियंत्रित कर सकता है। अदालत ने कहा कि नर बलि और सती की पुरानी प्रथा कानून के तहत हत्या है और इसे आवश्यक धार्मिक प्रथा के आधार पर नहीं बचाया जा सकता है।

उच्चतम न्यायालय की नौ सदस्यीय संविधान पीठ ने सोमवार को धार्मिक स्वतंत्रता के दायरे से संबंधित मुद्दों पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। न्यायालय इस मुद्दे पर भी विचार कर रहा है कि क्या कोई व्यक्ति किसी आस्था विशेष से संबंधित नहीं होने के बाद भी उस धर्म की धार्मिक परंपराओं पर सवाल उठाते हुए जनहित याचिका दायर कर सकता है? प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने धर्म और विभिन्न पंथों से संबंधित मौलिक अधिकारों के बारे में सात सवाल तैयार किए हैं। यह पीठ इन मुद्दों से निबटने के लिए एक न्यायिक नीति भी तैयार करेगी।

सुप्रीम कोर्ट फाइल

सबरीमाला पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उठे मुद्दे
वकीलों के एक वर्ग ने 14 नवंबर, 2019 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के फैसले को अस्पष्ट बताया था। उनका कहना था कि कुछ तथ्यों के बिना इन मुद्दों को तय नहीं किया जा सकता है। इसके बाद इन मुद्दों को नए सिरे से तैयार किया गया है। ये मुद्दे सबरीमाला मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उठे हैं।

केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बहस शुरू करते हुए संविधान के अंतर्गत धार्मिक रिवाजों और उनके प्रचार के मौलिक अधिकारों के बारे में सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि सरकार और न्यायालय को धर्म के पंथनिरपेक्ष हिस्से को नियंत्रित करने का अधिकार है। संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति आर भानुमति, अशोक भूषण, एल नागेश्वर राव, एमएम शांतनगौदर, एस अब्दुल नजीर, आर सुभाष रेड्डी, बीआर गवई और सूर्यकांत शामिल हैं।

पीठ ने 10 फरवरी को संविधान के तहत धार्मिक स्वतंत्रता और आस्था से संबंधित मुद्दों से जुड़े सात सवाल तैयार किए थे। इनमें यह सवाल भी शामिल है कि क्या कोई व्यक्ति किसी धर्म या धार्मिक पंथ विशेष का सदस्य नहीं होते हुए भी उस धर्म से जुड़ी आस्थाओं पर जनहित याचिका के माध्यम से सवाल उठा सकता है?

एक सवाल है कि संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत व्यक्तियों के अधिकार और अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक संप्रदाय के अधिकारों के बीच अंतर क्या है? एक और सवाल यह है कि क्या अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक संप्रदाय का अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अलावा अन्य मौलिक अधिकारों के अधीन है।

THE STUDY
प्राचीन भारत
से नया बैच प्रारंभ
-मणिकांत सिंह
20th FEB
8:00 AM
210, VIRAT BHAWAN, NEAR POST OFFICE
MUKHERJEE NAGAR, DELHI-110009
9999516388, 9999278966, 42870015

70 करोड़ रुपये नए वित्तीय वर्ष में मिलेंगे कुपोषण की जंग लड़ रहे उत्तराखंड को केंद्र सरकार से बतौर अनुदान। यह कदम 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के बाद उठाया जा रहा है।

साप्ताहिक अवकाश के लिए हाई कोर्ट पहुंचे हरियाणा के पुलिसकर्मी, लेकिन राहत नहीं

दयानंद शर्मा, चंडीगढ़

साप्ताहिक अवकाश के लिए हरियाणा के पुलिसकर्मियों ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन सोमवार को हाई कोर्ट ने इसे प्रशासनिक विषय करार देते हुए इस मामले में किसी भी तरह का आदेश जारी करने से इन्कार कर दिया। साथ ही याची को इस विषय को सरकार के सामने उठाने का निर्देश दिया। बता दें हरियाणा सरकार के मुखिया मनोहर लाल ने 2017 में पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने की घोषणा कर दी थी, लेकिन इसे आज तक अमलीजामा नहीं पहनाया जा सका है। कभी बिगड़ी कानून व्यवस्था तो कभी पुलिस कर्मियों की संख्या में कमी का बहाना बनाकर पुलिस वालों को साप्ताहिक अवकाश से वंचित रखा जा रहा है।

नियम साप्ताहिक अवकाश देने और पूरे दिन में अलग-अलग शिफ्टों की बजाय एक बार ही मात्र आठ घंटे ड्यूटी लेने का है, लेकिन पुलिस के आला अधिकारी इस नियम का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। याचियों का आरोप है कि हरियाणा के करीब 65 हजार पुलिस वाले तनाव की जिंदगी जी रहे हैं। इन पुलिस वालों को न तो साप्ताहिक अवकाश मिलता है और न ही आठ घंटे की ड्यूटी लगाई जा रही है।

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट। फाइल

देनी पड़ रही 12 से 16 घंटे ड्यूटी : हाई कोर्ट में मदन पाल व अन्य ने याचिका दायर कर सभी पुलिस स्टेशन व पुलिस चौकी में कार्यरत पुलिस कर्मियों के लिए काम के आठ घंटे तय करने व साप्ताहिक अवकाश देने की मांग की है। हाई कोर्ट को बताया या कि हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में पुलिस एक्ट के अनुसार उनको 24 घंटे सातों दिन ड्यूटी पर माना जाता है। व्यवस्था ऐसी है कि एक पुलिस वाले को दिन में 12 से 16 घंटे ड्यूटी पर रहना पड़ता है और वह भी बिना किसी सप्ताहिक अवकाश के। ऐसे में इसका बुरा प्रभाव उनकी सेहत और कार्यप्रणाली पर पड़ता है।

उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ने भी की थी वकालत : दरअसल पुलिस कर्मियों की आठ घंटे की ड्यूटी के नाम पर उनसे शिफ्ट में काम लिया जा रहा है। उदाहरण के लिए एक पुलिसकर्मी से दो घंटे अलग समय, चार घंटे अलग समय और बाकी बचे दो घंटे रात के समय ड्यूटी कराई जाती है। इस तरह इन पुलिस कर्मियों को पूरे 24 घंटे काम में जूझना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह इस व्यवस्था के खिलाफ हैं। पुलिस सुधारों की दिशा में काम करने वाले प्रकाश सिंह ने अपनी रिपोर्ट में पुलिस को साप्ताहिक अवकाश देने और उनके काम के नियमित घंटे निर्धारित करने का मुद्दा कई बार उठाया, लेकिन अधिकतर राज्य इसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं। कुछ राज्यों में हालांकि पुलिस कर्मियों को वीकली ऑफ देने की परंपरा शुरू की गई है।

आंदोलन के बाद मिलना था ऑफ, लेकिन नहीं मिला : हरियाणा में जब जाट आरक्षण आंदोलन चरम पर था, तब तत्कालीन डीजीपी डॉ. केपी सिंह ने भरोसा दिलाया था कि पुलिस कर्मियों को आंदोलन के बाद शांति की स्थिति में साप्ताहिक अवकाश दिया जाएगा, मगर यह व्यवस्था अब तक धरातल पर नहीं उतरी।

थप्पड़ कांड में राजगढ़ कलेक्टर निधि को राहत मिलना तय

राज्य ब्यूरो, भोपाल : मध्य प्रदेश के बहुचर्चित थप्पड़ कांड में राजगढ़ की कलेक्टर निधि निवेदिता को राहत मिलना तय माना जा रहा है। एएसआइ नरेश शर्मा को कलेक्टर द्वारा थप्पड़ मारने की शिकायत की उच्चस्तरीय जांच में पुष्टि नहीं हुई है। भोपाल से भेजे गए जांच अधिकारी प्रमुख सचिव संजय दुबे और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक उपेंद्र जैन की रिपोर्ट में कलेक्टर और एएसआइ के साथ मौके पर गए पुलिस वाहन के ड्राइवर ने भी घटना से इन्कार किया है। दुबे ने सोमवार को मप्र के गृह विभाग को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। अब इसे अंतिम निर्णय के लिए मुख्य सचिव सुधिरंजन मोहंती के माध्यम से मुख्यमंत्री कमलनाथ को भेजा जाएगा।

जांच अधिकारियों ने राजगढ़ जाकर राजस्व और पुलिस के अधिकारियों से बंद कमरे में अलग-अलग बात की थी। इस दौरान कलेक्टर और पुलिस वैन के चालक के भी बयान लिए गए। कलेक्टर के ड्राइवर ने जहां घटना से साफ इन्कार किया है, वहीं, एएसआइ के ड्राइवर ने सिर्फ इतना कहा, साहब ने बताया कि मैडम ने झकझोरा है। वहीं, मौके पर ड्यूटी कर रहे राजस्व और पुलिस के अधिकारियों व कर्मचारियों ने भी घटना होने को लेकर साफ-साफ कुछ भी नहीं कहा।

कमलनाथ–सिंधिया विवाद के बीच राज्यसभा चुनाव पर सियासी दांवपेच

रवींद्र कैलासिया, भोपाल

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच बढ़ती कड़वाहट के दौर में राज्यसभा चुनाव पर राजनीतिक दांवपेच शुरू हो गए हैं। माना जा रहा है कि सिंधिया को राज्यसभा में जाने से रोकने के लिए उनके विरोधियों ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के नाम की मांग का दांव खेला है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह समेत कई और नेता भी इस कतार में हैं, जो सिंधिया की राह में रोड़े अटका सकते हैं।

सिंधिया के सड़क पर उतरने के बयान के बाद प्रदेश कांग्रेस में उन्हें किनारे करने की कोशिश शुरू कर दी गई है। सूत्र बताते हैं कि राज्यसभा चुनाव को टारगेट बनाकर यह प्रयास चल रहे हैं और प्रियंका गांधी का नाम मध्य प्रदेश की एक सीट से चर्चा में लाकर इन कोशिशों को परवान चढ़ाया जाए। बताया जाता है कि राज्यसभा की रिक्त होने वाली तीन सीटों में से कांग्रेस को दो सीटें मिलना तय हैं, जिनमें एक सीट को इस तरह सुरक्षित बताकर दूसरी सीट पर वैकल्पिक नामों में सिंधिया-दिग्विजय के बीच प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति बनाने का प्रयास है। संगठन से जुड़े वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि इस स्थिति में प्रदेश व हाईकमान में दिग्विजय सिंह के नाम पर सहमति बनाकर सिंधिया को दौड़ से बाहर किया जा सकता है। वहीं, कुछ वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश से राज्यसभा में नहीं जाएंगी, क्योंकि वे अपनी राजनीति का केंद्र उत्तर प्रदेश को ही रखना चाहेंगी।

मतभेद नहीं, मनभेद भी नजर आए : प्रदेश में कांग्रेस सरकार बने सवा साल हो चुका है, लेकिन दिग्गज नेताओं और उनके समर्थकों की तल्ख बयानबाजी से लगता है कि पार्टी में भीतर सबकुछ ठीक नहीं है। नेताओं के बीच मतभेद ही नहीं, मनभेद भी नजर आने लगे हैं। प्रदेश के दिग्गज नेता, सिंधिया और उनके समर्थक कई बार सरकार के कामकाज व दिग्विजय सिंह की दखलंदाजी को लेकर तीखे तेवर भी दिखाते रहते हैं। वहीं, कमलनाथ के करीबी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा हों या वरिष्ठ मंत्री डॉ. गोविंद सिंह, सिंधिया और उनके समर्थकों की बयानबाजी पर सरकार का बचाव करते दिखते हैं।

राजनीतिक गलियारों में कांग्रेस नेताओं की खेमेबाजी नई नहीं है। आज की स्थिति में माना जाता है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में प्रमुख रूप से कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे हैं, जिनके इर्द-गिर्द सियासत चलती है। इनके अलावा पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अरण यादव के गुट भी प्रदेश कांग्रेस की सियासत को प्रभावित करते रहते हैं। इन सभी में सिंधिया सबसे अलग हैं। क्योंकि अन्य सभी मौका आने पर एक-दूसरे से समन्वय कर राजनीति करते रहते हैं।

'हनुमान चालीसा का पाठ शक्ति देगा' : वचन पत्र को लेकर सिंधिया के बयान पर गरमा रही राजनीति पर अब विपक्ष के नेताओं ने भी चुटकी लेनी शुरू कर दी है। सोमवार को इंदौर से विधायक रमेश मेंदोला ने सिंधिया को चिट्ठी लिखी। हनुमान चालीसा पढ़ने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि वचन पत्र की याद दिलाने के बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आपके साथ जैसा व्यवहार किया है, वह पीड़ादायी है। पितृेश्वरधाम हनुमान मंदिर के प्राण-प्रतिष्ठा समारोह में विधायक मेंदोला ने सिंधिया को आमंत्रित करते हुए कहा कि यहां चल रहा हनुमान चालीसा पाठ आपके साथ पार्टी में हो रहे अन्याय से लड़ने और जीतने की शक्ति देगा। विधायक ने ग्वालियर के पते पर पत्र के साथ आयोजन का आमंत्रण कार्ड भी भेजा है।

न्यूज गैलरी

उप्र में भाजपा के विरुद्ध विपक्ष को एकजुट करेंगे शरद पवार

लखनऊ : महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के गठबंधन से चल रही सरकार का फार्मूला दोहराने की उत्तर प्रदेश में भी कोशिश की जाएगी। एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार उत्तर प्रदेश में सभी विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर लाकर भाजपा के खिलाफ ताल ठोंकने की तैयारी कर रहे हैं। उप्र और केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ आंदोलन का खाका खींचने के लिए एनसीपी का राज्य प्रतिनिधि सम्मेलन 20 फरवरी को लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। राज्य प्रतिनिधि सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को युवाओं, किसानों, महिलाओं और व्यापारियों के मुद्दों को गर्माने के लिए शरद पवार गुरुमंत्र देंगे। बैठक में एनसीपी के पैर यूपी में जमाने के लिए कार्यकर्ताओं से विचार–विमर्श किया जाएगा। एनसीपी के अध्यक्ष केके शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम में एनसीपी के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल भी शामिल होंगे। सम्मेलन में महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक और जितेंद्र अहवाड़ भी शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि यूपी में बेरोजगारी बढ़ रही है और लोगों में आपसी वैमनस्यता का भाव बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में इसके खिलाफ व्यापक जनआंदोलन होगा। (राब्यू)

विधायक सिमरजीत बैंस के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

पटियाला : पंजाब के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री व मौजूदा स्थानीय निकाय मंत्री ब्रह्म मोहिंदरा पर दवा सप्लाई के टेंडर चहेतों को देने के बयान के डेढ़ साल बाद लोक इंसाफ पार्टी के विधायक सिमरजीत सिंह बैंस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बैंस के खिलाफ पटियाला की अदालत ने मानहानि केस में गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। वारंट थाना सिविल लाइन पुलिस को भेजे गए हैं, ताकि पुलिस बैंस को गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर सके। ब्रह्म मोहिंदरा ने विधायक बैंस के खिलाफ पटियाला की अदालत में मानहानि का केस अगस्त 2018 में दायर किया था। इस मामले में सात बार अदालत में पेश होने के लिए बैंस को वारंट जारी किया गया, लेकिन वह पेश नहीं हुए। मंत्री के वकील गुरप्रीत भसीन ने कहा कि अदालत ने 14 फरवरी को बैंस के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। आदेश की कॉपी सोमवार को प्राप्त हुई है। सिमरजीत सिंह बैंस के पास गिरफ्तारी से बचने के लिए दो ही रास्ते बचे हैं या तो उन्हें खुद अदालत में पेश होकर जमानत करवानी होगी, नहीं तो वह अग्रिम जमानत हासिल करें। अदालत ने बैंस को छह मार्च तक अदालत में पेश करने के लिए पुलिस को वक्त दिया है। (जासं)

14 साल बाद मरांडी की घर वापसी, झाविमो का भाजपा में विलय

साथ–साथ ▸ अमित शाह की मौजूदगी में हजारों कार्यकर्ताओं संग थामा पार्टी का दामन

बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और रघुवर दास की तिकड़ी के हाथ में रहेगा नेतृत्व

राज्य ब्यूरो, रांची

झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी सोमवार को भाजपा में वापस लौट आए। 2006 में उन्होंने भाजपा छोड़कर झारखंड विकास मोर्चा का गठन किया था। हालिया विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार के बाद बाबूलाल मरांडी की वापसी की कवायद शुरू हुई थी। लगभग दो माह तक कई दौर की बैठकों के बाद इस पर मुहर लगी। 11 फरवरी को बाबूलाल मरांडी ने झारखंड विकास मोर्चा का विलय भाजपा में करने की घोषणा की थी। सोमवार को रांची के जगन्नाथ मैदान में भाजपा ने उन्हें हाथोंहाथ लिया। हजारों झाविमो कार्यकर्ताओं का भी स्वागत हुआ। मंच से पूर्व भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने जहां उनकी खूब सराहना की, वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी प्रशंसा के पुल बांधे। गदगद बाबूलाल

रांची में सोमवार को झारखंड विकास मोर्चा के भाजपा में विलय के ऐलान के दौरान झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने गृहमंत्री अमित शाह का कुछ यूं अभिवादन किया। प्रेट्र

मरांडी ने इसे घर वापसी बताते हुए कहा कि उन्हें पद का लोभ नहीं है। भाजपा अगर उन्हें झाड़ू लगाने का भी काम देगी तो भी वह करेंगे।

अमित शाह ने कहा, मैं यहां आकर बहुत प्रसन्न हूं। खुशी की बात है, आज कई सालों बाद बाबूलाल मरांडी ने फिर से भाजपा के कमल का निशान लेकर घर वापसी की है। कभी आपको नहीं लगेगा कि आप कहीं बाहर से आए हैं। शाह ने कहा कि झारखंड की महान भूमि को राज्य की पहचान देने का काम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। जब राज्य में पहली बार हमें मौका मिला, बाबूलाल मरांडी को ही हमने मुख्यमंत्री बनाया। कुछ निजी कारणों से, कुछ संगठनात्मक कारणों से बाबूलाल ने पार्टी छोड़ दी थी। एक लंबा अरसा, स्वतंत्र अस्तित्व के एक अलग नेता की छवि बनाते हुए वह लोगों के सुख-दुख से जुड़े रहे। यह भी दिखाया कि सत्ता के बगैर भी कैसे रहा जा सकता है।

जिद्दी व्यक्ति हैं बाबूलाल : अमित शाह ने कहा कि आज मेरे लिए बड़ा हर्ष का दिन है। क्योंकि मैं 2014 में जब पार्टी का अध्यक्ष बना, तब से प्रयास कर रहा था कि बाबूलाल भाजपा में आ जाएं लेकिन बाबूलाल बड़े जिद्दी प्रकार के व्यक्ति हैं। तब नहीं माने। लेकिन आज हम सबकी इच्छानुसार वह भाजपा में आए हैं। इसका मुझे विशेष आनंद है। बाबूलाल के भाजपा में आने से रघुवर दास, अर्जुन मुंडा, कड़िया मुंडा को एक नया अनुभवी संघर्षरत योद्धा प्राप्त होगा। कहा, बाबूलाल को पूरा भरोसा दिलाना चाहता हूं कि भाजपा आपको हमेशा से अपना ही मानती है और अब भी आपको अपना मानकर आपकी शक्तियों का अधिकतम उपयोग जनता के हित में हो इस दिशा में भाजपा आगे बढ़ेगी। सिर्फ बाबूलाल ही नहीं, आप सभी जो हजारों कार्यकर्ता भाजपा को अपना घर मानकर आए हैं। आपका उचित सम्मान भी होगा और आपको उचित जिम्मेदारी भी दी जाएगी।

शाह ने कहा–भाजपा का लक्ष्य चुनाव जीतना या हारना नहीं

राज्य ब्यूरो, रांची

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड विधानसभा चुनाव में हुई भाजपा की हार को खुले दिल से स्वीकारा है। विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार झारखंड आए अमित शाह ने धुर्वा के जगन्नाथपुर मैदान में आयोजित भाजपा के मिलन समारोह में जनादेश को स्वीकार करते हुए कहा कि भाजपा का लक्ष्य चुनाव हारना या जीतना नहीं है, बल्कि प्रदेश और देश को आगे बढ़ाना है। भाजपा झारखंड को पतन के रास्ते पर जाते हुए नहीं देख सकती। भाजपा इसी लक्ष्य को लेकर कार्य कर रही है, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भाजपा ने सालों तक विपक्ष में काम किया है।

शाह ने कहा कि झारखंड की जनता ने जो जनादेश दिया, भाजपा उस जनादेश का सम्मान करती है। उन्होंने राज्य की जनता को भरोसा दिलाया कि हमने सत्ता में रहते हुए जितना काम किया, उससे कहीं अधिक काम विपक्ष में रहते हुए करेंगे। कहा, जनता के विकास के लिए, गरीबों और आदिवासियों के विकास के लिए प्रदेश सरकार जो योजनाएं लाती है उसका तो समर्थन करेगी परंतु भ्रष्टाचार, नक्सलवाद, आंतकवाद की बढ़ोतरी करने का जो प्रयास हो रहा है, उसके खिलाफ पार्टी डटकर मुकाबला करेगी।

जेवीएम के दो विधायकों ने थामा कांग्रेस का हाथ

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : झारखंड विकास मोर्चा के दो विधायकों ने उनसे अलग होकर सोमवार को दिल्ली में कांग्रेस का हाथ थाम लिया। साथ ही खुद को असली बताते हुए उन्होंने जेवीएम का कांग्रेस में विलय कराने का भी दावा किया। कांग्रेस के झारखंड प्रभारी आरपीएन सिंह की मौजूदगी में जेवीएम के जिन दो विधायकों ने पार्टी का हाथ थामा, उनमें प्रदीप यादव और बंधु तिर्की शामिल हैं।

आज अपने इरादे जाहिर करेंगे पीके

राज्य ब्यूरो, पटना

▸ जदयू से निकाले जाने के बाद पहली बार पहुंच रहे पटना

▸ करेंगे प्रेस वार्ता, जदयू नेताओं के हमले का भी देंगे जवाब

जदयू से निकाले जाने के बाद प्रशांत किशोर (पीके) पहली बार मंगलवार को पटना आ रहे हैं। समझा जा रहा कि वह प्रेस वार्ता कर बिहार में अपनी अगली रणनीति की घोषणा करेंगे। पार्टी विरोधी गतिविधियों और बयानों के बाद जदयू ने उन्हें निष्कासित कर दिया था। माना जा रहा है कि जदयू नेताओं के हमले का प्रशांत जवाब भी देंगे। बिहार की राजनीति को पीके के नए पैंतरे का इंतजार है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ संबंधों में खटास के बाद प्रशांत पहली बार पटना आ रहे हैं। रहस्य यह है कि रणनीतिकार से राजनेता बनने का संकेत दे चुके प्रशांत का अगला कदम क्या होगा? अपनी अलग पार्टी बनाएंगे या बिहार में पहले से सक्रिय विभिन्न दलों का मोर्चा तैयार करेंगे। उन्होंने इतना जरूर साफ कर दिया है कि वह बिहार चुनाव में किसी दल के लिए रणनीति नहीं बनाएंगे। किंतु जो भी करना है, उसके बारे में मंगलवार को ही बताया जाएगा। प्रशांत की टीम के अहम सदस्य का दावा है कि 2015 केविस चुनाव में जदयू की ओर से महागठबंधन के लिए काम करते हुए उन्होंने बड़ी संख्या में युवाओं को खुद से

प्रशांत किशोर। फाइल

जोड़ा था। दिल्ली में कामयाबी के बाद वह बिहार में भी खुद को केजरीवाल की तरह स्थापित करने की कोशिश कर सकते हैं।

पहले 11 को पटना आना था : प्रशांत ने पहले ही एलान कर रखा था कि पटना में आकर अपने ऊपर लगाए जा रहे प्रत्येक आरोप का जवाब देंगे। पहले उनके आने का कार्यक्रम 11 फरवरी को था। किंतु दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे के चलते बाद में बढ़ाकर 18 फरवरी कर दिया गया।

ममता सरकार ने दी जेड श्रेणी की सुरक्षा

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : प्रशांत किशोर को बंगाल सरकार ने 'जेड' श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला लिया है। पिछले साल ही तृणमूल कांग्रेस ने पीके को अपनी चुनावी रणनीति की जिम्मेदारी सौंपी है। तृणमूल से जुड़ने के बाद ममता सरकार की ओर से उन्हें जेड सुरक्षा मुहैया कराई गई है। राज्य के गृह विभाग के सूत्रों का कहना है कि चूंकि प्रशांत किशोर एक जाने–माने चुनावी रणनीतिकार हैं, ऐसे में वह विरोधियों के निशाने पर हो सकते हैं। इसीलिए उन्हें जेड सुरक्षा देने का फैसला लिया गया है। पुलिस अधिकारियों का भी कहना है कि प्रशांत किशोर को लेकर कई खुफिया इनपुट मिल रहे थे कि उनपर हमला हो सकता है, इसलिए उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। जेड श्रेणी की सुरक्षा में चार से पांच एनएसजी कमांडो सहित कुल 22 सुरक्षागार्ड तैनात होते हैं। इसमें दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ के कमांडो व स्थानीय पुलिसकर्मी भी शामिल होते हैं।

पंजाब में 59 सीटों पर लड़ेगी भाजपा, हाईकमान तैयार

कैलाश नाथ, चंडीगढ़

▸ भाजपा के वरिष्ठ नेता मदन मोहन मित्तल ने किया दावा

पंजाब में ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर अकाली दल की सहयोगी भारतीय जनता पार्टी अब खुल कर बोलने लगी है। अभी तक भाजपा 49 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात करती रही थी, लेकिन खुल कर कोई भी नेता सामने नहीं आता था। अब भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन मोहन मित्तल ने पंजाब में 59 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा ठोका है। उनका यह भी दावा है कि पार्टी हाईकमान ने भी इसके लिए तैयारी करने को कहा है।

भाजपा प्रदेश की 117 विधानसभा सीटों में से 23 पर चुनाव लड़ती है। बाकी पर अकाली दल लड़ता है। मित्तल ने यह दावा तब किया है जब बीते गुरुवार को ही पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने भाजपा को नसीहत दी थी कि वह सहयोगी पार्टियों को साथ लेकर चले। भविष्य में कभी चुनाव न लड़ने की बात कर चुके मित्तल ने दैनिक जागरण से बातचीत में कहा कि पार्टी हाईकमान को पंजाब यूनिट ने स्पष्ट कह दिया था कि प्रदेश प्रधान हमें ऐसा चाहिए जो 59 सीटों पर चुनाव लड़े, ना कि 23 सीटों तक सीमित रहे। मित्तल ने दावा किया कि तभी भाजपा ने अश्विनी शर्मा को प्रधान बनाया है और पार्टी ने 59 सीटों पर लड़ने की तैयारी भी शुरू कर दी है।

एक सवाल के जवाब में मित्तल ने कहा कि हम गठबंधन में रहकर ही 59 सीटें मांग रहे हैं। उनसे जब पूछा गया कि अकाली दल इतनी सीटों को लेकर तैयार नहीं हुआ तो क्या गठबंधन रहेगा तो बोले- न तो हम गठबंधन तोड़ना चाहते हैं और न ही वो। हम तो गठबंधन में रहते हुए ही सीटें बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।

ग्रामीण सीटों पर भी लड़ेगी भाजपा

भाजपा क्या शहरी सीटों पर चुनाव लड़ेगी जैसे सवाल के जवाब में मित्तल कहते हैं कि पंजाब में किसानों, सिखों व व्यापारियों की मानसिकता को देखना पड़ेगा। भाजपा केवल शहर ही नहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी चुनाव लड़ेगी।

मांझी ने कहा–मंत्रियों, अफसरों के घर नहीं मिली शराब तो छोड़ दूंगा राजनीति

राज्य ब्यूरो, पटना : बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने सरकार पर हमला बोला है। उपेंद्र कुशवाहा ने सोमवार को कहा, कैसी शराबबंदी? अब तो लोगों के घर पर शराब की डिलेवरी हो रही है। वहीं मांझी ने नीतीश कुमार को चुनौती देते हुए कहा कि जिन्हें लगता है बिहार में शराबबंदी है, वह मंत्रियों और अधिकारियों के यहां छापेमारी करें। यदि मंत्री और अधिकारियों के घर शराब नहीं मिली तो वे राजनीति छोड़ देंगे।

जीतन राम मांझी ने कहा कि शराबबंदी कानून सिर्फ गरीब, दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को प्रताड़ित करने के लिए बना है। क्योंकि इस कानून के जो लोग शराब पीने के आरोप में पकड़ कर जेल भेजे गए हैं उनमें से अधिकांश इसी तबके से आते हैं। मांझी ने तंज कसते हुए कहा जिन्हें लगता है शराबबंदी कानून सफल रहा है, उन्हें मानसिक इलाज की दरकार है।

लालू बोले–पहले बिहार में ठीक से शराबबंदी लागू कराएं नीतीश : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिहार की तरह पूरे देश में शराबबंदी की बात करने पर राजद प्रमुख लालू प्रसाद भड़क गए। लालू ने ट्वीट कर नीतीश पर हमला बोला। पहले ट्वीट में नीतीश को नसीहत देते हुए लिखा कि शराबबंदी को पहले बिहार में ही ठीक से लागू करवा लें उसके बाद पूरे देश की बात करें। दूसरे ट्वीट में नीतीश के बयान में गांधी की चर्चा को मुद्दा बनाया और लिखा कि महात्मा गांधी ने सबसे बड़ा सामाजिक पाप सिद्धांत के बिना राजनीति को बताया था। किंतु नीतीश भाजपा के साथ मिलकर पिछले 25 वर्षों से विभाजनकारी राजनीति कर रहे हैं। लालू के बाद रघुवंश प्रसाद सिंह का बयान आया। उन्होंने बिहार में शराबबंदी के दावे को ढोंग करार दिया और कहा कि यह पहले से भी ज्यादा बिक रही है। गांधी जी की यह मंशा नहीं रही थी कि पहले शराब की बिक्री बढ़ा दी जाए और बाद में बंद कर दी जाए।

दो टूक

जमशेदपुर शताब्दी वर्ष पर उपराष्ट्रपति ने जारी किया डाक टिकट, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म को बताया देश की जरूरत, कहा, लोकतंत्र में वॉक आउट चल सकता है, ब्रेक आउट किया तो जनता कर देगी ऑलआउट

आतंकवाद और हिंसा देश के विकास में बाधक : उपराष्ट्रपति

जासं, जमशेदपुर

उपराष्ट्रपति एम वैंकेया नायडू ने कहा कि आतंकवाद और हिंसा की घटनाएं देश के विकास के लिए बाधक हैं। बस और पुल जलाने से देश आगे नहीं बढ़ेगा। इससे हमें बाहर निकलना होगा, तभी समग्र विकास की राह में आगे बढ़ सकते हैं। उपराष्ट्रपति सोमवार को जमशेदपुर के नामकरण के 100 वर्ष पूरे होने पर एक्सएलआरआइ सभागार में टाटा स्टील की ओर से आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने जमशेदपुर शताब्दी वर्ष के मौके पर एक डाक टिकट भी जारी किया।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह आपका देश है। जब आप विकास में बाधा पहुंचाते हैं तो इससे सभी को नुकसान होता है। देश के विकास में सभी शेयर होल्डर हैं। यह देश वसुधैव कुटुम्बकम की नीति पर चलता है। इसका उद्देश्य शेयर एंड केयर है। कहा कि डिस्कशन, डिबेट एंड डिसाइड यानी थ्री डी से ही लोकतंत्र मजबूत होगा। कहा, मैं राज्यसभा में भी सदस्यों से यही कहता हूं। किसी भी विषय पर चर्चा करें, लोकतंत्र में वॉक आउट चल सकता है, पर ब्रेक आउट नहीं चलेगा। जनता ने अपनी बात रखने के लिए भेजा है। यदि अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरे तो जनता ऑल आउट कर देगी। जब सभी एकसाथ एक दिशा में काम करेंगे, तभी विकास की गति तेज हो सकती है।

रूसी मोदी सेंटर फॉर एक्सीलेंस में पौधारोपण करते उपराष्ट्रपति एम वैंकेया नायडू। जागरण

उपराष्ट्रपति ने पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि इन्होंने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का संदेश दिया है। पुरानी व्यवस्था को बदलें, बदलाव के साथ बेहतर प्रदर्शन करें और उसके फायदे जनता तक पहुंचाएं। उन्होंने कंपनी मालिकों से उत्पादन लागत में कमी लाकर विकास करने और उसके लाभ जनता तक पहुंचाने की अपील की। अपने 42 मिनट के संबोधन में उपराष्ट्रपति ने स्किल इंडिया, शिक्षा नीति, स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल इंडिया, काला धन सहित कई विषयों पर अपनी बातें रखी।

एलपीजी का मतलब समझाया : उपराष्ट्रपति ने एलपीजी का मतलब बताते हुए कहा कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं, बल्कि लिब्रलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन (उदारीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण) होता है। इसके जरिए भविष्य में आने वाली चुनौतियों के प्रति आगाह भी किया। कहा कि हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। जब हम एलपीजी का सही इस्तेमाल करेंगे तो चुनौतियों से जीत पाएंगे।

मोदी के लिए नहीं, अपनी बॉडी के लिए करें योग : उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रह सकता है। जब टेंशन लेंगे तो किसी काम में अटेंशन नहीं प्राप्त कर पाएंगे। वर्तमान में बाबा रामदेव और पंडित रविशंकर देश के विभिन्न हिस्सों में योग केंद्र खोल रहे हैं। कुछ लोग योग इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं। ऐसे लोगों से आग्रह है कि योग प्रधानमंत्री मोदी के लिए नहीं, अपनी बॉडी के लिए करें। इससे आपका फायदा होगा।

1,486 लोगों को 2001 से 2015 के बीच मृत्युदंड सुनाया गया। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली (एनएलयूडी) के मुताबिक, केवल पांच फीसद (73) अपील की प्रक्रिया के बाद भी मृत्युदंड की कतार में थे।

निर्भया के दोषियों के लिए तीसरी बार डेथ वारंट जारी, 3 मार्च को होगी फांसी

चारों को सुबह 6 बजे फांसी देने का आदेश, दोषी मुकेश ने भी खुद को वकील से किया अलग

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

निर्भया कांड के दोषियों के खिलाफ तीसरी बार डेथ वारंट जारी हुआ है। सोमवार को निर्भया के परिजनों और दिल्ली सरकार की अर्जी पर पटियाला हाउस की एक अदालत ने चारों दोषियों को तीन मार्च की सुबह छह बजे फांसी देने का आदेश जारी किया है।

अतिरिक्त सत्र न्यायालय में सुनवाई के दौरान दोषी मुकेश की तरफ से बताया गया कि वह नहीं चाहता है कि अब अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर उसका प्रतिनिधित्व करें। इस पर वृंदा ग्रोवर ने अदालत से अपील की कि उन्हें इस केस से मुक्त किया जाए। इस दलील को मानते हुए जज ने वृंदा ग्रोवर को केस से मुक्त कर दिया। इसके बाद मुकेश की मां ने एक अर्जी दायर कर वकील मुहैया कराने की मांग की। जज ने इस अर्जी पर अधिवक्ता रवि काजी को ही मुकेश का प्रतिनिधित्व करने के लिए कहा। रवि काजी को पिछली सुनवाई पर दोषी पवन का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया गया था, क्योंकि पवन ने अपने पुराने अधिवक्ता एपी सिंह से खुद को अलग कर लिया था।

निर्भया दुष्कर्म कांड के दोषी (बाएं से) मुकेश सिंह, अक्षय ठाकुर, विनय शर्मा और पवन गुप्ता की फाइल फोटो। एपी

सुनवाई के दौरान विनय के अधिवक्ता एपी सिंह ने अदालत को बताया कि वह तिहाड़ जेल में 11 फरवरी से भूख हड़ताल पर है। इस पर जज ने जेल अधीक्षक को निर्देश दिया कि विनय का ध्यान रखा जाए। साथ ही अदालत को बताया गया कि विनय पर जेल में हमला हुआ था और उसके सिर पर गंभीर चोट आई थी। चोट की वजह से उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और ऐसे में उसे फांसी नहीं दी जा सकती। वहीं अक्षय के परिजनों ने अधूरी दया याचिका दायर कर दी है। ऐसे में उसमें सुधार कर फिर से दायर किया जाना है।

पवन के अधिवक्ता रवि काजी ने अदालत में दलील दी कि अदालत ने सभी उपाय करने के लिए दोषियों को सात दिन का समय दिया था, लेकिन पवन अभी तक अपनी क्यूरेटिव पिटिशन और दया याचिका दायर नहीं कर पाया। क्योंकि उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई वकील नहीं थे। अब उनकी पवन के साथ बैठक है और उसके बाद क्यूरेटिव पिटिशन दायर करेंगे। हालांकि तमाम दलीलों के बाद अदालत ने नया डेथ वारंट जारी कर दिया।

दोषियों का वजन जेल प्रशासन के लिए अहम : डेथ वारंट के बाद जेल प्रशासन की नजर अब निर्भया के दोषियों के स्वास्थ्य पर है। जेल प्रशासन को दोषियों के डेथ वारंट जारी होने की जानकारी मिलते ही जेल संख्या तीन के हाई सिक्योरिटी सेल की सुरक्षा बढ़ा दी गई। शाम में चारों दोषियों का वजन किया गया, जिसे इनकी फाइलों में दर्ज किया गया। अब रोजाना सुबह-शाम इनका वजन किया जाएगा। रोजाना इनकी काउंसिलिंग भी की जाएगी। बता दें कि जेल मैनुअल के मुताबिक फांसी की सजा पर अमल तभी हो सकेगा, जब ये शारीरिक व मानसिक तौर पर पूरी तरह फिट रहेंगे। स्वास्थ्य जांच के दौरान अन्य बातों के अलावा इनके वजन पर नजर रखी जा रही है। वजन के हिसाब से यह तय होगा कि किस दोषी को फंदे से कितना नीचे लटकाया जाएगा।

आज खुल सकता है फांसी घर का ताला

मंगलवार को फांसी घर के मुख्य दरवाजे पर जड़ा ताला खुलने की पूरी संभावना है। पिछली बार जल्लाद द्वारा किए गए ट्रायल के बाद फांसी घर को बंद कर दिया गया था। अब जबकि डेथ वारंट जारी हो गया है और फांसी की तारीख निश्चित हो चुकी है। मंगलवार को अधिकारियों की टीम वहां के इंतजामों का जायजा लेगी, इसकी संभावना है।

मध्यस्थों से बातचीत के लिए शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी तैयार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली में शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) के खिलाफ धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि वे कोर्ट द्वारा नियुक्त किए मध्यस्थों से बातचीत के लिए तैयार हैं। प्रदर्शनकारी सीएए, एनआरसी और एनपीआर पर सरकारी अधिकारियों से भी वार्ता को तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर सोमवार सुबह से ही शाहीन बाग में प्रदर्शनकारी बेहद उत्सुक नजर आए।

कोर्ट ने जब कहा कि दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार को प्रदर्शनकारियों से बातचीत करनी चाहिए तो धरने पर बैठीं महिलाओं ने तालियां बजाकर इसका स्वागत किया। धरने पर बैठीं दादी बिलकिस ने मंच से दूसरी महिलाओं को इस निर्णय के बारे में जानकारी दी। दादियों ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल से वह भी बात करेंगी और अपनी बात विस्तार से रखेंगी। शीर्ष अदालत ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने के लिए वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े, साधना रामचंद्रन और पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह को मध्यस्थ नियुक्त किया। इस पर प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वह कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रतिनिधिमंडल और सरकारी अधिकारियों से बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन पुलिस से वह बात नहीं करेंगे।

कोर्ट में सुनवाई से पहले शाहीन बाग में मामूली सी भीड़ थी, लेकिन जैसे ही सुनवाई पूरी हुई लोगों का हुजूम एकदम से मंच के पास पहुंचने लगा। हर कोई एक-दूसरे से कोर्ट के फैसले पर चर्चा करता हुआ नजर आया।

दिल्ली के शाहीन बाग में सीएए, एनआरसी और एनपीआर के विरोध में महिलाओं का धरना सोमवार को भी जारी रहा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सड़क अवरुद्ध करने के खिलाफ फैसला सुनाने का कोई फर्क नही पड़ा। प्रेट्र

शरजील इमाम ने ही जामिया के छात्रों को दंगे के लिए उकसाया : पुलिस

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- पुलिस को शरजील की एक दिन की रिमांड मिली, देशद्रोह में भी है आरोपित
- पिछले साल 13 दिसंबर को जामिया में प्रदर्शन के दौरान दिया था भड़काऊ भाषण

दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा है कि 15 दिसंबर को जामिया इलाके में शरजील के भाषणों की वजह से ही हिंसा भड़की थी। सोमवार को दंगे भड़काने के आरोपित शरजील इमाम को तिहाड़ जेल से साकेत कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने एक दिन की पुलिस रिमांड की मांग को मंजूर किया। जांच में दिल्ली में दंगा करने के लिए उकसाने की बात सामने आने पर क्राइम ब्रांच ने अब उसके खिलाफ दंगा करने के लिए उकसाने व आपराधिक साजिश रचने का मुकदमा भी दर्ज कर किया है। देश के खिलाफ आपत्तिजनक व भड़काऊ भाषण देने का वीडियो वायरल होने पर क्राइम ब्रांच ने स्वतः संज्ञान लेते हुए देशद्रोह के आरोपित शरजील के खिलाफ पहले देशद्रोह का मामला दर्ज कर उसके पैतृक गांव जहानाबाद से उसे गिरफ्तार किया था। शरजील के खिलाफ दिल्ली, असम व अलीगढ़ समेत कई राज्यों में मुकदमा दर्ज है। अभी केवल दिल्ली पुलिस ने ही उससे दो बार लंबे समय के लिए रिमांड पर लेकर पूछताछ की है। वह अभी तिहाड़ जेल में ही बंद था।

डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश देव ने बताया कि 13 दिसंबर को जामिया मिल्लिया के छात्रों व स्थानीय लोगों ने जब नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में पहली बार प्रदर्शन किया था तब शरजील उसमें शामिल था। उसने उक्त प्रदर्शन के दौरान छात्रों व स्थानीय लोगों को दंगा करने के लिए उकसाने के लिए भड़काऊ भाषण दिया था। शरजील का भाषण सुनकर ही लोग उग्र हो गए थे। अगले दिन 14 दिसंबर को भी छात्रों व स्थानीय लोगों ने जामिया, शाहीनबाग व आसपास के इलाके में जोरदार प्रदर्शन किया था। पुलिसकर्मियों ने हाथापाई व मारपीट की थी।

इसके बाद 15 दिसंबर को छात्रों व स्थानीय लोगों ने जामिया इलाके में जमकर हिंसा और तोड़फोड़ की थी। जिसके बाद दक्षिण-पूर्वी जिला पुलिस ने अज्ञात दंगाइयों के खिलाफ तीन केस दर्ज किए थे। विस्तृत जांच के लिए पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक ने केस को क्राइम ब्रांच में ट्रांसफर कर दिया गया था। उक्त मामले में क्राइम ब्रांच की एसआइटी 40 से अधिक उपद्रवियों को गिरफ्तार कर चुकी है। गिरफ्तार आरोपितों में एक ने पूछताछ में बताया कि 13 दिसंबर को शरजील ने जामिया के बाहर भड़काऊ भाषण दिया था। उसके बयान को आधार बनाकर व उस आरोपित को गवाह बनाते हुए क्राइम ब्रांच ने शरजील के खिलाफ दंगे भड़काने का मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है। सुबूत के तौर पर क्राइम ब्रांच ने शरजील के 13 दिसंबर के वीडियो को हासिल कर लिया है। जामिया मिल्लिया में छात्रों व स्थानीय लोगों को भड़काने के बाद वह अलीगढ़ विश्वविद्यालय में भी गया और वहां भी भड़काऊ भाषण दिया था।

मुसलमानों ने लिखी चिट्ठी, कब्रिस्तान पर न बनाएं मंदिर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन कर दिया गया है। 19 फरवरी को ट्रस्ट की पहली बैठक होने वाली है। इस बीच अयोध्या के कुछ मुसलमानों ने वकील के जरिये ट्रस्ट को पत्र भेजकर मुसलमानों की कब्रों पर राम मंदिर नहीं बनाए जाने का आग्रह किया है। पत्र में कहा गया है कि आज भले ही वहां कब्रें न दिख रही हों, लेकिन वहां 4-5 एकड़ जमीन पर मुसलमानों की कब्रें थीं। ऐसे में वहां मंदिर की नीव कैसे रखी जा सकती है?

करीब नौ मुसलमानों ने पत्र में कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा 1993 में अयोध्या में अधिगृहीत की गई 67 एकड़ जमीन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने राम मंदिर निर्माण के लिए दे दी है। उस जमीन पर मुसलमानों की कब्रें थीं। वह जमीन करीब 4-5 एकड़ है। केंद्र सरकार ने इस पहलू पर विचार नहीं किया कि मुसलमानों के कब्रिस्तान पर भव्य राममंदिर नहीं बन सकता। यह धर्म के विरुद्ध है। पत्र में ट्रस्टियों से कहा गया है कि आप सभी प्रबुद्ध लोग हैं और आपको हिंदू धर्म की जानकारी है। आप लोगों को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या राम मंदिर की नींव मुसलमानों की कब्रों पर रखी जा सकती है? ट्रस्ट के प्रबंधन को यह फैसला करना होगा। ट्रस्ट से आग्रह किया गया है कि 4-5 एकड़ जमीन जहां ढहाए गए विवादित ढांचे के आसपास कब्रें थीं, उस जगह का प्रयोग न किया जाए। भले ही आज वहां कब्रें नजर नहीं आ रही हों लेकिन इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि 1949 को जब वहां अंदर मूर्तियां रखी गईं से लेकर 1992 तक वह जगह अलग तरह से प्रयोग होती रही है। ट्रस्टियों को भेजा गया यह पत्र 15 फरवरी का लिखा हुआ है।

बैठक में बुलाए गए महंत नृत्यगोपालदास, सदस्य बनाए जाने के कयास

रमाशरण अवस्थी, अयोध्या

रामजन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए गठित श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की पहली बैठक में रामजन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष एवं रामनगरी की शीर्ष पीठ मणिरामदास जी की छावनी के महंत नृत्यगोपालदास (85) को भी आमंत्रित किया गया है। बैठक बुधवार को दिल्ली में प्रस्तावित है। हालांकि, महंत नृत्यगोपालदास ट्रस्ट में शामिल नहीं हैं और इसको लेकर स्थानीय संतों का असंतोष भी मुखर है। ऐसे में बैठक के लिए उन्हें आमंत्रित किया जाना, इस संभावना से जोड़कर देखा जा रहा है कि श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में उन्हें शामिल किया जा सकता है।

बैठक के दो दिन पूर्व सोमवार को ट्रस्ट के तीन सदस्य जगद्गुरु स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती, अयोध्या राजपरिवार के मुखिया बिमलेंद्रमोहन मिश्र एवं डॉ. अनिल मिश्र की महंत नृत्यगोपालदास से मुलाकात इसी संभावना से जोड़ कर देखी जा रही है। महंत नृत्यगोपालदास की गणना मंदिर आंदोलन के प्रमुख संवाहकों में होती है। साढ़े तीन दशक पूर्व मंदिर आंदोलन की शुरुआत से ही नृत्यगोपालदास आंदोलन के अहम किरदार के रूप में सामने आए। साधन-सुविधा युक्त उनका आश्रम और उनके लाखों विरक्त-गृहस्थ शिष्य भी मंदिर आंदोलन के लिए उपयोगी सिद्ध हुए।

कई वर्षों तक मंदिर आंदोलन के संरक्षक की भूमिका में रहे नृत्यगोपालदास 2003 में रामचंद्रदास परमहंस के साकेतवास के बाद रामजन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष की जिम्मेदारी का भी निर्वहन कर रहे हैं।

ट्रस्ट गठन में उनकी अनुपस्थिति ने सभी को चौंकाया। यही वजह थी कि एलान के अगले दिन ही स्थानीय संतों का असंतोष उभरा। बाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महंत नृत्यगोपालदास एवं उनके उत्तराधिकारीमहंत कमलनयनदास से वार्ता कर दखल दिया। ट्रस्ट में न्यास अध्यक्ष को शामिल किए जाने का आश्वासन दिया था। तभी से यह कयास हैं कि श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में महंत नृत्यगोपालदास को शामिल किया जा सकता है।

यूपीपीएससी 2019 की प्रारंभिक परीक्षा में 6320 अभ्यर्थी सफल

राज्य ब्यूरो, प्रयागराज

- उप्र लोक सेवा आयोग ने घोषित किया प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट
- 15 दिसंबर को प्रदेश के 19 जिलों में एक साथ कराई गई थी परीक्षा

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2019 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। सोमवार देर रात घोषित रिजल्ट में 6320 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए सफल हुए हैं। आयोग की ओर से कहा गया है कि प्रारंभिक परीक्षा में सम्मिलित पदों की विशिष्ट अर्हताओं व अभ्यर्थियों के ऑनलाइन दावों को देखते हुए सामान्य चयन का रिजल्ट सात अलग-अलग ग्रुपों में जारी किया है। इसी के साथ एसीएफ व आरएफओ प्रारंभिक परीक्षा 2019 का भी परिणाम जारी किया गया है।

यूपीपीएससी ने सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (पीसीएस), सहायक वन संरक्षक (एसीएफ) व क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा (आरएफओ) प्रारंभिक परीक्षा 2019 बीते 15 दिसंबर को एक साथ कराई थी। आयोग ने 16 अक्टूबर 2019 को पीसीएस के 309, एसीएफ के दो व आरएफओ के 53 पदों की भर्ती का विज्ञापन जारी किया था, 13 नवंबर 2019 तक ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। पीसीएस के पदों की संख्या बढ़कर अब 529 हो गई है। 19 जिलों में 1166 केंद्रों पर दो पालियों में परीक्षा कराई गई। आयोग के सचिव जगदीश ने बताया कि परीक्षा परिणाम से संबंधित अंतिम उत्तरकुंजी, प्राप्तांक व श्रेणीवार, पदवार कटऑफ अंक अंतिम चयन परिणाम घोषित होने के बाद आयोग की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। आयोग के परीक्षा कैलेंडर में पीसीएस 2019 की मुख्य परीक्षा 20 अप्रैल से प्रस्तावित है। आयोग ने इस परीक्षा के दो माह पहले ही प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। जल्द ही मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों से आवेदन जाएंगे और फिर अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र जारी होगा। इसके लिए आयोग अलग से विज्ञप्ति जारी करेगा।

देशद्रोह मामले में इंजीनियरिंग कॉलेज के तीनों कश्मीरी छात्र दोबारा गिरफ्तार

हुबली, प्रेट्र : देशद्रोह के आरोपित तीन कश्मीरी छात्रों को दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 169 के तहत बांड भरवाकर छोड़े जाने के मामले में कर्नाटक पुलिस को मुंह की खानी पड़ी। भारी विरोध-प्रदर्शन के बाद पुलिस को तीनों आरोपितों को सोमवार को दोबारा गिरफ्तार करना पड़ा।

कर्नाटक के हुबली में स्थित एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले तीनों छात्रों को शनिवार को गिरफ्तार किया गया था। उन पर पुलवामा आतंकी हमले की बरसी पर पाकिस्तान के पक्ष में नारेबाजी करने और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करने का आरोप है। जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में गत वर्ष 14 फरवरी को सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला हो गया था। इसमें 40 जवान शहीद हो गए थे।

पुलिस ने रविवार को सीआरपीसी की धारा 169 के तहत बांड भरवाकर तीनों आरोपितों को छोड़ दिया था। इसके बाद लोगों ने पुलिस को निशाने पर ले लिया था। दक्षिणपंथी संगठनों ने पुलिस मुख्यालय पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया था। श्रीराम सेना प्रमुख प्रमोद मुथालिक ने भी तीनों आरोपितों को छोड़े जाने की कड़ी आलोचना की थी। पुलिस सूत्रों का कहना है कि राज्य के गृह मंत्री बासवराज बोम्मई ने भी इस संबंध में अधिकारियों से बात की थी।

हुबली-धारवाड़ के पुलिस आयुक्त आर. दिलीप ने बताया, 'आरोपित तीनों कश्मीरी छात्रों को गिरफ्तार कर कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।'

देशद्रोह के आरोप में तीन कश्मीरी छात्रों को दोबारा गिरफ्तार कर कर्नाटक पुलिस ने सोमवार को उन्हें हुबली जिला अदालत में पेश किया। प्रेट्र

एकल अभियान के जरिये गांव-गांव पहुंचेगा रामराज : योगी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

योगी आदित्यनाथ फाइल

एकल अभियान के परिवर्तन कुंभ का शुभारंभ करते हुए उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा शासन में देश व प्रदेश में आ रहे परिवर्तन पर भी रोशनी डाली। संस्था के सेवाकार्यों की सराहना करते हुए कहा कि इसे ही विराट रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ा रहे हैं। यदि एकल अभियान के माध्यम से शासन की योजनाएं जरूरतमंदों तक पहुंचेंगी तो गांव-गांव रामराज का मार्ग प्रशस्त होगा। डॉ. राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय के सभागार में सोमवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आनुषांगिक संगठन एकल अभियान के परिवर्तन कुंभ का उद्घाटन समारोह था।

बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि एकल अभियान इस बात को साबित करता है कि हमारे यहां सेवा किसी सौदे का माध्यम नहीं है, बल्कि हमें सनातन परंपरा से मिली है। अशोक सिंहल ने जिस एकल अभियान का बीजारोपण किया था, आज वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भावनाओं के अनुरूप एक लाख की संख्या पार कर सेवा के क्षेत्र में, शिक्षा के प्रसार में निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहा है।

योगी ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में दी गई सुविधाओं की गति अगर 1947 से होती तो आज ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता, जिसे इन योजनाओं की जरूरत होती। पूर्व की सरकारों के पास विजन नहीं था। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं के आंकड़े रखने के साथ ही कहा कि भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो चुका है। यह वनवासी जीवन को मान्यता देने का काम भी है।

गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति का किया जाएगा भव्य स्वागत, सात घेरे की सुरक्षा में तैनात होंगे 25,000 जवान और अफसर

ट्रंप की सुरक्षा कार लेकर पहुंचा वायुसेना का विमान

शत्रुघ्न शर्मा, अहमदाबाद

गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गुजरात की धरा पर भव्य स्वागत किया जाएगा। सोमवार को अमेरिकी वायुसेना का विमान ट्रंप के सुरक्षा काफिले की कार लेकर अहमदाबाद पहुंच गया।

मुख्यमंत्री रूपाणी ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति 24 फरवरी को वाशिंगटन से सीधे अहमदाबाद पहुंचेंगे। वह करीब तीन घंटे यहां रुकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वह गांधी आश्रम आएंगे और दुनिया के सबसे बड़े मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम के उद्घाटन समारोह में शिरकत करेंगे। स्टेडियम में एक लाख से अधिक लोग ट्रंप का भव्य स्वागत करेंगे। उनके स्वागत में गुजरात के महिला-पुरुष और बच्चे पलक पावड़े बिछाए हुए हैं। ट्रंप की यात्रा के इस दौरान अहमदाबाद का वायुक्षेत्र नो-फ्लाई जोन रहेगा। अहमदाबाद आने वाली सभी उड़ानों को वडोदरा डायवर्ट किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति अहमदाबाद दौरे से एक सप्ताह पहले उनकी सुरक्षा में लगा अमेरिकी वायुसेना का ग्लोब मास्टर विमान सोमवार को अहमदाबाद के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा। ट्रंप की सुरक्षा कार फोर्ड डी00074 भी यहां पहुंच गई।

इस यात्रा के दौरान ट्रंप और मोदी सुरक्षा के सात घेरों में रहेंगे। गुजरात सरकार ने सुरक्षा में 25,000 सुरक्षाकर्मी तैनात किए हैं, इनमें 25 आइपीएस शामिल हैं। गांधी आश्रम से मोटेरा स्टेडियम तक सुरक्षा इंतजामों का जायजा लेने के लिए जल्द ही अमेरिकी खुफिया एजेंसी के साथ भारत के स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (एसपीजी) और नेशनल सिक्यूरिटी गार्ड (एनएसजी) की टीमें भी यहां पहुंचेंगी।

गुजरात के अहमदाबाद में सोमवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सुरक्षा काफिले का वाहन। इसे ट्रंप के भारत दौरे के मद्देनजर अमेरिकी वायुसेना के विमान से यहां लाया गया। जागरण

नमस्ते ट्रंप की थीम पर होगा स्वागत

ट्रंप की यात्रा के मद्देनजर साबरमती आश्रम और मोटेरा स्टेडियम को सजाने संवारने का काम पूरी गति से हो रहा है। मुख्यमंत्री रूपाणी ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति की इस यात्रा की थीम 'नमस्ते ट्रंप' रखी गई है। उनकी यात्रा से पहले तैयारियों का जायजा लेने के लिए रूपाणी सोमवार को खुद मोटेरा स्टेडियम पहुंचे। उनके साथ गृह राज्यमंत्री प्रदीप सिंह जडेजा, पुलिस महानिदेशक शिवानंद झा, बीसीसीआइ सचिव जय शाह, गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष धनराज नथवाणी आदि भी मौजूद थे।

ट्रंप की यात्रा की तैयारियां 'गुलाम मानसिकता' का प्रदर्शन : शिवसेना

मुंबई, प्रेट्र : शिवसेना ने सोमवार को कहा कि ट्रंप की यात्रा की तैयारियां भारतीयों की गुलाम मानसिकता प्रदर्शित करती हैं। शिवसेना ने अपने मुखपत्र 'सामना' के संपादकीय में लिखा है कि ट्रंप की भारत यात्रा बादशाह की यात्रा की तरह है। संपादकीय के मुताबिक, 'स्वाधीनता से पहले ब्रिटिश राजा या रानी भारत जैसे अपने गुलाम देशों की यात्रा किया करते थे। ट्रंप के आगमन के लिए करदाताओं के पैसे से उसी तरह की तैयारियां की जा रही हैं।' ट्रंप के यात्रा मार्ग पर झुग्गियों को छिपाने के लिए अहमदाबाद नगर निगम द्वारा दीवार बनवाने के लिए शिवसेना ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना भी साधा। पार्टी ने कहा, 'पूर्व पीएम इंदिरा गांधी ने एक बार गरीबी हटाओ का नारा दिया था जिसका लंबे समय तक मजाक उड़ाया गया। अब ऐसा लगता है कि मोदी की योजना गरीबी छिपाओ की है। अहमदाबाद में बनाई जा रही ऐसी दीवार लिए क्या कोई वित्तीय आवंटन किया गया है? क्या देशभर में ऐसी दीवारें बनाने के लिए अमेरिका भारत को कर्ज देने का प्रस्ताव करने जा रहा है? हमने सुना है कि ट्रंप अहमदाबाद में सिर्फ तीन घंटे के लिए रहेंगे, लेकिन दीवार के निर्माण से राज्य के खजाने पर करीब 100 करोड़ का बोझ पड़ रहा है।' शिवसेना ने दावा कि यह प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच सिर्फ एक राजनीतिक सामंजस्य है।

झुग्गियों को छिपाने के लिए दीवार बनाना अमानवीय : कांग्रेस

मुंबई, प्रेट्र : अमेरिकी राष्ट्रपति की यात्रा से पहले अहमदाबाद में झुग्गी बस्ती को छिपाने के लिए दीवार बनाने के भाजपा सरकार के फैसले की कांग्रेस ने आलोचना करते हुए इसे अमानवीय करार दिया है। महाराष्ट्र कांग्रेस के महासचिव सचिन सावंत ने कहा कि यह दीवार दिखाती है कि मुख्यमंत्रित्व काल के दौरान गुजरात के विकास के नरेंद्र मोदी के दावे झूठे थे। इस बीच, आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाराज गुजरात कांग्रेस ने 24 फरवरी को मोटेरा स्टेडियम के बाहर विरोध प्रदर्शन करने की धमकी दी है। पार्टी की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर केंद्र सरकार समुचित कदम उठाए।

1.50 लाख हेक्टेयर खेती राजस्थान में टिड्डी हमले से प्रभावित हुई है। 1.35 लाख हेक्टेयर में भारी नुकसान पहुंचा है। राज्य सरकार ने 100 करोड़ रुपये नुकसान के मुआवजे के तौर पर किसानों को देने के लिए मंजूर किए हैं।

न्यूज गैलरी

जम्मू-कश्मीर में आगामी महीनों में इंटरनेट में छूट बढ़ेगी

बेंगलुरु : जम्मू-कश्मीर के उप राज्यपाल के सलाहकार केवल कुमार शर्मा का कहना है कि आने वाले महीनों में इस केंद्र शासित प्रदेश में इंटरनेट और कनेक्टिविटी के मुद्दे में मिली छूट को और बढ़ा दिया जाएगा। उप राज्यपाल के सलाहकार केवल कुमार शर्मा ने सोमवार को निवेशकों से बातचीत के दौरान कहा कि मौजूदा प्रतिबंध सिर्फ यह सुनिश्चित करने के लिए है कि इन सुविधाओं का दुरुपयोग हिंसा और अशांति फैलाने के लिए न किया जाए। इसलिए आने वाले कुछ महीनों में यह संभव है कि कनेक्टिविटी से जुड़े विभिन्न प्रतिबंधों में छूट दे दी जाए। शर्मा ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हालात की समीक्षा के दिशा-निर्देश के बाद प्रशासन हर हफ्ते बैठक कर रहा है। इसके साथ ही हर पखवाड़े इंटरनेट कनेक्टिविटी की पाबंदियों में छूट देने की तैयारी है। कानून-व्यवस्था की स्थिति पर उन्होंने कहा कि अनुच्छेद-370 हटाए जाने के बाद से बड़े बदलाव आए हैं। (प्रेट्र)

पुंछ में दो मोर्टार शेल किए गए निष्क्रिय

राजौरी : पुंछ जिले के मेंढर सेक्टर से खेत में दो जिंदा मोर्टार शेल बरामद किए गए। सेना के बम निरोधक दस्ते ने शेल को निष्क्रिय कर बड़ा हादसा टाल दिया। जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले मेंढर में पाक सेना ने भारी गोलाबारी की थी। कई मोर्टार शेल फटे नहीं थे। सोमवार को स्थानीय लोग खेत में काम कर रहे थे। इस दौरान एक व्यक्ति ने खेत में पड़े दो मोर्टार शेल देखे। बम निरोधक दस्ते को जानकारी दी। बम निरोधक दस्ते के जवान दोनों मोर्टार को उठाकर सुरक्षित स्थान पर ले गए। वहां दोनों मोर्टार शेल को निष्क्रिय कर दिया। (जासं)

केंद्रीय विवि के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगे राष्ट्रपति

जम्मू : केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू का दूसरा दीक्षांत समारोह की तैयारियां शुरू हो गई हैं। हालांकि, इसकी तारीख पर संशय है, लेकिन मुख्य अतिथि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होंगे। विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह 14 या 15 मार्च को प्रस्तावित किया है। (राब्यू)

दिल्ली हाई कोर्ट ने 2010 में दिया था आदेश

प्रथम पृष्ठ से आगे

दिल्ली हाई कोर्ट ने 12 मार्च 2010 में सरकार को महिला सैन्य अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने का आदेश दिया था जिसके खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की थी। कोर्ट ने कहा कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं की शारीरिक क्षमता को कम आंकना, उनकी शादी और परिवार को लेकर जिम्मेदारियां महिलाओं को बराबरी का मौका नहीं देने का वैध आधार नहीं हो सकते।

जम्मू-कश्मीर में पर्यटन ढांचे पर खर्च होंगे दो हजार करोड़

राज्य ब्यूरो, जम्मू

जम्मू-कश्मीर के पर्यटन विभाग के सचिव जुबैर अहमद ने सोमवार को कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में केंद्र सरकार के सहयोग से पर्यटन ढांचे को मजबूत करने के लिए दो हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। वह कोलकाता में रोड शो में भाग ले रहे थे।

जम्मू-कश्मीर में मई में होने वाले वैश्विक निवेशक सम्मेलन से पहले देश के विभिन्न हिस्सों में रोड शो शुरू हो गए हैं। पहले दिन बेंगलुरु और कोलकाता में रोड शो हुए। इसमें जम्मू-कश्मीर के अधिकारियों ने राज्य में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अहम जानकारियां दीं। अधिकारी जम्मू-कश्मीर के हालात के बारे में सही तस्वीर रख-रख रहे हैं। कोलकाता में रोड शो में भाग ले रहे पर्यटन विभाग के सचिव जुबैर अहमद ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। वर्ष 2019 में जम्मू-कश्मीर में एक करोड़ से अधिक पर्यटक आए। मौजूदा वर्ष में यह आंकड़ा और बढ़ने की पूरी उम्मीद है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग निहित स्वार्थ के कारण जम्मू-कश्मीर के बारे में दुष्प्रचार कर रहे हैं। सचिव ने कहा कि पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

स्कूल शिक्षा विभाग के आयुक्त सचिव हृदेश कुमार ने कहा कि वैश्विक निवेशक सम्मेलन जम्मू-कश्मीर में मई में होगा और इससे पहले ही सरकार को 20 हजार करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव आ गए हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के हालात बिल्कुल सामान्य है और जरूरत इस संदेश को फैलाने की है। हम निवेशकों और पर्यटकों के मन से शक दूर कर रहे हैं। हालांकि पहले जम्मू कश्मीर में हालात कुछ खराब रहे हैं, लेकिन ऐसी एक भी घटना नहीं है, जिसमें किसी व्यापारी या पर्यटक को तंग किया गया हो। अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद लोग जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीद सकते हैं और वोटर भी बन सकते हैं। पहले लोग जाने से हिचकते थे, लेकिन अब परिदृश्य बदल चुका है।

पर्यटकों से गुलजार कश्मीर... : कश्मीर फिर पर्यटकों की पसंद बन गया है। हसीन वादियों का दीदार करने के लिए देशभर से सैलानियों का आना शुरू हो गया है। पर्यटन विभाग का कहना है कि पिछले वर्ष कश्मीर में एक करोड़ सैलानी आए। पूरी उम्मीद है कि इस वर्ष यह आंकड़ा और बढ़ेगा। जम्मू-कश्मीर में पर्यटन समेत विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए इस समय राज्य प्रशासन की ओर से देशभर में रोड शो किए जा रहे हैं। अनुच्छेद 370 हटने व केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद कश्मीर में हालात अब पूरी तरह सामान्य हैं। सोमवार को श्रीनगर के लाल चौक में घूमते पर्यटक। कामरान रशीद बट

परिसीमन आयोग का काम देखेंगे सुशील चंद्रा

राज्य ब्यूरो, जम्मू : केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर के परिसीमन पर तेजी से आगे बढ़ रही है। जल्द ही परिसीमन आयोग को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने परिसीमन आयोग के लिए अपने प्रतिनिधि की घोषणा कर दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा को जम्मू-कश्मीर के परिसीमन आयोग में अपना प्रतिनिधि नामित किया है। राज्य में परिसीमन आयोग के गठन होते ही सियासी गतिविधियां तेज होने का अनुमान है।

आयोग के प्रवक्ता के अनुसार केंद्र सरकार के आग्रह के बाद चंद्रा को अपनी तरफ से नामित किया गया है। यहां बता दें कि जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन के बाद राज्य में विधानसभा के गठन से पूर्व परिसीमन का कार्य पूरा करना है।

राज्य के पुनर्गठन से पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा में 87 सीटें थी। इनमें लद्दाख की चार सीटें शामिल थीं। इसके अलावा गुलाम कश्मीर की 24 सीटें रिक्त रखी जाती थीं। इस तरह कुल 111 सीटें थी। अब लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। राज्य के पुनर्गठन के बाद लद्दाख की चार सीटें कम हो गईं।

शर्तों के साथ पंचायत उपचुनावों में उतरने को तैयार कांग्रेस

मांग ▸ कहा, पार्टी के नेताओं की रिहाई के बाद ही ले सकते हैं निर्णय

नेशनल कांफ्रेंस ने भी वरिष्ठ नेताओं की रिहाई की शर्त रखी थी

जेएनएन, जम्मू

केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर में पंचायत उपचुनाव का बिगुल बज गया है, लेकिन नेकां और कांग्रेस ने कहा है कि जब तक उनके नेताओं को रिहा नहीं किया जाएगा तब तक वह चुनाव लड़ने के बारे में निर्णय नहीं ले सकती हैं। उनकी मांग है कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को रिहा किया जाए।

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर ने कहा कि हम पंचायत उपचुनाव में कैसे हिस्सा ले सकते हैं, जबकि पार्टी के बहुत से नेता व कार्यकर्ता या तो अपने घरों में नजरबंद हैं या फिर जेलों में हैं। मीर ने कहा, प्रशासन पहले नजरबंद रखे गए और हिरासत में लिए गए हमारे सभी पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं को रिहा करें, उसके बाद ही हम लोगों की राय के आधार पर इन चुनाव में हिस्सा लेने या न लेने के बारे में कोई फैसला कर सकते हैं। हम चुनाव का बहिष्कार नहीं कर रहे हैं चाहे परिणाम कुछ भी आए, लेकिन जब हमारे नेताओं को प्रचार करने की अनुमति ही नहीं है तो फिर यह कैसे संभव होगा।

उन्होंने कहा कि 2018 में पंचायत चुनाव गैर राजनीतिक आधार पर करवाए गए थे, लेकिन अब राजनीतिक आधार पर हो रहे हैं। ऐसे में सरकार को या तो पहले करवाए गए चुनाव को रद कर देना चाहिए अन्यथा ये उप चुनाव भी गैर राजनीतिक आधार पर कराए जाएं। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी 90 साल की मां को देखने के लिए जाने का आग्रह किया था, लेकिन आज तक इस संबंध में मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैंने अब चुनाव के सिलसिले में जम्मू से बाहर जाने के लिए पुलिस प्रशासन से इजाजत मांगी थी, लेकिन कहा गया कि जम्मू नहीं छोड़ सकते। नेशनल कांफ्रेंस के वरिष्ठ नेता शौकत अहमद मीर ने कहा, जब हमारी पार्टी के अध्यक्ष न केवल अपने घर में नजरबंद हैं, बल्कि उन पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट भी लगाया गया है तो ऐसे में हम कैसे चुनाव में हिस्सा लेने की सोच सकते हैं।

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ नेता निजामुद्दीन भट ने कहा कि वह चुनाव लड़ने संबंधित कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। भट ने कहा कि चुनाव लड़ने या इसी तरह कोई भी राजनीतिक काम करने से पहले पार्टी अपने तमाम पार्टी सदस्यों से सलाह की जाती है। हमारी पार्टी की लीडरशिप या तो जेलों में बंद हैं या अपने घरों में नजरबंद। पार्टी अध्यक्ष पर पीएसए भी लगाया गया है। ऐसे में चुनाव लड़ने या न लड़ने का फैसला कैसे कर सकते हैं।

जम्मू में सोमवार को कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष जीए मीर (मध्य) संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए। उनके (दाएं) प्रवक्ता रविंद्र शर्मा व (बाएं) पूर्व मंत्री रमण भल्ला। जागरण

सियासी दलों की हां-न के बीच निर्वाचन अधिकारी ने बुलाई सर्वदलीय बैठक

राज्य ब्यूरो, जम्मू : केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में होने वाले पंचायत उपचुनावों में हिस्सा लेने के लिए राजनीतिक पार्टियों की हां और न के बीच राज्य निर्वाचन अधिकारी ने मंगलवार को सभी सियासी दलों की बैठक बुलाई है। बैठक में पंचायत उपचुनावों को लेकर बातचीत की जाएगी। कांग्रेस और नेशनल कांफ्रेंस ने अपने पार्टी नेताओं को रिहा करने की शर्त के साथ चुनाव में हिस्सा लेने के संकेत दिए हैं।

दरअसल, जम्मू-कश्मीर के इतिहास में पहली बार पंचायत चुनाव दलीय आधार पर कराए जा रहे हैं। मसलन, उम्मीदवार अपनी पार्टी के चुनाव चिह्न के साथ चुनाव मैदान में होंगे। चुनाव चिह्न के आधार पर वोट डाले जाएंगे और पार्टी की रणनीति बताते हुए उम्मीदवार मतदाताओं के पास वोट मांगने जाएंगे।

जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी शैलेंद्र कुमार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। इसमें जम्मू-कश्मीर की क्षेत्रीय पंजीकृत राजनीतिक पार्टियों और राष्ट्रीय दलों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया है। बैठक मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में होगी।

घोषणा के बाद बैठक बुलाने का क्या औचित्य : कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने कहा कि चुनाव की घोषणा के बाद बैठक बुलाने का क्या औचित्य है। यह बैठक पहले बुलाई जानी चाहिए थी। हर्षदेव सिंह ने कहा कि बैठक में पार्टी का पक्ष रखेंगे। सरकार ने पहले चुनाव गैर राजनीतिक आधार पर करवाए और अब राजनीतिक आधार पर करवाए जा रहे हैं।

शहीद मेजर विभूति की पत्नी भी बनेंगी फौज में अफसर

जागरण संवाददाता, देहरादून

- एक साल पहले शहीद हुए थे दून निवासी मेजर विभूति शंकर ढौंडियाल
- पत्नी निकिता सेना के लिए टेस्ट और साक्षात्कार कर चुकी हैं क्लियर

देश के एक मोर्चे पर हमारे जांबाज जवान डटे होते हैं तो दूसरे मोर्चे उनकी मां, बहन और पत्नी। यह उनका साहस ही है, जिसके बूते हमारे जवान बिना किसी चिंता देश पर कुर्बान होने के लिए हर समय तत्पर रहते हैं... और सलाम कीजिए उन महिलाओं को, जब कोई वीर तिरंगे में लिपटकर घर आता है तो वह अपने दर्द को पीछे छोड़कर साहस की एक नई इबारत लिखती हैं। हम बात कर रहे हैं शहीद मेजर विभूति शंकर ढौंडियाल की पत्नी निकिता की। पति की शहादत के बाद अब वह देश की सेवा को उनकी राह चल पड़ी हैं। सैन्य अफसर बनने की ओर वह कदम बढ़ा चुकी हैं। इसके लिए टेस्ट और साक्षात्कार वह क्लियर कर चुकी हैं और उन्हें उम्मीद है कि मेरिट में भी वह अपना स्थान बना लेंगी।

गत वर्ष 18 फरवरी को आंतकी मुठभेड़ में हुए थे शहीद : शहीद मेजर विभूति शंकर ढौंडियाल देहरादून के रहने वाले थे। वह बीती गत वर्ष 18 फरवरी को आंतकी मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी को आतंकवादियों ने सीआरपीएफ की टुकड़ी पर फिदायीन हमला किया था। इसके तीन दिन बाद यहां पर आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें मेजर विभूति शहीद हो गए थे।

माथा चूमकर सैल्यूट से दी थी अंतिम विदाई

शहीद पति को अंतिम विदाई देते वक्त उन्होंने जो हिम्मत दिखाई, वह अब भी उनके हौसले को बयां करती है। वह ताबूत के पास खड़ी रहीं और पति का चेहरा हाथों से चूमकर उन्हें आइ लव यू कहकर उन्हें सैल्यूट कर अंतिम विदाई दी थी। अब वह पति के नक्शे कदम पर चल पड़ी हैं। वह दिन दूर नहीं, जब वह उनकी ही तरह फौजी वर्दी में दिखाई देंगी।

तीन बहनों के इकलौते भाई थे ढौंडियाल

34 वर्षीय मेजर विभूति ढौंडियाल सेना के 55 आरआर (राष्ट्रीय राइफल) में तैनात थे। वह तीन बहनों के इकलौते भाई थे। वर्ष 2018 अप्रैल माह में उनकी शादी हुई थी। शादी को एक साल भी नहीं हुआ था, जब उनकी शहादत की खबर आ गई। पर उनकी पत्नी निकिता ने न केवल खुद को, बल्कि परिवार को भी संभाला।

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपनाया था सख्त रुख

प्रथम पृष्ठ से आगे

सूत्रों का यह भी कहना है कि वोडाफोन ने 2,500 करोड़ का भुगतान कर दिया है और कुछ दिन में 1,500 करोड़ के भुगतान की बात कही है। इसका अर्थ है कि वोडाफोन अब 4,000 करोड़ चुकाने में समर्थता जता रही है। पिछले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर बकाये को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया था और यहां तक कह दिया था कि इस देश में कानून का राज नहीं है व सुप्रीम कोर्ट को बंद कर देना चाहिए। इसके बाद हरकत में आए दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने शुक्रवार को आधी रात तक सभी को बकाया राशि के भुगतान का आदेश दिया था। उस आदेश के तहत ही वोडाफोन सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुई थी और अभी 3,500 करोड़ रुपये का भुगतान करने की पेशकश की थी। न्यायाधीश अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस पेशकश को खारिज कर दिया। साथ ही कंपनी को राहत देने संबंधी अन्य पेशकश को भी निरस्त कर दिया। वोडाफोन की तरफ से बताया गया कि अभी वह इतनी ही राशि का इंतजाम कर पाई है और उसके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उधर, एयरटेल की तरफ से बताया गया है कि उसने 10 हजार करोड़ रुपये का भुगतान सरकार को कर दिया है। यह भुगतान भारती एयरटेल, भारती हेक्साकॉम व टेलीनॉर की तरफ से किया गया है। सरकार की गणना के मुताबिक इस समूह पर कुल 35,586 करोड़ रुपये की राशि बकाया है जिसका भुगतान उसे दूरसंचार विभाग को करना है। सोमवार देर शाम टाटा समूह की टीटीएसएल ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 2197 करोड़ रुपये बतौर एजीआर भुगतान की जानकारी दी। यह राशि स्पेक्ट्रम शुल्क व लाइसेंस फीस के बकाये के तौर पर अदा की गई है। कंपनी ने अपना पूरा बकाया चुका दिए जाने की बात कही है। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया है कि एजीआर मामले में टेलीकॉम मंत्रालय को ही फैसला करना है।

गैर-टेलीकॉम कंपनियों का संकट ज्यादा बड़ा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : दूरसंचार कंपनियों के अलावा सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जद में सरकारी क्षेत्र की कुछ गैर दूरसंचार कंपनियां भी आ रही हैं जिन पर 2.7 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का बकाया होने की बात सामने आ रही है। इनमें कई पेट्रोलियम सेक्टर की कंपनियां हैं जो स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करती हैं। इसमें गेल लिमिटेड, ऑयल इंडिया, पावरग्रिड जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। इनमें से कुछ कंपनियों से सरकार जितनी राशि मांग रही है वह उनकी नेटवर्थ से भी ज्यादा है। मसलन, गेल लिमिटेड पर 1.83 लाख करोड़ रुपये के बकाये की गणना डीओटी की तरफ से की गई है। बहरहाल, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जद में गैर दूरसंचार कंपनियां नहीं आती हैं। जो स्थिति उत्पन्न हुई है वह सही तरह से सूचना नहीं पहुंचने की वजह से हुई है। हम डीओटी से बात कर रहे हैं।

स्कूल की केमिस्ट्री लैब में धमाका, चार बच्चे घायल

जागरण संवाददाता, शिमला : उपमंडल ठियोग के मतियाना में सोमवार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल की केमिस्ट्री लैब में जोरदार धमाका होने से चार विद्यार्थी घायल हो गए। इनमें से दो को पीजीआइ चंडीगढ़ रेफर किया गया है। पुलिस ने देर शाम लैब को सील कर जांच शुरू कर दी है। उच्चतर शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत शर्मा ने भी मामले की जांच का आदेश दे दिया है।

स्कूल की केमिस्ट्री लैब में सोमवार दोपहर को 12वीं कक्षा के विज्ञान संकाय के विद्यार्थी पांच-पांच के ग्रुप में प्रेक्टिकल कर रहे थे। विद्यार्थियों ने जब बोतल में केमिकल मिलाया तो अचानक धमाका होने से भगदड़ मच गई। लैब में खून के धब्बे बिखरे दिखे।

घायल हुए चार विद्यार्थियों को इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (आइजीएमसी) शिमला पहुंचाया। दो छात्रों की हालत ज्यादा खराब होने पर उन्हें पीजीआइ चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। दोनों विद्यार्थियों को चेहरे पर काफी चोटें आई हैं।

डोकलाम विवाद के दौरान चीनी सेना पर नजर रख रहा था पी-8आइ विमान

- सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने इस लड़ाकू विमान की तैनाती की पुष्टि की
- भूटान के पठारी क्षेत्र में 73 दिनों तक आमने-सामने थे दोनों देशों के सैनिक

नई दिल्ली, प्रेट्र : पूर्वोत्तर के क्षेत्र डोकलाम में 73 दिनों तक चले विवाद के दौरान भारत नौसेना के पनडुब्बी-रोधी लड़ाकू विमान पी-8आइ से चीन के सैनिकों की गतिविधियों पर नजर रख रहा था।

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल बिपिन रावत ने इस लड़ाकू विमान की तैनाती की पुष्टि की। उन्होने कहा, 'डोकलाम विवाद के दौरान भारतीय नौसेना के पी-8आइ विमान को तैनात किया गया था।' पिछले साल पुलवामा में आतंकी हमले के बाद भी पाकिस्तानी सेना की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए पी-8आइ विमान को निगरानी के काम में लगाया गया था।

बता दें कि भूटान के पठारी इलाके डोकलाम में 16 जून, 2017 को भारत और चीन के जवान आमने-सामने आ गए थे। दरअसल, चीन डोकलाम को अपना हिस्सा बताता है और उसने पर उस पर कब्जा भी कर रखा है।

चीनी सेना ने वहां सड़क बनाने का काम शुरू किया था, जिसे भारतीय सेना ने रुकवा दिया था। इसी के बाद डोकलाम में विवाद पैदा हो गया था। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक स्तर पर 10 दौर की बातचीत में यह मामला सुलझा था और 28 अगस्त 2017 को दोनों ही पक्ष ने डोकलाम से अपनी सेनाएं हटा ली थी।

समुद्री व पहाड़ी क्षेत्रों पर रखता है सटीक नजर : रक्षा विशेषज्ञ कैप्टन डीके शर्मा (रिटायर्ड) का कहना है कि समुद्र हो या पहाड़ी क्षेत्र निगरानी रखने के लिए पी-8आइ विमान सबसे भरोसेमंद है। डोकलाम विवाद के दौरान भी इससे जो डाटा मिले थे, उससे आगे की रणनीति तय करने और फैसला लेने में मदद मिली थी। शर्मा ने कहा कि पी-8आइ की तैनाती मुश्किल हालात में सेना और नौसेना के बीच बेहतर समन्वय का उदाहरण है।

भारत के पास आठ पी-8आइ विमान : पी-8आइ बोइंग की अगली पीढ़ी के विमान 737 पर आधारित है। यह अमेरिकी नौसेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पी-8ए श्रेणी का विमान है। बोइंग से यह विमान खरीदने वाला भारत पहला अंतरराष्ट्रीय ग्राहक था। भारतीय नौसेना में इस टोही विमान को 2013 में शामिल किया गया। नौसेना के पास अभी आठ पी-8आइ विमान है। 2016 में रक्षा मंत्रालय ने और चार पी-8आइ विमानों का ऑर्डर दिया था, जो इस साल अप्रैल से मिलने शुरू हो जाएंगे। पिछले साल भी अतिरिक्त छह पी-8आइ विमानों के अधिग्रहण को मंजूरी दी गई थी।

बदलाव

शीतकालीन अवकाश के बाद मार्च में खुलेंगे कश्मीर के स्कूल

कश्मीर के स्कूलों में फिर से लौटेगी बहार

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

कश्मीर में मौसम बदल रहा है और उसके साथ ही फिर से बदलाव की तस्वीर साफ दिख रही है। शीतकालीन अवकाश के बाद मार्च माह में फिर से स्कूल खुल जाएंगे। हालांकि कुछ स्कूलों में इस दौरान अतिरिक्त कक्षाएं चल रहीं थी ताकि राज्य के पुनर्गठन के बाद कश्मीर में अलगाववादियों के बंद से हुए नुकसान की भरपाई की जा सके।

बता दें कि कश्मीर में बर्फबारी के सीजन में नवंबर माह से करीब ढाई माह के लिए स्कूलों में अवकाश रहता है और मार्च में नया सत्र आरंभ होता है। इससे पूर्व अगस्त में जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के एलान के बाद वादी में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए थे। हालांकि सरकार ने चरणबद्ध ढंग से स्कूल खोलने का एलान कर दिया था, लेकिन आंतकियों और अलगाववादियों की धमकियों के कारण वादी में बड़ी संख्या में स्कूल बंद रहे या आंशिक तौर पर ही खुले रहे। इस कारण उपस्थिति काफी कम रही थी। इन तमाम चुनौतियों के बावजूद राज्य प्रशासन अक्टूबर और नवंबर में वार्षिक परीक्षाओं के आयोजन में पूरी तरह सफल रहा। 99 फीसद से अधिक छात्रों ने वार्षिक परीक्षाएं दीं। उसके बाद शीतकालीन अवकाश घोषित हो गए।

सर्दी में भी खुले रहे थे स्कूल : अब अवकाश के बाद एक मार्च को कश्मीर में स्कूल खुल जाएंगे। छात्र और अभिभावक भी स्कूलों के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। कुछ स्कूलों में नियमित अतिरिक्त कक्षाएं के कारण हालांकि पहली बार हुआ कि सर्दी के मौसम में भी स्कूल आंशिक तौर पर खुले रहे।

प्रशासन कर रहा है आवश्यक प्रबंध

राज्य प्रशासन ने इसके लिए सारे प्रबंध कर लिए हैं। प्रशासन का लक्ष्य है कि असामाजिक तत्वों को किसी तरह का अवसर न मिले। अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजने के लिए उत्सुक हैं।

अब और न हो पढ़ाई का नुकसान

एक स्थानीय निवासी बसरत ने बताया कि पहले ही काफी पढ़ाई प्रभावित हो चुकी है। बच्चे घरों में ही पढ़ रहे है। हम नहीं चाहते कि बच्चों की पढ़ाई में और खलल पड़े। कश्मीर में काफी लोग शीतकालीन अवकाश के दौरान जम्मू में अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं। अब यह लोग वापस घरों को लौटने लगे हैं।

एम्स विजयपुर में इसी वर्ष अकादमिक सत्र होगा शुरू

राज्य ब्यूरो, जम्मू : विजयपुर क्षेत्र में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में निर्माण शुरू होने के साथ इस साल अकादमिक सत्र चालू करने की भी तैयारी तेज हो गई है। सोमवार को एम्स में फैकल्टी के 164 पद भरने की अधिसूचना जारी कर दी है। एम्स ऋषिकेश के निदेशक ने एम्स विजयपुर की तरफ से प्रोफेसरों, एडिशनल प्रोफेसरों, एसोसिएट प्रोफेसरों, असिस्टेंट प्रोफेसरों के पदों को सीधे, डेपूटेशन या कांट्रेक्ट पर भरने के लिए उम्मीदवारों से आवेदन पत्र मांगे हैं। बायोकेमिस्ट्री, एनाटोमी, फार्माकोलॉजी, फोरेंसिक मेडिसिन, माइक्रोबोलॉजी, पैथोलॉजी, डर्मोटालाजी, जनरल मेडिसिन, एनसथीसियोलॉजी व अन्य विभागों में पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। उम्मीदवार 29 फरवरी से लेकर 7 अप्रैल 2020 तक आवेदन कर सकते हैं। इन पदों में सामान्य और विभिन्न आरक्षित वर्गों के पद शामिल हैं। गौरतलब है कि 13 फरवरी को एम्स का निर्माण कार्य शुरू करवाने के लिए पूजा अर्चना की थी। इसमें पीएओ में राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह शामिल हुए थे। एम्स विजयपुर का नींव पत्थर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा था।

'13 फरवरी से पहले इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली थी'

प्रथम पृष्ठ से आगे

जब डेबी अब्राहम्स से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे 13 फरवरी से पहले इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली थी। उसके बाद से वह ऑफिस नहीं गईं और लगातार यात्रा कर रही थीं। ब्रिटेन में उनके दफ्तर ने इस बात की पुष्टि की कि डेबी को दुबई के एक विमान में वापस भेजा गया है। चूंकि वह दुबई से ही भारत आईं थीं। डेबी के साथ उनका भारतीय मूल का स्टाफ भी मौजूद था। इससे पहले, सोमवार की सुबह आइजीआइ एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद डेबी ने ट्विटर पर अपनी आपबीती साझा करते हुए कहा कि जब वह एयरपोर्ट पहुंची तब उन्हें बताया गया कि उनका ई-वीजा रद हो चुका है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि वह इमिग्रेशन डेस्क पर अपने दस्तावेज और ई-वीजा के साथ पहुंची थीं। लेकिन वहां मौजूद अधिकारी ने कंप्यूटर पर डाटा जांचने के बाद बताया कि उनका वीजा रद हो चुका है। उसने उनका पासपोर्ट लिया और दस मिनट गायब रहा। उसके बाद वह लौटा तो उसका व्यवहार बहुत बुरा था और वह साथ चलने के लिए मुझ पर चिल्ला रहा था। फिर वह मुझे 'डिपोर्टी सेल' ले गया। डेबी ने बताया कि उसके बाद उन्होंने अपनी ननद की कजिन काई को फोन किया, जहां वह ठहरने वाली थीं। काई ने ब्रिटिश उच्चायोग में संपर्क साधा और मामले का पता करने की कोशिश की। डेबी के पति जॉन अब्राहम्स ब्रिटिश क्रिकेटर रह चुके हैं। ध्यान रहे कि डेबी ने पिछले साल अगस्त में जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद एक औपचारिक पत्र लिखकर इसका कड़ा विरोध किया था। विपक्षी सांसद अब्राहम्स ने ब्रिटेन के तत्कालीन विदेश मंत्री डोमिनिक राब को चिट्ठी लिखकर कहा था कि वह केंद्रीय मंत्री अमित शाह के भारतीय संविधान से अनुच्छेद 370 हटाने की घोषणा से बेहद चिंतित हैं।

2 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार करने वाले योग्य बड़े करदाताओं में से लगभग 92 फीसद ने वार्षिक जीएसटी रिटर्न दाखिल किया है वित्त वर्ष 2017-18 के लिए गत 12 फरवरी तक।

पूर्व डीआइजी कुलतार, डीएसपी हरदेव सहित छह दोषी करार

फैसला ▸ ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर हरदीप ने परिवार के साथ कर ली थी आत्महत्या

हरदीप के हाथों हुई थी पिता की हत्या, शव ठिकाने लगाते ताया की बहू ने देखा तो करने लगी थी ब्लैकमेल

जागरण संवाददाता, अमृतसर

पंजाब में अदालत ने 30 अक्टूबर, 2004 को मां, पत्नी, बेटे और बेटी के साथ चौक मोनी में रहने वाले हरदीप सिंह की तरफ से की गई सामूहिक आत्महत्या के मामले में पूर्व डीआइजी कुलतार सिंह, वर्तमान में गोइंदवाल साहिब के डीएसपी व तत्कालीन एसएचओ हरदेव सिंह बोपाराय सहित छह लोगों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने यह फैसला आत्महत्या के लिए उकसाने और ब्लैकमेलिंग के आधार पर सुनाया है। दोषियों में हरदीप के ताया महिंदर सिंह, उसकी बहू सबरीन कौर, बेटी परमिंदर कौर और दामाद पलविंदर पाल सिंह भी शामिल हैं। 19 फरवरी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप सिंह बाजवा की अदालत सभी दोषियों को सजा सुनाएगी।

चौक मोनी में रहने वाले हरदीप सिंह का अपने पिता सुंदर सिंह के साथ विवाद चल रहा था। 11 अगस्त, 2004 को झगड़े में हरदीप के हाथों पिता की हत्या हो गई थी। शव ठिकाने लगाते समय ताया महिंदर सिंह की बहू सबरीन कौर ने उसे देख लिया। इसके बाद महिंदर सिंह, सबरीन कौर, परमिंदर कौर और उसके पति पलविंदर पाल सिंह ने पुलिस से पकड़वाने की धमकियां देकर हरदीप को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। आरोपितों ने धमकाकर हरदीप से सात लाख रुपये ले लिए थे। इनके चंगुल से छुटकारा पाने के लिए हरदीप के एक दोस्त ने उसकी मुलाकात तत्कालीन एसएसपी कुलतार सिंह के साथ करवाई। कुलतार सिंह ने हरदीप के खिलाफ कमजोर केस दर्ज करने के लिए पांच लाख रुपये लिए। बाद में सात लाख रुपये की और मांग करने लगा। आरोप है कि कुलतार ने हरदीप की पत्नी के साथ अपने दफ्तर में दुष्कर्म भी किया था। वह हरदीप को ब्लैकमेल करते हुए उसकी पत्नी को चंडीगढ़ के एक गेस्ट हाउस में भी लेकर गया था। कुलतार अब डीआइजी के पद से रिटायर्ड हो चुके हैं।

आत्महत्या से पहले दीवार पर लिखे थे आरोपितों के नाम

पुलिस और रिश्तेदारों की ब्लैकमेलिंग से परेशान हरदीप सिंह ने 30 अक्टूबर, 2004 की रात मां जसवंत कौर, पत्नी रोमी, बेटे इमरत (6) और बेटे सनमीत (9) के साथ घर में आत्महत्या कर ली थी। हरदीप ने आत्महत्या से पहले घर की दीवार पर लिखे सुसाइड नोट पर उक्त आरोपितों के नाम लिख इन्हें जिम्मेदार ठहराया था। सी डिवीजन थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी इंस्पेक्टर हरदेव सिंह जब घटना स्थल पर पहुंचे तो उन्होंने कुलतार के आदेश पर दीवार पर लिखे गए सुसाइड नोट को मिटाना शुरू किया था, लेकिन मीडिया के पहुंचने से मामले का राजफाश हो गया था।

न्यूज गैलरी

तीन हत्याओं का वांछित सुरक्षा गार्ड दिल्ली में गिरफ्तार

मुंबई : वर्ष 2000 से तीन लोगों की हत्या के आरोपित सिक्यूरिटी गार्ड को मुंबई पुलिस ने नई दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। सुरक्षा गार्ड पर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चचेरे भाई समेत दो लोगों की हत्या करने का आरोप है। उस पर पिछले साल मुंबई के पवई में एक साथी सुरक्षा गार्ड की हत्या करने का भी आरोप है। पुलिस के मुताबिक, आरोपित अविनाश कुमार लक्ष्मीकांत पांडे को नई दिल्ली के कमला नगर मार्केट इलाके से रविवार को गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने उस पर 10 हजार रुपये का इनाम भी घोषित कर रखा है। 38 वर्षीय पांडे के खिलाफ उत्तर प्रदेश में आर्म्स एक्ट का भी एक मामला दर्ज है। पुलिस उपायुक्त (जोन एक्स) अंकित गोयल ने कहा कि 27 अक्टूबर 2019 को पांडे ने मुंबई में 22 वर्षीय अंकित देवीप्रसाद सिंह की हत्या कर दी और उसकी लाश पवई में टुंगा गांव के लोढा सुप्रीम अपार्टमेंट की पार्किंग में छोड़ दिया। इसके बाद वह पुणे भाग गया और फिर वहां से गुजरात चला गया। ओडिशा में कुछ समय गुजारने के बाद वह दिल्ली पहुंचा। डीसीपी ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में उसकी मौजूदगी सूचना के बाद उसे गिरफ्तार किया जा सका। (प्रेट्र)

आगरा में अपहृत अधिवक्ता को कराया गया मुक्त

आगरा : सिकंदरा क्षेत्र से अगवा फीरोजाबाद के अधिवक्ता अकरम अंसारी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन से पहले मुक्त करा लिया गया। अधिवक्ता का आगरा से तीन फरवरी को अपहरण किया गया था। एक सप्ताह से बीहड़ में डेरा डाली पुलिस टीमों को छह बदमाशों को दबोचने में भी कामयाबी मिली है। फीरोजाबाद के मुहल्ला राजपूताना निवासी अधिवक्ता अकरम अंसारी का आगरा के सिकंदरा क्षेत्र से अपहरण करने के बाद बदमाशों ने उनके भाई के मोबाइल पर कॉल करके 50 लाख फिरौती मांगी। तभी से पुलिस उनकी तलाश में लगी थी। एक सप्ताह से पुलिस की टीमों ने तांतपुर और धौलपुर में तलाश शुरू की थी। उधर, फीरोजाबाद और आगरा में अधिवक्ताओं में अपहरण के बाद भारी आक्रोश था। रविवार रात को एसएसपी बबलू कुमार पुलिस टीम के साथ राजस्थान के बॉर्डर पर डटे रहे। धीरे-धीरे पुलिस की टीमें बदमाशों के करीब पहुंच गईं। सोमवार रात आठ बजे पुलिस ने अधिवक्ता को राजस्थान के बाड़ी से मुक्त करा लिया। बदमाशों ने उन्हें एक घर में बंधक बनाकर रखा था। दबोचे गए बदमाशों से पूछताछ जार है। अपहरण करने वाले गैंग के सरगना का नाम सुरेंद्र पता चला है। आगरा पुलिस की टीम अपहृत को मुक्त कराने के बाद अपने साथ आगरा ले आई है। एसएसपी बबलू कुमार ने बताया कि शेष बदमाशों को भी गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। (जांस)

न्याय देवता गोलज्यू भी कानून की शरण में

जागरण संवाददाता, नैनीताल : उत्तराखंड स्थित कुमाऊं में न्याय देवता गोलज्यू खुद कानून की शरण में पहुंच गए हैं। अल्मोड़ा में प्रसिद्ध चितई मंदिर में अनियमितता बंद करने के लिए गोलज्यू भगवान ही पक्षकार बने हैं। हालांकि हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता से पुजारियों को पक्षकार बनाने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी। गोलज्यू के भक्त नैनीताल निवासी अधिवक्ता दीपक रूवाली ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि चितई गोलज्यू मंदिर में हर साल लाखों का चढ़ावा आता है। चंद लोग चढ़ावे की रकम पर अपना अधिकार समझते हैं। याचिका में चितई गोलज्यू के मंदिर का ट्रस्ट बनाने की मांग की गई है। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। अब कुछ लोग गोलज्यू की तरफ से प्रार्थना पत्र लेकर कोर्ट में आए हैं। उनका कहना है कि मंदिर में धांधली की जा रही है। प्रार्थना पत्र में चढ़ावे व दान से मिली रकम को जमा करने के लिए बैंक खाता खोलने की मांग की गई है। स्पेशल ऑडिट करने व अनियमितताओं की जांच की मांग भी है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति रमेश चंद्र खुल्बे की खंडपीठ ने सोमवार को सुनवाई के दौरान पुजारियों को पक्षकार बनाने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।

वनवासियों को नगरीय समाज से जोड़ने की कवायद

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- दिल्ली में वनवासी परिवार रक्षा कुंभ का आयोजन
- फाउंडेशन ने की अपील, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए लोग इससे जुड़ें

देश के सुदूर पहाड़ व जंगलों में बसे वनवासियों के जीवन को संवारने में वर्षों से लगे वनवासी रक्षा परिवार फाउंडेशन अब शहरों का ध्यान भी इस ओर आकृष्ट करना चाहता है। वनवासी समाज की गरीबी, अशिक्षा और इसके कारण होने वाले धर्मांतरण के मुद्दों से शहरी समाज को अवगत कराकर उन्हें वनवासी क्षेत्रों से जोड़ना चाहता है। इसी संदर्भ में दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 23 फरवरी को वनवासी रक्षा कुंभ का आयोजन किया जाएगा।

फाउंडेशन ने अपील की है कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए लोग इससे जुड़ें और आर्थिक रूप से भी मदद करें। स्वागत समिति सदस्यता के लिए दो लाख और स्वागत समिति संरक्षण सदस्यता के लिए पांच लाख रुपये की राशि की अपील की गई है।

यूं तो वनवासी फाउंडेशन के कामकाज को सिर्फ वनवासियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और राष्ट्रभावना से ही जोड़कर देखा जाता रहा है लेकिन एक बड़ी सच्चाई यह भी है कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से जूझने में भी ये हमारी मदद करते हैं। ऐसी स्थिति में फाउंडेशन ने वनवासियों को सामने लाकर ही लोगों को उद्वेलित करने का मन बनाया है।

फाउंडेशन के राष्ट्रीय संगठन प्रभारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि एकल अभियान के तहत देश के चार लाख गांवों में कार्य हो रहा है। देश भर में 70 हजार संस्कार केंद्र चल रहे हैं। कुंभ में 15 हजार वनवासी और वहां कार्य कर रहे लोग उपस्थित होंगे। इसके साथ ही नगरीय समाज के लोगों को भी आमंत्रित किया गया है। यह वक्त है कि देश का हर व्यक्ति समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझे। उन्होंने उम्मीद जताई की बड़ी संख्या में लोग इससे तन मन धन से जुड़ेंगे।

सोना तस्करी हवाला रैकेट का पर्दाफाश 39 किग्रा सोना-चांदी किया गया जब्त

- ईडी की कार्रवाई में 3.75 करोड़ की नकदी भी जब्त
- फेमा के तहत जयपुर, कोलकाता और चेन्नई में मारे गए थे छापे
- बड़े पैमाने पर सीमा शुल्क, जीएसटी व आयकर चोरी का भी पता लगा

नई दिल्ली, प्रेट्र : सोना तस्करी हवाला रैकेट से कथित रूप से जुड़े ज्वैलर्स के यहां छापों में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 3.75 करोड़ रुपये की अघोषित नकदी और 39 किग्रा से ज्यादा सोना-चांदी जब्त की है। ये छापे विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून (फेमा) के तहत जयपुर, कोलकाता और चेन्नई में मारे गए थे। इसमें बड़े पैमाने पर सीमा शुल्क, जीएसटी और आयकर चोरी का भी पता लगा है।

ईडी ने एक बयान जारी कर बताया, 'ईडी को इस बात की विश्वसनीय जानकारी मिली थी कि जयपुर के महाराजा ज्वैलर्स (स्वामित्व- तारा चंद सोनी), भगवती ज्वैलर्स (स्वामित्व- राम गोपाल सोनी) और लाडीवाला एसोसिएट्स (स्वामित्व- हनी लाडीवाला) चेन्नई के हर्ष बोथरा और बांका बुलियंस प्राइवेट लिमिटेड आदि से तस्करी का सोना खरीद रहे थे। जयपुर, कोलकाता और चेन्नई में विभिन्न परिसरों की तलाशी में 3.75 करोड़ रुपये की अघोषित भारतीय व विदेशी नकदी, 26.97 किग्रा सोना, 12.22 किग्रा चांदी और कई दस्तावेज बरामद हुए। जब्त इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल उपकरणों की जांच की जानी बाकी है और इनकी जांच से कई गैरकानूनी सौदों की जानकारी मिल सकती है।'

ईडी को कार्रवाई के दौरान पता चला कि सोने की तस्करी और उसे जयपुर भेजने में कई लोग शामिल थे। तस्करी का सोना उच्च शुद्धता स्तर का होता था और इसे जयपुर में कोलकाता के रास्ते लाया जाता था। संदिग्ध लोग सोने की छड़ों पर अंकित विदेशी निर्माता का चिह्न या बैंक का नाम मिटा देते थे और उसके बाद उसे तस्करी करके देश में लाते थे। प्रवर्तन एजेंसियों की निगाह से बचने के लिए इस सोने को विभिन्न घरेलू बाजारों में परिवहन के अलग-अलग साधनों से भेजा जाता था। ईडी का कहना है कि आरोपित ज्वैलर तस्करी के सोने से बनी ज्वैलरी और उससे अर्जित आय का कोई लेखा जोखा नहीं रखते थे। इस धन को उपरोक्त शहरों में स्थित हवाला एजेंटों के जरिये ट्रांसफर कर दिया जाता था।

एयरफोर्स जवान की पत्नी ने चेन झपटमार को पटका

जागरण संवाददाता, लुधियाना : पंजाब के लुधियाना में एयरफोर्स जवान रविवार सायं पत्नी और बच्चे के साथ जब बाइक पर जा रहा था, तो एक अन्य बाइक सवार छपटमार ने उक्त जवान की पत्नी के गले में पहनी सोने की चेन झपटने की कोशिश की। इस पर एयरफोर्स अधिकारी की जांबाज पत्नी ने हिम्मत दिखाते हुए झपटमार की बाजू पकड़कर उसे गिरा दिया। बाद में झपटमार को पुलिस के हवाले कर दिया गया।

थाना सुधार की एसआइ रमनदीप कौर ने बताया कि एयरफोर्स स्टेशन हलवारा में तैनात कोरपोरल गुरदीप सिंह ने पुलिस को इस बारे में शिकायत दी है। गुरदीप सिंह ने बताया है कि वह रविवार देर सायं पत्नी प्रियंका और दो साल के बेटे रेहान के साथ बाइक पर खाना खाकर हलवारा लौट रहे थे। जब वह रकबा गेट से थोड़ा आगे पहुंचे, तो उनके पीछे बिना नंबर वाली एक प्लेटिना बाइक पर एक व्यक्ति आया। उसने पत्नी के गले में पहनी सोने की चेन झपटने की कोशिश की। इस पर पत्नी ने हिम्मत दिखाते हुए उसकी बाजू पकड़ ली। कुछ देर झपटमार जद्दोजहद करता रहा, परंतु पत्नी ने उसे छोड़ा नहीं और उसे पटकने का प्रयास किया। इस पर थोड़ा आगे जाकर दोनों बाइक अनियंत्रित होकर गिर गईं।

थाने से दस मीटर दूर दिन दहाड़े फाइनेंस कंपनी से 30 किलो सोने के गहने लूटे

जागरण संवाददाता, लुधियाना

पंजाब के लुधियाना में इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के ऑफिस से पांच नकाबपोश हथियारबंद लुटेरे सोमवार को 30 किलो सोने के गहने व साढ़े तीन लाख रुपये लूटकर फरार हो गए। सोने के गहनों की कीमत करीब 12 करोड़ बताई जा रही है।

बता दें कि घटना गिल रोड स्थित पुलिस की क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के थाने से मात्र दस मीटर दूर हुई। लुटेरों ने मैनेजर समेत चार कर्मियों को रस्सियों से बांध दिया और 12 मिनट में वारदात को अंजाम देकर भाग निकले। इतना ही नहीं, जाते समय लुटेरे ऑफिस के बाहर ताला भी जड़ गए। एक महिला कर्मचारी के अनुसार लुटेरे शाखा के हर सिस्टम से वाकिफ थे। उन्हें शाखा में चार जगह लगे सिक्योरिटी अलार्म के बटन की भी जानकारी थी।

सभी लुटेरे सफेद रंग की गाड़ी में सवार होकर आए थे। एक लुटेरा गाड़ी को स्टार्ट कर बाहर ही रहा और चार अंदर दाखिल हुए। इनमें से दो के पास पिस्टल और राइफल थी, जबकि दो के पास चाकू था। शाखा में मैनेजर हरप्रीत सिंह, डिप्टी मैनेजर अमित कुमार, कर्मचारी मोहम्मद अजहर और दर्जा चार कर्मचारी अमित कुमार मौजूद थे।

हाथ बांध मुंह नीचे करके बैठने को कहा : महिला कर्मचारी गुरप्रीत कौर ने बताया कि लुटेरों ने सभी कर्मियों के हाथ बांध दिए व मुंह नीचे कर बैठने को कहा। शाखा में स्ट्रांग रूम पर डिजिटल लॉक लगा था और सेफ भी अंदर रखी हुई थी। लुटेरों ने पिस्तौल के बल पर मैनेजर से लॉक खुलवाया और लूट कर फरार हो गए। मैनेजर ने पड़ोसी दुकानदार और मालिक को सूचित कर गेट खुलवाया। सूचना मिलने पर पुलिस कमिश्नर राकेश अग्रवाल व अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे।

कर्मचारियों पर भी शक

पुलिस को इस मामले में कंपनी के ही कुछ कर्मचारियों के मिले होने का शक है। इसलिए उनसे पूछताछ की जा रही है। कर्मचारियों के बयान को एक-दूसरे के बयान से मिलाया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।

बिहार में पांच मिनट में बैंक से 14 लाख लूटे

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर : मुजफ्फपुर में बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से सोमवार दोपहर लगभग तीन बजे अपराधियों ने मात्र पांच मिनट में लगभग 14 लाख रुपये लूट लिए। पांच की संख्या में लुटेरे बैंक के अंदर घुसे थे। उस समय बैंक में 50 से 60 ग्राहक थे। बदमाशों ने ग्राहकों से भी लगभग 80 हजार रुपये लूट लिए। लुटेरे पांच मिनट में ही वारदात को अंजाम देकर भाग चले। बैंक में घुसते ही एक लुटेरे ने कैश काउंटर पर बैठे कर्मचारी को पिस्टल के बल पर अपने कब्जे में ले लिया। दूसरा लुटेरा कैश काउंटर में रखा लगभग 14 लाख रुपये बोरा में भर लिया। तीसरा लुटेरे ने बैंक प्रबंधक अमरजीत सिंह के कक्ष में घुस कर पिस्टल के बल पर उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। उनका मोबाइल छीन लिया। बैंक में लगे सीसी कैमरे में लूट की घटना के फुटेज कैद हैं। बैंक की सुरक्षा में तैनात चौकीदार सोमवार को अनुपस्थित था।

मुंबई के जीएसटी भवन में आग लगी, कोई हताहत नहीं

मुंबई, प्रेट्र : दक्षिण मुंबई स्थित जीएसटी भवन में आग लगने बाद वहां से सैकड़ों कर्मचारियों को निकाला गया। अधिकारियों ने बताया कि बहु मंजिली इमारत में लगी आग में कोई हताहत नहीं हुआ। मझगांव इलाके में स्थित भवन में करीब 3500 कर्मचारी काम करते हैं। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि दोपहर 12:30 के आसपास आग भड़की। उन्होंने आग लगने के कारणों की जांच करने का आश्वासन दिया, लेकिन दस्तावेजों के डिजिटलाइजेशन के कारण आग से रिकार्ड को पहुंचे नुकसान के बारे में वह कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सके। आग की लपटों पर काबू पाने के लिए अग्निशमन कर्मचारियों को लगभग तीन घंटे तक संघर्ष करना पड़ा। अधिकारियों ने बताया कि 10 मंजिलों वाले सरकारी भवन की नौवीं मंजिल से शुरू हुई आग जल्द ही 10वीं मंजिल में फैल गई। मौके पर मौजूद अजीत ने कहा कि भवन में कागज और लकड़ी के सामान होने के कारण आग तेजी से फैली। इसके बाद भवन से धुआं उठने लगा। आग पर काबू पाने के लिए 20 से ज्यादा दमकल गाड़ियां लगाई गईं।

भाजपा, कांग्रेस ने किया महिलाओं को स्थायी कमीशन देने का स्वागत

- राजनाथ बोले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पूरे दिल से समर्थन करता हूं
- राहुल ने की केंद्र सरकार की आलोचना, तो मीनाक्षी ने दिया जवाब

नई दिल्ली, एजेंसियां : सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कांग्रेस और भाजपा ने स्वागत किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को ट्वीट किया, 'सशस्त्र बलों में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मैं पूरे दिल से समर्थन करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को स्थायी कमीशन देने के विचार का समर्थन कर चुके हैं और इस संबंध में नीतिगत बदलाव का उन्होंने 2018 के स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में समर्थन किया था।'

राजनाथ ने यह भी कहा कि महिलाओं को फील्ड ऑपरेशन में अनुमति देने का एक ऐतिहासिक निर्णय पूर्ववर्ती राजग शासन के दौरान लिया गया था। उस समय घोषणा की गई थी कि महिलाओं को सेना की सैन्य पुलिस में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए भर्ती प्रक्रिया 2019 में शुरू हो गई है। सरकार की योजना अपराधों की जांच से लेकर फील्ड ऑपरेशन तक में महिलाओं को जिम्मेदारी सौंपने की है।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद कांग्रेस और भाजपा ने भी एक-दूसरे पर निशाना साधा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दावा किया कि नरेंद्र मोदी सरकार ने इस मुद्दे पर शीर्ष अदालत में जो दलील दी वह देश की हर महिला का अपमान है। गांधी ने ट्वीट कर कहा, 'सरकार ने यह दलील देकर हर महिला का अपमान किया है कि महिला सैन्य अधिकारी कमान मुख्यालय में नियुक्ति पाने या स्थायी सेवा की हकदार नहीं हैं, क्योंकि वे पुरुषों के मुकाबले कमतर होती हैं।'

इसके जवाब में भाजपा ने कांग्रेस पर यह कहकर हमला किया कि 'कमांड पोस्ट' से इन्कार का मुद्दा कांग्रेस की विरासत था। सुप्रीम कोर्ट में महिला सैन्य अधिकारियों की पैरवी करने वाली भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा, 'राहुल गांधी कृपया रिफ्रेश मेमोरी बटन क्लिक कीजिए। यह कांग्रेस थी, जिसने 2010 में दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने के खिलाफ जोर-शोर से तर्क दिया था।' लेखी ने नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, 'यह आपकी सरकार थी जिसने उच्चतम न्यायालय में फैसले को चुनौती दी, जहां महिलाओं के पक्ष में फैसला आया।'

इस बीच, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने ट्वीट किया, 'सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले ने देश की महिलाओं की उड़ान को नए पंख दिए हैं। महिलाएं सेना में, शौर्य में और जल, थल, नभ में सक्षम हैं।' उन्होंने इसे पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो नारी शक्ति का विरोध करने वाली मोदी सरकार को करारा जवाब भी बताया है। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्रांतिकारी है। हालांकि, मुझे लगता है कि सरकार की तुलना में सेना की मानसिकता में बदलाव ज्यादा जरूरी है।

बसौदी के निशाने पर थे सलमान खान, रेकी के लिए छह बार गया था मुंबई

डीपी आर्य, सोनीपत : उत्तर भारत के कुख्यात राजू बसौदी अभिनेता सलमान खान की हत्या करना चाहता था। इसके लिए वह छह बार मुंबई का दौरा भी कर चुका था। वहां पर उसने गैंग की मूवमेंट भी शुरू कर दी थी और अपना गैंग सक्रिय कर रहा था। इसमें मुंबई के स्थानीय युवाओं को भी जोड़ना शुरू कर दिया था। राजू ने सलमान के आवासीय क्षेत्र का भी दौरा कर वहां के रास्तों, पुलिस चेक पोस्ट आदि की पूरी जानकारी भी जुटाई थी। बताया जाता है कि वह विदेश में रहकर इसे अंजाम देने की पूरी तैयारी में था। ऐसा वह लारेंस बिश्नोई के कहने पर करने वाला था। क्योंकि बिश्नोई समाज काले हिरण की पूजा करता हैं और इसको मारने के चलते लारेंस सलमान खान से रंजिश रखता था।

राजस्थान की जेल में बंद लारेंस बिश्नोई ने जनवरी 2018 में सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी और इसके लिए अपने गैंग को लगा भी दिया था। जून 2018 में लारेंस गैंग के वांछित गैंगस्टर संपत नेहरा की गिरफ्तारी के बाद एसटीएफ (स्पेशल टास्क फोर्स) ने बताया था कि संपत अभिनेता सलमान खान को मारने के लिए मुंबई गया था, लेकिन सुरक्षा के कारण वह सफल नहीं हो पाया।

उसकी गिरफ्तारी के बाद लारेंस गैंग की कमान राजू बसौदी ने संभाल ली थी। एसटीएफ सूत्रों के अनुसार लारेंस ने अब यह टास्क राजू को सौंप दिया था। पूरी प्लानिंग के साथ इस वारदात को अंजाम देने के लिए राजू छह बार मुंबई का दौरा कर चुका था।

राजू बसौदी ने मुंबई का कई बार दौरा किया। उसके गिरोह की वहां पर मूवमेंट है। मुंबई के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उसका आवागमन रहा है। उससे पूछताछ में कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ रहे हैं। अभी पूछताछ जारी है।

-सतीश देशवाल, प्रभारी एसटीएफ, सोनीपत

खोली राह

सेना में महिलाओं के स्थायी कमीशन की खोली राह, वायु सेना में रहते हुए बुलंद की महिलाओं की आवाज

रंग लाया विंग कमांडर अनुपमा का संघर्ष

जागरण संवाददाता, देहरादून

सेना में महिलाओं के स्थायी कमीशन का रास्ता साफ हो गया है। इस सपने को कहीं न कहीं दून निवासी विंग कमांडर (सेनि) अनुपमा जोशी ने पंख दिए। महिला अधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन की उनकी लड़ाई अब मुकाम तक आ पहुंची है।

देहरादून निवासी अनुपमा जोशी ने वायु सेना में रहते हुए महिला अधिकारियों के अधिकारों की आवाज बुलंद की और अपने संघर्ष को अंजाम तक पहुंचाया। अनुपमा का 1992 में एयर फोर्स में चयन हुआ। इसके बाद वह अपनी मेहनत और जज्बे के बल पर आगे बढ़ती रहीं। पहले पांच साल की सर्विस के बाद आवाज उठाई तो उन्हें तीन साल और फिर तीन साल का एक्सटेंशन मिला। हर बार टुकड़ों में मिल रहे एक्सटेंशन से वह खिन्न आ गईं। ऐसे में 2002 में उन्होंने इसके लिए अपने सीनियर अधिकारियों से लिखित में जवाब मांगा। यहां से कोई जवाब न मिलने पर चीफ को पत्र लिखकर जवाब मांगा। लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आया। इस पर उन्होंने कोर्ट में मुकदमा करने की ठान ली। 2006 में उन्होंने कोर्ट में याचिका दाखिल की। कोर्ट ने इस केस की सुनवाई में नई भर्तियों को स्थायी कमीशन देने का फैसला दिया, लेकिन सेवारत महिला अधिकारियों का फैसला नहीं हो पाया।

2008 में वह रिटायर हो गईं, लेकिन उनका संघर्ष जारी रहा। इस बीच कुछ अन्य अधिकारियों ने भी सेना में तैनात महिलाओं को स्थायी कमीशन देने को मामला दायर किया। इस पर हाईकोर्ट ने महिला अधिकारियों के पक्ष में अपना निर्णय सुनाया। अनुपमा का कहना है कि वायुसेना ने यह निर्णय तभी मान लिया था। इसके तहत सरकार ने महिलाओं को लड़ाकू विमान उड़ाने की अनुमति दी। हाईकोर्ट के फैसले के नौ साल बाद सरकार ने फरवरी 2019 में सेना के 10 विभागों में महिला अफसरों को स्थायी कमीशन देने की नीति बनाई, लेकिन यह कह दिया कि मार्च 2019 के बाद से सर्विस में आने वाली महिला अफसरों को ही इसका फायदा मिलेगा। इस तरह वे महिलाएं स्थायी कमीशन पाने से वंचित रह गईं, जिन्होंने इस मसले पर लंबे अरसे तक कानूनी लड़ाई लड़ी। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट ने एतिहासिक फैसला दिया है।

अनुपमा का कहना है कि यह बहुत पहले हो जाना चाहिए था। खैर, देर आए दुरुस्त आए। वह अभी देश के प्रतिष्ठित दून स्कूल में डायरेक्टर पर्सनल के पद पर कार्यरत हैं।

देहरादून निवासी विंग कमांडर (सेनि.) अनुपमा जोशी। जागरण आर्काइव

अदालत के फैसले से देशभर में महिलाओं का उत्थान होगा

नई दिल्ली, प्रेट्र : महिला सैन्य अधिकारियों ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय के उस आदेश का स्वागत किया, जिसमें उसने केंद्र को निर्देश दिया है कि वह उन्हें स्थायी कमीशन दे। महिला अधिकारियों ने कहा कि इससे न सिर्फ सशस्त्र बलों में बल्कि देशभर में महिलाओं का उत्थान होगा। कोर्ट के आदेश के बाद अदालत परिसर के बाहर संवाददाताओं से बातचीत करते हुए एक महिला अधिकारी ने कहा कि जो भी काम लायक हो उसे कमांड करने का अवसर दिया जाना चाहिए। महिला अधिकारी के साथ सेना में उनकी कुछ सहकर्मी भी मौजूद थीं। न्यायालय के आदेश का तीन महीने में अनुपालन किया जाना है। अधिकारी ने कहा, 'कमान सीधे नहीं सौंपी जा सकती। उसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इसलिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और जो भी मानदंड पर खरा उतरता है, उसे अवसर दिया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय के फैसले के मुताबिक यह आदेश सभी सेवारत महिला अधिकारियों पर लागू होगा।'

महिला आयोग ने किशोरी की हत्या पर स्वत: संज्ञान लिया

नई दिल्ली, प्रेट्र : राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने उत्तर प्रदेश में मेरठ में किशोरी की हत्या पर स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने मेरठ के पुलिस अधीक्षक से कहा कि वह एक लड़के द्वारा अपनी चचेरी बहन की कथित रूप से हत्या करने के मामले को देखें और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करें। मीडिया में आई खबर के मुताबिक, मेरठ में 19 वर्षीय लड़की को उसके ताऊ के बेटे ने गोली मार दी थी। आयोग ने कहा कि वह घटना से 'क्षुब्ध' है जिसमें कहा गया है कि पीड़िता के परिवार ने जांच को गुमराह करने के लिए मौत का असल कारण छुपाने की कोशिश की और मृत्यु का कारण लूट बताया। बयान के अनुसार आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि दिवंगत किशोरी को न्याय मिले। मेरठ के पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे को पत्र लिखकर अच्छी तरह से मामले को देखने और सभी अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और की गई कार्रवाई पर जल्द से जल्द आयोग को रिपोर्ट करने को कहा गया है।

दैनिक जागरण
अच्छा आचरण मनुष्य का शृंगार होता है

राह रोकने वाला धरना

नोएडा को दिल्ली से जोड़ने वाले रास्ते पर शाहीन बाग इलाके में दो माह से जारी धरने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह सही कहा कि विरोध प्रदर्शन करना लोगों का अधिकार है, लेकिन इस तरह किसी मार्ग को बाधित नहीं किया जा सकता। उसने यह सही सवाल उछाला कि अगर हर कोई इस तरह सड़कों पर उतर कर उन्हें बाधित करने लगेगा तो क्या होगा? निःसंदेह इससे अराजकता ही पैदा होगी और इसकी इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। हर अधिकार की अपनी सीमाएं होती हैं। कोई अधिकार असीमित नहीं हो सकता। विरोध, हड़ताल अथवा आंदोलन के अधिकार के नाम पर लोग सड़क अथवा रेल मार्ग बाधित नहीं कर सकते, लेकिन दुर्भाग्य से अपने देश में ऐसा ही अधिक होता है। यह और कुछ नहीं, आम लोगों को बंधक बनाने वाला कृत्य है। कई बार तो ऐसे कृत्यों के कारण लाखों लोगों की दिनचर्या प्रभावित होती है। शाहीन बाग धरना भी यही कर रहा है। इससे खराब बात और कोई नहीं कि सड़क पर कब्जा करके दिए जा रहे जिस धरने के कारण बीते दो महीने से दिल्ली-एनसीआर के लाखों लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है वह अभी भी समाप्त होता नहीं दिखता। सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग धरने को लेकर अपनी चिंता अवश्य जताई, लेकिन कोई नहीं जानता कि उसने उसे समाप्त करने की जरूरत क्यों नहीं महसूस की?

विरोध के नाम पर मनमानी का प्रदर्शन करने वाले धरने के प्रति नरमी दिखाना कानून के शासन के साथ-साथ शांतिप्रिय लोगों के अधिकारों की अनदेखी ही है। यह ठीक नहीं कि विरोध अथवा असहमति जताने के नाम पर मनमानी बढ़ती ही जा रही है। अब तो विरोध प्रदर्शनों के दौरान आगजनी, पत्थरबाजी और तोड़फोड़ आम है। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देश के विभिन्न हिस्सों में जिस तरह बड़े पैमाने पर आगजनी और तोड़फोड़ हुई उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। इस तरह की हरकतों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए, लेकिन यह देखने में आ रहा है कि इस तरह के मामलों में कई बार अदालतें भी नरम रवैया अपना लेती हैं। इससे कुल मिलाकर विरोध के बहाने अराजकता फैलाने वालों को ही बल मिलता है। इसमें संदेह है कि शाहीन बाग में धरने पर बैठे लोग अपना अड़ियल रवैया आसानी से छोड़ेंगे। पहले वे नागरिकता संशोधन कानून वापस लेने पर अड़े थे, फिर यह मांग करने लगे कि सरकार को उनसे बात करने धरना स्थल आना चाहिए। इसके बाद उन्होंने हजारों की संख्या में एकत्रित होकर गृहमंत्री से कथित तौर पर वार्ता करने की ठानी। आखिर यह कब समझा जाएगा कि यह धरना आम जनता के सब्र का इम्तिहान ले रहा है?

तस्करी पर लगाम जरूरी

जम्मू-कश्मीर में गोवंश की तस्करी के तीन मामले सामने आना चिंताजनक है। पुलिस ने जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सकेतर, नगरोटा और विजयपुर के बरोटिया इलाके में तस्करी के तीन बड़े प्रयासों को विफल कर 34 मवेशियों को तस्करों के चुंगल से मुक्त करा लिया। पुलिस ने पांच तस्करों को गिरफ्तार कर उनसे 6 वाहन जब्त किए है। इनमें एक स्कार्पियो यात्री वाहन भी है। तस्कर गोवंश की तस्करी में अब यात्री वाहनों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, जिससे कि वह आसानी से मवेशियों को कश्मीर घाटी पहुंचा सकें। विडंबना यह है कि गोवंश को एक जिले से दूसरे जिले में ले जाने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति की जरूरत होती है, लेकिन मवेशियों की तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही है। जम्मू-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुलिस के दर्जन से भी अधिक नाके हैं, फिर भी मवेशियों की तस्करी पुलिस प्रशासन पर कई सवाल खड़े करती है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि पुलिस की जांच-पड़ताल में कहीं न कहीं खामी जरूर है। इसे दूर करना होगा। नाको पर तैनात पुलिस कर्मियों को चाहिए कि वे वाहनों की अच्छी तरह जांच करने के बाद ही छोड़ें। यह दीगर बात है कि हरेक ट्रक या वाहन की जांच कठिन होती है, लेकिन इसमें सर्तकता बरती जाए तो ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचा जा सकता है। मवेशी तस्करों ने भी मवेशियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए नए हथकंडे अपनाए हुए हैं। जिससे कई बार तो पुलिस भी धोखा खा जाती है। तस्कर भी यात्री वाहनों की सीटें निकाल कर मवेशियों के हाथ पांव बांध कर उनकी तस्करी से बाज नहीं आ रहे हैं। कई बार तो एक-एक कर मवेशियों को पैदल एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, जिससे कि उन पर कोई शक नहीं हो। पुलिस प्रशासन को चाहिए कि तस्करों के इन हथकंडों पर विशेष ध्यान दे, क्योंकि लोगों का विश्वास पुलिस पर ही है। प्रशासन को भी चाहिए कि पुलिसकर्मियों के तबादला की नीति को पारदर्शी बनाए। गोवंश की तस्करी को लेकर जम्मू और उसके साथ लगते इलाकों में सांप्रदायिक माहौल के बिगड़ने की आशंका रहती है। बेहतर होगा कि जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर फुल बॉडी स्कैनर लगवाए जाएं। जिससे गोवंश की तस्करी के साथ आतंकवादियों को ट्रकों में चोरी छिपे घाटी पहुंचने पर रोक लग सके।

कश्मीर पर विषवमन का उपचार

विवेक काटजू

भारत ने तुर्की और मलेशिया के खिलाफ सही रुख अपनाया, लेकिन आखिर वह विदेशी राजनयिकों को जम्मू-कश्मीर क्यों ले जा रहा है?

मोदी सरकार ने बीते साल पांच अगस्त को जबसे जम्मू-कश्मीर में संवैधानिक परिवर्तन किए हैं तबसे कुछ लोग उसके खिलाफ लगातार विषवमन में जुटे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन भी उनमें से एक हैं। बीते शुक्रवार को एक बार फिर इसकी बानगी दिखी जब पाकिस्तानी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कश्मीर का राग अलापा। कश्मीरी अलगाववाद की तुलना प्रथम विश्व युद्ध में विदेशी प्रभुत्व के खिलाफ तुर्की की लड़ाई से करते हुए एर्दोगन ने पाकिस्तान को आश्वस्त किया कि कश्मीर तुर्की के लिए भी उतना ही संवेदनशील मसला है जितना पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाते हुए उन्होंने दोहराया कि भारत का कदम एकतरफा है जिसकी मार कश्मीरियों पर पड़ रही है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की उनकी कोशिशों को खारिज कर एकदम सही किया। साथ में यह उचित हिदायत भी दी कि तुर्की वास्तविक तथ्यों को लेकर अपनी समझ बढ़ाए और इस पर भी विचार करे कि पाकिस्तान कैसे भारत और इस समूचे क्षेत्र में आतंक को पाल-पोस रहा है।

दरअसल 1950 के दशक से ही इन दोनों देशों में गहरा दोस्ताना रहा है। इनके चलते तुर्की कश्मीर सहित तमाम मामलों पर पाक का हमदर्द बना रहा। 2016 में भी पाक दौरे पर एर्दोगन ने कहा था कि तुर्की कश्मीरियों के दुख-दर्द से भलीभांति परिचित है। बहरहाल ताजा संदर्भ में एर्दोगन ने जो तल्ख बयान दिया उसके पीछे इस्लामिक जगत का सिरमौर बनने की महत्वाकांक्षा ही है। वह तुर्की को उसी दौर में वापस ले जाना चाहते हैं जब ऑटोमन साम्राज्य के स्वर्णिम दौर में तुर्की के सुल्तान को खलीफा की पदवी हासिल थी। अब इस्लामिक उम्मा का नेतृत्व व्यापक रूप से सऊदी अरब के हाथ में है और कई अन्य अरब देश भी तुर्की से आगे निकल गए हैं। अरब देश और इस्लामिक उम्मा के तमाम मुल्कों ने पांच अगस्त के बाद पाकिस्तानी दुष्प्रचार को व्यापक रूप से नजरअंदाज ही किया, लेकिन तुर्की ने अलग राह पकड़ी। इससे भारत-तुर्की संबंधों में स्वाभाविक रूप से खटास आ गई। गत वर्ष सितंबर में संयुक्त राष्ट्र के मंच से एर्दोगन के भारत विरोधी भाषण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने प्रस्तावित तुर्की दौरे को रद कर दिया।

एर्दोगन के अलावा मलेशियाई प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने भी कश्मीर पर सरकार के कदमों की तल्ख शब्दों में आलोचना की थी। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि भारत ने कश्मीर में कब्जा कर लिया है। यह निहायत ही बेतुका बयान था। आखिर कोई देश अपनी ही जमीन पर कैसे कब्जा कर सकता है? इस पर मोदी सरकार ने अपनी नाखुशी जाहिर की। इसके जवाब में भारतीय व्यापारियों ने मलेशियाई पाम ऑयल के आयात से किनारा किया। इससे मलेशिया के आर्थिक हितों पर करारी चोट हुई। नतीजतन सहयोगियों के सुझाव पर महातिर को अपने तेवर नरम करने पड़े।

अवधेश राजपूत

तुर्की और मलेशिया के खिलाफ भारत ने एकदम सटीक तरीके से कूटनीतिक कार्रवाई की, लेकिन क्या यही बात सरकार की उस कवायद को लेकर कही जा सकती है जिसके तहत उसने राजनयिकों के दो समूहों को जम्मू-कश्मीर का दौरा कराया? इस सिलसिले में 15 सदस्यीय पहला समूह पिछले महीने वहां गया था। इसमें भारत में अमेरिका के राजदूत भी शामिल थे। इस कड़ी में दूसरा दौरा गत सप्ताह यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियों का हुआ। इन समूहों को वहां भेजने की मंशा स्पष्ट रूप से यही थी कि उनके माध्यम से कश्मीर को लेकर पाकिस्तानी दुष्प्रचार की हवा निकाली जाए। पाकिस्तान अभी भी इस बदजुबानी में जुटा है कि कश्मीर घाटी में मानवाधिकारों का उल्लंघन जारी है और तमाम शहरों में कर्फ्यू सरीखे हालात हैं। इन समूहों के जरिये छनकर आने वाली खबरों के मुताबिक राजनयिकों ने अपने दौरे में विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और कारोबारी वर्गों के प्रतिनिधियों से भी चर्चा की। प्रयास यह किया गया कि राजनयिकों की मुलाकात न केवल उन लोगों के साथ कराई जाए जो सरकारी कदमों का समर्थन करते हैं, बल्कि उनसे भी मिलाया जाए जो संचार सहित कुछ प्रतिबंधों के आलोचक हैं। इससे राजनयिकों को बड़ी हद तक वस्तुनिष्ठ समझ बनाने में मदद मिली होगी जिसे उन्होंने अपनी सरकारों के साथ अवश्य साझा किया होगा। फरवरी में गए समूह ने जम्मू का भी दौरा किया था। जम्मू के लोगों से विमर्श के बाद प्रतिनिधिमंडल को राज्य के जटिल हालात समझ आए होंगे।

कोई देश अमूमन राजनयिकों को अपनी अपनी आर्थिक संभावनाएं दिखाने के लिए ही विभिन्न स्थानों का दौरा कराता है। इसके पीछे आर्थिक सहयोग और पर्यटन को बढ़ावा देने जैसे मकसद होते हैं। राजनयिकों को राजनीतिक निहितार्थ वाले दौरे नहीं कराए जाते। इसकी सीधी वजह यही है कि यदि ऐसे दौरे कराए जाएं तो दूसरे देशों को आंतरिक मामलों पर टीका-टिप्पणी का मौका मिल जाता है। राजनयिकों के इन दोनों दौरों में यही हुआ। अपने राजदूत के दौरे के बाद अमेरिकी विदेश विभाग ने कश्मीरी नेताओं की नजरबंदी के अलावा राज्य में इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध को लेकर चिंता जताई। इसी तरह दूसरे समूह के दौरे के बाद कुछ राजनयिकों ने आशा व्यक्त की कि संचार संबंधी प्रतिबंध भी जल्द हटा लिए जाएंगे। ऐसे बयानों पर भारत का नाखुश होना स्वाभाविक ही है। हालांकि अंतरराष्ट्रीय मामलों में ऐसा कूटनीतिक विनिमय आम है, फिर भी सरकार यह नहीं कर सकती कि राजनयिकों को दौरा भी कराए और उनसे यह अपेक्षा भी रखे कि वे कोई टिप्पणी न करें।

अपनी नियुक्ति वाले देश के विभिन्न इलाकों के हालात की सूचनाओं के लिए राजनयिकों के अपने सूत्र भी होते हैं। वे ऐसे दौरों के बजाय अपने इन सूत्रों पर ज्यादा भरोसा करते हैं। खासतौर से जम्मू-कश्मीर जैसे मामलों में यह और ज्यादा होता है जहां ऐसे दौरों में सुरक्षा घेरे के चलते वे अपनी पसंद की जगह पर स्वतंत्र विचरण करने में सक्षम नहीं होते। कुल मिलाकर इस अनुभव से सीख लेते हुए सरकार को आकलन करना चाहिए कि जम्मू-कश्मीर में राजनयिकों के ऐसे दौरों की आखिर क्या उपयोगिता है? संतुलन की कवायद में नकारात्मकता सकारात्मकता पर हावी हो सकती है। ऐसे में बेहतर यही होगा कि राजनीतिक दौरों से बचने की जांची-परखी परंपरा का ही पालन किया जाए।

(लेखक विदेश मंत्रालय में सचिव रहे हैं)

response@jagran.com

दिल्ली मॉडल की चुनौतियां

विकास सारस्वत

दिल्ली की बेहतरी के लिए या तो राजस्व बढ़ाने के प्रयास करने होंगे या लोकलुभावन योजनाओं में कटौती

दिल्ली विधानसभा चुनावों के नतीजों को विश्लेषक अलग-अलग नजरिये से देख रहे हैं। एक वर्ग का कहना है कि भाजपा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण में असफल रही। जनादेश की यह व्याख्या तथ्यों का जितना सरलीकरण है उतनी ही सत्य से परे भी। अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को नागरिकता कानून पर बहस से दूर रखा और अपनी हिंदुवादी छवि गढ़ने का पूरा प्रयास किया। उन्होंने अपनी रैलियों में भारत माता की जय और वंदे मातरम् का उत्साहपूर्वक उद्घोष करवाया। स्पष्ट है कि दिल्ली चुनाव का नतीजा राष्ट्रवाद की जय-पराजय से हटकर क्षेत्रीय मुद्दों पर आधारित रहा। दिल्ली के नतीजों ने राजनीतिक दलों के लिए यह बड़ा संदेश दिया है कि मतदाता की अपेक्षाएं राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर भिन्न-भिन्न रहती हैं। यह मानना पड़ेगा कि दिल्ली में पानी की सप्लाई लाइनें नए क्षेत्रों में बिछाई गई हैं, भले ही पीने के पानी की गुणवत्ता चिंताजनक रही हो। इसी प्रकार नए स्कूल भले ही वादे के एक दहाई भी न खुले हों, परंतु चालू स्कूलों की स्थिति में निश्चित ही परिवर्तन आया है। दिल्ली में स्कूलों में दाखिले की बड़ी समस्या को देखते हुए स्कूलों की सुधरी स्थिति ने अभिभावकों को बड़ी राहत प्रदान की है। शिक्षा अधिकार कानून के कड़े क्रियान्वयन से निजी स्कूलों में दाखिले की सुगमता को भी दिल्ली सरकार की उपलब्धि के रूप में देखा गया, परंतु सिर्फ तीन-चार विभागों की सुधरी स्थिति और योजनाओं का सफल क्रियान्वयन चुनाव तो जिता सकते हैं, पर इतना बड़ा जनादेश नहीं दे सकते।

केजरीवाल की बड़ी जीत में मुफ्त योजनाओं की खास भूमिका रही। यह भी तथ्य है कि भाजपा अभियान में बहुत देर से और बिना मजबूत उम्मीदवार के उतरी। उसने सिर्फ और सिर्फ सीएए के विरोध और शाहीन बाग को मुद्दा बनाकर क्षेत्रीय चुनाव को राष्ट्रीय बनाने का प्रयास किया। इसमें पार्टी को आंशिक सफलता भी मिली और उसका मत प्रतिशत पिछले चुनाव के मुकाबले में थोड़ा बढ़ा, परंतु यह बढ़ा मत ठोस परिवर्तन लाने के लिए अपर्याप्त था। भाजपा ने दिल्ली के मतदाताओं की व्यावहारिक मानसिकता की अनदेखी की। दिल्ली वही राज्य है जिसने भीषण मुंबई हमले के चंद दिन बाद हुए विधानसभा चुनाव में भी अपनी तरजीह नहीं बदली थी। जहां आप दिल्ली को दिल्ली विधानसभा चुनाव की तरह लड़ रही थी वहीं भाजपा लोकसभा चुनाव मान कर।

दिल्लीवासियों के लिए कम प्राथमिकता वाली विषयवस्तु-सुरक्षा के सिवाय भाजपा के पास देने के लिए अधिक कुछ न था। भाजपा की हार पर यह भी मानना पड़ेगा कि समाजवाद के साथ विश्वसनीय नेतृत्व भारतीय राजनीति में आज भी लगभग अपराजेय मेल है। इसे हराना तब तक मुश्किल है जब तक कि नेतृत्व की विश्वसनीयता कमजोर न पड़े। देश और विदेश की राजनीति में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां लंबे समाजवादी शासन तब बमुश्किल खत्म हुए जब उन्होंने अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। एक कार्यकाल में बिजली, पानी और बस यात्रा में छूट देकर आप सरकार ने लोगों को यह भरोसा दिया है कि अन्य सरकारें महंगी दरों पर बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं देकर लोगों के साथ छलावा करती हैं, परंतु वास्तविकता थोड़ी भिन्न है और चिंताजनक भी। दिल्ली में पिछले पांच वर्षों में न तो एक नया कॉलेज खुला है और न ही दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने एक भी नई बस खरीदी है। निजी डिस्कॉम लगभग 3000 करोड़ रुपये के घाटे में हैं। पांच साल पहले मुनाफे में चल रहे जल बोर्ड की हालत भी पतली है। दिल्ली को सोलर सिटी बनाने के वादे सिर्फ कागजों तक सीमित हैं। शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र में सीमित प्रयासों को छोड़कर दिल्ली सरकार ने किसी भी आधारभूत परियोजना का एलान नहीं किया। एकीकृत परिवहन प्राधिकरण का खाका भी तैयार नहीं हुआ है। दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण का काम आचार संहिता लागू होने से मात्र दस दिन पहले शुरू हुआ। निम्न आय वर्ग के लिए आवासीय योजना पर काम भी अभी सिर्फ कागजों में है। 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' में दिल्ली 15 से 23वें स्थान पर आ गई है। इसलिए फिर से मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद केजरीवाल के सामने चुनौतियां भी वही हैं जो दो बार से उनकी जीत का कारण बनी हैं। उत्तर भारत की सबसे बड़ी व्यापार और आर्थिक मंडी होने के कारण दिल्ली इतना राजस्व तो पैदा करती है कि दो-चार क्षेत्रों में मुफ्त योजनाओं का लाभ दिया जा सके, परंतु नई योजनाओं और दिल्ली को एक भविष्योन्मुखी शहर बनाने के लिए या तो राजस्व बढ़ाने के गंभीर प्रयास करने पड़ेंगे या लोकलुभावन योजनाओं में कटौती। दिल्ली के लिए चिंता का विषय है कि उसका राजस्व अधिशेष आप के शासन काल में लगातार गिरता आया है। फिलहाल इस घाटे की भरपाई जीएसटी एक्ट के प्रावधान के तहत हो रही है, परंतु यह लाभ भी अगले दो वर्षों तक ही मिल सकेगा।

यह देखना दिलचस्प होगा कि अब केजरीवाल लोकलुभावन नीतियों और बढ़ती जनअपेक्षाओं में तालमेल कैसे बैठाते हैं? दिल्ली मॉडल को देखकर एक बड़े वर्ग ने मुफ्त बिजली, पानी, चिकित्सा, यातायात और यहां तक कि मुफ्त उच्च शिक्षा तक की मांग शुरू कर दी है। स्वयं केजरीवाल ने इसे राष्ट्रीय राजनीति में प्रमुख मुद्दा बनाने का एलान किया है। यह मॉडल, मोदी मॉडल से इस लिहाज से काफी अलग है कि पीएम मोदी ने कल्याणकारी योजनाओं को एक लक्षित वर्ग के सशक्तीकरण तक सीमित रखा है। मुफ्त सुविधाओं की बढ़ती अपेक्षाओं, बढ़ती आबादी और राजस्व वृद्धि की गिरती दर के बीच बुनियादी ढांचे के लिए जूझती दिल्ली को विश्वस्तरीय शहर बनाने के लिए केजरीवाल जो भी चमत्कार दिखाएंगे वही उनके राजनीतिक भविष्य की दिशा तय करेगा।

(लेखक इंडिक अकादमी से संबद्ध हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

मंत्रों का महत्व

हिंदू धर्म में जन्म से मृत्यु तक प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्य, उत्सव, पूजा-पाठ और हवन आदि मंत्रोच्चारण के बिना पूर्ण नहीं होते हैं। यह भी सच है कि आज के भागदौड़ भरे युग में यह संपूर्ण विधि-विधान मात्र औपचारिकता से ही हो चले हैं। ऐसे में अपनी व्यस्त दिनचर्या में से थोड़ा समय निकाल कर सच्चे हृदय से पूजा, अर्चना, मंत्रोच्चारण आदि के महत्व के बारे में जानने का प्रयास भी आवश्यक है। वेद-पुराणों का ज्ञान यह अवश्य बताता है कि मंत्र साधना सभी अन्य साधनाओं से उत्तम है। मंत्र विद्या रहस्यपूर्ण तो अवश्य है, फिर भी आंतरिक इच्छा से श्रद्धा एवं विधिपूर्वक की गई पूजा, अर्चना समय आने पर सुखद परिणाम अवश्य देती हैं। यूं ही नाम को श्रद्धारहित मंत्र जाप करने का कोई अर्थ नहीं। दुखद बात तो यह है कि मान्यताएं केवल धार्मिक गतिविधियों को संपन्न कराने तक ही सीमित हो चुकी हैं और तो और पूजा, अर्चना, मंत्र, हवन का भी व्यापार सा ही होने लगा है। लोग धर्म के ठेकेदारों के चंगुल में फंसते चले जाते हैं।

हमें मंत्रों के गूढ़ महत्व को जानना होगा। वास्तव में मंत्रों में तो ऐसी शक्तियां होती हैं जिनके सही उच्चारण एवं श्रवण से सकारात्मक तरंगों का उद्दीपन होने लगता है। मानस जाप के लिए कोई नियम का बंधन नहीं है, प्रत्येक स्थान, समय दोषमुक्त हैं। हम जाने-अनजाने इच्छापूर्ति हेतु या कष्ट में कितने ही मंत्रों का जाप मन ही मन करते रहते हैं, इसी आस में कि एक न एक दिन हमें दुखों से मुक्ति अवश्य प्राप्त होगी। हृदय में आस्था हो तो हम मंत्रों की तरंगों का अवश्य ही अनुभव कर पाएंगे जिससे आंतरिक शांति का संचार होगा एवं ऊर्जा में उत्तरोत्तर वृद्धि होना निश्चित है। मंत्रों के सार को जानना एक यात्रा है जो जीवन को लौकिक से पारलौकिक तत्व की ओर ले जाने में सक्षम है। मंत्रों के सही महत्व को समझे बिना उनकी मान्यता को निर्धारित करना अनुचित है।

छाया श्रीवास्तव

कुदरत की ओर मुखातिब होने का समय

हरीश बड़थ्वाल

योग, व्यायाम और सब्जियों-फलों के अधिकाधिक सेवन कैंसर रोगियों के लिए लाभकारी हो सकते हैं

विश्वस्तर पर कैंसर के इलाज एवं देखभाल पर 113 अरब डालर खर्च किए जाने के बावजूद इस भयावह बीमारी से सालाना 96 लाख (भारत में 30 लाख) मौतें हो रही हैं। यह राशि 2021 में 147 अरब डालर तक पहुंच जाएगी। कैंसर से पीड़ित 70 फीसद व्यक्ति रोग लगने के पांच साल में दम तोड़ देते हैं। सौ से अधिक कैंसरों में भारत में छाती, स्तन, सर्वाइकल (गरदन), ओरल (जबड़े) के मामले अधिक हैं। पिछले कुछ वर्षों से हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, केरल और मिजोरम में अधिक मामले देखे गए हैं। इसकी व्यापकता प्रति एक लाख जनसंख्या पर 106.6 है। अन्य देशों से तुलना करें तो उच्चतम दर ऑस्ट्रेलिया में है, 468 प्रति लाख आबादी। उसके बाद न्यूजीलैंड, आयरलैंड, डेनमार्क, हंगरी आदि हैं।

तेजी से बढ़ती इस भयावह बीमारी से बचे रहने के लिए आरंभिक लक्षण दिखने पर तुरंत जांच करानी चाहिए। पाचन क्रिया या मूत्रालय की कार्यप्रणाली में तब्दीली, न भरने वाला जख्म, छाती या अन्यत्र गांठ पैदा होना, निगलने में कठिनाई, वजन में गिरावट, थकान, तनाव, मल में खून, तिल या मस्से के आकार आदि में बदलाव, लगातार खांसी या खराश, त्वचा या स्तनों में बदलाव, अंडकोश में गांठ, महिलाओं की योनि से रक्तस्राव जैसी स्थितियों में डॉक्टरी परामर्श अनिवार्य है। रोग बढ़ जाने पर इसे काबू करना प्रायः दुष्कर होता है। इसीलिए कैंसर नियंत्रण कार्यनीति का दारोमदार जांच केंद्रों के व्यापकीकरण और सुदृढ़ीकरण पर होना चाहिए।

शरीर के जिन अंगों-प्रत्यंगों से निरंतर कार्य न लिया जाए उनमें रक्तप्रवाह और हरकत क्षीण होते-होते खत्म हो जाते हैं और वे मृतप्रायः हो जाते हैं। शरीर के ये अंदुरूनी स्थल कैंसर की कोशिकाओं को पनपने का अनुकूल वातावरण प्रदान करते हैं। इसीलिए स्वस्थ रहने के लिए शारीरिक व्यायाम पर जोर दिया जाता है। शारीरिक सक्रियता से भले ही आपके वजन में गिरावट न आए, किंतु यह आप में कैंसर, दिल की बीमारियों, स्ट्रोक और गठिया का जोखिम घट जाएगा। कैंसर के इलाज में रासायनिक दवाओं के खामियाजे और सीमित, अल्पकालिक लाभ का सत्य विशेषज्ञों सहित अनेक स्वास्थ्यकर्मी स्वीकारने लगे हैं। उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्रों में इलाज के लिए दवाओं के एवज में या इनके साथ व्यायाम, योग, प्राकृतिक जड़ी बूटियों और सब्जियों-फलों का समावेश आरंभ किया है।

वहीं कैंसरग्रस्त व्यक्ति से दूर हो जाना अमानवीय कृत्य है, ऐसे वक्त में उसे नैतिक संबल की अधिक जरूरत रहती है। मनुष्य का आत्मिक बल उसे किसी भी विषम परिस्थिति से उबार सकता है। उसे अलग-थलग छोड़ने के बजाय उससे आपसी एवं अन्य सरोकार साझा करें, उसे डॉक्टर के पास लाने-ले जाने में, कभी-कभार भोजन खिलाने में मदद करें।

(लेखक स्वास्थ्य विषयों के जानकार हैं)

मेलबाक्स

गांधी जी की इच्छा पर कुर्बान पटेल

हृदयनारायण दीक्षित का तर्कपूर्ण आलेख 'महापुरुषों के मूल्यांकन की कसौटी' पढ़ा। फ्रेंच पत्रकारों लेरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपिअर की पुस्तक 'फ्रीडम एट मिडनाइट' में भी उल्लेख है कि 14 अगस्त, 1947 की शाम को जब भावी प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अपने मंत्रिमंडल की सूची गवर्नर जनरल लार्ड माउंटबेटन को देने गए तो उन्हें खाली लिफाफा पकड़ा कर आ गए थे। लेखक ने यह ठीक ही लिखा है कि सरदार पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और बाबा साहब आंबेडकर को मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए गांधी जी का नेहरू पर बहुत भारी दबाव था। आंबेडकर के स्थान पर नेहरू एक अंग्रेज विधिवेत्ता इवोर जेंनिंग को लेने का मन बना चुके थे। तब गांधी जी ने उनसे कहा था कि दुनिया क्या कहेगी, अंग्रेजों से आजादी हासिल करने के बाद भी भारत को अपना संविधान बनाने के लिए एक अंग्रेज ही मिला! पटेल के संबंध नेहरू से कितने तनावपूर्ण रहते थे, यह पटेल की पुत्री मणिबेन पटेल की डायरी से स्पष्ट होता है। नौ अक्टूबर, 1948 को खुद नेहरू, निजलिंगप्पा और अन्य नेताओं की उपस्थिति में दिल्ली में पटेल ने कहा था कि यदि उन्होंने गांधी जी को वचन न दिया होता तो वे नेहरू को पार्टी एवं सरकार से बाहर का रास्ता दिखा देते। साफ है भले ही नेहरू प्रधानमंत्री थे, पार्टी में पटेल की ही चलती थी। इसीलिए 1949 में नेहरू के उम्मीदवार जेबी कृपलानी को हराकर पुरुषोत्तमदास टंडन को उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष निर्वाचित करवाया था। इसके बाद रफी अहमद किदवई ने नेहरू से कहा था कि हम लोग कांग्रेस छोडकर सोशलिस्ट पार्टी में चले जाएं, क्योंकि पटेल के रहते हमारा गुजारा यहां नहीं हो सकेगा। वास्तव में पटेल की शीघ्र मृत्यु के कारण ही नेहरू कांग्रेस में बने रह सके, वर्ना पार्टी में पटेल के वर्चस्व के चलते उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का अपना मन लगभग बना ही लिया था। आज ये बातें अकल्पनीय लगती हैं, किंतु पटेल कांग्रेस के राजा थे, मुकुट-विहीन राजा, ये बात याद रखने वालों के लिए ये विवरण आश्चर्य-कारक नहीं हैं। उन दिनों गांधी जी के सबसे निकट के अनुयायी जीडी बिरला भी नेहरू के स्थान पर पटेल का ही साथ देते थे। मैं लेखक के इस विचार से सहमत हूं कि रामचंद्र गुहा को नारायणी दास की पुस्तक पर उतनी तीखी प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए थी, जितनी उन्होंने दी है। महापुरुषों का आकलन एक सतत प्रक्रिया है। नए तथ्य आएंगे और आकलन भिन्न होता जाएगा।

अजय मित्तल, मेरठ

महापुरुषों का सम्मान हो

देश में महापुरुषों को लेकर जो मान अपमान वाली टीका टिप्पणी होती है, वह शायद ही किसी देश में होती होगी। यह बहुत ही पीड़ादायक बात है। जिस प्रकार प्रकृति द्वारा प्रदत्त रंगों को किसी भी वर्ण, जाति, धर्म, दलों में नहीं बांटा जा सकता, इसी प्रकार देश के महापुरुषों को भी किसी दल या वर्ग में नहीं बांटा जा सकता है। उन्होंने सब के कल्याण व हित के लिए ही अपना रचनात्मक योगदान दिया व समर्पण किया है। ये सभी महापुरुष सभी के लिए समान रूप से पूज्य हैं। केवल राजनीतिक चश्मे से महापुरुषों को देखना व बांटना किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं है।

hemahariupadhyay@gmail.com

शहादत पर गर्व

पिछले साल जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में सेना के कई जवान शहीद हो गए थे। देश को जान कुर्बान करने वाले बहादुर जवानों पर गर्व है, लेकिन कुछ नेता ऐसे अवसर पर भी राजनीति से बाज नहीं आते। राहुल गांधी का यह ट्वीट कि पुलवामा हमले से सबसे ज्यादा फायदा किसे मिला, बेहद ही शर्मनाक है। वह भूल गए कि पुलवामा हमले के बाद हमारी वायु सेना के बहादुर जवानों ने पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी ठिकानों को तहस-नहस कर पाकिस्तान को उसकी औकात बता दी थी। देश की रक्षा में जवानों की कुर्बानी सदा वंदनीय है। नेताओं को यह सोचना चाहिए कि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जवानों की शहादत पर राजनीति शहादत का अपमान है।

रणजीत वर्मा, फरीदाबाद

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

1988 में अमेरिकी प्रशासन ने 'ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट' शुरू किया था। मानव आनुवंशिकी और जीनोम विश्लेषण पर दुनिया की इस सबसे बड़ी परियोजना को 2003 में पूरा किया गया।

डॉ. दर्शनी प्रिय
स्वतंत्र टिप्पणीकार

आजकल

तनाव दूर करने में भी सहायक हो पाठ्यक्रम

आमतौर पर बोर्ड परीक्षा शुरू होने से पहले बड़ी संख्या में छात्रों में अनेक कारणों से तनाव बढ़ जाता है। अभिभावक भी कई बार पसोपेश में रहते हैं। कई बार छात्र गलत कदम भी उठा लेते हैं। इसका एक बड़ा कारण परीक्षा में आने वाले अंकों और भविष्य में करियर को लेकर होता है। ऐसे में हैपिनेस पाठ्यक्रम के जरिये छात्रों में तनाव को कम किया जा सकता है। इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि छात्रों को उनके स्वाभाविक रूप में रहने दिया जाए और उम्र के हिसाब से मानसिक बोझ को अधिक नहीं बढ़ाया जाए

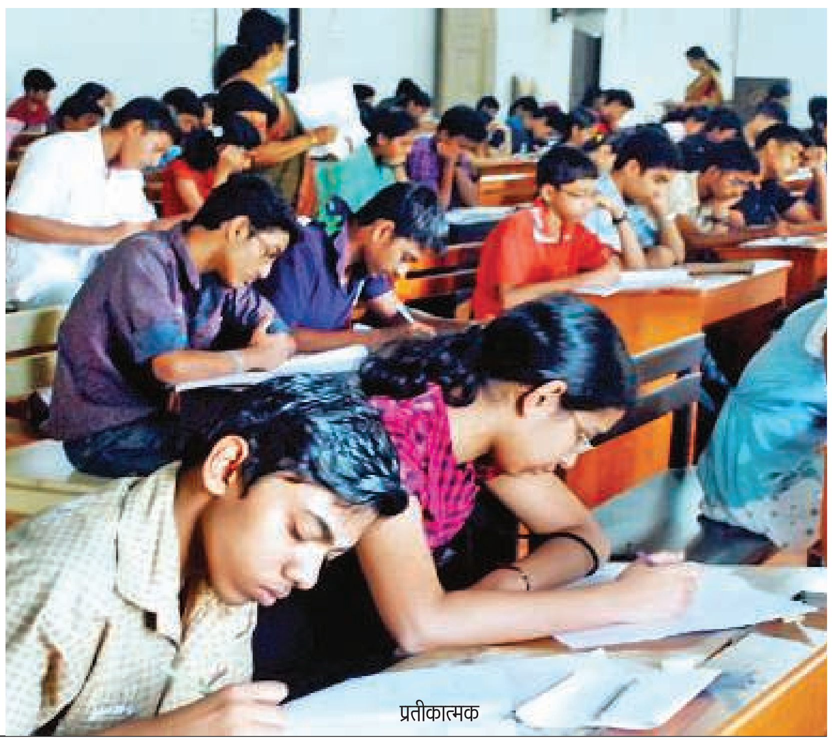

प्रतीकात्मक

दसवीं और बारहवीं के इम्तिहान शुरू हो चुके हैं। ऐसे में छात्रों पर परीक्षा का भय तारी है। कड़ी प्रतिस्पर्धा के साथ सबसे आगे निकलने की होड़ ने छात्रों को असमय ही थकान और उब से भर दिया है। गला-काट प्रतिस्पर्धा ने परीक्षाओं का मिजाज बदला है। आत्मविश्वास हिला देने वाली परीक्षाओं की प्रकृति ने दबाव का वातावरण तैयार किया है जिसके परिणामस्वरूप छात्रों में हताशा और निराशा से खुदकुशी जैसी घटनाओं में इजाफा हुआ है। हालिया आंकड़ों से पता चलता है कि परीक्षाओं में असफलता से उपजे ग्लानि और अपराध-बोध के भाव के चलते हजारों छात्रों ने आत्महत्या की है। बढ़ते परीक्षा संबंधी दबाव ने कई जिंदगियों को लील लिया है। दरअसल जिस तरह कोचिंग संस्थानों द्वारा परीक्षाओं को लेकर परीक्षा का हौवा पैदा किया जाता है, वह विशुद्ध व्यावसायिकता को ही दर्शाता है, वहीं अभिभावक भी इसे लेकर अतिव्यग्रता दिखाने से नहीं चूकते। खेलने-कूदने और आनंद से भरपूर जीवन जीने की उम्र में आज बच्चे परीक्षाओं का बोझ लिए अवसाद को गले लगा रहे हैं। निस्संदेह यह स्थिति चिंतनीय है।

एक अनुमान के अनुसार भारत की लगभग 4.5 प्रतिशत आबादी इस समय अवसाद के उच्चतम स्तर यानी 'एक्यूट डिप्रेशन' से जूझ रही है। 13 से 15 साल की उम्र के एक-चौथाई किशोर अवसाद से पीड़ित हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण-पूर्व एशिया के करीब 8.6 करोड़ लोग इस बीमारी की चपेट में हैं। दस दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में सर्वाधिक आत्महत्या दर भारत में है। इसमें 'दक्षिण-पूर्व एशिया में किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य स्थिति' संबंधी रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारत में 15 से 29 वर्ष की उम्र वर्ग के प्रति एक लाख व्यक्ति पर अवसाद संबंधी आत्महत्यों की दर 35.5 है। परीक्षाओं और अन्य कारणों से उपजे अवसाद संबंधी ये आंकड़े स्थिति की भयावहता की ओर इशारा करते हैं।

हैपिनेस कैरिकुलम : ऐसे में हैपिनेस कैरिकुलम या खुशहाली पाठ्यक्रम की आवश्यकता बढ़ जाती है। अपनी खूबियों के चलते यह आजकल विमर्श के केंद्र में है। 'हैप्पीनेस' या खुशी एक मानसिक स्थिति है जिसे किसी भी कार्यक्षेत्र में बेहतर कार्य प्रदर्शन का पैमाना माना जाता है। एक प्रसन्न व्यक्ति ना केवल अपने परिवार या समाज के लिए अपितु राष्ट्र के विकास के लिए भी उत्पादक माना जाता है। दरअसल खुशहाली पाठ्यक्रम के तहत युवाओं को आभासी दुनिया से बाहर निकल कर वास्तविक दुनिया में घुलने-मिलने, शिक्षक और दोस्तों के साथ अपनी भावनाओं को साझा करने और व्यवहार में सकारात्मक प्रवृत्ति विकसित करने का अवसर दिया जाता है। इसमें समग्र चिंतन, योग, ध्यान, मनोरंजन आधारित गतिविधियों सहित व्यावहारिक कुशलता पर भी खासा ध्यान दिया जाता है। खुशनुमा माहौल, दोस्तों और सहयोगियों का सहयोगात्मक रवैया और सकारात्मक सोच व्यक्ति को अवसाद के क्षणों से निकालने के कुछ कारगर कदम माने जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षिक फ्रेमवर्क में सभी स्कूलों में हैप्पीनेस कैरिकुलम को समवेत रूप से स्वीकारने संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

परंपरागत शिक्षा से उलट निजी स्कूलों की शिक्षा अपने भारी-भरकम पाठ्यक्रम और मोटे किताबों से छात्रों के नाजुक मन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। पाठ्यक्रम के बोझ से उनका बचपन असमय कहीं खो सा गया है। एकरस और उबाऊ शिक्षा पद्धति के प्रभाव में उनकी स्वाभाविक मनोदशा गायब हो रही है। बचपन स्कूली परिक्षाओं, परियोजनाओं और कक्षा कार्यों की भारी-भरकम बोझ की मार झेल रहा है। शिक्षकों और अभिभावकों का प्रतिस्पर्धात्मक दबाव छात्रों से उनका सहज बचपन छीन रहा है। खेल-कूद और अन्य रचनात्मक गतिविधियों के समय को भारी सिलेबस की खानापूर्ति के नाम पर सिमेटा जा रहा है।

अव्यावहारिक सिलेबस ने छात्रों के आस-पास अवसाद, चिड़चिड़ेपन और तनाव का एक ऐसा संजाल खड़ा कर दिया है जो अभेद्य किले के रूप में तब्दील हो चुका है। तनाव के इस किले में सेंध लगाने की आवश्यकता है। जाहिर है हैप्पीनेस कैरिकुलम एक शस्त्र की तरह काम करेगा जो अवसाद और तनाव के मजबूत किले को भेदकर एक उज्ज्वल भविष्य की नींव तैयार करेगा।

सकारात्मक परिणाम : देश के जिन राज्यों ने इसे स्कूली पाठ्यक्रम में तरजीह दी है वहां से सकारात्मक नतीजे सामने आ रहे हैं। अभिभावक खुलकर इस बात को स्वीकारने लगे हैं कि खुशी पाठ्यक्रम के चलते उनके बच्चों में बदलाव आ रहे हैं। छात्रों पर शिक्षकों और अभिभावकों, दोनों ओर से बढ़ते अंकों के दबाव से निपटने में यह पाठ्यक्रम एक महती भूमिका अदा कर सकता है। स्पष्ट है कि छात्र इसके जरिये ये सीख पाएंगे कि जीवन सिर्फ अंकों की दौड़ नहीं, बल्कि अनुभवों से सीखने की एक निमित्त कला है। एक अवसाद मुक्त पीढ़ी तैयार करने की दिशा में शिक्षा के बुनियादी स्तरों पर प्रसन्नता पाठ्यक्रम को लागू करना ही होगा जिससे छात्रों में खुश रहने की प्रवृत्ति आसानी से जड़ जमा सके।

वर्तमान परिस्थितियों में बढ़ते तनाव, हताशा, कुंठा और आक्रामकता ने स्कूलों में हैप्पीनेस पाठ्यक्रम को समवेत रूप से स्वीकारने पर बल दिया है। जीवन में आनेवाली चुनौतियों से लड़ने में सक्षम यह टूल न केवल संकटग्रस्त परिस्थितियों से उबारने में सहायक होगी, अपितु मानसिक स्वास्थ्य के लिहाज से भी नौनिहालों के हक में होगी। मानसिक और शारीरिक गतिविधियों पर आधारित यह पाठ्यक्रम समग्र चिंतन परंपरा और ध्यान शैली पर केंद्रित है जिसके जरिये बच्चे एक सुनहरे कल और समुन्नत भविष्य की ओर कदम बढ़ा सकेंगे, क्योंकि खुशहाली में ही खिलखिलाता बचपन छिपा है जो एक खुशनुमा राष्ट्र की मजबूत आधारशिला बन सकता है।

मिड डे मील योजना में हो सुधार

शिवांशु राय

मिड डे मील योजना में पिछले दिनों कई जगहों पर अनियमितताएं या घटनाएं सामने आई हैं। इन घटनाओं को देखते हुए यह पूरी योजना, उसके कार्यान्वयन, निगरानी और व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है कि आखिर बच्चों के भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ हो रहा है? इस योजना को बेहतर ढंग से क्रियान्वित करने और इसके लिए जरूरी उपक्रमों के विकास के लिए सरकार बजट में रकम क्यों नहीं बढ़ा रही है?

मिड-डे-मील जैसी स्कीम चलाने का तीन सीधा उद्देश्य है जिसमें यह योजना प्रभावी रूप से खरी उतरी है। पहला सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब परिवार के बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना जिससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास हो सके। आज भी देश में कई ऐसे गरीब परिवार हैं जो दो वक्त की रोटी बमुश्किल जुटा पाते हैं और इनके बच्चे भूखे पेट स्कूल आते हैं। ऐसे में सरकार इस स्कीम के माध्यम से उनके बच्चों को लाभान्वित कर चहुमुखी शारीरिक विकास के लिए प्रेरित करती है। अब सवाल उठता है कि व्यापक सुधारवादी उद्देश्य के साथ शुरू की गई इस योजना में आखिर कहां पर चूक हो रही है जिससे तमाम विसंगतियां देखने को मिल रही हैं?

इस योजना में भोजन निर्माण का कार्य मुख्यतः ग्राम पंचायतों या वार्ड सभासदों की देखरेख में किया जाता है। भोजन को अध्यापक अपनी देखरेख में विद्यालय परिसर में बने किचन शेड में तैयार करवाते हैं। भोजन से संबंधित अन्य सामग्रियों की व्यवस्था ग्राम प्रधान आदि करते हैं। गोदाम से स्कूलों में खाद्यान्न पहुंचने तक बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार होता है। इस वजह से खाने की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट में भी ये सामने आया है कि कम से कम नौ राज्यों के मामलों में तय पोषण नहीं पाया गया।

इस योजना में बुनियादी सुविधाओं का बड़े स्तर पर अभाव है। सैकड़ों बच्चों को भोजन बनाने के लिए साफ-सुथरी किचन और बर्तन तथा उपकरणों का अभाव पाया जाता है। अनेक स्कूलों में भोजन टिन शेड में बनते हैं जिसमें साफ-सफाई का अभाव है। साफ-सफाई, देखभाल और सावधानी की समुचित व्यवस्था न होने से अनेक बार विषाक्त भोजन बनने और उससे बच्चों के बीमार पड़ने की घटनाएं सामने आती हैं।

गुणवत्तापूर्ण भोजन और बुनियादी सुविधाओं के अभाव में मुख्य रूप से इस योजना की कमी आवश्यक मात्रा में रकम का उपलब्ध न होना और जारी की गई रकम में भी भ्रष्टाचार का व्याप्त होना है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी आकड़ों के मुताबिक प्राइमरी स्तर के प्रति छात्रों के खाना तैयार करने का खर्च अब 4.48 रुपये, उच्च प्राइमरी स्तर के प्रति छात्र पर खाना बनाने का खर्च 6.71 रुपये है। इतनी रकम में एक छात्र को गुणवत्तापूर्ण और पौष्टिक आहार दे पाने की उम्मीद करना बेकार है।

सबसे बड़ी कमी इस योजना में निगरानी तंत्र की है। वर्तमान में कार्यक्रम की निगरानी के लिए केंद्र की निगरानी में राज्य-स्तर पर दिशा-नियंत्रक- सह-निरीक्षण समितियों का गठन किया गया है जो इसके निगरानी तंत्र में मंडल, जिले, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर इस योजना के क्रियान्वयन और निरीक्षण का कार्य विभिन्न अधिकारियों द्वारा करवाते हैं, परंतु निगरानी तंत्र अपनी दायित्वों को भली-भांति नहीं पूरा करते। अनेक जगहों पर यह देखने को मिला है कि विद्यार्थियों की कम उपस्थिति संख्या होने के बावजूद रजिस्टर में अधिक एंट्री होती है।

शहरों में हालत ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले काफी बेहतर है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में जांच, निगरानी और क्रियान्वयन बेहतर तरीके से नहीं हो पाता। इस योजना में सर्वाधिक नाकाम राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड हैं तो वहीं अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, असम और कर्नाटक आदि राज्यों ने अच्छा प्रदर्शन किया है।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

खरी-खरी

एक 'इंडियन' का 'भारत' भ्रमण

कुमार सुरेश

इधर मैं और मेरे जैसे कुछ और जेंटलमैन 'इंडिया' में रहने लगे हैं। हमारे कुछ रिश्तेदार 'भारत' में छूट गए हैं। कभी-कभार 'भारत' जाना पड़ता है। मेरे एक दोस्त को एक शादी में इंडिया से भारत जाना पड़ा। दोस्त की ससुराल में उसके लिए अलग कमरे की व्यवस्था की गई थी।

सुबह मेरा दोस्त अंग्रेजी अखबार लेकर अफसरी रौब के साथ टॉयलेट में घुसा। वहां देसी व्यवस्था थी। वो बैठ तो गया पर थोड़ी देर बाद पैर सुन्न हो गए। दोस्त अंग्रेजी में डांटने लगा। बाहर लोग इकट्ठा होकर 'क्या हुआ-क्या हुआ' पूछने लगे। टॉयलेट के दरवाजे के इस पार हिंदी और उस पार अंग्रेजी की जुगलबंदी होने लगी। स्थिति तनावपूर्ण किंतु नियंत्रण में आ जाने पर दोस्त उठा। यूं वह 'अंटशंट' खाने का आदी था, किंतु आज उसने खाने को लेकर ही 'अनशन' कर दिया। शाम तक उसे ऐसे होटल में पहुंचा दिया गया, जहां निस्तारण, अखबारी अध्ययन, चिंतन, एक साथ करने की उत्तम व्यवस्था थी।

कुछ दिन बाद मेरी ससुराल से एक शादी का बुलावा आया। मैंने अपने लिए एडवांस में एक होटल में कमरा बुक करा लिया। होटल में तैयार हो जब ससुराल पहुंचे तो सास ने खाने का आग्रह किया। शादी के एक दिन पहले भारतीय देसी खाना यानी कढ़ी-चावल आदि बनाया गया था। खिलाने की व्यवस्था भी जमीन पर बैठाकर देसी ढंग से की गई थी। अफसर कभी जमीन पर बैठता नहीं, लेकिन पत्नी का तमतमाया मुंह देख मैं किसी तरह पैर मोड़ कर नीचे बैठ गया। खाते वक्त ग्रास मुंह में रखने के लिए मुझसे झुकते नहीं बन रहा था। कुछ खाना कपड़ों और कुछ नीचे जमीन पर गिरा। पीठ अकड़ने लगी। मेरी खराब दशा को लोगों ने भांप लिया था। होटल लौटते वक्त मैंने साले साहब को कानाफूसी करते सुना- 'ये हाल है इनका, आदमी देसी हैं, पर व्यवस्था चाहिए विदेशी।' सामने वाले ने भी कुछ कहा, जिसमें से 'कौआ', 'हंस' और 'चाल' शब्द ही मुझे साफ सुनाई दिए।

जो लोग भी 'भारत' छोड़ 'इंडिया' में बस गए हैं, उनके साथ ये होता है। मटका, एयर कंडीशनर-पसीना, गीजर-ठंडा पानी के बीच भारत और इंडिया का ये द्वंद्व चलता रहता है।

ट्वीट-ट्वीट

सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद अब महिला अफसरों को भी पुरुषों की तरह 14 साल की सेवा के बाद परमानेंट कमीशन मिलेगा। एक वकील के तौर पर इस मामले को अंजाम तक पहुंचाकर देश की बहादुर बेटियों को सेना में बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए मीनाक्षी लेखी जी का भी शुक्रिया।

समीर अब्बास@TheSamirAbbas

कोरोना वायरस ने चीन में बड़ी तबाही मचा रखी है। चीन की बड़ी आबादी इसकी चपेट में आ चुकी है। ऐसे में अगर इस कोरोना वायरस पर समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो यह चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के पराभव की जमीन तैयार कर देगा।

प्रकाश सिंह@singh_prakash

उम्मीद है कि दिल्ली की अदालत द्वारा डेथ वारंट जारी होने के बाद निर्भया के दोषियों को तीन मार्च को फांसी पर चढ़ा ही दिया जाएगा। निर्भया के परिवार ने न्याय पाने के लिए आखिर बहुत संघर्ष किया है।

अभिषेक सिंघवी@DrAMSinghvi

यह बड़ी शानदार खबर है कि भारत ऑस्ट्रेलिया के अपने अगले दौरे पर वहां पहली बार डे-नाइट टेस्ट मैच खेलेगा। भारत के नजरिये से बेहतर होगा कि पर्थ के बजाय उसे एडिलेड में यह अवसर मिले।

आकाश चोपड़ा@cricketaakash

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या दूरसंचार कंपनियों को मौजूदा संकट से उबारने के लिए सरकार को तात्कालिक राहत पैकेज जारी करना चाहिए?

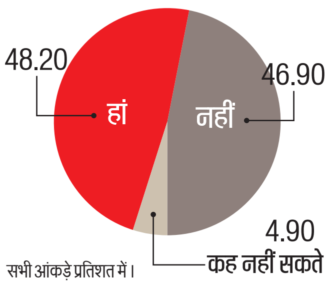

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या आम आदमी पार्टी के उभार से अन्य भाजपा विरोधी दलों के लिए चुनौती बढ़ गई है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

सेना पाकिस्तान की दिखा गई करतूत,
सरक गया बिल में कहीं मजहर मियां मसूद।
अजहर मियां मसूद फंसे इमरान बिचारे,
जाएंगे बेभाव बंधु पेरिस में मारे।
एफएटीएफ जाय पड़ेगा उत्तर देना,
आतंकी भगवाय फंसा बैठी है सेना।

– ओमप्रकाश तिवारी

अनुराग अग्रवाल
स्टेट ब्यूरो चीफ, हरियाणा

हरियाणा डायरी

आचार्य देवव्रत और हरियाणा की सेहत

सुबह का भूला यदि शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। हरियाणा सरकार के बारे में फिलहाल तो यही कहा जा सकता है। हरियाणा में पहली बार जीरो बजट प्राकृतिक खेती की बात होने लगी है। ऐसी प्राकृतिक खेती, जिसका खाना खाने से न तो लोग बीमार होंगे और न ही कैंसर सरीखे रोग से पीड़ित होंगे। राज्य में यदि सरकार और लोग रासायनिक खादों से मुक्त प्राकृतिक खेती की अवधारणा पर सोचने लगे हैं तो इसका श्रेय गुरुकुल कुरुक्षेत्र के आचार्य देवव्रत को जाता है, जो अब गुजरात के राज्यपाल हैं।

उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और पंजाब से सटा हरियाणा ऐसा राज्य है, जहां हर साल औसतन पांच हजार लोग कैंसर से अपनी जान गंवा रहे हैं। पांच प्रतिशत लोगों को कैंसर है। हालांकि यह आंकड़ा बहुत अधिक नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय अनुपात के लिहाज से छोटे से राज्य के लिए काफी बड़ा आंकड़ा है। महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर तेजी के साथ बढ़ रहा है। इसकी एक बड़ी वजह साफ सुथरे और पौष्टिक आहार का अभाव तथा समुचित जागरुकता व उसके बाद इलाज की कमी को माना जा सकता है।

गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ऐसी शख्सियत हैं, जिन्होंने हरियाणा के लोगों के दिलो-दिमाग में प्राकृतिक खेती से पैदा होने वाली वस्तुओं के सेवन का बीज बो दिया है। अब अगला काम सरकार का है। आचार्य का खुद का गुरुकुल कुरुक्षेत्र में करीब 250 एकड़ का जैविक खेती का फार्म हाउस है, जिसे देश-दुनिया की कई बड़ी हस्तियां देखने के लिए वहां जा चुके हैं। विश्वविद्यालयों के कुलपति और प्रोफेसर से लेकर लोकसभा और राज्यसभा के अनेक सदस्य तथा कई कृषि वैज्ञानिक गुरुकुल की प्राकृतिक खेती के फार्मूले के मुरीद हो चुके हैं।

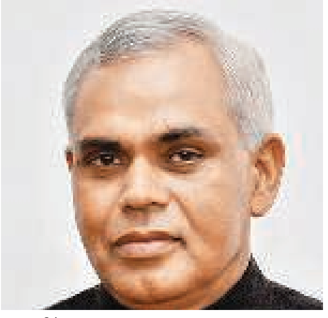

आचार्य देवव्रत। फाइल

आचार्य देवव्रत की सबसे बड़ी सफलता यही है कि अब हरियाणा सरकार भी उनके कम लागत वाले प्राकृतिक खेती के फार्मूले को आत्मसात करने को तैयार हो गई है। राज्य के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल जहां गाय के गोबर, मूत्र, नीम के पत्ते और मिट्टी से देसी खाद बनाने के फार्मूले से प्रभावित हो चुके हैं, वहीं जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने राज्य भर की खाली पड़ी जमीनों पर कैदियों से जैविक खाद के जरिये हानिकारक रसायनों से मुक्त फसलों की बुवाई का खाका तैयार किया है। राज्य सरकार अपने प्रदेश में जैविक खेती के लिए एक अलग विभाग तक बनाने को तैयार हो चुकी है।

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद आचार्य देवव्रत के इस मिशन से इत्तेफाक रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में आचार्य के इस फार्मूले को न केवल प्रोत्साहित कर चुके हैं, बल्कि केंद्रीय बजट में भी आचार्य के जीरो बजट खेती फार्मूले को समाहित किया जा चुका है। अब हरियाणा सरकार चाहती है कि आचार्य के इस खेती फार्मूले को पूरे राज्य में लागू किया जाए।

इस फार्मूले को समझने के लिए पूरी राज्य सरकार यानी मुख्यमंत्री, उनकी कैबिनेट के सभी मंत्री, भाजपा के विधायक, कांग्रेस व इनेलो के साथ निर्दलीय विधायक 14 मार्च को गुरुकुल पहुंच रहे हैं। सांसदों का एक दल पहले ही आचार्य देवव्रत के कुरुक्षेत्र आश्रम स्थित कृषि फार्म का दौरा कर चुका है। विधायकों के साथ-साथ जिला परिषद सदस्य, ब्लाक समितियों के चेयरमैन और सरपंच भी यदि जहर रहित इस खेती के फार्मूले को समझते हुए स्वस्थ, सुंदर और सुशिक्षित हरियाणा की ओर कदम बढ़ाएंगे तो वह दिन दूर नहीं, जब जहर बेचने वाली कंपनियों की दुकानों पर ताले लग जाएंगे और स्वदेशी व्यवस्था से गायों की कद्र करते हुए स्वास्थ्य तथा विकास के ऐसे द्वार खुलेंगे, जिसकी बरसों से दरकार थी। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि अब वह दिन दूर नहीं, जब प्रदेश के किसान रासायनिक खाद छोड़कर खुद की तैयार की गई प्राकृतिक खाद के जरिये फसलों की पैदावार लेने की ओर मुड़ने वाले हैं।

हारे हुए मंत्रियों के साथ प्री-बजट चर्चा नहीं : वित्त मंत्री के नाते हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बार पहली दफा बजट पेश करने वाले हैं। 20 फरवरी से आरंभ होने वाले बजट सत्र में 28 फरवरी को बजट की पोटली खुलने की संभावना है। मुख्यमंत्री लोगों से बजट पर राय ले रहे हैं। पहले सांसदों से राय ली गई। फिर 19 फरवरी तक विधायकों के साथ प्री-बजट मंथन किया गया। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा सरकार के आठ मंत्री चुनाव हार गए थे और दो मंत्रियों के टिकट कट गए थे। चुनाव में हारे इन मंत्रियों के दिल में टीस छिपी है कि आखिर मुख्यमंत्री हमसे भी तो बजट के बारे में कोई राय ले सकते थे। बहरहाल अभी समय है। यदि मुख्यमंत्री ने इन पराजित मंत्रियों को बातचीत के लिए बुला लिया तो ठीक, अन्यथा कहने के लिए उनके पास यह तो हो जाएगा कि हमारी अनदेखी की जा रही है।

तकनीक

प्रदीप
विज्ञान विषय के जानकार

जीनोम मैपिंग से स्वास्थ्य रक्षा

देशकाल की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जीनोम मैपिंग योजना देश की स्वास्थ्य रक्षा के लिए बेहद जरूरी कदम है। इससे तमाम बीमारियों के इलाज में सुविधा होगी

प्रतीकात्मक

हाल ही में विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय ने एक परियोजना के तहत जैव-प्रौद्योगिकी विभाग को भारत के बीस हजार लोगों के जीनोम की सिक्वेंसिंग यानी अनुक्रमण किए जाने की योजना को मंजूरी दी है। यह पहला मौका होगा जब भारत में इतने बड़े स्तर पर जीनोम के गहन अध्ययन के लिए खून के नमूने एकत्रित किए जाएंगे। इसके लिए 'जीनोम इंडिया' प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी गई है। 240 करोड़ लागत वाली इस महत्वाकांक्षी परियोजना को भारत की आनुवंशिक विविधता के निर्धारण की दिशा में पहला प्रयास माना जा रहा है।

हम जीव विज्ञान की सदी में रह रहे हैं। अगर 20वीं सदी भौतिक विज्ञान की सदी थी तो 21वीं सदी जैव-प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी की होगी। पिछले दो-तीन दशकों में जैव-प्रौद्योगिकी में, विशेषकर आणविक जीव विज्ञान के क्षेत्र में चमत्कृत कर देने वाले नए अनुसंधान तेजी से बढ़े हैं। ऐसा स्वास्थ्य, कृषि, पर्यावरण, खाद्य सुरक्षा, उद्योग आदि क्षेत्रों में, जिनके केंद्र बिंदु में जीव जगत है, के सतत मांग की वजह से मुमकिन हुआ है।

मात्र दो अक्षरों का शब्द 'जीन' आज मानव इतिहास की दशा और दिशा बदलने में समर्थ है। जीन सजीवों में सूचना की बुनियादी इकाई और डीएनए का एक हिस्सा होता है। जीन इस लिहाज से स्वार्थी होते हैं कि उनका एकमात्र उद्देश्य होता है स्वयं की ज्यादा से ज्यादा प्रतिलिपियों को अगली पीढ़ी में पहुंचाना। इसलिए जीन माता-पिता व पूर्वजों के गुण और रूप-रंग संतान में पहुंचाता है। कह सकते हैं कि काफी हद तक हम वैसा ही दिखते हैं या वही करते हैं, जो हमारे शरीर में छिपे सूक्ष्म जीन तय करते हैं। डीएनए के उलट-पुलट जाने से जींस में विकार पैदा होता है और इससे आनुवांशिक बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी बच्चों को अपने पुरखों से विरासत में मिलती हैं।

मानव शरीर में जीनों की संख्या अस्सी हजार से एक लाख तक होती है। इस विशाल समूह को 'जीनोम' नाम से जाना जाता है। जीनोम के अध्ययन को जीनोमिक्स कहा जाता है। चूंकि शरीर में क्रियाशील जीन की स्थिति ही बीमारी विशेष को आमंत्रित करती है, इसलिए वैज्ञानिक लंबे समय से मनुष्य की जीन कुंडली को पढ़ने में जुटे हैं। 1988 में अमेरिकी सरकार ने अपनी 'ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट' की शुरुआत की। मानव आनुवंशिकी और जीनोम विश्लेषण पर इस सबसे बड़ी परियोजना को वर्ष 2003 में पूरा किया गया। वैज्ञानिकों ने इस प्रोजेक्ट के जरिये इंसान के पूरे जीनोम को पढ़ा। इस परियोजना का लक्ष्य जीनोम सिक्वेंसिंग के जरिये बीमारियों को बेहतर ढंग से समझने, दवाओं के शरीर पर प्रभाव की सटीक भविष्यवाणी, फोरेंसिक विज्ञान में उन्नति और मानव विकास को समझने में मदद हासिल करना था।

जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा बीस हजार लोगों के जीनोम की सिक्वेंसिंग किए जाने की योजना ने जीनोमिक्स के क्षेत्र में भारत के प्रवेश की भूमिका तैयार कर दी है जिससे चिकित्सा विज्ञान में नई संभावनाओं के दरवाजे खुलेंगे। इस परियोजना में बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान एवं कुछ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों सहित लगभग 20 संस्थान शामिल होंगे। जीनोम की सिक्वेंसिंग खून के नमूने के आधार पर की जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति के डीएनए में मौजूद एडानीन, गुआनीन, साइटोसीन और थायमीन के सटीक क्रम का पता लगाया जाएगा। डीएनए सीक्वेंसिंग से लोगों की बीमारियों का पता लगाकर समय रहते इलाज किया जा सकता है। साथ ही भावी पीढ़ी को रोगमुक्त करना संभव होगा। परियोजना में भाग लेनेवाले छात्रों को बताया जाएगा कि क्या उनमें जीन वेरिएंट हैं जो उन्हें कुछ दवाओं के प्रति कम संवेदनशील बनाते हैं। दुनिया के कई देश अब अपने नागरिकों की जीनोम मैपिंग करके उनके यूनीक जेनेटिक ट्रेट्स को समझने में लगे हैं, ताकि किसी बीमारी विशेष के प्रति उनकी संवेदनशीलता के मद्देनजर व्यक्तिगत दवाओं को तैयार करने में मदद मिल सके।

मानव जीनोम को अनुक्रमित किए जाने के बाद प्रत्येक व्यक्ति की अद्वितीय आनुवंशिक संरचना तथा रोग के बीच संबंध को लेकर वैज्ञानिकों को एक नई संभावना दिख रही है। जीनोम अनुक्रम को जान लेने से यह पता लग जाएगा कि कुछ लोग कैंसर, कुछ मधुमेह और अल्जाइमर और अन्य बीमारियों से ग्रस्त क्यों होते हैं। हम यह जान सकते हैं कि किसको कौन सी बीमारी हो सकती है और उसके क्या लक्षण हो सकते हैं। जीनोम मैपिंग से बीमारी होने का इंतजार किए बगैर व्यक्ति की जीन-कुंडली को देखते हुए उसका इलाज पहले से शुरू किया जा सकेगा। इसके माध्यम से पहले से ही पता लगाया जा सकेगा कि भविष्य में कौन सी बीमारी हो सकती है। वह बीमारी न होने पाए तथा इसके नुकसान से कैसे बचा जाए इसकी तैयारी आज से ही शुरू की जा सकती है। लगभग दस हजार बीमारियां हैं जिनमें सिस्टिक फाइब्रोसिस, थैलेसीमिया शामिल हैं, जिनके होने का कारण एकल जीन में खराबी को माना जाता है। जीनोम थेरैपी के जरिये दोषपूर्ण जीन को निकाल कर स्वस्थ जीन को रोपित करना संभव हो सकेगा।

अब समय आ गया है कि भारत अपनी खुद की जीनोमिक्स क्रांति की शुरुआत करे। तकनीकी समझ और इसे सफलतापूर्वक लॉन्च करने की क्षमता हमारे देश के वैज्ञानिकों तथा औषधि उद्योग में मौजूद है। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक विजन तथा कुशल नेतृत्व की आवश्यकता है।

1.36 करोड़ भारतीय विदेशों में रहते हैं। इनमें से एक चौथाई यूएई में रहते हैं। यूएई में रहने वाले भारतीयों की संख्या 34,20,000 है।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
मंगलवार 18 फरवरी 2020

उत्तराखंड

पारिस्थितिकीय पर्यटन से उम्मीद

आर्थिक मोर्चे पर संघर्ष कर रहे उत्तराखंड में सरकार आय के संसाधन बढ़ाने के लिए तमाम प्रयास कर रही है। पर्यटन और तीर्थाटन जैसे पारंपरिक स्रोतों के साथ ही नवाचार की राह भी अपनाई जा रही है। हालांकि सरकार की मंशा पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, लेकिन इस सच से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि ज्यादातर योजनाओं की कवायद अभी फाइलों से आगे नहीं बढ़ पाई है। इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रदेश पर कुदरत ने जो नेमतें बरसाई हैं, यदि उन्हीं में उचित प्रबंधन किया जाए तो उत्तराखंड का आर्थिक परिदृश्य बदल सकता है।

71 फीसद वन भूभाग वाले प्रदेश में जैव विविधता का अपार भंडार है। सूबे में छह नेशनल पार्क, सात अभयारण्य और चार कंजर्वेशन रिजर्व हैं। बावजूद इसके हकीकत यह है कि उत्तराखंड बने 20 साल होने को हैं, लेकिन नए डेस्टिनेशन विकसित ही नहीं हो पाए। आज भी 70 फीसद सैलानी जिम कार्बेट नेशनल पार्क आते हैं और शेष राजाजी की सैर कर वापस लौट जाते हैं। पर्यटकों की बेहद कम संख्या नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में पड़ने वाले फूलों की घाटी तक पहुंचती है और अन्य पार्कों के बारे में तो ज्यादातर सैलानियों को पता ही नहीं है। कुमाऊं के प्रसिद्ध नंधौर पार्क में तो पिछले साल एक भी सैलानी नहीं पहुंचा। बर्ड वाचिंग के लिए उत्तराखंड एक शानदार डेस्टिनेशन है। देहरादून के पास आसन वेटलैंड, हरिद्वार की झिलमिल झील, कुमाऊं के पवलगढ़ एवं नैना देवी कंजर्वेशन रिजर्व को विकसित किया जाए तो ये नए पर्यटक स्थलों के तौर पर पहचान बना सकते हैं।

> जैव विविधता के धनी उत्तराखंड में कुदरत से छेड़छाड़ किए बिना पारिस्थितिकीय पर्यटन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। निसंदेह आर्थिक मोर्चे पर संघर्ष कर रहे प्रदेश के लिए यह संजीवनी साबित होगा।

यूरोप के देशों में बर्ड वाचिंग बड़ा कारोबार है, जबकि उत्तराखंड की पक्षी विविधता के मामले में बेजोड़ है। भारत में पाई जाने वाली 1300 पक्षी प्रजातियों में से साढ़े सात सौ से ज्यादा यहां पाई जाती हैं। प्रवासी परिंदों के लिए यहां की धरती किसी स्वर्ग से कम नहीं है। न सिर्फ देश के अन्य राज्यों, बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में मेहमान परिंदे यहां आते हैं। जाहिर है उत्तराखंड बर्ड वाचिंग का हब साबित हो सकता है। आखिर आर्थिकी संवारने के लिए इससे बेहतर तरीका क्या होगा कि कुदरत से छेड़छाड़ किए बिना सैलानियों को आकर्षित किया जाए। अच्छी बात यह है कि गुजरात की राजधानी गांधीनगर में हो रही कांफ्रेंस में उत्तराखंड अपनी जैवविविधता को लेकर प्रस्तुति दे रहा है। विश्व के सवा सौ से ज्यादा देश इस कांफ्रेंस में भाग ले रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड दुनिया के सामने अपनी विरासत का प्रदर्शन तो कर ही सकता है। निश्चित ही आने वाले दिनों में प्रदेश को इसका लाभ मिलेगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार इस दिशा में कदम उठाएगी।

झारखंड

जहरीली शराब का बढ़ता कहर

गिरिडीह जिले के सरिया प्रखंड के फकीरापहरी और देवरी प्रखंड के गादीकला गांव में जहरीली शराब पीने से पिछले पांच दिनों में 16 लोगों की मौत हो गई है। इससे गिरिडीह के गांवों में दहशत का माहौल कायम हो गया है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त को ट्वीट कर उनसे जवाब तलब किया है। अपने जवाब में उपायुक्त ने सीएम को सूचित किया है कि यह रहस्यमयी मौत नहीं है, बल्कि इसका कारण जहरीली शराब का सेवन है। उपायुक्त ने सीएम को बताया कि एहतियात के तौर पर दोनों गांवों में स्वास्थ्य शिविर लगा दिए गए हैं। जिनकी हालत ज्यादा खराब है, उन्हें रिम्स रेफर किया गया है। इधर जहरीली शराब से इतनी मौतों के बाद उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने ताबड़तोड़ कई छापामारी कर छह लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं ग्रामीणों का दावा है कि सभी मौतों का कारण जहरीली शराब या फूड प्वाइजनिंग नहीं है।

बहरहाल झारखंड में एक बार फिर जहरीली शराब ने कहर ढाना शुरू कर दिया है, जो कि चिंता की बात है। हालांकि प्रशासन इन लोगों की मौत की वजह अत्यधिक शराब का सेवन बता रहा है, लेकिन काबिले गौर यह भी है कि इसके शिकार सभी लोगों ने अलग-अलग समय में अलग-अलग जगह से शराब

प्रतीकात्मक फोटो

खरीदकर पी। ऐसे में सभी लोगों ने अधिक मात्रा में शराब पी ली हो, यह बात गले से नहीं उतरती। पुलिस-प्रशासन से लेकर सरकार तक को इस पूरे मामले की तह में जाकर जांच और कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि इन घटनाओं के सामने आने के बाद पुलिस छापेमारी कर अवैध शराब नष्ट कर रही है, लेकिन केवल इतनी कार्रवाई भर कर देने से यह सिलसिला नहीं थमनेवाला। भले ही अभी जहरीली शराब से किसी एक इलाके में मौत की घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन यह जानलेवा समस्या राज्यव्यापी और देशव्यापी है। इस कारण इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए।

शराब को अधिक नशीली बनाने के चक्कर में कच्ची या देसी शराब बनाने वाले लोग उसमें ऑक्सीटोसिन दवा (गाय और भैंस का दूध उतारने के लिए इंजेक्शन में इस्तेमाल की जानेवाली दवा) के साथ यूरिया, नौसादर, सड़ा गुड़, शीरा, धतूरे के बीज और इस तरह की कई चीजें मिलाते हैं। ऑक्सीटोसिन जब यूरिया और नौसादर जैसी चीजों से मिलता है तो मिथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है। तय मात्रा में मिलाने पर यह मिश्रण शराब को नशीली बनाता है, लेकिन मिश्रण का संतुलन बिगड़ने से शराब जहरीली बन जाती है। चूंकि देसी शराब के कारोबार से जुड़े लोगों के पास न तो इसकी वैज्ञानिकता का ज्ञान है न ही सुरक्षित शराब बनाने का प्रशिक्षण, इसलिए उनकी जरा भी चूक शराब पीने वाले लोगों के लिए जानलेवा साबित होती है।

दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि इसकी निगरानी का भी कोई तंत्र नहीं है, अगर है भी तो वह प्रभावी नहीं है। शराब पीने वाले भी बिना जांचे-परखे शराब पीते हैं। कच्ची और देसी शराब बनाने वालों से लेकर पीने वालों तक के लिए बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान भी चलाए जाने की जरूरत है।

बंगाल

रिश्तों में सुधार की नई पहल

बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सोमवार को हुई मुलाकात से एक बार फिर नई उम्मीद जगी है। महामहिम और सरकार की लड़ाई की आंच पर राजनीतिक दल भले हाथ सेंकते हों, लेकिन बंगाल की आम जनता को यह रास नहीं आ रहा है। इसलिए राजभवन जाकर महामहिम से मुख्यमंत्री की गुफ्तगू को अहम माना जा रहा है। अब तक राज्यपाल और राज्य सरकार का वाक्युद्ध किसी से छिपा नहीं है, पर यह उम्मीद फिर से जगी है कि धनखड़ और ममता सरकार के बीच रिश्ते सुधरेंगे। ऐसी उम्मीदें पहले भी कई बार बनीं, लेकिन कारगर नहीं हो सकीं। राज्य के बजट सत्र को लेकर संसदीय कार्य और शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने राज्यपाल से मिलकर रिश्ते ठीक करने की पहल की और बजट सत्र में इसका असर भी दिखा, लेकिन बजट प्रस्ताव पेश होने के बाद माहौल में फिर गर्मी आ गई।

दरअसल हुआ यह कि राज्यपाल के अभिभाषण का सीधा प्रसारण नहीं हुआ, जबकि वित्त मंत्री के बजट भाषण का सीधा प्रसारण किया गया। सरकार

बंगाल की सीएम ममता बनर्जी एवं राज्यपाल जगदीप धनखड़।

की खामियां गिनाने का कोई मौका न चूकने वाले जगदीप धनखड़ ने इसे मुद्दा बना दिया। धनखड़ का सवाल वाजिब भी था, लेकिन उनके तीखे तेवर से रिश्तों की गांठ मजबूत होने से पहले ही ढीली हो गई। इसके पहले भी कई मौके आए थे जब धनखड़ ने तीखी टिप्पणी की और सरकार के मंत्रियों ने उन पर जमकर हमला बोला। बात इतनी बढ़ गई कि दूसरे राज्यों के राज्यपाल भी इस पर टिप्पणी करने लगे। मेघालय के राज्यपाल तथागत रॉय ने तो ममता सरकार पर निशाना साधते हुए यहां तक कह दिया कि धनखड़ के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है वह ठीक नहीं है। उन्होंने दीक्षा समारोह से वापस लौटाए जाने की निंदा भी कर दी। यह बात तो सही है कि राज्यपाल सरकार पर आक्रामक हैं, लेकिन वह जबसे कार्यभार संभाले हैं तबसे उन पर भी खूब हमले हो रहे हैं।

जादवपुर विश्वविद्यालय और कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षा समारोह से उन्हें वापस लौटाने की घटना ने तो स्थिति खराब की ही थी, कूच बिहार विश्वविद्यालय ने तो दीक्षा समारोह में उन्हें आमंत्रित करना तक उचित नहीं समझा। गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने गए राज्यपाल के साथ पुलिस अधिकारी की अनुशासनहीनता ने भी माहौल खराब किया था। इसके पहले पार्थ चटर्जी ने राज्यपाल से मुलाकात कर रिश्तों को ठीक करने का एक प्रयास जरूर किया था, लेकिन अब मुख्यमंत्री की मुलाकात ने नई उम्मीदों को जन्म दिया है। बंगाल की आम जनता का मंसूबा यही है कि राजभवन और राज्य सचिवालय (नवान्न) के बीच रिश्ता बना रहे।

पंजाब

कानून-व्यवस्था को चुनौती देते अपराधी

पंजाब में एक तरफ दिनों-दिन लुटेरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, वहीं पुलिस और कानून जैसी व्यवस्था न जाने कहां खोई हुई है। कदाचित यही कारण है कि प्रदेश के नगरों में लूटपाट की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। निस्संदेह यह चिंता का विषय है। लुधियाना में खासतौर पर लुटेरे पुलिस को चुनौती देते दिखाई दे रहे हैं। विगत तीन दिनों में लगातार इस महानगर में लुटेरों ने बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है। शनिवार को लुटेरों ने एक व्यापारी से दिनदहाड़े साढ़े तीन लाख रुपये लूट लिए। अगले दिन राष्ट्रीय राजमार्ग पर परिवार सहित जा रहे बठिंडा के एक व्यापारी से लूटपाट की गई। व्यापारी की कार भी तोड़ी गई और परिवार से मारपीट भी की गई। सोमवार को भी इसी नगर में गोल्ड लोन देने वाली एक कंपनी के कार्यालय से चार हथियारबंद लुटेरों ने करीब तीस किलो सोना लूट लिया।

बात सिर्फ लुधियाना की ही नहीं है, अपितु शनिवार को अमृतसर में भी एक आभूषण विक्रेता के यहां स्टाफ को बंधक बनाकर लुटेरे करीब साढ़े तीन लाख के गहने और 37 हजार रुपये नकद लूट ले गए। इस नगर में भी फरवरी के पहले पखवाड़े में ही लूट की पांच बड़ी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। जालंधर, पटियाला, बठिंडा सहित अन्य शहर भी लूट की घटनाओं से अछूते नहीं हैं। यदि लूटपाट की घटनाएं इसी तरह बढ़ती रहीं तो एक तरफ लुटेरे बेखौफ होते जाएंगे वहीं दूसरी तरफ जनता के बीच भय का माहौल बढ़ता जाएगा। यह किसी भी सभ्य समाज के लिए कतई आदर्श स्थिति नहीं है। पुलिस प्रशासन को इन घटनाओं का शीघ्र संज्ञान लेना चाहिए और सक्रियता बढ़ानी चाहिए। पुलिस की निष्क्रियता के कारण ही जनता में यह गलत संदेश प्रसारित होता है कि लुटेरों को कहीं न कहीं पुलिस की शह मिली हुई है। पुलिस को चाहिए कि वह लुटेरों की धरपकड़ करे और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस उपाय भी करे। जब तक लुटेरों के मन में पुलिस का भय नहीं होगा, तब तक ऐसी घटनाएं रुकने वाली नहीं हैं।

> यदि लूटपाट की घटनाएं इसी तरह बढ़ती रहीं तो एक तरफ लुटेरे बेखौफ होते जाएंगे और दूसरी तरफ जनता के बीच भय का माहौल भी बढ़ता जाएगा

दरअसल ऐसी नौबत आने के इसके कई कारण हैं। सबसे पहले तो पुलिस की निष्क्रियता के चलते कई बार अपराधी पहले तो पकड़ में ही नहीं आते हैं। किसी तरह पुलिस की गिरफ्त में आ भी जाते हैं तो अदालतों की सुस्त कार्यप्रणाली उनके लिए फायदेमंद साबित होने लगती हैं। वे जमानत पर बाहर आ कर फिर उसी अपराध की दुनिया में जीने लगते हैं। उधर अदालतों में उनके केस सालों-साल चलते हैं। यह अनिर्णय की स्थिति समाज और कानून व्यवस्था के लिए घातक साबित हो रही है। इसमें सुधार के लिए दो काम यथाशीघ्र करने होंगे। पहला, पुलिस की कार्यप्रणाली में सुधार लाकर उसे चुस्त किया जाना चाहिए। दूसरा, न्यायिक सुधार कर अदालतों को त्वरित निर्णय लेने के लिए तैयार किया जाना चाहिए।

अद्भुत है ढोलकल महोत्सव, तीन हजार फीट ट्रैकिंग करते हैं श्रद्धालु

छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बैलाडिला की तीन हजार फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित भगवान गणेश की प्रतिमा के दर्शन के लिए सोमवार को स्विट्जरलैंड के क्रिस्टिन आर यास्मीन व उनका परिवार पहुंचा। नईदुनिया

योगेंद्र ठाकुर, दंतेवाड़ा : जिला मुख्यालय से 12 किमी दूर फरसपाल गांव से सटे बैलाडीला के पहाड़ पर स्थित हैं ढोलकल गणेश। तीन हजार फीट ऊंची चोटी पर ललितासन में विराजित प्राचीन गणेश की यह मूर्ति 11वीं सदी की बताई जाती है। वर्षों तक सिर्फ गांव के लोग ही इसे जानते थे। 2012 में दैनिक जागरण के सहयोगी अखबार नईदुनिया की टीम जब यहां पहुंची, तब ढोलकल गणेश की प्रसिद्धि देश-दुनिया तक पहुंच गई। पहाड़ की चोटी से विहंगम नजारा दिखता है।

अब फरसपाल के वार्षिक मेले को ढोलकल महोत्सव के साथ जोड़ दिया गया है। इस वर्ष इसे परशुराम ढोलकल महोत्सव के नाम से प्रचारित किया गया। ढोलकल में ट्रैकिंग के लिए शुल्क देना होता है पर महोत्सव के दौरान यह फ्री है। मंगलवार को तीन दिवसीय महोत्सव का अंतिम दिन है। महोत्सव के दौरान स्थानीय लोगों के साथ देशी- विदेशी सैलानी भी जुट रहे हैं। छत्तीसगढ की राजधानी रायपुर से 390 किमी दूर दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय और यहां से 12 किमी दूर ढोलकल पहाड़ी है। बैलाडीला पहाड़ी के एक इसी हिस्से में 11वीं सदी के गणेश प्रतिमा विराजित हैं। बचेली वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इस पहाड़ी की ऊंचाई समुद्र तल से 2994 फीट है। यहीं पर फूलगट्टा वन कक्ष में ढोलकल शिखर पर अद्भुत ललितासन गणेश प्रतिमा है जिसके दर्शन के लिए हजारों लोग यहां पहुंचते हैं।

4000 किलोमीटर के शाही सफर पर निकला विंटेज कारों का कारवां

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम

सेक्टर-80 स्थित करमा लेक लैंड्स गोल्फ कोर्स से विंटेज कारों का कारवां सोमवार को 4000 किलोमीटर के शाही सफर पर निकल पड़ा। इसे द इनक्रेडिबल इंडिया रैली का नाम दिया गया है। इसमें शामिल कारों को विंटेज ब्यूटीज के तौर पर जाना जाता है। ये कारें अगले 23 दिनों तक देश के 17 शहरों की तत्कालीन रियासतों का दौरा करेंगी। देश को ग्लोबल मोटरिंग टूरिज्म मैप पर स्थापित करने के मकसद से यह रैली पहला प्रयास है।

- **द इनक्रेडिबल इंडिया रैली करमा लेक लैंड्स गोल्फ कोर्स से हुई रवाना**

इस विंटेज कार रैली का आयोजन 21 गन सैल्यूट हेरिटेज एंड कल्चरल ट्रस्ट द्वारा केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है। इस संयुक्त प्रयास का उद्देश्य देश को वैश्विक मंच पर एक हेरिटेज मोटरिंग डेस्टिनेशन के तौर पर स्थापित करना है। रैली जब रवाना हुई तो उस समय अंतरराष्ट्रीय कार विशेषज्ञों सहित देश-विदेश के मोटरिंग क्षेत्र के दिग्गज भी मौजूद रहे। 21 गन सैल्यूट के चेयरमैन एवं ट्रस्टी मदन मोहन ने कहा कि यह रैली एक खास शुरुआत है। इससे

गुरुग्राम में सोमवार को दिल्ली-जयपुर हाईवे स्थित करमा लेक लैंड्स गोल्फ कोर्स से निकला विंटेज कारों का कारवां। जागरण

देश के 17 शहरों की सड़कों पर लोगों को अलग-अलग दौर की शानदार मास्टर पीस कारों के दीदार का मौका मिलेगा।

रैली में 1960 अल्फा रोमियो, 2000 टूरिंग स्पाइडर कारें भी शामिल होंगी। इसके मालिक इटली के राउल सैन जियोर्गी हैं। यह कार अभी भी अपने मूल इंजन के साथ है। रैली में शामिल एक और शानदार बेंटले एमके फोर बिग बोर है, जो स्पोर्ट्स सैलून, फ्रीस्टोन एंड वेब द्वारा निर्मित थी। इसके अलावा 1936 रोल्स-रॉयस 25-30 गुर्ने नटिंग कूपे हैं। इसके मालिक डेविड कोहेन हैं। इस कार का भारत से विशेष संबंध है, क्योंकि यह मूल रूप से मुंबई में रहने वाले रोल्स-रॉयस प्रतिनिधि के लिए बनाई गई थी। रैली का पहला पड़ाव आगरा (ओबेरॉय अमर विलास) होगा। इसके बाद कारों का काफिला सवाई माधोपुर जाएगा। यात्रा का तीसरा पड़ाव गुलाबी शहर जयपुर होगा।

रखरखाव कार्यों के कारण 2019 में रद हुई 3,000 से ज्यादा ट्रेनें

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारतीय रेलवे नेटवर्क के रखरखाव कार्यों के कारण पिछले साल 3,000 से ज्यादा ट्रेनें रद हुईं। वर्ष 2014 के बाद पिछले ही साल सबसे ज्यादा ट्रेनें रद की गईं। रेलवे ने एक आरटीआइ के जवाब में यह जानकारी दी।

आरटीआइ के जवाब में रेलवे ने बताया कि वर्ष 2014 में रखरखाव कार्यों के कारण 101 ट्रेनें रद हुईं, जबकि वर्ष 2017 में इनकी संख्या 829 हो गई। वर्ष 2018 में 2,867 ट्रेनों को रद करना पड़ा तो वर्ष 2019 में कुल 3,146 ट्रेनें रद हुईं। मध्यप्रदेश निवासी चंद्रशेखर गौर ने सूचना का अधिकार (आरटीआइ) कानून के तहत रेलवे से ट्रेनों के रद किए जाने से संबंधित जानकारियां मांगी थीं।

अधिकारियों ने बताया कि गत वर्ष रेलवे के 58 सुपर क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स में सात को पूरा किया गया। इनमें से एक परियोजना वर्ष 2018 में ही पूरी हो चुकी है। बाकी 50 परियोजनाओं को मार्च 2022 तक पूरा किया जाना है।

एक अधिकारी ने बताया, 'बड़े पैमाने पर जारी सुधारात्मक कार्यों के कारण बड़ी संख्या में ट्रेनों को रद करना पड़ा। इसके कारण यात्रियों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है, लेकिन यह बेहद जरूरी और लंबे समय से लंबित काम है।' अधिकारियों ने बताया कि रेलवे ने अपने नेटवर्क के विद्युतीकरण का कार्य वर्ष 2023 तक व मार्गों के दोहरीकरण का काम वर्ष 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

58 सुपर क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स में से आठ किए जा चुके हैं पूरे

2022 तक बाकी 50 को पूरा करने का है लक्ष्य

पटरियों का रखरखाव नहीं होने से होते हैं हादसे

रेलवे का कहना है कि पटरियों के रखरखाव का काम ठीक से न होने और मरम्मत कार्यों के लंबित होने की वजह से ज्यादातर ट्रेन हादसे होते हैं। पिछले पांच वर्षों में 50 फीसद दुर्घटनाएं ट्रेनों के पटरी से उतरने के कारण हुईं।

उल्लेखनीय है कि रेलवे के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया जारी है। सरकार ने वर्ष 2020-21 में नई पटरियां बिछाने के लिए 12,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जबकि पिछले वर्ष यह राशि 7,881 करोड़ रुपये थी। ट्रैकों के नवीकरण पर चालू वर्ष में 8,461 करोड़ रुपये खर्च किए गए, जिसे आगामी वर्ष के लिए बढ़ाकर 10,599 करोड़ रुपये कर दिया गया है। आने वाले दिनों में रेलवे पूरी तरह से आधुनिक हो जाएगी।

आइआइटी बीएचयू का शोध नासा की दशकीय उपलब्धि में शामिल हुआ

हिमांशु अस्थाना, वाराणसी

- **डॉ.अभिषेक के नेतृत्व में हुआ शोध एसडीओ मिशन के प्राइम टेन में शामिल**
- **अमेरिका के द एस्ट्रो फिजिकल जर्नल में प्रकाशित हुआ शोध**

अब आइआइटी बीएचयू के तार अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा से भी जुड़ गए हैं। संस्थान में भौतिकी विभाग के प्रोफेसर डॉ. अभिषेक श्रीवास्तव के नेतृत्व में किए गए एक अनुसंधान को नासा ने अपने सोलर डायनामिक्स आब्जर्वेटरी (एसडीओ) मिशन में दशकीय उपलब्धि के तौर पर शामिल कर लिया है। उनका शोध नासा के प्राइम टेन में शुमार चुका है। डॉ.अभिषेक के नेतृत्व में पीएचडी के छात्र सुधीर मिश्रा व प्रो.बीएन द्विवेदी ने सूर्य के कोरोना के वातावरण पर एक अध्ययन किया है, जिसमें उन्होंने नये चुंबकीय विस्फोट की खोज की है।

दस लाख केल्विन पहुंच जाता है कोरोना पर तापमान : अपने अध्ययन में उन्होंने पाया कि सूर्य के वातावरण से आए एक विक्षोभ द्वारा दो चुंबकीय क्षेत्र आपस में टकराते हैं, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। इससे कोरोना पर तापमान लगभग दस लाख केल्विन तक पहुंच जाता है। इससे सूरज का उच्च तापमान बना रहता है। उनका यह शोध अमेरिका के द एस्ट्रो फिजिकल जर्नल में प्रकाशित भी हो चुका है। कोरोना सूर्य के वर्णमंडल के परे के भाग को कहते हैं। पूर्ण सूर्यग्रहण के समय वह श्वेत रंग होता है।

फरवरी में एक और मिशन की शुरुआत

इसी साल फरवरी में इस मिशन के दस साल पूरे होने पर 11 फरवरी को यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर नासा ने सोलर आर्बिटर सेटेलाइट लांच किया है। डॉ .अभिषेक ने बताया कि इसके तहत सूरज के ध्रुवीय क्षेत्र में व्याप्त रहस्यों को उजागर किया जाएगा। इस क्षेत्र में अभी तक कोई भी शोध या अनुसंधान नहीं हुआ है। इसमें सौर पवनों की उत्पत्ति व गतिविधियों के बारे में जानकारियां जुटाई जाएंगी।

धरती से है इस खोज का संबंध : डॉ. अभिषेक ने बताया कि पृथ्वी के बाहरी आवरण पर सौर पवनों का काफी प्रभाव होता है। वहीं सौर पवनों पर सूर्य के कोरोना में होने वाली चुंबकीय गतिविधियों का काफी असर पड़ता है। इस तरह से सूर्य के साथ ही इस अनुसंधान से धरती के वातावरण व मौसम की भविष्यवाणी की जा सकेगी। साथ ही अंतरिक्ष में सेटेलाइटों के संचालन में भी आसानी होगी।

नासा ने 2010 में शुरू किया था यह मिशन : नासा ने सूर्य के बारे में अध्ययन करने के लिए फरवरी 2010 में एसडीओ मिशन शुरू किया था। इसके बाद से दुनिया भर के वैज्ञानिक इस पर अनुसंधान करने के लिए जुड़े व नासा द्वारा दस वर्ष की उपलब्धि का एक खाका तैयार किया गया। इसमें उन्होंने डॉ.अभिषेक व उनके दल द्वारा पिछले साल किए गए शोध को अपनी दशकीय उपलब्धि में शुमार कर लिया।

बंगाल के मदरसा बोर्ड में हिंदू परीक्षार्थियों की संख्या बढ़ी

जासं, कोलकाता : इस वर्ष बंगाल के मदरसा बोर्ड की दसवीं की परीक्षा में रिकार्ड संख्या में हिंदू छात्रों ने परीक्षा दी है। पिछले एक सप्ताह से जारी परीक्षा में इस वर्ष बंगाल मदरसा बोर्ड में 70 हजार परीक्षार्थी हैं जिनमें 18 फीसद हिंदू छात्र हैं। पिछले वर्ष मदरसा बोर्ड की परीक्षा में बैठने वालों में 12.77 फीसद हिंदू छात्र थे जो इस वर्ष संख्या 18 फीसद पहुंच गयी।

बंगाल मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष अबु ताहेर कमरुद्दीन का कहना है कि बीते कुछ वर्षों से मदरसों में हिंदू छात्रों की संख्या में 2 से 3 फीसद का हर वर्ष इजाफा हो रहा है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि रजिस्ट्रेशन कराने वाले सभी छात्र परीक्षा में नहीं बैठते हैं जिसके चलते कुछ प्रतिशत की गिरावट दर्ज हो जाती है। कमरुद्दीन का कहना है कि भारी संख्या में दसवीं की परीक्षा में मदरसा बोर्ड में छात्र निबंधन कराते हैं। खासकर पुरुलिया, वीरभूम, बांकुड़ा में चार ऐसे बड़े मदरसे हैं जहां मुस्लिम छात्र से अधिक गैर मुस्लिम छात्र हैं। पूरे राज्यभर में करीब 600 मदरसे हैं। जिन्हें सरकारी फंड मिलता है।

केंद्रीय अनुसंधान केंद्र ने विकसित किए लोहा समेत पोषक तत्व से भरपूर आलू

नीरज कुमार, पटना

- **केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों ने विकसित की नई प्रजाति 'कुफरी माणिक'**
- **नई प्रजाति में आयरन सहित पोषक तत्वों की प्रचुरता, दूर होगी कुपोषण की समस्या**

केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र, पटना ने आलू की खास प्रजाति विकसित की है, जिसे 'कुफरी माणिक' नाम दिया गया है। आलू की नई प्रजाति में आयरन, जिंक, कॉपर एवं कैल्शियम की प्रचुरता का दावा किया गया है। इसका रंग लाल है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस आलू के नियमित सेवन से शरीर में आयरन, जिंक, कॉपर एवं कैल्शियम की कमी दूर की जा सकती है। इसका कोई दुष्प्रभाव भी नहीं है।

पांच वर्षों का शोध रंग लाया : पटना स्थित केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉ.शंभू कुमार ने बताया कि पिछले पांच वर्षों की रिसर्च के बाद कुफरी माणिक को विकसित किया गया है। 100 ग्राम माणिक आलू में 41.06 पीपीएम (पार्ट्स पर मिलियन) आयरन, 20.70 पीपीएम जिंक, 422.30 पीपीएम कैल्शियम एवं 6.40 पीपीएम कॉपर की मात्रा है। यह आलू 100 दिन में तैयार होता है। इसी महीने आलू के बीज को राज्य सरकारों को मुहैया कराया

प्रतीकात्मक

जाएगा जो अपने किसानों को उपलब्ध कराएंगी।

आलू का छिलका कैंसररोधी : डॉ.शंभू कुमार ने कहा कि आलू को हमेशा छिलका सहित खाना चाहिए। कुफरी माणिक के छिलके में एंथोसाइनीन पिगमेंट होता है, जो मानव शरीर को कैंसर से बचाने में सहायता प्रदान करता है। यह आलू देश से कुपोषण की समस्या दूर करने में काफी सहायक होगा। कुपोषित मरीजों में आयरन, कैल्शियम, जिंक एवं कॉपर की कमी होती है। आलू प्रमुख सब्जी है। इस आलू को मधुमेह के मरीज भी नियंत्रित मात्रा में खा सकते हैं।

50 फीसद महिलाएं एनीमिया की शिकार : डॉ.शंभू कुमार के अनुसार आलू का सब्जी में प्रयोग हर घर में होता है। खून और विटामिन की कमी से रोगों की शिकार महिलाओं के लिए भी यह आलू स्वास्थ्यवर्द्धक होगा। पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (पीएमसीएच) के प्राचार्य डॉ.विद्यापति चौधरी का कहना है कि भारत में लगभग 50 फीसद महिलाएं खून की कमी की समस्या से जूझ रही हैं। महिलाओं और किशोरियों को आयरन की बहुत जरूरत होती है। बच्चों के विकास में भी आयरन का महत्वपूर्ण योगदान है। आयरन की कमी से सांस लेने में समस्या भी होती है। एनीमिया के मरीजों को भूख नहीं लगती है। किडनी में दिक्कत आने लगती है।

600 रुपये किलो अखरोट तो 300 रुपये किलो साबुत कश्मीरी बादाम मिल रहा है। अखरोट की फसल पर मौसम की मार पड़ने से दक्षिण कश्मीर शोपियां और सेंट्रल कश्मीर बड़गाम में अखरोट की पैदावार काफी कम हुई है। देश में 85 फीसदी अखरोट का उत्पादन कश्मीर में होता है।

परिजनों की नई मुसीबत 'स्कल ब्रेकर चैलेंज'

सोशल मीडिया पर इन दिनों 'स्कल ब्रेकर चैलेंज' से जुड़े वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं। बच्चे इस चुनौती को स्वीकार करके खुद को नुकसान पहुंचा दे रहे हैं। उनकी यह चुनौती अभिभावकों पर भारी पड़ रही है। इसे लेकर वे चिंतित हैं। ऐसे में बच्चों को इस खेल के प्रति जागरूक किए जाने की जरूरत महसूस की जा रही है।

यह है चैलेंज

यह चैलेंज वीडियो शेयर एप टिकटॉक के जरिए काफी लोकप्रिय हो चुका है। इसमें तीन लोग साथ में खड़े होते हैं। वे साथ में उछलते हैं और जब वे हवा में ही होते हैं उसी वक्त दोनों ओर खड़े लोग बीच वाले शख्स के पैरों में पांवों को मारकर के उसका संतुलन बिगाड़ देते हैं और वो शख्स गिर जाता है। बहुत बार इसे एक प्रैंक की तरह किया जाता है और कई बार चुनौती के रूप में।

यह है नाम

इस चुनौती का नाम स्पेनिश शब्द 'रोमकप्रेनेस' या अंग्रेजी में 'स्कलब्रेकर' से लिया गया है। अभी तक यह ज्ञात नहीं है कि पहला वीडियो कहां से आया लेकिन वायरल पहले वीडियो में एक को वेनेजुएला के एक स्कूल में रिकॉर्ड किया गया था। इसके बाद यह यूरोप और अमेरिका में चलन में आया। अब यह भारत तक भी पहुंच चुका है।

इसलिए चिंता का सबब

इस चैलेंज का नाम ही इससे होने वाले संभावित नुकसान की कहानी कह देता है। इसके दौरान गिरने के कारण सिर में चोट आ सकती है या फिर जोड़ों में चोट लग सकती है। इससे कारण आपकी खोपड़ी तक टूट सकती है। दुनिया भर से इस चुनौती के चलते गंभीर रूप से चोटिल होने वाले लोगों के मामले सामने आ रहे हैं।

बच्चों को जागरूक करना जरूरी

बच्चों के परिजन इस तरह के चैलेंज के सामने आने के बाद काफी चिंतित हैं। परिजन डर रहे हैं कि कहीं उनके बच्चे इस प्रवृत्ति का शिकार हो सकते हैं और खुद को घायल कर सकते हैं। ऐसे में उन्हें अपने बच्चों से बात करनी चाहिए। साथ ही ऐसे किसी भी चैलेंज में भाग लेने से दूर रखने के लिए कहा जाना चाहिए। साथ ही यदि यह प्रैंक के रूप में हो तो बच्चों को इतनी समझ दी जानी चाहिए कि वे इस तरह के प्रैंक को समझ सकें और खुद को इससे बचा सकें।

कई और चुनौतियों ने किया परेशान

यह पहली बार नहीं है जब इस तरह के किसी ऑनलाइन ट्रेंड ने चिंता पैदा की है। सोशल मीडिया पर इस तरह के कई खतरनाक स्टंट प्रैंक और चुनौती के नाम पर सामने आते रहते हैं। इससे पहले भी कई चुनौतियां सामने आ चुकी हैं।

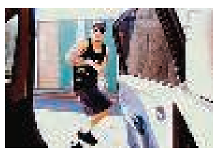

दालचीनी चैलेंज : इसमें पिसी हुई दालचीनी को एक चम्मच में रखकर के 60 सेकेंड तक मुंह में रखना होता था। दालचीनी के कारण मुंह सूख जाता था और खांसी और उल्टी जैसी स्थिति बन जाती थी। वहीं निमोनिया और फेफड़ों के काम करना बंद कर देने का खतरा भी रहता है।

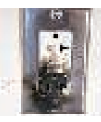

आउटलेट चैलेंज : ये सबसे खतरनाक चैलेंज था। जिसमें लोग सॉकिट और प्लग के बीच सिक्का रखकर के तमाशा देखते थे। बेहद मूर्खतापूर्ण इस चैलेंज को करने से भी बहुत से लोग बाज नहीं आए। इससे आग लगने का खतरा था।

किकी चैलेंज : यह कनाडाई हिप-हॉप सुपरस्टार ड्रेक के हिट गाने 'इन माई फीलिंग्स' पर आधारित था। इसमें सड़क पर चल रही कार के साथ चलते-चलते नृत्य करना होता है और फिर वापस कार में आना होता है। इस क्रम में दुर्घटना के पूरे आसार बने रहते थे।

आइस बकेट चैलेंज : इस चुनौती में आपको अपने शरीर पर बर्फ से भरी एक बाल्टी उड़ेलनी होती थी। कई बार ऐसा लोग बिना बताए भी कर देते थे।

एयर वेंट्स तकनीक से सींच रहे धरती की कोख

'रिचार्ज वेल विद एयर वेंट्स' तकनीक आधारित प्रयोग। जागरण

रमेश यादव, प्रयागराज

- **रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की तुलना में डेढ़ गुना अधिक है इसकी वाटर रिचार्ज क्षमता**
- **मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, प्रयागराज में सफल रहा इसका ट्रायल**

प्रयागराज, उप्र स्थित मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एमएनएनआइटी) ने भूगर्भ जल स्तर को बढ़ाने की दिशा में सफल प्रयोग किया है। 'रिचार्ज वेल विद एयर वेंट्स' नामक इस युक्ति से रेन वाटर हार्वेस्टिंग की पुरानी पद्धति के मुकाबले डेढ़ गुना अधिक वाटर रिचार्ज होता है।

संस्थान के एसोसिएट प्रोफेसर हेमंत कुमार पांडेय कहते हैं, भूगर्भ जलस्तर को सुधारने के लिए सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक स्थलों, बहुमंजिला इमारतों और रिहायशी सोसाइटी में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगे हुए हैं। इसके कुएं (वेल) में जो पानी इकट्ठा होता है, वह धीरे-धीरे रिस कर जमीन में जाता है। अधिक बारिश होने पर पानी नालियों में बह जाता है। लेकिन हमारी तकनीक में इस समस्या का समाधन है।

जल संरक्षण

दरअसल, एमएनएनआइटी के हॉस्टल में भी जो वेल बना था, उसका पानी भी बह जाता था। इसके लिए वहां पर दूसरे वेल को बनाने की जरूरत महसूस की गई। वेल बनाने के खर्च को बचाने के लिए सिविल विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर हेमंत कुमार पांडेय ने यह तकनीक तैयार की। उन्होंने वेल में चार एयर वेंट्स लगाए। इसको लगाने के बाद देखा गया कि वाटर रिचार्ज डेढ़ गुना अधिक हो गया। 40 मीटर गहरे वेल में पहले 150 लीटर पानी प्रति मिनट रिचार्ज होता था। वह बढ़कर 225 लीटर प्रति मिनट हो गया। पांडेय ने बताया, यहां पर एयर वेंट्स का सफल ट्रायल होने के बाद अन्य स्थानों पर इसका प्रयोग करने की तैयारी चल रही है।

वेल में लगाए जाते हैं चार पाइप : रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जहां पर बना होता है, उस वेल या गड्ढे में एक इंच डाया वाले चार पाइप 40 फीट तक डाले जाते हैं। इससे जमीन की पहली परत तक सीधे हवा पहुंचती है, जिसके कारण ज्यादा तेजी से पानी रिचार्ज होता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में एयर वेंट्स लगाने में पांच हजार से लेकर 10 हजार तक का खर्च आता है।

> एयर वेंट्स तकनीक पर प्रयोग सफल रहा है। इस तकनीक के माध्यम से रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को पहले के मुकाबले डेढ़ गुना तक अधिक वाटर रिचार्ज करने लायक बनाया जा सकता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को इस तकनीक पर अपडेट करने में खर्च भी अधिक नहीं आता है। अब लोगों को इसके प्रति जागरूक करने की जरूरत है।
>
> **– हेमंत कुमार पांडेय, एसोसिएट प्रोफेसर, एमएनएनआइ, प्रयागराज**

पांडेय कहते हैं, भूगर्भ जलस्तर का सबसे ज्यादा दोहन सिंचाई में होता है। उत्तर भारत में ट्यूबवेल के माध्यम से ज्यादा सिंचाई होती है। अगर किसी भी जगह एक मीटर जलस्तर गिर जाता है, तो वहां पर चलने वाला एक ट्यूबवेल 0.4 किलोवाट ज्यादा बिजली खर्च करता है।

लिहाजा, अन्य बुनियादी कारकों के साथ-साथ किसानों को घाटे से उबारने के लिए भी भूगर्भ जल स्तर का बढ़ाया जाना बेहद आवश्यक है और इसमें किसानों को भी भूमिका निभाना चाहिए।

सरोकार की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/positive-news

करियर पर निशाना लगा रहीं बेटियां

जागरण विशेष ▶ विश्व में चंबल की नई तस्वीर पेश करना चाहती हैं, बदनाम नहीं करेगी यह बंदूक...

भिंड जिले की 21 बेटियों ने राज्य स्तर की शूटिंग प्रतिस्पर्धा में मनवाया लोहा

अब्बास अहमद, भिंड

चंबल के बीहड़ अब बदल रहे हैं। यह बीहड़ अब ऐसी युवा पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं, जो बंदूक के शौक से पहले की तरह बीहड़ को बदनाम नहीं बल्कि देश को गौरवान्वित करेगी। जी हां! बीहड़ की बेटियां बंदूक के शौक को करियर का विकल्प बना रही हैं। इसके जरिए बेटियां उस मानसिकता को भी बदल रहीं हैं, जिसमें उन्हें बेटों से कमतर आंकते हैं। हाल में जिले की 21 बेटियों ने राइफल, पिस्टल शूटिंग में राज्य स्तर की प्रतिस्पर्धा में अपना लोहा मनवाया है।

निशानेबाजी से करियर पर निशाना लगा रही बेटियों का लक्ष्य देश के लिए गोल्ड जीतना है। कहती हैं, विश्व पटल पर चंबल के बीहड़ की एक नई तस्वीर पेश करना है...। भिंड, मप्र के उत्कृष्ट स्कूल क्रमांक-1 की 21 बेटियों ने आर्मी में नॉन कमीशंड अफसर रहे कोच भूपेंद्र कुशवाह से प्रेरित होकर पहली बार करीब एक साल पहले बंदूक थामी। कोच ने बेटियों को बंदूक के जरिए खेल करियर के बारे में बताया। साथ ही बेटियों को बताया कि शूटिंग में ओलंपिक पदक जीतकर वह चंबल की धरती और देश का नाम रोशन कर सकती हैं।

बीहड़ की इन बेटियों के संभावनाओं से भरे बेहतर खेल करियर के प्रति लालायित होने के पीछे एक अन्य कारण बीहड़ और बंदूक का पुराना रिश्ता भी रहा है। जिस बीहड़ में मुंह से निकलने वाली बोली की जगह बंदूक से निकलने वाली गोली को तवज्जो दी जाती रही, जहां बात-बात पर गोली चलती और जहां बंदूक मर्दाना शान का प्रतीक रही, वहां बेटियों का बंदूक से यह नया जुड़ाव पुरुषवादी समाज की रूढ़ियों को तोड़ने का एक सशक्त प्रयास भी है।

राइफल और पिस्टल थाम अचूक निशाने का अभ्यास करतीं इन बेटियों में से एक ने हमसे कहा- बंदूक हमें हौसला देती है। इसे थामते ही मजबूती का अहसास होता है...। कोच भूपेंद्र कुशवाह कहते हैं कि राइफल शूटिंग में 14 से 19 वर्ष उम्र की बेटियां बढ़चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। वर्तमान में अंडर-14, अंडर-17 और अंडर-19 में 21 बेटियों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में अपनी निशानेबाजी का लोहा मनवाया है।

बेटियों की वजह से बना पहला शूटिंग क्लब : उत्कृष्ट स्कूल क्रमांक-1 में भिंड जिले का पहला शूटिंग क्लब बना है। बेटियों के निशानेबाजी में बढ़ते लगाव के कारण ही इस क्लब का गठन किया गया। हालांकि इसमें बेटियों के साथ बेटे भी अभ्यास कर रहे हैं। राइफल शूटिंग के प्रति बेटियों में जुनून इतना है कि रविवार या दूसरी छुट्टी के दिन भी क्लब की एक्टिविटी जारी रहती है। यहां बेटियों को राइफल-पिस्टल थामकर लक्ष्य पर निशाना लगाते देख एकबार तो आंखें ठिठक जाती हैं, बीहड़ और बंदूक का पुराना रिश्ता मन में कौंध उठता है। लेकिन बेटियों के हाथों में यह बंदूक तो पदक पर निशाने के लिए है, यह बात सुखद अहसास से भर देती है।

जागरण विशेष की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/jagran-special

> पहली बार बंदूक थामकर एक अलग अहसास हुआ। राइफल शूटिंग का खेल आकर्षित करता है। यह हमें अंदर से आत्मविश्वास भी देता है। अच्छी पढ़ाई के साथ हम शूटिंग को करियर बनाएंगे। इससे हमारे जिले, प्रदेश और देश का नाम होगा।
>
> **– प्रियांशी, छात्रा**

> बंदूक शुरू से ही लुभाती रही है। हमें कोच ने प्रेरित किया तो पहली बार इसे करियर के लिए हाथों में उठाया। राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धा में पहुंचे तो अब उम्मीद जागी है कि इसके जरिए हम खेल में बेहतर करियर बना पाएंगे। यह रोमांचक भी है।
>
> **– स्वाति राजावत, छात्रा**

उत्कृष्ट स्कूल क्रमांक-1 में बना है भिंड का पहला शूटिंग क्लब, जहां अभ्यास करतीं छात्राएं। नईदुनिया

भिंड में निशानेबाजी का अभ्यास करतीं स्कूली छात्राएं। नईदुनिया

सॉफ्टवेयर नहीं होने देगा भ्रूण के लिंग की पहचान

अनिल भारद्वाज, गुरुग्राम : केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी 'बेटी बचाओ' मुहिम को अब तकनीकी संबल मिलने जा रहा है। सरकार के भ्रूण लिंग परीक्षण संबंधी कानून को दरकिनार कर चोरी-छिपे भ्रूण लिंग जांच करने वाले अल्ट्रासाउंड संचालकों की दुकान एक सॉफ्टवेयर के जरिए जल्द ही बंद होने वाली है। जल्द ही ऐसा सॉफ्टवेयर आ रहा है, जिससे अल्ट्रासाउंड करने वाले डॉक्टर भी नहीं जान पाएंगे कि गर्भ में पल रहा भ्रूण लड़के का है या लड़की का। इस सॉफ्टवेयर को बनाने वाले परपल रिसर्च एवं डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की टीम से हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों की बैठक हो चुकी है।

दरअसल, भ्रूण लिंग जांच के बाद कन्या भ्रूण का गर्भपात पूरे देश में बड़ी समस्या है। खासकर हरियाणा इस समस्या से सबसे ज्यादा जूझ रहा है। परपल रिसर्च एवं डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की टीम का दावा है कि सॉफ्टवेयर अल्ट्रासाउंड मशीन में लगने के बाद गर्भ में पल रहे भ्रूण लिंग का वह हिस्सा नहीं देखा जा सकेगा, जिसे देखकर भ्रूण के लिंग की पहचान होती है। इस ऑर्गेनाइजेशन में आइआइटी व आइएम के छात्र काम करते हैं। पिछले सप्ताह हरियाणा सरकार के उच्च अधिकारियों संग इनकी बैठक भी हो चुकी है। टीम का कहना है कि सॉफ्टवेयर बनने के बाद सरकार से देश में बिकने वाली अल्ट्रासाउंड मशीनों में इसे लगवाया जाएगा। इतना ही नहीं, अगर कोई सॉफ्टवेयर से छेड़छाड़ की कोशिश करेगा, तो इसकी जानकारी सॉफ्टवेयर बनाने वालों को हो जाएगी। इस बारे में सिविल सर्जन डॉ. जसवंत सिंह पूनिया ने कहा कि इस पर उच्च अधिकारियों और सॉफ्टवेयर बनाने वालों की बैठक हो चुकी है। ऑर्गेनाइजेशन ने दावा किया है कि वह जल्द ही ऐसा सॉफ्टवेयर ला रहे हैं। अगर यह सॉफ्टवेयर आता है तो सरकार इसे प्रदेश में लगवाएगी।

हिमाचल में बढ़ेगा हरित आवरण

रमेश सिंगटा, शिमला

हिमाचल के वनों में विभिन्न प्रजातियों के पेड़ हैं। ये पेड़ धरा के रक्षक तो हैं ही, लोगों को प्राणवायु भी देते हैं। प्रदेश में अपार वन संपदा है। सुकून वाली बात यह है कि इसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अब क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (कैंपा) फंड से प्रदेश में हरियाली बढ़ेगी। 1660 करोड़ का कैंपा फंड धरातल पर खर्च होगा। पहले चरण में 157 करोड़ रुपये की कार्ययोजना लागू हो गई है। जल्द ही इसके सकारात्मक परिणाम नजर आने लगेंगे।

सरकार ने वर्ष 2024 तक हरित आवरण को 33 फीसद तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। अभी यह 27.72 फीसद है। किसी समय प्रदेश में हरित आवरण 38 फीसद तक होता था। तब वनों के कटान पर पूर्ण पाबंदी नहीं थी। वर्ष 1981-82 से इस पर पूरी तरह से रोक लगी है। कैंपा के तहत प्राप्त राशि मलबे के वैज्ञानिक तरीके से निष्पादन (मक डंपिग), पौधरोपण, छोटे जलाशयों व तालाबों के निर्माण आदि पर खर्च होगी।

इसके माध्यम से प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण होगा। वन मंडलों को इस संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। विकास प्रोजेक्टों के लिए वन भूमि का उपयोग गैर वानिकी कार्यों के लिए इस्तेमाल होने की एवज में क्षतिपूर्ति के लिए कैंपा के तहत राशि स्वीकृत की जाती है। प्रदेश में हर साल विभिन्न योजनाओं के तहत 80 लाख से एक करोड़ पौधे रोपे जाते हैं, लेकिन अब जंगलों को बचाने पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसके तहत राज्य में हरित आवरण और बढ़ाया जाएगा।

हिमाचल में वन संपदा

वन	क्षेत्र	फीसद
संरक्षित वन (आरएफ)	1883 वर्ग किमी	4.96
चिह्नित संरक्षित वन (डीपीएफ)	12852 वर्ग किमी	33.87
गैर चिह्नित संरक्षित वन (यूडीएफ)	16035 वर्ग किमी	42.25
अन्य वन (वन विभाग के अधीन)	7160 वर्ग किमी	18.87
ऐसे वन जिनका प्रबंधन वन विभाग के अधीन नहीं	18 वर्ग किमी	0.05

(फीसद कुल वन संपदा का)

अधिक व मध्यम घनत्व वाले जंगलों में बढ़ोतरी

हिमाचल में हरित आवरण में वृद्धि हुई है। वर्ष 2017 के मुकाबले वर्ष 2019 में इसमें 334 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अधिक घनत्व और मध्यम घनत्व वाले जंगलों में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि, खुले जंगल में थोड़ी गिरावट आई है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया (एफएसआइ) की वर्ष 2019 की रिपोर्ट से इसका पता चला है। हर दो वर्ष बाद देशभर के वनों का सर्वे करवाया जाता है। पिछली सर्वेक्षण रिपोर्ट वर्ष 2017 में जारी की गई थी। तब प्रदेश का हरित आवरण 15100 वर्ग किलोमीटर था जो अब 15434 वर्ग किलोमीटर हो गया है। यह कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 27.72 फीसद है।

जगह छोटी और सोहबत बुरी सुधार की राह में मुश्किलें बड़ी

नीलमणि चौधरी, रांची

- **रांची बाल सुधार गृह के बड़े बंदी बिगाड़ रहे हैं छोटों को, हत्या और सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में बंद हैं ज्यादातर बंदी**
- **2018 में बिरसा मुंडा जेल से किशोर बंदी को बाल सुधार गृह में किया गया था शिफ्ट**
- **किशोर बंदी को बाल सुधार गृह से अलग प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखने का है प्रावधान**

डुमरदगा स्थित बाल सुधार गृह में सुधरने की बजाय बाल बंदी बिगड़ रहे हैं। उन्हें नशे समेत अन्य बुराइयों की लत वहीं पर विभिन्न अपराधों में बंद उनसे बड़ी उम्र के किशोर लगवा रहे हैं। यही नहीं बाल सुधार गृह के कई बाल बंदियों के साथ अप्राकृतिक यौनाचार जैसे घृणित कार्य भी किये जाने बात सामने आती रही है। बच्चे प्रबंधन से इसकी शिकायत भी करते हैं लेकिन बदनामी के डर से इन शिकायतों को अंदर ही दबा दिये जाने के आरोप लगते रहे हैं। भय व शर्म के कारण बच्चे अपनी पीड़ा अभिभावकों को भी नहीं बता पाते हैं।

नियम के मुताबिक बाल सुधार गृह में 16 आयु वर्ग से नीचे के बाल कैदियों को रखा जाना है, लेकिन यहां 16-18 आयु वर्ग के 30 किशोर बंदियों को रखा जा रहा है। इनमे से अधिकतर कैदी सामूहिक दुष्कर्म, दुष्कर्म और हत्या जैसे बेहद संगीन जुर्म में बंद हैं। प्रावधान के अनुसार 16-18 आयु वर्ग के किशोर बंदियों को प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखना है। प्लेस आफ सेफ्टी पहले अस्थायी तौर पर बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल, होटवार, रांची के ही एक हिस्से में बनाया गया था। 2018 में मानवाधिकारों संगठनों की शिकायत पर जेल के प्लेस ऑफ सेफ्टी में रह रहे किशोर बंदियों को बाल सुधार गृह स्थानांतरित कर दिया गया। उस समय किशोर बंदियों की संख्या पांच थी जो कि डेढ़ साल में अब छह गुना अधिक हो गई है।

लाइब्रेरी बंद कर वहां भी रखा जा रहा है बंदियों को : बाल सुधार गृह में बच्चों के विकास व उनका ज्ञानवर्द्धन के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था की गई थी। जिसमें महापुरुषों की कहानी की किताबों के साथ अन्य अच्छी किताबें रखी जाती थीं। बच्चों और किशोरों को ये किताबें पढ़ने के लिए कहा जाता था, ताकि उनमें अच्छे संस्कार विकसित हो सकें। अब क्षमता से अधिक बंदियों के होने से बाल सुधार गृह में जगह की भी दिक्कत होने लगी। इस कारण अब लाइब्रेरी बंद कर वहां भी बंदियों को रखा जाता है। इनमें 30 वे भी हैं, जिन्हें प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखा जाना था। आने से ऐसे में सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि बच्चों में यहां कितना सुधार होता होगा।

> प्लेस ऑफ सेफ्टी के लिए जमीन को चिह्नित कर ली गई है। संबंधित क्षेत्र में चारदीवारी और भवन में निर्माण कार्य के बाद प्लेस ऑफ सेफ्टी को बाल सुधारगृह से अलग कर दिया जाएगा।
>
> **– सुमन सिंह, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, रांची**

दोहरे हत्याकांड के आरोपित भी यहीं हैं बंद : पिछले साल रातू रोड कब्रिस्तान में दोहरे हत्याकांड में संलिप्त 17 वर्षीय नाबालिग को भी रांची के डुमरदगा बाल सुधार गृह में ही रखा गया है। इसके अलावा कई अन्य किशोर बंदी संगीन अपराध में ट्रायल फेस कर रहे हैं।

सुधरने के बजाय नशे की चपेट में आ रहे बाल बंदी : अपराध में लिप्त बच्चों को बाल सुधार गृह इसलिए भेजा जाता है ताकि उनके मस्तिष्क से आपराधिक भावनाएं निकाल कर उन्हें सही रास्ते पर लाया जा सके। इसके ठीक उलट सुधार गृह में संगीन अपराध में लिप्त किशोरों के साथ बच्चे सुधरने के बजाय और बिगड़ रहे हैं। पाबंदियों के बावजूद सुधार गृह में धड़ल्ले से नशीला पदार्थ पहुंचता है और बच्चे भी इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। वहीं 16 से 18 साल के किशोर बंदी की दादागिरी चलती है। वे छोटे बंदियों से अपनी सेवा भी करवाते हैं। बात नहीं मानने पर छोटे बंदियों की बुरी तरह पिटाई करते हैं।

सेटेलाइट से की जाएगी हरिद्वार महाकुंभ में निगरानी

तैयारी

वर्ष 2021 में होने वाले महाकुंभ के लिए जियोस्पेसियल डाटाबेस तैयार करने में जुटा अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, नासा के सेटेलाइट वर्ल्डव्यू व भारतीय सेटेलाइट कार्टोसेट से लाइव निगरानी की तैयारी

सुमन सेमवाल, देहरादून

यह पहली बार होगा, जब महाकुंभ पर सेटेलाइट से नजर रखी जाएगी। इसकी शुरुआत हरिद्वार में वर्ष 2021 में होने वाले महाकुंभ से की जा रही है। कुंभ मेला क्षेत्र की व्यवस्थाओं के लिए लगाए जाने वाले सीसीटीवी कैमरे सेटेलाइट से भी लिंक किए जाएंगे। इसके लिए उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र (यूसैक) जियोस्पेसियल डाटाबेस तैयार करने में जुट गया है। सोमवार को इस संबंध में यूसैक निदेशक डॉ. एमपीएस बिष्ट ने मेलाधिकारी दीपक रावत के समक्ष प्रस्तुतीकरण भी दिया।

यूसैक के निदेशक डॉ. बिष्ट के अनुसार हाई रेजोल्यूशन सेटेलाइट डेटा के लिए भारतीय सेटेलाइट कार्टोग्राफ के साथ ही नासा के सेटेलाइट वर्ल्डव्यू की भी मदद ली जाएगी। नासा के सेटेलाइट से लाइव-व्यू के लिए हैदराबाद स्थित नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर (एनआरएससी) के पास आवेदन भी कर दिया गया है। सेटेलाइट की मदद से महाकुंभ मेला क्षेत्र में धरातल पर एक मीटर की किसी भी वस्तु को स्पष्ट देखा जा सकेगा।

सोमवार को हरिद्वार में मेलाधिकारी दीपक रावत के समक्ष दिए गए प्रस्तुतीकरण के दौरान यूसैक निदेशक ने बताया कि महाकुंभ क्षेत्र की सेटेलाइट मैपिंग कर ली गई है। साथ ही धरातल पर सभी अहम संरचनाओं, भवनों, प्रतिष्ठानों का डेटा एकत्रित किया जा रहा है। हर महत्वपूर्ण स्थलों के ग्राउंड कंट्रोल प्वाइंट्स एकत्रित कर उन्हें जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम (जीआइएस) के प्लेटफार्म पर तब्दील कर दिया गया है। लैटीट्यूड व लॉंगीट्यूड से एक क्लिक पर इनकी स्थिति स्पष्ट की जा सकती है।

मेला क्षेत्र के 41 सेक्टर में से 23 पर काम पूरा : महाकुंभ मेला क्षेत्र को 41 सेक्टर में बांटा गया है। इनमें से यूसैक ने 23 सेक्टर का डेटा एकत्रित कर लिया है। यूसैक निदेशक के अनुसार 15 मार्च तक सभी 41 सेक्टर पर काम पूरा कर दिया जाएगा।

आपात स्थिति या अधिक भीड़भाड़ को संभालने में मिलेगी मदद : पूरे कुंभ मेला क्षेत्र की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की व्यवस्था रहेगी। इसके लिए क्षेत्र के सभी प्रमुख प्रवेश व निकास मार्गों, खाली स्थानों आदि की जानकारी जुटाई जा रही है। इससे आपात स्थिति या अधिक भीड़ होने पर वैकल्पिक प्लान को लागू करने में भी मदद मिलेगी। निगरानी को सुगम बनाने के लिए मोबाइल एप भी तैयार की जा रही है। आम व्यक्ति भी इसकी मदद से मेला क्षेत्र की स्थिति से वाकिफ हो सकता है या मदद मांग सकता है। साथ ही ऑनलाइन निगरानी तंत्र को सीएम डैशबोर्ड व प्रमुख कार्यालयों से भी जोड़ा जाएगा।

प्रतीकात्मक

कुंभ स्नान में बहाव की भी निगरानी

यूसैक ऐसी व्यवस्था भी तैयार कर रहा है कि कुंभ स्नान के दौरान गंगा नदी में पानी के बहाव की भी निगरानी की जा सके। स्नान से पहले ही बहाव का आकलन कर लिया जाएगा।

सायरस मिस्त्री ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा

मुंबई : टाटा संस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के एक महीने के भीतर ही कंपनी के पूर्व चेयरमैन सायरस मिस्त्री फैसले पर विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे हैं। उन्होंने एक क्रॉस अपील के जरिये एनक्लैट के फैसले में विसंगतियों को दूर करने की मांग की है। दिसंबर में एनक्लैट ने मिस्त्री को टाटा संस के चेयरमैन पद से हटाने वाले फैसले को अवैध बताते हुए उनकी बहाली का आदेश दिया था। जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने एनक्लैट के फैसले पर रोक लगा दी थी। (प्रेट्र)

किसानों की मेहनत व वैज्ञानिकों के अनुसंधान से हम खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर ही नहीं निर्यातक बन गए हैं। हालांकि अभी इस दिशा में और भी कदम उठाने की जरूरत है।
— नरेंद्र सिंह तोमर
कृषि मंत्री

सेंसेक्स	निफ्टी	सोना (प्रति दस ग्राम)	चांदी (प्रति किलोग्राम)	डॉलर	क्रूड (ब्रेंट) प्रति बैरल
41,055.69	12,045.80	₹ 41,565	₹ 47,170	₹ 71.32	$ 57.23
▼ 202.05	▼ 67.75	▼ ₹ 233	▼ ₹ 157	▼ ₹ 0.05	

सॉयल हेल्थ कार्ड से बढ़ रही कृषि आमदनी

दिख रहा असर ▸ राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद ने जारी की पहली इंपैक्ट रिपोर्ट

खेती में प्रति एकड़ 30 हजार रुपये तक बढ़ी आमदनी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▸ वैज्ञानिकों व किसान संगठनों ने रिपोर्ट के आंकड़ों पर उठाए सवाल

प्रतीकात्मक फोटो

सरकार की महत्वाकांक्षी योजना सॉयल हेल्थ कार्ड के प्रभावों पर रिपोर्ट सोमवार को जारी कर दी गई। रिपोर्ट का दावा है कि इस योजना की वजह से देश के किसानों की आय में 30 हजार रुपये प्रति एकड़ तक का इजाफा हुआ है। रिपोर्ट का लब्बोलुआब यह है कि योजना से खेती की लागत घटी है और उत्पादन बढ़ा है। लेकिन कृषि वैज्ञानिकों, किसान संगठनों व विशेषज्ञों ने इस रिपोर्ट को लेकर कई गंभीर सवाल उठा दिए हैं। जानकार कह रहे हैं कि लागत घटने व उत्पादन बढ़ने के जो आंकड़े हैं उससे आमदनी में 30 हजार रुपये तक की वृद्धि संभव नहीं है।

नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल (एनपीसी) की यह रिपोर्ट देश के 19 राज्यों में 76 जिलों के 170 सॉयल हेल्थ टेस्टिंग लैब और 1,700 किसानों से पूछे सवालों के जवाब के आधार पर तैयार की गई है। देश के लगभग 12 करोड़ किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। एनपीसी ने यह रिपोर्ट फरवरी, 2017 में सरकार के समक्ष पेश कर दी थी, जिसे कृषि मंत्रालय की ओर से दो साल बाद अब जाकर सोमवार को जारी की गई है। किसान जागृति मंच के अध्यक्ष डॉक्टर सुधीर पंवार ने रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा कि जमीनी हकीकत से इसका कोई वास्ता नहीं है। एक एकड़ की खेती में बमुश्किल चार से पांच हजार रुपये की खाद लगती है। रिपोर्ट के मुताबिक 10 किलो यूरिया प्रति हेक्टेयर घट जाए और उत्पादन 30 फीसद बढ़ भी जाए तो भी आमदनी में 30 हजार रुपये तक की वृद्धि नहीं हो सकती है।

एनपीसी रिपोर्ट के मुताबिक खाद की बचत और उत्पादन बढ़ने से किसानों की आमदनी में वृद्धि दर्ज की गई है। नजीर के तौर पर दलहनी फसलों में अरहर की प्रति एकड़ खेती में 25 से 30 हजार रुपये की आमदनी हुई है। जबकि सूरजमुखी में 25 हजार रुपये, मूंगफली की खेती में 10 हजार रुपये और कपास में 12 हजार रुपये प्रति एकड़ की अतिरिक्त आमदनी होने का आकलन किया गया है। हालांकि रिपोर्ट में धान की खेती में 4,500 रुपये और आलू में 3,000 रुपये प्रति एकड़ तक की ही वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है।

खेती में बचत के तौर पर नाइट्रोजन वाली खाद यूरिया की खपत में कमी आई है। धान की खेती की लागत में नाइट्रोजन की बचत से 16 से 25 फीसद की बचत का अनुमान लगाया गया है। इससे प्रति एकड़ 20 किलो यूरिया की बचत हुई है। जबकि दलहनी फसलों की खेती में 15 फीसद कम खाद यानी 10 किलो यूरिया की कम खपत हुई है। तिलहनी फसलों में 10 से 15 फीसद कम यूरिया का प्रयोग किया गया, जिससे प्रति एकड़ नौ फीसद कम यूरिया का प्रयोग हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक मूंगफली की खेती में 23 किलो और अरंडी खेती में 30 किलो यूरिया प्रति एकड़ कम लगी।

सॉयल हेल्थ कार्ड के चलते धान, गेहूं और ज्वार की खेती में खाद के उचित प्रयोग से उनके उत्पादन में 10 से 15 फीसद तक की वृद्धि दर्ज की गई है। इसी वजह से दलहनी फसलों में 30 फीसद तक और तिलहनी फसलों में 40 फीसद तक की वृद्धि का आकलन किया गया है। चौधरी पुष्पेंद्र का कहना है कि एक एकड़ की खेती में इतनी अतिरिक्त आमदनी का होना वास्तविकता से परे है।

इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के पूर्व महानिदेशक डॉ. मंगला राय ने कृषि अनुसंधान व विकास पर घटते निवेश पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि वर्ष 2008-09 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 0.84 फीसद खर्च होता था, जो घटकर 0.53 फीसद हो गया है। उन्होंने बुनियादी सुविधाओं में सॉयल हेल्थ कार्ड पर एनपीसी की अध्ययन रिपोर्ट को जल्दबाजी में तैयार किया गया बताया।

सर्विस एक्सपोर्ट पर इनसेंटिव हटाने की तैयारी में सरकार

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकार सर्विस सेक्टर के एक्सपोर्ट को दिया जाने वाला प्रोत्साहन हटाने की तैयारी में है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सर्विसेज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम (एसईआइएस) के जरिये सर्विस सेक्टर के निर्यात को दिया जाने वाला प्रोत्साहन हटाने पर विचार हो रहा है। यह स्कीम देश के निर्यात को बढ़ावा देने में विफल रही है। इसके तहत सर्विस सेक्टर के निर्यात को टैक्स लाभ दिए जाते हैं। इसके लिए शुल्क में छूट या सर्टिफिकेट प्रदान किए जाते हैं।

गोयल ने कहा कि उद्योग जगत को सब्सिडी की मानसिकता से बाहर निकलने की जरूरत है। इससे लंबी अवधि के लिए देश का हित प्रभावित होता है। सरकार सर्विसेज के एक्सपोर्ट पर सब्सिडी देती है। मुश्किल से 2,200 कंपनियां यह सब्सिडी लेती हैं। इनमें से कुछ बड़े नाम हैं, जो हजारों करोड़ रुपये का मुनाफा कमाती हैं। इसलिए ऐसी कंपनियों को सब्सिडी देने का कोई मतलब नहीं है। गोयल ने कहा कि सब्सिडी नहीं मिलने पर भी यह कंपनियां एक्सपोर्ट बंद नहीं करेंगी। सही मायनों में पर्यटन जैसे उद्योगों को सब्सिडी की जरूरत है।

भारतीय उद्योग पर मंडराने लगा कोरोना का असर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▸ कई सेक्टर को सताने लगी है कच्चे माल की कमी
▸ चीन से सप्लाई सुचारू नहीं होने पर घरेलू उद्योग प्रभावित होने की आशंका

चीन में फैले कोरोना वायरस का असर भारतीय उद्योग पर मंडराने लगा है। चीन से कच्चे माल की सप्लाई जल्द ही सुचारू नहीं होने पर कई औद्योगिक क्षेत्रों को कच्चे माल की कमी होने की आशंका है। इससे निर्यात और घरेलू उद्योग दोनों पर विपरीत असर होगा। चीन भारतीय वस्तुओं के निर्यात के लिए भी बड़ा बाजार है। कई औद्योगिक संगठनों ने भारत सरकार से उद्योगों को बचाने के लिए वैकल्पिक उपाय करने की मांग की है। कोरोना फैलने के बाद चीन में पिछले 15 दिनों से औद्योगिक इकाइयां बंद हैं। इन इकाइयों को चीन ने 17 फरवरी से खोलने का एलान किया था, लेकिन अब आगामी 25 फरवरी से इन्हें खोलने की बात कही जा रही है।

यूं तो चीन के मुकाबले भारत के उद्योगों को विकसित करने के लिए यह एक सटीक अवसर के रूप में भी देखा जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो हालात हैं उसमें कोरोना ने उद्योग व्यापार को बीमार करना शुरू कर दिया है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशंस (फियो) के अध्यक्ष शरद कुमार सर्राफ कहते हैं - 'अभी यह कहना मुश्किल है कि कोरोना वायरस की वजह से भारत के निर्यात में कितनी कमी आएगी, लेकिन इतना तय है कि इसका असर दिखेगा। उन्होंने कहा कि जनवरी माह में भी वस्तुओं के निर्यात में पिछले साल के जनवरी के मुकाबले 1.6 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। इस गिरावट में चीन के कोरोना वायरस का भी हाथ था।' फियो के पूर्व अध्यक्ष एवं चमड़ा निर्यातक रफीक अहमद कहते हैं, चमड़े व उत्पाद के निर्माण के लिए कच्चे माल की कमी होने लगी है और काफी हद तक कच्चे माल के लिए हम चीन पर निर्भर है।

इंजीनियरिंग गुड्स के निर्यातक एवं फियो के पूर्व अध्यक्ष एससी रल्हन कहते हैं- 'चीन से आने वाले कच्चे माल की कमी दिखने लगी है। नायलॉन जैसे कई उत्पाद बाजार में नहीं मिल रहे हैं।' कॉन्फेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया का कहना है कि कोरोना वायरस से देश के व्यापार और लघु उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव दिखना शुरू हो गया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान परिस्थितियों में चीन भारत के लिए सबसे बड़ा निर्यातक देश है और आपूर्ति श्रृंखला बनाए रखने के लिए, सरकार को तत्काल उपाय करने की जरूरत है। आम तौर पर आयातक सामानों के स्टॉक को दो महीने तक बफर स्टॉक के रूप में रखते हैं और अब स्टॉक खत्म होने के कगार पर हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक कोरोना की वजह से मुख्य रूप से खिलौने, फर्नीचर, बिल्डर हार्डवेयर, फुटवियर, कपड़े, फर्निशिंग फैब्रिक, एफएमसीजी उत्पाद, गिफ्ट का सामान, घड़ी, मोबाइल, मोबाइल उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स, बिजली के सामान, चिकित्सा और सर्जिकल उपकरणों, सर्जिकल सामान, फार्मास्युटिकल्स, आयरन और स्टील के उत्पाद प्रभावित होंगे।

मेक इन इंडिया अभियान को हो सकता है फायदा

चीनी कोरोना वायरस की वजह से भले ही आयातित कच्चे माल की कमी हो रही है, लेकिन इससे कई भारतीय उद्योग को लाभ मिल सकता है। क्लोथ मैन्यूफैक्चरिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के पदाधिकारी मोहन सदवानी कहते हैं, चीन से आने वाले फैब्रिक की सप्लाई प्रभावित हो गई है, अगर यही हाल रहा तो चीनी कच्चे माल से गारमेंट बनाने वाले निर्माता भारत में तैयार होने वाले फैब्रिक लेने लगेंगे। हालांकि इससे उनकी लागत अधिक आएगी। गारमेंट में इस्तेमाल होने वाले कई विशेष प्रकार के फैब्रिक चीन से आते हैं। अभी भारत में उन विशेष फैब्रिक का उत्पादन मामूली होता है। लेकिन चीनी हालत में सुधार नहीं होने पर इस प्रकार के फैब्रिक का उत्पादन भारत में भी शुरू हो सकता है। इंजीनियरिंग गुड्स के निर्यातकों ने बताया कि चीन से आने वाले कच्चे माल भारत में निर्मित कच्चे माल के मुकाबले सस्ते होते हैं, लेकिन चीन से माल नहीं आने की स्थिति में उन्हें भारत में निर्मित कच्चे माल से ही काम चलाना होगा, भले ही उसकी कीमत अधिक क्यों न हो। ऐसे में, निश्चित रूप से भारतीय घरेलू उद्योग को फायदा होगा।

नए फिनटेक प्रोडक्ट की लाइव टेस्टिंग का रास्ता साफ

मुंबई, प्रेट्र : बाजार नियामक सेबी ने फिनटेक (फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी) के विकास में लगी कंपनियों को उनके नए उत्पादों, सेवाओं और कारोबारी मॉडल का चुनिंदा ग्राहकों के बीच वास्तविक परिस्थितियों में परीक्षण की अनुमति दे दी है। सोमवार को सामने आए सेबी के इस निर्णय से वित्तीय उत्पाद प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इनोवेशन को प्रोत्साहन मिलेगा। नियामक ने कहा कि शुरू में सेबी के पास पंजीकृत इकाइयां ही इस 'सैंडबॉक्स' (प्रायोगिक क्षेत्र) व्यवस्था में भाग लेने की पात्र होंगी।

नियामकीय सैंडबॉक्स व्यवस्था में कंपनियां नए उत्पादों, प्रक्रियाओं और कारोबारी मॉडलों का वास्तविक माहौल सीधे परीक्षण कर सकती है। इसके लिए सीमित संख्या में पात्र ग्राहकों को जोड़ने की सुविधा होती है। यह परीक्षण सीमित अवधि के लिए होगा और इसमें कुछ नियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन से ढील दी जाएगी।

सेबी के निदेशक मंडल की बैठक में नियामकीय सैंड बॉक्स के लिए विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग की अनुमति देने का निर्णय किया गया है। यानी नियमित इकाइयों को उन गतिविधियों के समाधानों के परीक्षण की भी अनुमति होगी जिसके लिए वे पंजीकृत नहीं हैं। सेबी ने कहा कि इस प्रकार के परीक्षण के लिए सीमित पंजीकरण की मंजूरी दी जाएगी। बाद में नियामक द्वारा निर्धारित नहीं होने वाले फिनटेक स्टार्ट-अप और अन्य इकाइयों को भी इसकी अनुमति दी जा सकती है।

सैंडबॉक्स का मकसद

प्रस्तावित नियामकीय सैंडबॉक्स का मकसद नए कारोबारी मॉडल और प्रौद्योगिकी के लिए परीक्षण आधार उपलब्ध कराना है जिससे निवेशकों, भारतीय बाजार और कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था को लाभ है। इस व्यवस्था में पात्र इकाइयों को वित्तीय प्रौद्योगिकी के वास्तविक परिवेश में कुछ ग्राहकों के साथ प्रयोग की अनुमति होती है।

क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत का विकास दर अनुमान फिर घटाया

नई दिल्ली, प्रेट्र : क्रेडिट रेटिंग और मार्केट रिसर्च कंपनी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने जनवरी से शुरू हुए कैलेंडर वर्ष 2020 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 5.4 प्रतिशत कर दिया है। इससे पहले एजेंसी ने इस वर्ष भारत की जीडीपी के 6.6 प्रतिशत की दर से विकास का अनुमान लगाया था।

मूडीज ने वैश्विक आर्थिक परिदृश्य पर अपनी नई रिपोर्ट में कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था में पिछले दो साल में सुस्ती आई है। हालांकि चालू तिमाही में अर्थव्यवस्था की रफ्तार सुधने की उम्मीद है। रेटिंग एजेंसी ने कहा, 'हमारा अनुमान है कि आर्थिक वृद्धि सुधरने की गति पहले के अनुमान के मुकाबले धीमी होगी। इसीलिए हमने 2020 की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 6.6 प्रतिशत से घटाकर 5.4 और 2021 का 6.7 प्रतिशत से घटाकर 5.8 प्रतिशत कर दिया है।'

भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2019 में पांच प्रतिशत रही है। मूडीज ने कहा है कि कमजोर अर्थव्यवस्था और कर्ज वृद्धि में नरमी का एक-दूसरे पर प्रतिकूल असर होता है। ऐसे में आर्थिक गति तेजी से सुधरने का अनुमान मुश्किल है।

किस बारे में क्या कहा?

बजट 2020-21 : मांग सुस्त पड़ने की मुश्किल से निपटने के लिए केंद्रीय बजट में ठोस प्रोत्साहन उपाय नहीं किए गए हैं। अन्य देशों के समान प्रकार के नीतिगत उपायों के अनुभव से पता चलता है कि जब लोग जोखिम से बचने के मूड में होते हैं तो करों में कटौती से उपभोग और निवेश में बढ़ोतरी की संभावना कम रहती है।

मौद्रिक नीति : मूडीज ने कहा कि उसे रिजर्व बैंक की तरफ से नीतिगत ब्याज दरों के मामले में नरम रुख बरकरार रखे जाने की उम्मीद है। हालांकि खुदरा कीमतों के हिसाब से महंगाई दर यदि आगे भी ऊंची बनी रहती है तो केंद्रीय बैंक के लिए रेपो रेट जैसी नीतिगत दरों में और कटौती करना चुनौतीपूर्ण मामला हो जाएगा।

वैश्विक अर्थव्यवस्था : कोरोना वायरस के चलते इस साल वैश्विक वृद्धि में स्थिरता की उम्मीद धूमिल हुई है। मूडीज ने जी-20 देशों की आर्थिक वृद्धि 2020 में 2.4 प्रतिशत और 2021 में 2.8 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। चीन की वृद्धि दर इस साल 5.2 प्रतिशत और अगले साल 5.7 प्रतिशत रहने का अंदाजा लगाया गया है।

मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस का अंदाजा

साल 2020	
ताजा अनुमान	5.4%
पुराना अनुमान	6.6%
साल 2021	
ताजा अनुमान	5.8%
पुराना अनुमान	6.7%

निवेश सलाहकार बनने के मानक होंगे कड़े

मुंबई, प्रेट्र : पूंजी बाजार नियामक सेबी ने निवेशकों के हित को ध्यान में रखते हुए निवेश सलाहकार के लिए योग्यता नियमों में सुधार करने का फैसला किया है। इसके तहत नियमों को कड़ा बनाने और अधिकतम फीस तय की जाने की तैयारी है। निवेश सलाहकार के रूप में पंजीकृत नहीं होने की अवस्था में स्वतंत्र 'फाइनेंशियल एडवाइजर' या 'वेल्थ एडवाइजर' जैसे टाइटल के प्रयोग पर रोक लगाने की बात भी कही गई है।

▸ टाइटल के प्रयोग पर लगेगी पाबंदी, फीस की ऊपरी सीमा भी होगी तय

प्रतीकात्मक फोटो

सेबी ने बताया कि नए नियमों के मुताबिक सलाह और वितरण की सेवाएं किसी एक व्यक्तिगत सलाहकार द्वारा दिए जाने की अनुमति नहीं होगी। वितरण और सलाह संबंधी गतिविधियों को अलग करना होगा। सेबी के यह नियम सभी सुझावों से परामर्श के बाद तैयार किए गए हैं। इसका मकसद फीस के भुगतान में पारदर्शिता लाना और निवेशकों से वसूल की जाने वाली फीस की ऊपरी सीमा तय करना है। नियामक ने इसके लिए चार परामर्श पत्र जारी किए थे। अंतिम परामर्श पत्र आम लोगों की सलाह लेने के लिए इसी वर्ष जनवरी में जारी किया गया था।

इस बीच सेबी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के आइपीओ आवेदन की जांच जारी होने की बात कही है। इससे पहले एनएसई ने आइपीओ के लिए सेबी के पास आवेदन की जानकारी दी थी। यह आइपीओ ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) के रूप में होगा, जहां मौजूदा शेयरधारक अपनी हिस्सेदारी बेच सकेंगे। इससे पहले एनएसई अपनी इस योजना की समीक्षा कर चुका है। एक्सचेंज ऊपर को-लोकेशन सुविधा का गलत प्रयोग करके कुछ ट्रेडिंग मेंबर्स को विशेष पहुंच देने का आरोप है।

कार्वी जैसे मामलों को रोकने के लिए आएगा सर्कुलर : सेबी प्रमुख अजय त्यागी ने कहा है कि नियामक जल्द ही कार्वी जैसे मामलों से बचने के लिए एक सर्कुलर जारी करेगा। कार्वी ब्रोकिंग सर्विसेज लिमिटेड (केएसबीएल) पर ग्राहकों की इजाजत के बिना उनकी सिक्युरिटीज का उपयोग निजी लाभ के लिए करने का आरोप है।

त्यागी ने कहा कि कार्वी मामले में निवेशकों के हित का ख्याल रखा जाएगा। सेबी पहले ही कार्वी को पूंजी बाजार में प्रतिबंधित कर चुका है। इस दौरान सेबी प्रमुख ने बताया कि नियामक मिड-कैप और स्मॉल-कैप म्युचुअल फंड स्कीम्स को दोबारा श्रेणीबद्ध करने की तैयारी कर रहा है। जानकारों का मानना है कि इस सुधार के जरिये म्युचुअल फंड के निवेश का दायरा बढ़ाया जा सकता है। इससे पहले वर्ष, 2017 में सेबी ने लार्ज-कैप, मिड-कैप और स्मॉल-कैप को परिभाषित किया था।

गांव व कृषि क्षेत्र पर इकोनॉमी की मजबूती का दारोमदार : तोमर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : कृषि व किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गांव और कृषि जैसे क्षेत्र की महत्ता गिनाते हुए कहा कि इन्हीं क्षेत्रों पर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का दायित्व है। इसलिए इनके तानेबाने को और सुदृढ़ करने की जरूरत है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को झटकों से उबरने में मदद मिल सके।

नेशनल सीड कांग्रेस के समारोह के दौरान कृषि क्षेत्र की हालत को बेहतर करार देते हुए तोमर ने कहा कि अभी भी इसे लंबी यात्रा तय करनी है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की चुनौतियों से निपटा जा सकता है। किसानों की मेहनत और वैज्ञानिकों के अनुसंधान का नतीजा है कि देश खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि निर्यातक हो गया है। इसमें बीज तैयार करने वाले निजी निवेशकों की भूमिका भी अहम रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी को बढ़ाकर दोगुना करने की मंशा का जिक्र करते हुए, तोमर ने कहा कि इसके लिए बीजों की महत्ता सबसे अधिक है।

विदेश भ्रमण पैकेज पर अप्रैल से लगेगा टैक्स

राजीव कुमार, नई दिल्ली

▸ आइटीआर फाइलिंग के दौरान क्लेम कर सकेंगे यह टैक्स
▸ विदेश जाने के नाम पर कालेधन के इस्तेमाल पर लगाम के लिए कवायद

प्रतीकात्मक फोटो

अगले वित्त वर्ष (2020-21) की शुरुआत से विदेश यात्रा का पैकेज लेने पर पांच फीसद टैक्स देना होगा। नए नियमों के मुताबिक पैकेज की कुल राशि का पांच फीसद टैक्स कलेक्शन एट सोर्स (टीसीएस) के तहत अलग से देना होगा। पैकेज लेने वाले व्यक्ति के पास अगर पैन कार्ड नहीं है तो उसे पैकेज की राशि का 10 फीसद टीसीएस के रूप में देना होगा।

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देश में 1.5 करोड़ लोग सरकार को टैक्स देते हैं जबकि तीन करोड़ लोग हर साल में विदेश भ्रमण करते हैं। पर्यटन मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में पांच करोड़ भारतीयों के विदेश यात्रा पर जाने का अनुमान है। ऐसे में नई कवायद विदेश यात्रा के नाम पर कालेधन के इस्तेमाल पर निगरानी के लिए है। अधिकारियों के मुताबिक साल में कई बार विदेश यात्रा करने के बाद भी लोग सरकार को अपनी यात्राओं के बारे में जानकारी नहीं देते। अब विदेश यात्रा करने वाला हर शख्स सरकार की रडार पर होगा।

एक टैक्स विशेषज्ञ ने बताया कि मान लीजिए आपका पैकेज एक लाख रुपये का है तो पैकेज देने वाली कंपनी आपसे पांच हजार रुपये अलग से टीसीएस के नाम पर लेगी जो सरकार के खाते में जमा हो जाएगा। सीए राज चावला ने बताया कि इनकम टैक्स रिटर्न (आइटीआर) दाखिल करने के दौरान टीसीएस देने वाला व्यक्ति उस राशि को क्लेम कर सकता है। लेकिन इसके लिए, उसे अपने आइटीआर में विदेश यात्रा का जिक्र करना होगा। सरकार को अपनी आय कम दिखाने वाले लोग अमूमन अपने आइटीआर में विदेश यात्रा का जिक्र करने से बचते हैं। चावला ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति विदेश जाने के लिए खुद टिकट लेता है और अपना इंतजाम खुद करता है तो उसे टीसीएस नहीं देना होगा। उन्होंने बताया कि टीसीएस कटते ही इनकम टैक्स विभाग के पास इस बात का अलर्ट चला जाएगा।

सीए प्रवीण शर्मा के मुताबिक सरकार के इस फैसले से स्पांसरशिप के तहत सरकारी एवं निजी कंपनियों के अधिकारी भी विदेश यात्रा करने से बचेंगे। क्योंकि उन्हें अपने खाते से टीसीएस देना होगा, भले ही उनके कुल पैकेज का भुगतान कोई और कर रहा हो।

स्टॉक केंद्रित बिकवाली के चलते शेयर बाजारों पर दबाव

मुश्किल हालात

कोरोना वायरस के चलते भी बाजारों में है चिंता का माहौल, सेंसेक्स 202 अंक, निफ्टी 68 अंक गिरावट के साथ बंद

मुंबई, एजेंसियां : स्टॉक केंद्रित बिकवाली के चलते घरेलू शेयर बाजारों पर दबाव देखने को मिला। सोमवार को लगातार तीसरे सत्र में देश के प्रमुख शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। इस दौरान बीएसई के 30 शेयरों वाले सेंसेक्स में 202.05 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। इंट्रा-डे के दौरान 390 अंकों के दायरे में डोलते रहने के बाद यह 41,055.69 के स्तर पर स्थिर हुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला निफ्टी 67.75 अंक फिसलकर 12,045.80 पर बंद हुआ।

सेंसेक्स पैक में ओएनजीसी के शेयरों में सबसे ज्यादा 3.20 परसेंट की गिरावट दर्ज की गई। सन फार्मा, एनटीपीसी, बजाज ऑटो और एचडीएफसी के शेयर भी 2.37 परसेंट तक नीचे आकर स्थिर हुए। हालांकि टाइटन, नेस्ले, टीसीएस, कोटक बैंक, टाटा स्टील के स्टॉक्स में 1.86 परसेंट तक की बढ़त देखी गई। सेंसेक्स पैक में 10 स्टॉक्स लाल और 11 हरे निशान पर रहे। सेक्टोरल इंडेक्स में ऑयल एंड गैस कंपनियों के स्टॉक्स में सबसे ज्यादा 2.39 परसेंट की गिरावट आई। रियल्टी और हेल्थकेयर के स्टॉक्स भी गिरकर बंद हुए। इसके विपरीत आइटी और टेक कंपनियों के शेयरों में तेजी का रुख रहा।

जानकारों के मुताबिक मूडीज द्वारा जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान घटाने के कारण निवेशकों का मनोबल कमजोर हुआ। इसके अलावा कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। इससे भी शेयर बाजारों पर दबाव बना है। सोमवार को एशिया के अन्य शेयर बाजारों में मिलाजुला रुख देखने को मिला। इस बीच डॉलर के मुकाबले रुपये के भाव में आठ पैसे का सुधार हुआ। सोमवार को एक डॉलर 71.29 रुपये के भाव पर बिका।

इस शेयरों में रही गहमागहमी

रिलायंस इन्फ्रा : तिमाही मुनाफे में बढ़ोतरी के चलते सोमवार को कंपनी के शेयर बीएसई में कंपनी के शेयर 9.49 परसेंट की तेजी के साथ 21.35 रुपये प्रति शेयर के भाव पर बिके। वहीं एनएसई में यह 10 परसेंट उछलकर 21.45 रुपये पर स्थिर हुए। इससे पहले कंपनी ने बताया था कि चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के दौरान इसका शुद्ध मुनाफा 18 परसेंट बढ़कर 345.51 करोड़ रुपये रहा।

प्रतीकात्मक फोटो

ओएनजीसी : सोमवार को इस सार्वजनिक कंपनी के शेयरों में तीन परसेंट से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। बीएसई में कंपनी के शेयर 3.20 परसेंट गिरकर 100 रुपये प्रति शेयर पर बिके। वहीं एनएसई में यह 3.19 परसेंट लुढ़क गए। पिछले शुक्रवार को इस सरकारी ऑयल कंपनी ने बताया था कि चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के दौरान इसके शुद्ध मुनाफे में 49.8 परसेंट की गिरावट दर्ज की गई है।

मुथूट फाइनेंस : जोरदार तिमाही प्रदर्शन के बाद सोमवार को कंपनी के शेयरों में रिकॉर्ड तेजी देखने को मिली। इस दौरान बीएसई में कंपनी के शेयर 17.04 परसेंट उछाल के साथ 873.85 रुपये और एनएसई में 17.75 परसेंट की तेजी के साथ 879.50 रुपये प्रति शेयर के भाव पर बंद हुए। गौरतलब है कि कंपनी को चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के दौरान 803 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा हुआ है। यह पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही के दौरान हुए मुनाफे से 66 परसेंट अधिक है।

भूषण पावर के अधिग्रहण में जेएसडब्ल्यू की बाधा टली

नई दिल्ली, प्रेट्र : जेएसडब्ल्यू स्टील को भूषण पावर मामले में एनक्लैट की ओर से बड़ी राहत मिली है। कंपनी को भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड (बीपीएसएल) के अधिग्रहण के लिए नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनक्लैट) की ओर से हरी झंडी मिल गई है। जेएसडब्ल्यू को बीपीएसएल के मुकदमों से भी छुटकारा मिल गया है। 19,700 करोड़ की इस डील में एनक्लैट ने जेएसडब्ल्यू को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई से छूट की बात कही है। जस्टिस जेएस मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली एनक्लैट की दो सदस्यीय बेंच ने कहा कि बीपीएसएल द्वारा की गई गड़बड़ियों का भार जेएसडब्ल्यू पर नहीं आने दिया जाएगा।

इस दौरान एनक्लैट ने बीपीएसएल के पूर्व प्रमोटर्स पर चल रहा मनी लॉड्रिंग का मामला जारी रहने की बात भी कही। ट्रिब्यूनल ने परिचालन कर्जदाताओं द्वारा दावा बढ़ाने की याचिका को खारिज किया। बेंच ने कहा कि इन्सॉल्वेंसी प्रक्रिया के दौरान बीपीएसएल द्वारा सभी साधनों से जुटाया गया कुल राजस्व जेएसडब्ल्यू स्टील के खाते में जाएगा। पिछले वर्ष अक्टूबर में ईडी ने मनी लॉड्रिंग के मामले में कंपनी की 4,025 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति को जब्त कर लिया था।

इससे पहले रिजॉल्यूशन की मंजूरी के बाद जेएसडब्ल्यू ने कंपनी की संपत्ति के बचाव के लिए एनक्लैट का रुख किया था। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को तत्काल बीपीएसएल की संपत्ति रिलीज करने का आदेश दिया था। उस आदेश में कंपनी के रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल के हक में संपत्ति रिलीज करने की बात कही गई थी। उस दौरान ईडी ने कहा था कि उसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉड्रिंग एक्ट के तहत बीपीएसएल की संपत्ति जब्त करने का अधिकार है।

18 लाख रुपये की ठगी से बचा लिया भारतवंशी टैक्सी चालक राज सिंह ने कैलिफोर्निया में एक बुजुर्ग अमेरिकी महिला को। पुलिस ने राज को 50 डॉलर का गिफ्ट कार्ड भेंट किया। साथ ही कहा कि वह 'ग्रेट सिटिजन अवार्ड' के हकदार हैं।

40 साल पहले किताब में किया था वुहान-400 वायरस का जिक्र

कोरोना वायरस क्या एक जैविक हथियार है, जिसे वुहान 400 के नाम से चीन ने विकसित किया है? यह सवाल सोशल मीडिया पर कुछ दिनों से घूम रहा है और अब कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने यही सवाल अपने ट्वीट के माध्यम से किया है। कोरोना से हजारों लोगों के संक्रमण की जद में आने और सैकड़ों की मौत के बाद दुनिया में डर का माहौल है। वहीं चीन अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद इस पर काबू नहीं पा सका है। अपने सवाल के साथ साक्ष्य के रूप में मनीष तिवारी ने एक पुस्तक का जिक्र किया है और उसकी तस्वीर के साथ इसके कुछ अंशों को पढ़ने के लिए भी कहा है। इस पुस्तक में वुहान-400 वायरस का जिक्र है।

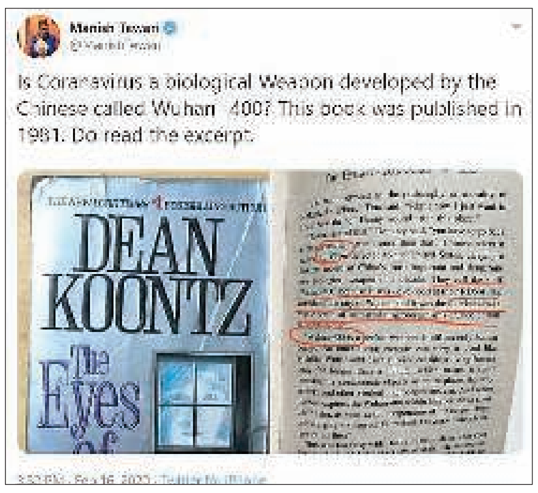

द आइज ऑफ डार्कनेस किताब

अमेरिकी लेखक डीन कुंट्ज ने 1981 में एक पुस्तक लिखी थी। इसका नाम 'द आइज ऑफ डार्कनेस' है और इसमें वुहान-400 वायरस का जिक्र है। साथ ही किताब ये भी बताती है कि इस वायरस को लेबोरेटरी के जरिए जैविक हथियार के रूप में विकसित किया गया था।

ऐसे सामने आई किताब

एक ट्विटर यूजर डेरेन प्लेमाउथ इस अप्रकट संदर्भ को सोशल मीडिया तक ले आए हैं। उन्होंने किताब के आवरण पृष्ठ और एक पृष्ठ की तस्वीर अपने अकाउंट से शेयर की है। किताब में साफ नजर आता है कि इसमें वुहान-400 वायरस का जिक्र किया गया है। साथ ही उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि यह अजीब दुनिया है, जिसमें हम रह रहे हैं।

सन्न सोशल मीडिया

वुहान वायरस के बारे में इस किताब में पढ़कर के हर कोई सन्न रह गया। कई लोगों ने इसके बारे में अपनी राय रखी है। बहुत से लोगों ने कहा कि यह एक संयोग भर है, लेकिन बहुत से लोगों को लगता है कि यह महज संयोग भर नहीं है बल्कि इसमें कुछ न कुछ सत्यता जरूर है। एक शख्स ने लिखा है कि किसी भी कल्पना में थोड़ी बहुत सत्यता छुपी होती है।

यह है किताब में

द आईज ऑफ डार्कनेस एक थ्रिलर उपन्यास है। इसमें एक मां यह पता लगाने की कोशिश करती है कि क्या उसका बेटा वास्तव में एक साल पहले मर गया था या फिर वो अभी भी जीवित है। वह अपने बेटे का पता लगाने का फैसला करती है।

उन अंशों में ये लिखा है

मनीष तिवारी ने किताब के जिन अंशों का जिक्र किया है उसमें लिखा है कि इसे वुहान-400 कहा गया है क्योंकि वुहान के बाहर स्थित आरडीएनए लैब में विकसित किया गया है। यह वायरस उस लैब में मानव निर्मित सूक्ष्मजीवों का चार सौवां स्ट्रेन था।

डीन कुंट्ज को जानिए

अमेरिकी लेखक डीन कुंट्ज दुनिया में जाना पहचाना नाम है। एक शब्द में कहें तो उनकी शब्दों की दुनिया सस्पेंस थ्रिलर के इर्द गिर्द सिमटी है, जो आतंक, फंतासी, रहस्य और हास्य व्यंग्य का पुट लिए होती है। उनकी कई किताबें न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर्स की लिस्ट में रहीं हैं। अपने शुरुआती लेखन में उन्होंने कई उपनामों से लिखा। उनकी किताबों की 38 भाषाओं में 50 करोड़ से ज्यादा प्रतियां बिक चुकी हैं। उनकी प्रमुख पुस्तकों में डेमन सीड, ओड थॉमस, वॉचर्स, फैंटम्स, इंटेसिटी प्रमुख हैं।

न्यूज गैलरी

पाकिस्तान में लापता रिपोर्टर का शव नहर में मिला

कराची : पत्रकारों के लिए खतरनाक माने जाने वाले पाकिस्तान में एक रिपोर्टर की हत्या कर दी गई। पाकिस्तान के दक्षिण-पश्चिम सिंध प्रांत में लापता होने के कुछ घंटे बाद ही एक पत्रकार का शव नहर में पाया गया। 56 वर्षीय अजीज मेमन एक स्थानीय टीवी के लिए बतौर रिपोर्टर और कैमरामैन काम करते थे। वह रविवार को काम पर निकले थे, लेकिन फिर लापता हो गए। अजीज के परिवार ने कहा कि उनकी निर्मम हत्या की गई, लेकिन यह पता नहीं कि इसके पीछे किसका हाथ है। पुलिस प्रमुख मुहम्मद फारुख ने बताया कि भारतीय युवक की गांव के समीप एक नहर से शव बरामद किया गया। अभी तक अजीज के अपहरण और हत्या की किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है। जबकि अजीज के भाई अब्दुल हाफिज ने कहा, 'उन्होंने पिछले साल यह खबर दिखाई दी थी कि इलाके के एक नेता ने एक विपक्षी रैली में स्थानीय लोगों को शामिल होने के लिए पैसे दिए थे। इसके बाद मेरे भाई को जान से मारने की धमकी मिली थी।' (एपी)

यूएई में पत्नी को बचाने में झुलसे भारतीय की मौत

दुबई: संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में घर में लगी आग से पत्नी को बचाने में एक भारतीय युवक की मौत हो गई। वह 90 फीसद जल गया था। केरल निवासी इस दंपती यूएई के उम अल कुवैन शहर में रहता था। खलीज टाइम्स में सोमवार को प्रकाशित खबर के अनुसार, भारतीय अनिल नैनन (32) एक हफ्ते पहले आग में घिरी पत्नी नीनू को बचाने में बुरी तरह झुलस गया था। उसकी पत्नी भी झुलस गईं, लेकिन उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। (प्रेट्र)

सीरियाई बलों ने अलेप्पो से विद्रोहियों को खदेड़ा

अम्मान : सीरिया की सरकारी सेना को देश के पश्चिमोत्तर प्रांत अलेप्पो से विद्रोहियों को खदेड़ने में बड़ी कामयाबी मिली है। सेना का प्रांत के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा हो गया है। सीरियाई सेना को यह सफलता ऐसे समय मिली, जब रूस और तुर्की के बीच पूर्वोत्तर सीरिया के मसले पर नए दौर की वार्ता शुरू होने वाली है। सीरियाई निगरानी मानवाधिकार संस्था के अनुसार, रविवार को रूसी लड़ाकू विमानों ने अनादन शहर समेत अलेप्पो के कई इलाकों में हवाई हमले किए। इसके बाद ईरान समर्थित मिलिशिया की मदद से सीरियाई बलों ने प्रांत के ज्यादातर हिस्से पर कब्जा कर लिया। (रायटर)

अफगान सैन्य अड्डे पर हमले में पांच सैनिकों की मौत

काबुल: अफगानिस्तान में एक सैन्य अड्डे पर तालिबान आतंकियों के हमले में पांच सैनिकों की मौत हो गई। यह हमला ऐसे समय किया गया, जब अमेरिका और तालिबान के बीच इस माह के आखिर तक शांति समझौते पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। तालिबान आतंकियों ने रविवार को कुंदुज प्रांत के शोरा खाक इलाके में एक सैन्य अड्डे को निशाना बनाया। अफगान रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा, 'पांच सैनिक शहीद और तीन घायल हो गए।' कुंदुज पुलिस के प्रवक्ता एनहामुद्दीन रहमानी ने बताया कि दोनों पक्षों में कई घंटे तक लड़ाई चली और कई हताहत हुए। (एएफपी)

कोरोना का साया चीन के संसद सत्र पर भी, 105 और मरे

सुधरे नहीं हालात ▶ संक्रमण के 2,048 नए मामले सामने आए, कुल संख्या 70,548 हुई

बीजिंग, एजेंसियां : कोरोना वायरस की महामारी की छाया चीन के संसदीय सत्र पर पड़ती दिख रही है। सरकारी मीडिया की मानें तो पांच मार्च को होने वाले संसदीय सत्र को स्थगित किया जा सकता है। उधर, चीन में सोमवार को 105 और लोगों की वायरस संक्रमण के चलते मौत हो गई। इस तरह मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,770 हो गई। वहीं राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने कहा है कि संक्रमण के 2,048 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमित लोगों की कुल संख्या 70,548 हो गई है।

पिछले साल दिसंबर में हुई आधिकारिक घोषणा के अनुसार, चीन की सर्वोच्च विधायिका नेशनल पीपुल्स कांग्रेस (एनपीसी) का सालाना सत्र बीजिंग में पांच मार्च को होने वाला है। सरकारी अखबार चाइना डेली की खबर के मुताबिक, कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए एनपीसी की स्थायी समिति इस पूर्ण सत्र को टालने पर विचार करेगी। एनपीसी का सत्र टाला जाना एक अभूतपूर्व फैसला होगा। बता दें कि सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना (सीपीसी) के वार्षिक एजेंडे में दो सत्र सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें एक राष्ट्रीय बजट का सत्र होता है।

जापान में क्रूज में फंसे 99 और लोग संक्रमित : जापान में खड़े क्रूज में 99 और लोगों के संक्रमित होने का पता चला है। इस तरह जहाज पर कोरोना वायरस से अब तक 454 लोग संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि इन आंकड़ों में वह 14 अमेरिकी भी शामिल हैं, जिनका टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद भी उन्हें स्वदेश जाने की अनुमति दी गई है। उधर, जापान से अमेरिकी लोगों को लेकर गया विमान सोमवार तड़के 2.30 बजे नार्थ कैलिफोर्निया स्थित ट्रैविस एयरफोर्स बेस पर पहुंच गया। यहां पर पहुंचते ही सभी को आइसोलेशन में भेजा दिया गया है। क्रूज में 380 अमेरिकी नागरिक सवार थे। बता दें कि डायमंड प्रिंसेज नामक यह जहाज पांच फरवरी को योकोहामा बंदरगाह पर पहुंचा था। हालांकि शिप में कोई संक्रमित व्यक्ति नहीं था, लेकिन हांगकांग में उतरे एक व्यक्ति का टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद इसे बंदरगाह पर ही रोक लिया गया था। इसके आइसोलेशन की अवधि 19 फरवरी को खत्म हो रही है।

जापान में नए सम्राट के जन्मदिन का उत्सव रद : जापान में संक्रमण के 65 नए मामले सामने आए हैं। इससे बचने के लिए अधिकारियों ने लोगों से एक जगह एकत्र होने से बचने की सलाह दी है। इसी को ध्यान में रखकर 23 फरवरी को जापान के नए सम्राट के जन्मदिन के सार्वजनिक उत्सव को रद कर दिया गया है। इसके साथ ही एक मार्च को होने वाली टोक्यो मैराथन में भाग लेने के लिए संख्या सीमित करने या आयोजन को रद करने पर आयोजक विचार कर रहे हैं। मैराथन में भाग लेने के लिए 38,000 लोगों ने अपना पंजीकरण कराया है।

चीनी राष्ट्रपति के दावे पर लोगों ने उठाए सवाल : संक्रमण के शुरुआती दौर में ही उस पर काबू पाने के चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के दावे इन दिनों सवालों के घेरे में आ गए हैं। लोगों का कहना है कि अगर इस महामारी के बारे में वह इतने ही गंभीर थे तो आम जनता को जल्द से जल्द सतर्क क्यों नहीं किया गया? बता दें कि तीन जनवरी को चिनफिंग का एक भाषण छपा था, जिसमें उन्होंने दावा किया था उन्होंने इस महामारी से लड़ने के लिए सात जनवरी को ही आदेश दे दिए थे। जबकि 23 जनवरी को वुहान में स्कूल, कॉलेज और कारखाने बंद करने का आदेश दे दिया था।

कोरोना वायरस प्रभावित चीन के वुहान शहर से एयरलिफ्ट कर लाए गए भारतीय नागरिकों को नई दिल्ली के छावला में स्थित आइटीबीपी कैंप से सोमवार से छुट्टी देने का सिलसिला शुरू हो गया। इस दौरान दो साल के एक बच्चे और उसके पिता ने आइटीबीपी को मदद के लिए सैल्यूट किया। एएनआइ

कोरोना पर चिनफिंग का इस्तीफा मांगने वाला गिरफ्तार

बीजिंग, रायटर : चीन के जानेमाने मानवाधिकार कार्यकर्ता और कानूनी विशेषज्ञ जू झियोंग को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने गत चार फरवरी को एक वेबसाइट पर प्रकाशित लेख में हांगकांग में सरकार विरोधी प्रदर्शनों और कोरोना वायरस को लेकर राष्ट्रपति शी चिनफिंग के इस्तीफे की मांग की थी। झियोंग के दोस्त और मानवाधिकार कार्यकर्ता हुआ जे ने सोमवार को बताया कि उन्होंने गत दिसंबर में मानवाधिकार पर केंद्रित एक बैठक में हिस्सा लिया था। दक्षिणी चीन के जियामेन शहर में हुई इस बैठक के बाद से वह छुपकर रह रहे थे। बैठक में शामिल होने वाले चार अन्य लोगों को पहले ही पकड़ा जा चुका है। पुलिस ने शनिवार रात झियोंग को गिरफ्तार किया। अमेरिका आधारित ह्यूमन राइट्स वाच चाइना की शोधकर्ता याकीउ वांग ने बताया कि शनिवार से झियोंग की गर्लफ्रेंड से संपर्क नहीं हो पाया है। वह बीजिंग में ही थीं। 2012 में न्यू सिटीजन मूवमेंट नाम से संगठन बनाने वाले झियोंग ने सरकारी अधिकारियों से अपनी संपत्ति उजागर करने की मांग की थी। इसके लिए उन्हें वर्ष 2014 में चार साल जेल की सजा सुनाई गई थी।

जू झियोंग। फाइल फोटो, रायटर

वुहान में फंसे भारतीयों को लेने फिर जाएगा विशेष विमान

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- दक्षिण एशिया के नागरिकों को भी साथ लाने का प्रस्ताव
- एयर इंडिया और मेडिकल टीम के सदस्यों को पीएम ने भेजा प्रशस्ति पत्र

कोरोना वायरस के प्रकोप में जकड़े चीन के वुहान शहर में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए एक बार फिर एयर इंडिया का विशेष विमान भेजा जाएगा। भारत ने दक्षिण एशिया के अन्य देशों के नागरिकों को भी वुहान से निकालने का प्रस्ताव किया है। इससे पहले एयर इंडिया के दो विशेष विमानों से वुहान से 600 से ज्यादा भारतीयों और मालदीव के सात लोगों को निकाला गया था। संकट की घड़ी में अपनी जान जोखिम में डालकर भारतीयों को वुहान से निकालने वाले एयर इंडिया और स्वास्थ्य विभाग की टीम के सदस्यों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सराहना की है और व्यक्तिगत रूप से उन्हें प्रशस्ति पत्र भेजा है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि इसी हफ्ते विशेष विमान वुहान भेजा जाएगा। वुहान में भारत के वाणिज्यिक दूतावास ने ट्वीट कर अपील की है कि दक्षिण एशिया के देशों के नागरिक यदि चाहें तो भारत उन्हें वहां से निकालने के लिए तैयार है, इसमें पाकिस्तान भी शामिल है। पिछले दिनों पाकिस्तान के अपने नागरिकों को वापस लाने से इन्कार कर दिया था, जिसके बाद भारत ने कहा था कि यदि पड़ोसी देश अनुरोध करे तो वह उसके नागरिकों को वापस लाने के लिए तैयार है। पाकिस्तान की ओर से ऐसा अनुरोध नहीं किया गया। जबकि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में पाकिस्तानी नागरिक वुहान से निकालने की गुहार लगाते नजर आए थे। इससे पहले, दो ट्रिप में वुहान से भारतीयों को वापस लाने वाले एयर इंडिया और चिकित्सा दल के 68 सदस्यों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सराहना की है। इनमें राम मनोहर लोहिया और सफदरजंग अस्पताल के 10 डाक्टरों और नर्सिंग स्टॉफ शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने इन सभी को लिखे व्यक्तिगत पत्र में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके इस साहसिक काम से दुनिया भर में फैले भारतवंशियों का देश पर भरोसा बढ़ा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सोमवार को सभी डाक्टरों व नर्सों को और उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एयर इंडिया के पायलटों और अन्य कर्मचारियों को प्रधानमंत्री का प्रशस्ति पत्र सौंपा। इन डाक्टरों और नर्सों ने एक और दो फरवरी को वुहान से दो विशेष विमान से मालदीव के सात नागरिकों से समेत कुल 645 भारतीयों को वापस लाने में अहम भूमिका निभाई थी। इनमें से 406 लोग आइटीबीपी के छावला कैंप में रखे गए थे, जिनकी जांच रिपोर्ट निगेटिव आई थी।

चिकित्सकीय सामान चीन भेजेगा भारत

बीजिंग में भारतीय दूतावास ने ट्वीट कर बताया है कि भारत इस हफ्ते कुछ चिकित्सकीय सामान वुहान भेजेगा। विशेष विमान से मेडिकल सामान भेजे जाएंगे। दूतावास ने यह नहीं बताया कि मेडिकल सामान में क्या-क्या होगा। लेकिन कोरोना वायरस से बचने के लिए चीन को अभी सबसे ज्यादा मास्क, ग्लव्स और मेडिकल स्टाफ व मरीजों के लिए कपड़ों की जरूरत है। चीन में मास्क की भारी कमी भी हो गई है।

पाकिस्तान में चार करोड़ बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो रोधी दवा

इस्लामाबाद, प्रेट्र : पाकिस्तान में सोमवार से राष्ट्रव्यापी पोलियो रोधी अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत मुल्क के पांच साल तक के करीब चार करोड़ बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाई जाएगी। इस मुहिम में दो लाख 65 हजार स्वास्थ्य कर्मचारियों को लगाया गया है। पाकिस्तान सरकार ने देश से पोलियो खत्म करने के लिए लोगों से मदद की अपील की है।

अभियान में जुटे दो लाख 65 हजार स्वास्थ्यकर्मी

स्वास्थ्य मसले पर प्रधानमंत्री इमरान खान के विशेष सलाहकार जफर मिर्जा ने कहा, 'पोलियो रोधी टीकाकरण के लिए सरकार हर बच्चे तक पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध है। हम लोगों से अपील करते हैं कि वे इस मुल्क से पोलियो को जड़ से उखाड़ फेंकने की मुहिम को सफल बनाएं।' जबकि स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि स्वास्थ्यकर्मी घर-घर जाकर 3.96 करोड़ बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाएंगे। यह अभियान ऐसे समय शुरू किया गया, जब कुछ दिन पहले ही देश में पोलियो के पांच नए मामले सामने आए हैं।

इन देशों में बचा है पोलियो : विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, पाकिस्तान दुनिया के उन तीन देशों में शामिल है, जहां पोलियो का प्रकोप बना हुआ है। अफगानिस्तान और नाइजीरिया में भी पोलियो खत्म नहीं हुआ है।

सामने आए पोलियो के 144 मामले : पाकिस्तान में वर्ष 2019 में पोलियो के रिकॉर्ड 144 मामले सामने आए थे। 2018 में 12 और 2017 में महज आठ मामलों का पता चला था। जबकि इस साल अब तक 17 मामले सामने आ चुके हैं।

इमरान ने बताया था, शर्म करने का मसला

प्रधानमंत्री इमरान खान ने गत वर्ष दिसंबर में कहा था कि पाकिस्तान दुनिया के उन देशों में शुमार है, जहां पोलियो खत्म नहीं हुआ है। यह मुल्क के लिए शर्म करने का मसला है।

आतंकी गुटों को मिल रही आर्थिक मदद : एफएटीएफ

नई दिल्ली, प्रेट्र : फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने सोमवार को कहा कि उसकी सख्ती के बावजूद कई आतंकी गुटों को उनके समर्थकों की तरफ से आर्थिक मदद मिल रही है। इसके अलावा आतंकी गुट अवैध गतिविधियों से भी धन जुटा रहे हैं। वहीं, भारत ने कहा है कि पाकिस्तान लश्कर ए तैयबा, जैश ए मुहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों को लगातार मदद मुहैया करा रहा है, इसलिए इस्लामाबाद के खिलाफ एफएटीएफ कार्रवाई करे।

पेरिस में एफएटीएफ की पूर्ण बैठक हो रही है, जो हफ्ते भर चलेगी। इसमें पाकिस्तान की किस्मत का फैसला होना है कि वह ग्रे सूची में बना रहेगा या काली सूची में जाएगा। ग्रे सूची से निकलने के लिए पाकिस्तान को 39 में से 12 मतों की जरूरत होगी, जबकि काली सूची में जाने से बचने के लिए उसे तीन देशों का समर्थन चाहिए।

पिछले साल हुई बैठक में उसे मलेशिया और तुर्की के साथ एफएटीएफ के तत्कालीन चेयरमैन देश चीन का समर्थन मिला था,जिससे वह काली सूची में जाने से बच गया था।

अरब जगत का पहला परमाणु बिजलीघर यूएई में लगेगा

अबूधाबी, एएफपी : अरब जगत में भी परमाणु गतिविधियों ने दस्तक दे दी है। भारत के मित्र संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने सोमवार को देश में पहला परमाणु रिएक्टर लगाने के लिए लाइसेंस जारी कर दिया। यह रिएक्टर देश के बाराक परमाणु बिजलीघर में काम करेगा। यह अरब देशों में बनने वाला पहला परमाणु बिजलीघर होगा।

यूएई के पास तेल और गैस के पर्याप्त भंडार हैं, बावजूद इसके वह ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को विकसित करने की कोशिश में जुटा हुआ है। इसी के तहत परमाणु बिजलीघर की स्थापना की जा रही है। करीब एक करोड़ की आबादी वाले इस देश में सौर ऊर्जा के विकास के लिए व्यापक कार्य हो रहा है और उसके लिए खासा निवेश किया गया है। बाराक परमाणु बिजलीघर अबूधाबी के पश्चिमी समुद्री तट पर बनाया गया है। इस बिजलीघर के लिए 2017 में काम शुरू हो चुका है लेकिन तमाम सुरक्षा और संचालन संबंधी औपचारिकताओं के चलते इसके शुरू होने में देरी हो रही है। लेकिन अब राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने बिजलीघर में लगे चार रिएक्टरों में से पहले को चलाने की अनुमति दे दी है। यह जानकारी अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आइएईए) के यूएई में मौजूद प्रतिनिधि हामद अल-काबी ने दी है। उन्होंने कहा, यूएई के लिए ये ऐतिहासिक क्षण है। परमाणु बिजलीघर चलाने वाला वह पहला अरब देश बन रहा है। ऐसा यूएई सरकार के परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण कार्यों में इस्तेमाल की नीति के चलते संभव हुआ है। यूएई के परमाणु बिजलीघर का निर्माण कोरिया के इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन ने किया है।

वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

अरब जगत का सबसे धनी देश सऊदी अरब भी परमाणु बिजलीघर स्थापित करने की घोषणा कर चुका है। उसकी 16 रिएक्टर लगाकर बिजलीघर चलाने की योजना है लेकिन उस पर काम आगे नहीं बढ़ पाया है।

रोहिंग्या पुनर्वास योजना को रद कर सकता है बांग्लादेश

ढाका, आइएएनएस : बांग्लादेश एक लाख रोहिंग्या शरणार्थियों को बंगाल की खाड़ी में स्थित एक निर्जन द्वीप (भाषण चार) पर बसाने की अपनी योजना को रद कर सकता है। यह जानकारी विदेश मंत्री अबुल कलाम अब्दुल मोमिन ने रविवार को दी। मोमिन ने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य शरणार्थियों को उनके देश भेजना है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने रोहिंग्या शरणार्थियों को धार्मिक रूप से सबसे अधिक प्रताड़ित आबादी के रूप में चिह्नित किया है।

बांग्लादेश में चीन के राजदूत ली जिमिंग के साथ बैठक के बाद मोमिन ने भाषण चार द्वीप पर चल रही विकास परियोजनाओं की सराहना की। साथ ही उसे एक बिजनेस हब के तौर पर विकसित करने की बात कही। मोमिन ने कहा कि नदी के कटाव और अन्य कारणों के चलते यहां रहने वाले बांग्लादेशी नागरिक बेघर हो गए हैं। दरअसल, भाषण चार द्वीप एक निर्जन द्वीप है। 2018 में बांग्लादेश ने यहां एक लाख शरणार्थियों को बसाने का एलान किया था। हालांकि अब आकलन में यहां की स्थितियां अच्छी नहीं पाई गई।

किया दावा

एफएटीएफ की बैठक से पहले इमरान खान का बयान, पाकिस्तानी पीएम को देश में शरणार्थी संकट का खतरा, कहा-भारत की अति राष्ट्रवादी नीतियां बढ़ा रहीं हैं चिंता

'पाकिस्तान में अब कोई आतंकी पनाहगाह नहीं'

इस्लामाबाद, प्रेट्र : पाकिस्तान में अब आतंकी संगठनों के लिए कोई सुरक्षित पनाहगाह नहीं है। यह बात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कही है। इमरान का यह बयान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) की पेरिस में होने वाली बैठक से ठीक पहले आया है। इस संगठन ने आतंकियों को धन मुहैया कराने के कारण पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल रखा है। सोमवार को आए इस बयान से पूर्व इमरान पाकिस्तान में आतंकी संगठनों के सक्रिय होने के बयान दे चुके हैं।

भारत, अफगानिस्तान और अमेरिका लंबे समय से आरोप लगाते रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकी संगठनों को सुरक्षित स्थान और आर्थिक मदद देता है। इस तरह की मदद पाने वालों में तालिबान, हक्कानी नेटवर्क, लश्कर ए तैयबा और जैश ए मुहम्मद जैसे दुर्दांत आतंकी संगठन हैं। अफगानिस्तान से आए शरणार्थियों पर आयोजित जिस कार्यक्रम में इमरान बोल रहे थे, उसमें संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस भी मौजूद थे। वह इन दिनों पाकिस्तान की यात्रा पर हैं। इमरान ने कहा, पहले क्या स्थिति थी-उन्हें नहीं मालूम, लेकिन अब वह अफगानिस्तान में शांति चाहते हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि संभव है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान में मौजूद अफगान शरणार्थियों के शिविरों में आतंकी भी रह रहे होंगे। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। सुरक्षा बल अब इन शिविरों पर लगातार नजर रख रहे हैं। गुतेरस ने भी माना कि पाकिस्तान में सुरक्षा के हालात बदले हैं और स्थिति बेहतर हुई है।

इमरान खान। फाइल

पाकिस्तान में सभी को विरोध प्रदर्शन का अधिकार

पाकिस्तान में सभी को विरोध प्रदर्शन का अधिकार है, हमारा देश भारत की तरह नहीं है। यह बात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनअल्लाह ने पश्तून तहाफ्फुज मूवमेंट और अवामी वर्कर्स पार्टी के 23 कार्यकर्ताओं की जमानत की अर्जी पर चर्चा के दौरान कही। ये कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए गिरफ्तार किए गए थे। मुख्य न्यायाधीश ने इन लोगों की जमानत मंजूर कर ली।

भारत के नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) पर मनमानी बयानबाजी करने वाले इमरान खान को अब अपने देश में शरणार्थी संकट का खतरा डरा रहा है। उन्होंने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय बिरादरी ने भारत की मौजूदा स्थिति पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में पाकिस्तान को शरणार्थी समस्या का सामना करना पड़ सकता है।

इमरान ने कहा, भारत में व्याप्त हिंदुत्व की विचारधारा के चलते कश्मीर में लोग 200 दिनों से बंधक बने हुए हैं। इसी विचारधारा पर चलते हुए भाजपा नेतृत्व वाली सरकार ने भेदभाव वाले दो कानून ऐसे बनाए हैं जो 20 करोड़ भारतीय मुसलमानों को सीधे निशाना बनाते हैं। जाहिर है इमरान का इशारा सीएए और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) पर बने कानूनों की तरफ था।

एमक्यूएम ने मसूद अजहर के लापता होने पर पाक को घेरा

लंदन, एएनआइ: मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट (एमक्यूएम) के संस्थापक अल्ताफ हुसैन ने अंतरराष्ट्रीय आतंकी मसूद अजहर के लापता होने को लेकर पाकिस्तान को कठघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं इमरान सरकार की प्रतिबंधित संगठनों के खिलाफ अपनाई जाने वाली नीति पर कई तरह के सवाल खड़ा करती हैं।

एक ट्वीट में हुसैन ने कहा कि जैश ए मोहम्मद सरगना मसूद अजहर और उसके परिवार के लापता होने की खबरें एफएटीएफ की बैठक के दौरान सामने आई हैं। एक अन्य ट्वीट में हुसैन ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस की पाकिस्तान यात्रा को लेकर भी अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने पूछा कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अपनी चार दिवसीय यात्रा के दौरान सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों का भी दौरा करेंगे और वहां के लोगों से सेना द्वारा किए जा रहे दमन की कहानियां सुनेंगे। बता दें कि हुसैन फिलहाल लंदन में नजरबंद हैं, लेकिन वह नियमित रूप से टीवी और टेलीफोन के जरिये अपने समर्थकों को संबोधित करते हैं। आतंकवाद के वित्तपोषण को लेकर एफएटीएफ की बैठक रविवार से पेरिस में शुरू हो चुकी है।

लंदन में पाक उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन: पाकिस्तान के मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और ब्रिटेन में रहने वाले भारतीयों ने रविवार को लंदन में पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन किया। ये लोग एक हिंदू लड़की महक कुमारी के लिए न्याय की मांग कर रहे थे। बता दें कि इस नाबालिग लड़की का 15 जनवरी को सिंध प्रांत के जैकोबाबाद जिले से अली रजा नाम के एक व्यक्ति ने अपहरण कर लिया था। बाद में इसका धर्म परिवर्तन करके अपहरणकर्ता ने उससे शादी कर ली थी।

मैं जब टेनिस की गेंद से क्रिकेट खेलता था तब उस गेंद से खेलने वाले शख्स ने मुझे कैरम बॉल फेंकना सिखाया था।
— रविचंद्रन अश्विन, भारतीय ऑफ स्पिनर

अतीत में नहीं जाना चाहता : शरजील

लाहौर, आइएएनएस : स्पॉट फिक्सिंग के कारण तीन साल का प्रतिबंध झेलने के बाद वापसी कर रहे पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज शरजील खान ने कहा है कि वह अतीत में नहीं जाना चाहते और आगे की तरफ ध्यान देते हुए पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं। शरजील 20 फरवरी से शुरू हो रहे पीएसएल के पांचवें संस्करण में कराची किंग्स की तरफ से खेलेंगे।

टेस्ट सीरीज में वापसी को तैयार ट्रेंट बोल्ट

भारत के खिलाफ शुरू होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए कीवी टीम घोषित, तेज गेंदबाज जेमिसन को भी मौका

वेलिंगटन, प्रेट्र : चोट के कारण वनडे और टी-20 सीरीज से बाहर रहने वाले बायें हाथ के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट की भारत के खिलाफ होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए न्यूजीलैंड टीम में वापसी हुई है। वहीं युवा तेज गेंदबाज काइली जेमिसन को पहली बार टेस्ट टीम में जगह मिली है। बोल्ट को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर बॉक्सिंग-डे टेस्ट में दायें हाथ में चोट लग गई थी। इसी कारण वह टेस्ट सीरीज के अंतिम मैच और भारत के खिलाफ वनडे और टी-20 सीरीज में नहीं खेल पाए थे। उनके आने से टिम साउथी और नील वैगनर से सज्जित न्यूजीलैंड की टीम के तेज गेंदबाजी आक्रमण को मजबूती मिलेगी।

टीम के मुख्य कोच गैरी स्टीड ने कहा कि बोल्ट की वापसी अच्छी बात है। वह बेहतरीन प्रतिभा के गेंदबाज हैं और उनके पास जो अनुभव है उससे टीम को मजबूती मिलेगी। भारत के खिलाफ वनडे सीरीज से पदार्पण करने वाले जेमिसन को अच्छे प्रदर्शन का इनाम मिला है। ऑस्ट्रेलिया में खराब प्रदर्शन के कारण बायें हाथ के स्पिनर मिशेल सेंटनर अपनी जगह गंवा चुके हैं। उनकी जगह टेस्ट सीरीज में स्पिन विभाग की जिम्मेदारी एजाज पटेल के जिम्मे आएगी। पटेल ने पाकिस्तान के खिलाफ खेली गई अपनी पदार्पण सीरीज में काफी प्रभावित किया था। वहीं टीम के अनुभवी बल्लेबाज रॉस टेलर अपने देश के लिए 100 टेस्ट मैच खेलने वाले खिलाड़ी बनने वाले हैं। वह इस क्रम में ब्रेंडन मैकुलम, डेनियल विटोरी और स्टीफन फ्लेमिंग की बराबरी करेंगे। साथ ही टेलर न्यूजीलैंड के लिए तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले देश के पहले खिलाड़ी भी बन जाएंगे। भारत ने कीवी टीम को पांच मैचों की टी-20 सीरीज में 5-0 से हराया था, लेकिन मेजबान टीम ने वनडे में वापसी करते हुए भारत को 3-0 से शिकस्त दी थी।

टेस्ट टीम : केन विलियमसन (कप्तान), टॉम लाथम, रॉस टेलर, टॉम ब्लंडेल, हेनरी निकोल्स, बीजे वॉटलिंग, ग्रैंडहोम, साउथी, वैगनर, ट्रेंट बोल्ट, एजाज पटेल, काइली जेमिसन और डेरिल मिशेल।

सीमित ओवरों के बाद सैनी की नजरें टेस्ट पर

वेलिंगटन : युवा तेज गेंदबाज नवदीप सैनी शीर्ष स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व कर काफी खुश हैं। उनका ध्यान सिर्फ अच्छा खेलने और टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा मैच जीतने पर है। सैनी ने बीसीसीआइ डॉट टीवी पर टीम के साथी मुहम्मद शमी से बातचीत में कहा कि मैं शीर्ष स्तर पर खेल कर काफी खुश हूं। किसी अन्य खिलाड़ी की तरह, देश के लिए खेलना मेरा सपना था जो सच हो गया। मैं सिर्फ अपने अच्छे प्रदर्शन को जारी रखना चाहता हूं। सैनी ने भारत के लिए अभी तक पांच वनडे और 10 टी-20 मैच खेले हैं जिनमें उन्होंने क्रमशः पांच और 13 विकेट लिए हैं। सैनी को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली जाने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भी टीम में चुना गया है। इस बातचीत में सैनी ने यह भी बताया कि वह पंजाबी में बात करना पसंद करते हैं। दायें हाथ के तेज गेंदबाज ने कहा कि मैं दिल से बहुत मासूम हूं। जब भाषा की बात आती है तो मैं पंजाबी में सहज महसूस करता हूं। मैं भारतीय टीम के अपने खिलाड़ियों से पंजाबी में बात करना पसंद करता हूं। इससे मुझे सहज महसूस होता है।

अब दोनों टीमें टेस्ट चैंपियनशिप के तहत खेली जाने वाले दो मैचों की टेस्ट सीरीज अपने नाम करने उतरेंगी।

ट्रेंट बोल्ट ● फाइल फोटो, एपी

सकारात्मकता और जुनून से भारतीय टीम को टी-20 विश्व चैंपियन बना सकता हूं : शार्दुल

मुंबई, प्रेट्र : न्यूजीलैंड में काफी रन लुटाने वाले तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर ने सोमवार को आत्मविश्वास जताते हुए कहा कि वह अपनी गलतियों से सीखेंगे और जुनून के साथ भारत को टी-20 विश्व कप का चैंपियन बनाने के लिए मेहनत करेंगे। शार्दुल न्यूजीलैंड के खिलाफ हाल में खत्म हुई वनडे सीरीज में काफी महंगे साबित हुए और खराब गेंदबाजी के लिए उनकी काफी आलोचना भी हुई। उनका ध्यान अब ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टी-20 विश्व कप पर है। उन्होंने कहा कि जाहिर है मेरा ध्यान विश्व कप पर है। मैं जिस सकारात्मकता से मुकाबले में जाता हूं और जो मेरा आत्मविश्वास एवं जुनून है उससे मैं टीम को विश्व चैंपियन बनाने में या अच्छे प्रदर्शन में मदद कर सकता हूं। अंतरराष्ट्रीय टी-20 में 15 मैचों में 21 विकेट लेने वाले शार्दुल की कोशिश मार्च के आखिरी में शुरू हो रहे आइपीएल से लय हासिल करने पर है। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से, आइपीएल महत्वपूर्ण है और मुझे वहां से हमें जो लय मिलेगी वह महत्वपूर्ण होगी। श्रीलंका के खिलाफ टी-20 सीरीज है और हम आइपीएल के बाद जिंबाब्वे जा रहे हैं। टी-20 विश्व कप से पहले हम एशिया कप में भी खेलेंगे। चेन्नई सुपरकिंग्स के इस खिलाड़ी ने कहा कि इसलिए आइपीएल से हमें जो लय मिलेगी वह महत्वपूर्ण होगी और उसे आगे जारी रखना होगा। न्यूजीलैंड दौरे के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वह इसे एक सीखने के अनुभव की तरह देखते हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपनी गलतियों का अध्ययन करूंगा और उससे सीखने के अनुभव के रूप में लूंगा। यह मेरा न्यूजीलैंड का पहला दौरा था और अन्य खिलाड़ियों की तुलना में मैंने भारत के लिए ज्यादा नहीं खेला है। गेंद के साथ शार्दुल ने बल्ले से भी भारत को मैच जिताया है। इस बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वह स्कूल और कॉलेज के लिए भी बल्ले से जरूरी योगदान दे चुके है। उन्होंने कहा कि मुझे हमेशा लगता है कि मैं बल्लेबाजी कर सकता हूं और टीम में उपयोगी योगदान दे सकता हूं। जब भी मैंने स्कूल, कॉलेज या घरेलू टीम लिए खेला है मेरी भूमिका नहीं बदली। अब मैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहा हूं। यहां भी मेरी भूमिका वही रहेगी। मैं जब भी बल्लेबाजी के लिए उतरता हूं , मेरी कोशिश परिस्थितियों के मुताबिक खेलने की होती है।

पूर्व नियोजित ब्रेक की आलोचना से हैरान हूं : स्टीड

वेलिंगटन, प्रेट्र : न्यूजीलैंड के कोच गैरी स्टीड ने सोमवार को कहा कि वह हैरान हैं कि भारत के खिलाफ इस महीने की शुरुआत में टी-20 सीरीज में 0-5 से हार के बाद पूर्व निर्धारित ब्रेक लेने के लिए उन्हें निशाना बनाया गया। स्टीड 21 फरवरी से शुरू हो रही टेस्ट सीरीज के लिए टीम से जुड़ गए हैं। वह सोमवार को जब यहां मीडिया से बात कर रहे थे तो उम्मीद के मुताबिक उनके ब्रेक को लेकर सवाल पूछा गया। पूर्व कप्तान जेरेमी कोनी उनके ब्रेक लेने के समय पर सवाल उठा चुके हैं। न्यूजीलैंड ने हालांकि टी-20 सीरीज के बाद वापसी करते हुए वनडे सीरीज 3-0 से जीती थी। स्टीड ने पांच दिन का ब्रेक लिया था और इस दौरान गेंदबाजी कोच शेन जुर्गेनसन टीम के प्रभारी थे। स्टीड ने कहा कि मैं काफी हैरान था। मेरे कहने का मतलब है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट और मैंने लंबे समय तक इस बारे में बात की थी, अपने स्टाफ और खिलाड़ियों को देखते हुए। उन्होंने कहा कि इसलिए हमने ऐसा किया और मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट वह कर रहा है जो हमें लगता है कि हम लोगों के लिए सही है। मैं काफी हैरान था। स्टीड ने कहा कि मुझे लगता है कि यह जरूरी नहीं है कि जेरेमी कोनी ने मेरे बारे में जो कहा उसका कोई संदर्भ हो। मुझे लगता है कि सभी को अपना नजरिया रखने का हक है।

कोच गैरी स्टीड ● फाइल फोटो, एपी

न्यूजीलैंड दौरे के अंत तक चुन लेंगे नए चयनकर्ता : मदन लाल

नई दिल्ली, प्रेट्र : बीसीसीआइ की क्रिकेट सलाहकार समिति (सीएसी) के सदस्य मदन लाल ने कहा कि अगले महीने की शुरुआत में भारत के न्यूजीलैंड दौरे के अंत तक दो नए चयनकर्ता चुन लिए जाएंगे। भारत के पूर्व क्रिकेटर रुद्र प्रताप सिंह और सुलक्षणा नाइक सीएसी के अन्य सदस्य हैं।

इस समिति को सीनियर चयन समिति के अध्यक्ष एमएसके प्रसाद और उनके साथी सदस्य गगन खोड़ा के विकल्प ढूंढने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रसाद और खोड़ा का कार्यकाल खत्म हो गया है। मदन लाल ने कहा कि हमें 44 आवेदकों की सूची मिली है और न्यूजीलैंड दौरे के अंत तक दो चयनकर्ताओं की नियुक्ति हो जानी चाहिए। भारत के न्यूजीलैंड दौरे का अंतिम चरण शुक्रवार से दो टेस्ट की सीरीज के साथ शुरू होगा। यह दौरा पांच मार्च को खत्म होगा। राष्ट्रीय चयन समिति में देवांग गांधी, जतिन परांजपे और सरनदीप सिंह भी शामिल हैं। इन सभी का एक-एक साल का कार्यकाल और बचा है। मदन लाल ने कहा कि इन आवेदकों में से कितनों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा इस पर अभी फैसला नहीं किया गया है। आवेदकों में पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज अजित अगरकर और वेंकटेश प्रसाद भी शामिल हैं। मदन लाल ने कहा कि इस सूची में बड़े नाम शामिल हैं लेकिन यही सब कुछ नहीं है। हमें काम के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को चुनना है और हमारा ध्यान इसी पर है। साथ ही बीसीसीआइ की ओर से कोई जवाब नहीं मिला है कि क्षेत्रीय नीति को कायम रखना है या नहीं। लक्ष्मण शिवरामाकृष्णन, अमय खुरासिया और नयन मोंगिया ने भी समिति में दो पद के लिए आवेदन किए हैं।

टी-20 रैंकिंग में कोहली 10वें स्थान पर खिसके : भारतीय कप्तान विराट कोहली आइसीसी की सोमवार को जारी नवीनतम टी-20 अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में 10वें स्थान पर खिसक गए हैं। हालांकि, उनके साथी लोकेश राहुल और रोहित शर्मा क्रमशः दूसरे और 11वें स्थान पर बरकरार हैं। कोहली (673 अंक) को एक स्थान का नुकसान उठाना पड़ा है। बता दें कि न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी-20 सीरीज में वह चार पारियों में 105 रन बना पाए थे।

दूसरी ओर, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज में इंग्लैंड की 2-1 की जीत के दौरान दो अर्धशतक की मदद से 136 रन बनाने वाले कप्तान इयान मोर्गन कुल 687 अंक के साथ नौवें स्थान पर पहुंच गए हैं। पिंडली की चोट से उबर रहे रोहित बल्लेबाजी रैंकिंग में 662 अंक के साथ 11वें स्थान पर हैं। पाकिस्तान के बाबर आजम इस सूची में शीर्ष पर चल रहे हैं। आजम के 879 अंक हैं। राहुल 823 अंक के साथ दूसरे स्थान पर चल रहे हैं।

गेंदबाजी में बुमराह 12वें नंबर पर : गेंदबाजी सूची में भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज शेल्डन जैक्सन के साथ संयुक्त 12वें स्थान पर हैं। दक्षिण अफ्रीका के बायें हाथ के स्पिनर तबरेज शम्सी नौ स्थान की छलांग के साथ शीर्ष 10 में शामिल हो गए हैं। वह आठवें स्थान पर हैं। इंग्लैंड के स्पिनर आदिल राशिद दक्षिण अफ्रीका के आंदिले फेलुकवायो को पछाड़कर छठे स्थान पर पहुंच गए हैं।

तैयारी

- सीएसी को प्रसाद और खोड़ा का ढूंढना है विकल्प
- अगरकर और वेंकटेश जैसे पूर्व खिलाड़ियों ने किया है आवेदन

एक नजर में

हंपी बनीं केर्न्स कप चैंपियन

सेंट लुइस (अमेरिका) : विश्व रैपिड चैंपियन कोनेरू हंपी ने एक अन्य भारतीय खिलाड़ी द्रोणावल्ली हरिका को केर्न्स कप शतरंज के नौवें और आखिरी दौर में ड्रॉ पर रोक कर पिछले दो महीने में अपना दूसरा खिताब हासिल किया। पिछले साल दिसंबर में विश्व रैपिड चैंपियन बनी हंपी इस टूर्नामेंट में छह अंक के साथ तालिका में शीर्ष पर रहीं। इस कामयाबी से उन्हें पांच एलओसी रेटिंग अंक मिलेंगे जिससे वह विश्व रैंकिंग में दूसरे पायदान पर पहुंच जाएंगी। भारतीय ग्रैंडमास्टर हंपी ने कहा, 'मैं इतना चुनौतीपूर्ण टूर्नामेंट जीतकर बहुत खुश हूं। इससे मुझे यह भी अहसास होता है कि विश्व रैपिड खिताब जीतना मेरे लिए कोई तुक्का नहीं था।' 32 साल की इस भारतीय खिलाड़ी को चैंपियन बनने के लिए आखिरी दौर में सिर्फ ड्रॉ की जरूरत थी। उन्हें रविवार रात को खेले गए मुकाबले में हरिका के खिलाफ ऐसा करने में कोई परेशानी नहीं हुई। विश्व चैंपियन वेंजुन जू 5.5 अंक के साथ दूसरे पायदान पर रहीं। (प्रेट्र)

भारत को पांच रजत

नई दिल्ली : भारत ने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में जारी 2020 एशियन यूथ एवं जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में पांच रजत और छह कांस्य पदक जीते। केवीएल पावनी कुमारी (45 किग्रा) ने यूथ गर्ल्स और जूनियर महिला वर्ग दोनों में रजत पदक जीते, जबकि सिद्धांत गोगोई (61 किग्रा) ने क्रमशः 145 किग्रा और 269 किग्रा भार उठाकर यूथ बॉयज एवं जूनियर पुरुष स्पर्धा में रजत पदक जीते। मुकुंद अहीर (49 किग्रा) ने यूथ बॉयज वर्ग में 189 किग्रा भार उठाते हुए रजत पदक जीता। हर्षदा गौड़ (45 किग्रा) ने 139 किग्रा वजन के साथ यूथ गर्ल्स एवं जूनियर महिला वर्ग में कांस्य पदक जीते। कांस्य पदक जीतने वालों में बोनी मांगखय (55 किग्रा), निर्मला देवी (59 किग्रा), एस गुरुनायडू (49 किग्रा) और गोलोम टिंकू (55 किग्रा) भी शामिल रहे। (प्रेट्र)

कौर को एनबीए न्योता

नई दिल्ली : भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी हरसिमरन कौर को 'द एनबीए ग्लोबल अकादमी' ने कैनबरा स्थित ऑस्ट्रेलिया के 'सेंटर ऑफ एक्सिलेंस में अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए आमंत्रण भेजा। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम सोमवार से शुरू हुआ और तीन मार्च तक चलेगा। हरसिमरन दूसरी बार एनबीए ग्लोबल अकादमी में प्रशिक्षण ले रही हैं। (प्रेट्र)

डब्ल्यूएफआइ के दांव से चित हुए यूडब्ल्यूडब्ल्यू और आइओसी

योगेश शर्मा ● नई दिल्ली

चीनी पहलवानों को वीजा नहीं देने के बाद भारतीय महासंघ पर कार्रवाई नहीं, एशियन कुश्ती चैंपियनशिप आज से

एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में चीनी पहलवानों को वीजा नहीं देने के बाद भी भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआइ) को कुश्ती की विश्व संस्था (यूडब्ल्यूडब्ल्यू) और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आइओसी) से किसी प्रकार कोई कार्रवाई का सामना करना नहीं पड़ेगा।

डब्ल्यूएफआइ ने ओलंपिक चार्टर और अच्छा दांव खेलते हुए, पहले पाकिस्तानी पहलवानों को यहां केडी जाधव स्टेडियम में सोमवार से शुरू हो रही एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में वीजा सरकार से दिलाया और फिर कोरोना वायरस के कारण स्वास्थ्य का हवाला देकर चीनी पहलवानों को वीजा नहीं दिया गया। यूडब्ल्यूडब्ल्यू और आइओसी का डब्ल्यूएफआइ पर दबाव था कि वह इस चैंपियनशिप के लिए हिस्सा लेने वाले सभी देशों को वीजा देगा नहीं तो उसे कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। पिछले साल दिल्ली में फरवरी में हुई निशानेबाजी विश्व कप में पाकिस्तान के निशानेबाजों को भारत सरकार ने वीजा नहीं दिया था और इसके बाद आइओसी ने भारत पर किसी भी टूर्नामेंट की मेजबानी को लेकर प्रतिबंध लगाया था। लेकिन बाद में इसे हटा दिया गया था।

डब्ल्यूएफआइ के सहायक सचिव विनोद तोमर ने कहा, 'हमें पता चला है कि सरकार ने चीन के दल को वीजा जारी नहीं किया है और इसलिए वे चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं ले रहे। पूरा विश्व कोरोना वायरस को लेकर चिंतित है और इसलिए, अब खिलाड़ियों का स्वास्थ्य मुख्य चिंता है। हम यूडब्ल्यूडब्ल्यू और आइओसी के सामने यहीं तर्क देंगे और इसलिए कार्रवाई का कोई सवाल नहीं उठता। हमने पाकिस्तान को भी वीजा दिया है तो हमारी तरफ से सभी स्थिति साफ है।' वहीं, भारत के खेल मंत्री किरन रिजिजू ने कहा, 'हम किसी भी देश के नागरिकों को वीजा देने से इन्कार नहीं कर सकते क्योंकि यह ओलंपिक चार्टर का एक हिस्सा है। हम खेलों को राजनीति से दूर रखने की कोशिश करते हैं लेकिन, जहां स्वास्थ्य की चिंता है या कोई तकनीकी समस्या है, उसके लिए अलग प्रावधान हैं।'

23 देश लेंगे हिस्सा : गत चैंपियन भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया (65 किग्रा) चैंपियनशिप में अपनी बादशाहत कायम रखना चाहेंगे, जबकि पिछले सत्र में कांस्य पदक जीतने वाली विनेश फोगाट (53 किग्रा) अपने पदक के रंग को बदलना चाहेंगी। इस चैंपियनशिप में 23 देश हिस्सा ले रहे हैं जिसमें ईरान, जापान और मंगोलिया जैसे देशों के शीर्ष पहलवान भाग लेंगे। इस चैंपियनशिप को यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने टोक्यो ओलंपिक के लिए रैंकिंग टूर्नामेंट का दर्जा दिया है। बजरंग और विनेश के अलावा 30 सदस्यीय भारतीय दल में दीपक पूनिया, रवि कुमार दहिया और ओलंपिक पदकधारी साक्षी मलिक भी पदक के दावेदारों में शामिल हैं। टूर्नामेंट तीन श्रेणियों में खेला जाएगा, जिसमें पुरुषों की फ्री स्टाइल, ग्रीको रोमन और महिलाओं की कुश्ती शामिल हैं। पहले दो दिन ग्रीको रोमन मुकाबले होंगे, उसके बाद अगले दो दिन महिलाओं की कुश्ती और फिर अंतिम दो दिन पुरुष फ्रीस्टाइल के मुकाबले होंगे।

डुप्लेसिस ने दक्षिण अफ्रीकी टीम की कप्तानी छोड़ी

जोहानिसबर्ग, प्रेट्र : सीनियर बल्लेबाज फाफ डुप्लेसिस ने सोमवार को दक्षिण अफ्रीका की टेस्ट और टी-20 टीम की कप्तानी तुरंत प्रभाव से छोड़ दी। डुप्लेसिस ने कहा है कि टीम को नई पीढ़ी के नेतृत्वकर्ताओं की जरूरत है। इंग्लैंड के खिलाफ हाल में समाप्त हुई वनडे सीरीज में डुप्लेसिस की जगह क्विंटन डिकॉक को कप्तान नियुक्त किया गया था।

डुप्लेसिस ने कहा कि उन्होंने यह फैसला इसलिए किया जिससे कि दक्षिण अफ्रीका को नए युग की शुरुआत करने में मदद मिले। डुप्लेसिस ने कहा कि अगर सभी चीजें सही होतीं तो मैं बाकी सत्र में टेस्ट मैचों और टी-20 विश्व कप में टीम की अगुआई करना पसंद करता। लेकिन, कभी-कभी नेतृत्वकर्ता के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह होता है कि वह स्वार्थी नहीं हो। मैं स्वस्थ, फिट, ऊर्जावान और प्रेरित हूं और निश्चित तौर पर खुद को टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए देखता हूं। डुप्लेसिस को इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की टी-20 सीरीज से आराम दिया गया था। इस सीरीज को दक्षिण अफ्रीका ने 1-2 से गंवाया। डुप्लेसिस का यह फैसला उस समय आया है जब दक्षिण अफ्रीका को शुक्रवार से यहां ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज और फिर तीन वनडे मैचों की सीरीज खेलनी है। डुप्लेसिस ने कहा कि पिछले कुछ सप्ताह के आराम के कारण खेल से दूर रहने से मुझे इस बारे में सोचने का मौका मिला कि खेल के तीनों प्रारूपों में देश का प्रतिनिधित्व और नेतृत्व करना कितने सम्मान की बात रही। उन्होंने कहा कि यह कभी-कभी शानदार, कभी मुश्किल और कभी सुनसान राह रही, लेकिन यह अनुभव काफी महत्वपूर्ण रहा जिसने मुझे वह व्यक्ति बनाया जिस पर आज मुझे गर्व है। डुप्लेसिस ने इसे अपने सबसे मुश्किल फैसलों में से एक बताया, लेकिन कहा कि वह बदलाव के इस दौर में डिकॉक की मदद करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। डुप्लेसिस ने एबी डिविलियर्स के हटने के बाद अगस्त 2017 में तीनों प्रारूपों में दक्षिण अफ्रीका की कप्तानी की जिम्मेदारी संभाली थी। उनकी अगुआई में 2019 विश्व कप में टीम का प्रदर्शन काफी खराब रहा और टीम ग्रुप चरण से ही बाहर हो गई।

धीमी ओवर गति के कारण इंग्लैंड पर लगा जुर्माना : इंग्लैंड क्रिकेट टीम पर रविवार को सेंचुरियन में द. अफ्रीका के खिलाफ खेले गए तीसरे टी-20 मैच में धीमी ओवर गति के कारण 20 फीसदी का जुर्माना लगा है। द. अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 222 रन का स्कोर बनाया, जिसे इंग्लैंड ने कप्तान इयोन मोर्गन के 22 गेंदों पर बनाए गए नाबाद 57 रन की पारी के दम पर पांच गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया। मोर्गन की कप्तानी वाली टीम इंग्लैंड समय सीमा के अंदर ओवर पूरे नहीं कर सकी।

बाउचर ने दिए डिविलियर्स की वापसी के संकेत

दक्षिण अफ्रीका मुख्य कोच मार्क बाउचर ने कहा है कि संन्यास ले चुके एबी डिविलियर्स को टी-20 विश्व कप के लिए दक्षिण अफ्रीकी टीम में जगह देने पर तभी विचार किया जाएगा जब वह अच्छी फॉर्म दिखाएंगे और साबित करेंगे कि इस काम के लिए वह सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं। पिछले साल दिसंबर में टीम का प्रभार संभालने के बाद बाउचर ने कहा था कि वह डिविलियर्स सहित हाल में संन्यास लेने वाले कुछ खिलाड़ियों को मनाने की कोशिश कर सकते हैं कि वे ऑस्ट्रेलिया में होने वाला टी-20 विश्व कप खेलें।

युवा नेतृत्वकर्ताओं को मौका देने के इरादे से लिया फैसला, 2019 विश्व कप में खराब रहा था टीम का प्रदर्शन

फाफ डुप्लेसिस ● फाइल फोटो, एएफपी

द. अफ्रीका में छींटाकशी स्मिथ व वार्नर को प्रेरित ही करेगी : वॉ

बर्लिन : ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान स्टीव वॉ का मानना है कि स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर को आगामी दक्षिण अफ्रीका दौरे पर दर्शकों द्वारा कठिन समय का सामना करना होगा, लेकिन उन्होंने साथ ही कहा है कि इससे ये दोनों खिलाड़ी अच्छा करने के लिए प्रेरित होंगे। 2018 में दक्षिण अफ्रीका दौरे पर ही केपटाउन में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच के दौरान स्मिथ और वार्नर गेंद से छेड़छाड़ के मामले में फंसे थे। स्मिथ और वार्नर पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने एक साल का प्रतिबंध लगाया था। उस घटना के बाद ये दोनों पहली बार दक्षिण अफ्रीका में खेलेंगे।

जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा भारत

लुसाने, प्रेट्र : अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ (एफआइएच) ने सोमवार को घोषणा की कि भारत अगले साल होने वाले जूनियर पुरुष विश्व कप की मेजबानी करेगा। यह दूसरा मौका होगा जब भारत इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। 2016 में भी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था और तब भारत फाइनल में बेल्जियम को 2-1 से हराकर चैंपियन बना था। यह भारत का दूसरा एफआइएच जूनियर पुरुष विश्व कप खिताब था।

एफआइएच ने कहा कि यह प्रतियोगिता 2021 के अंत में खेली जाएगी। जूनियर पुरुष विश्व कप में 16 टीमें खिताब के लिए चुनौती पेश करेंगी, जिसमें छह यूरोप, मेजबान भारत सहित चार एशिया, दो अफ्रीका, दो ओसेनिया और दो अमेरिका से होंगी। इन 16 टीमों में से छह यूरोपीय टीमें भारत में होने वाली इस प्रतियोगिता के लिए पहले ही क्वालीफाई कर चुकी हैं।

ओलंपिक डायरी उम्मीदों को जीवंत रखने के लिए आज से बार्सिलोना में शुरू हो रहे स्पेन मास्टर्स में दमदार प्रदर्शन करना चाहेंगे भारतीय खिलाड़ी

साइना व श्रीकांत की नजरें ओलंपिक क्वालीफिकेशन पर

बार्सिलोना, प्रेट्र : अनुभवी बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल और किदांबी श्रीकांत टोक्यो ओलंपिक 2020 में खेलने की उम्मीदों को जीवंत रखने के लिए मंगलवार से यहां शुरू हो रहे स्पेन मास्टर्स में दमदार प्रदर्शन करना चाहेंगे।

साइना और श्रीकांत की मौजूदा रैंकिंग क्रमशः 18वीं और 15वीं है, जबकि 'रेस टू टोक्यो' में यह दोनों खिलाड़ी क्रमशः 22वें और 26वें स्थान पर हैं। बीडब्ल्यूएफ ओलंपिक क्वालीफिकेशन नियमों के मुताबिक, अप्रैल अंत में शीर्ष-16 रैंकिंग के अंदर रहने वाले खिलाड़ी ओलंपिक के लिए सीधे क्वालीफाई कर सकते हैं, लेकिन सिंगल्स में एक देश के अधिकतम दो खिलाड़ी क्वालीफाई कर सकते हैं। भारतीय खिलाड़ियों में सिंगल्स में पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधू और बी साई प्रणीत के अलावा सात्विकसाईराज रेंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की पुरुष डबल्स जोड़ी ने अपना टिकट लगभग पक्का कर लिया है। ओलंपिक टिकट हासिल करने की आखिरी तारीख अप्रैल के अंत तक है और तब तक सिर्फ सात टूर्नामेंट बचे हैं, ऐसे में भारतीय खिलाड़ियों को लगातार अच्छा प्रदर्शन करना होगा। लंदन ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साइना अपने अभियान का आगाज जर्मनी की यूवोन्ने ली के खिलाफ करेंगी। तीसरी वरीयता प्राप्त श्रीकांत एक अन्य भारतीय शुभंकर डे के खिलाफ अपने अभियान का आगाज करेंगे। अन्य भारतीय खिलाड़ियों में सिंगल्स में पारुपल्ली कश्यप, एचएस प्रणय, सौरभ वर्मा, समीर वर्मा व बी साई प्रणीत भी चुनौती पेश करेंगे। अश्विनी पोनप्पा और एन सिक्की रेड्डी की महिला डबल्स जोड़ी, प्रणव जेरी चोपड़ा और कृष्ण प्रसाद गारगा की पुरुष डबल्स जोड़ी एवं मिक्स्ड डबल्स में प्रणव और सिक्की की जोड़ी भी कोर्ट पर उतरेगी।

सोमवार को जापान के टोक्यो में ओलंपिक रिंग के साथ फोटो खिंचवाते लोग ● रायटर

टोक्यो ओलंपिक के आदर्श वाक्य का अनावरण : टोक्यो 2020 के आयोजकों ने सोमवार को इस साल होने वाले ओलंपिक के लिए आदर्श वाक्य 'भावनाओं से एकता' का अनावरण किया, जिसमें उन्होंने 'सार्वभौमिक मूल्यों' व 'खेल की एकजुट शक्ति' को दर्शाया है। आयोजकों ने कहा, 'खेलों से पहले एक-दूसरे को नहीं जानने वाले दर्शकों की भीड़ एक साथ आएगी और सीखेगी कि यहां एक बहुत कुछ है जो उन्हें विभाजित करने के बजाय और ज्यादा एकजुट रखता है।'

भारत के खिलाफ प्रो लीग मैचों से होगी ओलंपिक की अच्छी तैयारी : जालेवस्की

भुवनेश्वर, प्रेट्र : ऑस्ट्रेलियाई हॉकी टीम के कप्तान अरान जालेवस्की ने कहा कि एफआइएच प्रो लीग में भारत जैसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ आगामी मुकाबलों से उनकी टीम को टोक्यो ओलंपिक की तैयारी करने में मदद मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे एफआइएच प्रो लीग में विश्व चैंपियन बेल्जियम से हारकर अपने अभियान की निराशाजनक शुरुआत की थी। उसने हालांकि ग्रेट ब्रिटेन पर जीत के साथ वापसी की। उसका सामना अब शुक्रवार व शनिवार को यहां भारत से होगा। जालेवस्की ने कहा कि टीम ने अभी तक अच्छा प्रदर्शन किया है।

ट्रायल नहीं देंगे कंबाला धावक श्रीनिवास

नई दिल्ली, जेएनएन : कर्नाटक की कंबाला रेस के पैडी श्रीनिवास गौड़ा ने भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) का ट्रायल नहीं देंगे।

गौड़ा ने कहा कि दोनों ही खेल अलग हैं। ट्रैक दौड़ में हम जहां अंगूठे के बल पर दौड़ते हैं वहीं कंबाला में हमें एड़ियों का इस्तेमाल करना होता है। यहां तक कि कंबाला में भैंसे की भी अहम भूमिका होती है। कंबाला रेस या भैंसा दौड़ कर्नाटक का पारंपरिक खेल है। यह रेस कीचड़ वाले इलाके में आयोजित की जाती है। श्रीनिवास ने पिछले सप्ताह कीचड़ से भरे धान के खेत में दौड़ते हुए 142.5 मीटर की दूरी 13.62 सेकेंड में पूरी कर उसैन बोल्ट से सुर्खियां बटोरी थीं। इसके बाद गौड़ा की तुलना दुनिया के सबसे तेज धावक उसैन बोल्ट से की जा रही थी। बोल्ट के नाम 100 मीटर रेस में 9.58 सेकेंड का विश्व रिकॉर्ड है। देखते ही देखते उनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था।

उम्मीदें बताती हैं, लोग समर्थन करते हैं : मनु भाकर

बेल्लारी (कर्नाटक), आइएएनएस : मनु भाकर जब टोक्यो में अपना ओलंपिक पदार्पण करेंगी तो निश्चित तौर पर उन पर उम्मीदों का भार होगा, लेकिन इस युवा खिलाड़ी को लगता है कि उम्मीदें बताती हैं कि लोगों का समर्थन उनके साथ है जो उन्हें ओलंपिक में मदद करेगा। यहां हुए हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग कैंप के अंत में मनु ने कहा कि मुझे लगता है कि उम्मीदों का मतलब है कि लोग आपका समर्थन करते हैं।

मैं दुनिया में कई क्रिकेटरों के साथ खेला हूं, लेकिन एबी डिविलियर्स मेरे लिए खास हैं। उनको जन्मदिन की बधाई।
– केएल राहुल, भारतीय बल्लेबाज

गत विजेता लिवरपूल के सामने एटलेटिको मैड्रिड की चुनौती

फुटबॉल डायरी ▶ यूएफा चैंपियंस लीग में अंतिम-16 के पहले चरण में भिड़ेंगी दोनों टीमें, लिवरपूल के सलाह पर होंगी सभी की निगाहें

डॉर्टमंड के खिलाफ मैच के लिए नेमार की पीएसजी की टीम में वापसी

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

गत विजेता लिवरपूल की टीम को मैड्रिड के वांडा मेट्रोपोलिटानो में मंगलवार देर रात होने वाले यूएफा चैंपियंस लीग में अंतिम-16 के पहले चरण के मुकाबले में एटलेटिको मैड्रिड की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।

मैनेजर जुर्जेन क्लोप की टीम लिवरपूल अपने खिताब को बचाने के लिए अग्रसर है। हालांकि इस लीग में दोनों टीमों दो बार एक-दूसरे का सामना कर चुकी हैं और दोनों बार मुकाबला 1-1 के स्कोर से बराबरी पर खत्म हुए हैं। दोनों टीमों के बीच पिछले पांच मुकाबलों की बात की जाए तो दोनों टीमें एक-दूसरे को एक-एक बार हरा चुकी हैं जबकि तीन मैच ड्रॉ पर समाप्त हुए हैं। मैड्रिड की टीम पिछले सात मैचों में से सिर्फ एक में जीत हासिल कर पाई है जबकि दो मैच उसने ड्रॉ खेले हैं और चार मुकाबलों में उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा है।

खिलाड़ियों की चोट से परेशान सिमोन : मैड्रिड के मैनेजर डिएगो सिमोन खिलाड़ियों की चोट से परेशान हैं जिसका असर टीम के गोल करने की रणनीति पर पड़ सकता है। मैड्रिड की उम्मीद अल्वारो मोराटा से है, लेकिन उनके खेलने पर संशय बना हुआ है। इसके अलावा मैड्रिड को डिएगो कोस्टा और जोआओ फेलिक्स के बिना उतरना होगा जबकि मोराटा की फिटनेस को लेकर भी अभी स्थिति साफ नहीं है क्योंकि वह वेलेंसिया के खिलाफ पिछले मैच में सिर्फ 24 मिनट तक ही मैदान पर उतरे थे। मैड्रिड के मैनेजर डिएगो सिमोन ने कहा, 'हम मैच जीत भी सकते हैं और हार भी, लेकिन मैं अपने खिलाड़ियों को जानता हूं कि वह नतीजा बदलने में सक्षम हैं।'

क्लोप के पास सलाह और माने : हालांकि इस मैच में क्लोप की टीम को जीत का दावेदार बताया जा रहा है क्योंकि उसके पास मुहम्मद सलाह जैसे अच्छे स्ट्राइकर मौजूद हैं। सलाह पिछले तीन मैचों में लगातार तीन गोल कर चुके हैं जबकि उन्होंने चैंपियंस लीग में चार में से तीन गोल दूसरे हाफ में दागे हैं। लिवरपूल के पिछले छह ग्रुप मैचों में से चार गोल 80वें मिनट के बाद हुए हैं। सलाह के अलावा क्लोप के पास सादियो माने भी हैं जिनके एकमात्र गोल से क्लब ने ईपीएल के पिछले मैच में नॉर्विक सिटी को हराया था। इसके साथ ही उन्होंने इंग्लिश फुटबॉल में अपने 100 गोल भी पूरे किए थे।

घरेलू दर्शकों के सामने मैड्रिड मजबूत : मैड्रिड अपने घरेलू दर्शकों के सामने काफी मजबूत टीम है और उसे पिछले 21 मैचों में से एक में ही शिकस्त का सामना करना पड़ा है। वहीं, लिवरपूल को यहां खेलने में हमेशा से परेशानी हुई है। उसे पिछले साल यहां जीत जून में मिली थी जब उसने छठा यूरोपियन कप का खिताब जीता था। ऐसे में अब देखना होगा कि यह टीम घरेलू दर्शकों के सामने कैसा प्रदर्शन करती है। दर्शकों को हालांकि अपनी टीम से उम्मीद होंगी।

लिवरपूल के सादियो माने। रायटर

नेमार ने दी टीम को राहत

डॉर्टमंड के खिलाफ मंगलवार देर रात को अंतिम-16 के पहले चरण के मैच में विश्व के सबसे महंगे फुटबॉलर नेमार की पीएसजी की टीम में वापसी हुई है। यह मैच डॉर्टमंड के सिगनल इडुना पार्क में होगा। नेमार की वापसी से मैनेजर थॉमस टुकेल को राहत की सांस मिली होगी क्योंकि टीम ने लीग-1 के मैच में एमिनेंज के खिलाफ चार गोल करने के बाद भी मैच 4-4 के स्कोर से ड्रॉ खेलना पड़ा था। यह ब्राजीली स्ट्राइकर पसली की चोट के बाद डॉर्टमंड के खिलाफ घोषित 21 सदस्यीय टीम में वापसी कर रहा है। एक फरवरी को पीएसजी के पिछले मैच में नेमार चोटिल हो गए थे। वह पिछले चार मैचों से नहीं खेल पाए हैं। शनिवार को एमिनेंज के खिलाफ मैच के लिए नेमार उपलब्ध थे, लेकिन मैनेजर टुकेल ने डॉर्टमंड के खिलाफ मैच को ध्यान में रखते हुए बिना कोई जोखिम उठाए नेमार को मैदान पर नहीं उतारा था। नेमार इस सत्र में लीग-1 में 13 गोल कर चुके हैं जबकि उन्होंने छह गोल करने में मदद की है। इसके अलावा उन्होंने चैंपियंस लीग में गालटासराय के खिलाफ मैच में भी गोल किया था।

सेल्टा विगो ने रीयल मैड्रिड के साथ खेला ड्रॉ

मैड्रिड : अंतिम सीटी बजने से पांच मिनट पहले डेनिस सुआरेज द्वारा सांटी मिना को दिए गए पास के कारण हुए गोल के दम पर सेल्टा विगो ने स्पेनिश लीग ला लीगा के मैच में रीयल मैड्रिड के जीत के सपनों पर पानी फेरते हुए मैच 2-2 से ड्रॉ करा दिया। सेल्टा विगो ने सातवें मिनट में ही फेडोर स्मोलोव की मदद से मैच में खाता खोला।

इयागो एस्पास ने स्मोलोव को गेंद दी, जिन्होंने मैड्रिड के गोलकीपर थिबाउट कुर्टियोस को छकाकर गेंद को नेट में डाल दिया। पहले हाफ में मैनेजर जिनेदिन जिदान की टीम रीयल मैड्रिड गोल करने के प्रयास में असफल रही। पहले हाफ के खत्म होने में कुछ मिनट ही बचे थे और मेहमान टीम ने लगभग दूसरा गोल कर दिया था लेकिन मेजबान टीम के गोलकीपर कुर्टियोस ने ऐसा होने नहीं दिया। दूसरे हाफ में मैड्रिड की टीम ने अपनी रणनीति को बदलते हुए दो गोल किए। मैड्रिड के गेरेथ बेल ने रामोस को गेंद दी जिन्होंने गोल कर दिया, लेकिन वार के कारण इसे ऑफ साइड करार दे दिया गया। मेजबान टीम को हालांकि बराबरी का गोल करने में ज्यादा समय नहीं लगा।

जर्मनी के टॉनी क्रूस ने 52वें मिनट में मार्सेलो द्वारा दिए गए पास पर गोल करते हुए स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। इसके बाद 65वें मिनट में मिली पेनाल्टी पर कप्तान रामोस ने गोल कर मैड्रिड को एक गोल से आगे कर दिया। मैड्रिड को यह पेनाल्टी सेल्टा के गोलकीपर रुबेन ब्लांको द्वारा ईडन हेजार्ड को गिराने के बाद मिली थी। इस बीच, सैंटी मीना ने गोल करके मेजबान टीम की उम्मीद तोड़ दी और मैच को बराबरी पर खत्म कर दिया।

अनधिकृत कबड्डी टीम के पाक में खेलने की होगी जांच

जागरण संवाददाता, अमृतसर : खेल मंत्री किरन रिजिजू ने सोमवार को राष्ट्रीय कबड्डी महासंघ (एकेएफआइ) को 'अनधिकृत' भारतीय टीम के पाकिस्तान में सर्कल शैली के विश्व कप में हिस्सा लेने की जांच करने के आदेश दिए हैं। इस बीच फाइनल में हार के बाद भारतीय खिलाड़ी सोमवार को वाघा-अटारी सीमा के रास्ते भारत लौट आए हैं, जिसके बाद टीम के मैनेजर ने कहा है कि 'अनौपचारिक' टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए स्वीकृति की जरूरत नहीं थी।

नई दिल्ली में खेल मंत्री रिजिजू ने कहा, 'यह सही नहीं है कि कोई भी अनधिकृत टीम कहीं भी जाए और भारत के नाम से खेले। हमने कोई आधिकारिक टीम नहीं भेजी। हम कबड्डी महासंघ से जांच करने को कहेंगे और उन लोगों की पहचान करेंगे, जो वहां गए और बिना स्वीकृति के भारत के नाम का इस्तेमाल किया।' हालांकि, उन्होंने साथ ही कहा, 'अगर कोई किसी निजी टूर्नामेंट के लिए जाता है तो हम कुछ नहीं कर सकते।'

वहीं, कबड्डी टीम के मैनेजर दविंदर बाजवा ने ज्वाइंट चेक पोस्ट अटारी पर पत्रकारों से कहा कि पिछले समय के दौरान भारत-पाक के बीच बेहद खराब रिश्तों के बीच गुरु नानक देव के 550वें प्रकाश पर्व पर पाकिस्तान में करवाए गए कबड्डी टूर्नामेंट के लिए इन कबड्डी खिलाड़ियों को पाकिस्तान बुलाया गया था। अगर जाते समय उन्हें भारत सरकार द्वारा रोका जाता या फिर लाहौर पहुंचने के बाद भी भारतीय दूतावास की ओर से ऐसी हिदायतें दी जातीं, तो वे अवश्य ही भारत लौट आते। एक कबड्डी मैच के दौरान ग्राउंड में खालिस्तान का झंडा लहराए जाने के बारे में पूछे जाने पर बाजवा ने कहा कि उन्होंने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। उनका पूरा ध्यान मैच की तरफ था।

भारत-पाक के बीच खटास भरे रिश्तों के बीच कबड्डी खिलाड़ियों का पाकिस्तान में खेलने जाने के बारे में पूछे गए सवाल को पहले तो बाजवा सवाल टाल गए। मगर, फिर कहा कि वे भारतीय कबड्डी टीम की ओर से नहीं गए। सभी खिलाड़ी व्यक्तिगत वीजा पर पाक गए और टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। फाइनल में भारत को हराकर खिताब जीतने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपनी टीम को ट्विटर पर बधाई दी। रिजिजू ने कहा कि पाक के प्रधानमंत्री के लिए यह बुद्धिमानी भरा नहीं है।

दक्षिण अफ्रीकी टी-20 टीम में डुप्लेसिस, रबादा की वापसी

▶ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होनी है तीन मैचों की टी-20 सीरीज

▶ इंग्लैंड के खिलाफ वनडे और टी-20 सीरीज से दिया गया था आराम

जोहानिसबर्ग, एएफपी : पूर्व कप्तान फाफ डुप्लेसिस और तेज गेंदबाज कैगिसो रबादा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुक्रवार को शुरू हो रही तीन टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीकी टीम में वापसी की। सोमवार को कप्तानी छोड़ने की घोषणा करने वाले डुप्लेसिस को क्विंटन डिकॉक की अगुआई वाली 16 सदस्यीय टीम में जगह दी गई है। डुप्लेसिस ने सोमवार को ही टी-20 और टेस्ट टीम से कप्तानी छोड़ी है।

डुप्लेसिस और रबादा दोनों को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाद हुई वनडे और टी-20 सीरीज से आराम दिया गया था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज का पहला मैच 21 फरवरी को जोहानिसबर्ग में होगा जबकि अगले दो मैच पोर्ट एलिजाबेथ (23 फरवरी) और केपटाउन (26 फरवरी) में खेले जाएंगे।

टीम : क्विंटन डिकॉक (कप्तान), तेंबा बावुमा, फाफ डुप्लेसिस, ब्योर्न फोरटुइन, हेनरिक क्लासेन, डेविड मिलर, लुंगी नगिदी, एनरिक नोर्त्जे, आंदिले फेलुकवायो, ड्वेन प्रिटोरियस, कैगिसो रबादा, तबरेज शम्सी, जॉन-जॉन स्मट्स, डेल स्टेन, पीट वान बिल्जोन और रेसे वान डेर डुसेन।

दुबई ओपन में खेलेंगी दिग्गज सानिया मिर्जा

टेनिस डायरी

दुबई, प्रेट्र : भारत की स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा पिंडली की चोट से उबरने के बाद बुधवार को दुबई ओपन के साथ वापसी करेंगी। पिंडली के चोट के कारण सानिया को जनवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन के मुकाबले के बीच से हटना पड़ा था। 33 वर्षीय सानिया ने इस टूर्नामेंट के लिए फ्रांस की कैरोलिन गार्सिया के साथ जोड़ी बनाई है।

यह जोड़ी महिला डबल्स के पहले दौर में बुधवार को रूस के एला कुद्रियावत्सेवा और स्लोवेनिया की कैटरीना सरेबोटनिक की जोड़ी से भिड़ेगी। सानिया ने कहा, 'चोट के कारण ग्रैंडस्लैम टूर्नामेंट के बीच से हटना दुखद अनुभव था। विशेषकर तब जब आप लंबे ब्रेक के बाद वापसी कर रहे हों। इस टूर्नामेंट के लिए मुझे फिट करने के लिए मैं अपने फिजियो डॉ. फैजल हयात खान की आभारी हूं। मैंने अभ्यास शुरू कर दिया है और टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए उत्सुक हूं।' मां बनने के कारण दो साल के ब्रेक के बाद सर्किट पर वापसी कर रही सानिया दाईं पिंडली की चोट कारण अपने पहले ग्रैंडस्लैम टूर्नामेंट के महिला डबल्स के पहले दौर के मुकाबले के बीच से हट गई थीं। ब्रेक के बाद शानदार वापसी करते हुए सानिया और यूक्रेन की उनकी जोड़ीदार नादिया किचेनोक ने होबार्ट अंतरराष्ट्रीय का डबल्स खिताब जीता था।

सानिया मिर्जा। फाइल फोटो, प्रेट्र

जोकोविक सर्वकालिक महान खिलाड़ियों की दौड़ में शामिल : बेकर

बर्लिन (जर्मनी), एएनआइ : छह बार के ग्रैंडस्लैम विजेता बोरिस बेकर का मानना है कि सर्बिया के नोवाक जोकोविक सर्वकालिक महान खिलाड़ियों की श्रेणियों में आ रहे हैं। बेकर तीन साल तक जोकोविक के कोच भी रह चुके हैं। विश्व के नंबर एक खिलाड़ी जोकोविक ने इस साल फाइनल में डोमिनिक थिएम को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता था। इसके साथ ही उन्होंने 17वीं बार ग्रैंडस्लैम की विजेता ट्रॉफी अपने नाम की थी। बेकर ने कहा, 'मुझे लगता है कि पूर्व विश्व में जोकोविक के करोड़ों में प्रशंसक हैं। मैं इस चीज से सहमत नहीं हूं कि सिर्फ फेडरर और नडाल के ही प्रशंसक हैं। लेकिन जब आप टेनिस के सर्वकालिक महान खिलाड़ियों की बात करते हैं तो इसमें जोकोविक धीरे-धीरे आ रहे हैं। फेडरर 20 और नडाल 19 ग्रैंडस्लैम खिताब जीत चुके हैं और जोकोविक धीरे-धीरे उनके करीब पहुंच रहे हैं। ये तीनों ही ज्यादातर ग्रैंडस्लैम जीत रहे हैं।

विविध

साकार होने लगा है गांधीजी की कल्पना का भारत : भागवत

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक डॉ. मोहन भागवत ने आश्वस्त किया कि देश महात्मा गांधी की कल्पना का भारत बनने की ओर आगे बढ़ रहा है और इसमें नई पीढ़ी प्रमुख भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि 20 सालों के बाद यह बदलाव स्पष्ट दिखाई देगा। उस बदलाव में हम गांधीजी से कह सकेंगे कि वह यहां आश्रम बनाकर रह सकते हैं। वह दिल्ली में सोमवार को 30 जनवरी मार्ग स्थित गांधी स्मृति में शिक्षाविद प्रो. जगमोहन सिंह राजपूत की पुस्तक 'गांधी को समझने का यही समय' के विमोचन पर लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये बात 20 साल पहले असंभव लगती थी, लेकिन आज पूरे देश में घूमने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि गांधीजी की कल्पना का भारत साकार होने लगा है।

भागवत ने कहा कि भारत का आदमी कैसा हो, इसके लिए गांधीजी ने भारत की दृष्टि के आधार पर सोचा। वह भारतीय दृष्टि के आविष्कार थे। वह अपनी धारणाओं का खुद पर प्रयोग करते थे और इसी वजह से हिंदू होने पर उन्होंने कभी लज्जा जाहिर नहीं की। बल्कि कई बार कहा कि वह पूरी तरह से सनातन में विश्वास रखते हैं और कट्टर हिंदू हैं। इसलिए पूजा में भेद को नहीं मानता हूं। मैं अपने धर्म में रहूं। तुम अपने धर्म में रहो। क्योंकि धर्म का अंतिम सत्य एक ही है।

उन्होंने मौजूदा शिक्षा नीति पर प्रहार करते हुए कहा कि शिक्षा के जरिये हमारा दिमाग बिगाड़ दिया गया है। एक समय था जब हमारी चीजों को गलत मानकर चला जाता था, लेकिन अब स्थिति बदल रही है। उन्होंने सत्य परक शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि इसके माध्यम से ये नहीं बताया जाना चाहिए कि ये हमारे पक्ष का है और ये विपक्ष का।

नई दिल्ली में सोमवार को गांधी स्मृति में स्मारक पर श्रद्धासुमन अर्पित करते आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। प्रेट्र

काशी-महाकाल एक्सप्रेस इंदौर पहुंची गूंजा 'बम-बम बोल रहा इंदौर'

नईदुनिया, इंदौर

मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को सोमवार सुबह 8:10 बजे एक नई सौगात उस वक्त मिली, जब रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर पांच पर देश की तीसरी कॉर्पोरेट ट्रेन काशी-महाकाल एक्सप्रेस पहुंची। यह ट्रेन का 'फेम रन' था, इस वजह से इसमें यात्री तो नहीं थे लेकिन ट्रेन में अयोध्या के राजेश कुमार के साथ 10 लोगों की भजन मंडली ढोल-मंजीरों के साथ आई। यह मंडली ट्रेन में भजन गाते हुए आई। ट्रेन रुकते ही झांझ-मंजीरे की आवाज के साथ प्लेटफॉर्म नंबर पांच 'बम बम बोल रहा इंदौर' से गूंज उठा। प्लेटफॉर्म पर पहले से ही रेलवे और आइआरसीटीसी के आला अफसर मौजूद थे।

21 फरवरी से यह ट्रेन इंदौर से सप्ताह में तीन दिन नियमित रूप से चलेगी। उस समय इसमें भजन मंडली तो नहीं होगी लेकिन ट्रेन में स्पीकर लगे हुए हैं। ऐसे में उज्जैन स्टेशन आने पर यात्री भोलेनाथ के भजन व पूरे सफर के दौरान मधुर गीत भी सुन सकेंगे।

सिर्फ ट्रायल रन के लिए कोच में बनाया महाकाल का दरबार : सोमवार को इंदौर पहुंची इस ट्रेन के कोच नंबर बी-4 की सीट नंबर 64 पर बाबा महाकाल का दरबार मंदिर की तरह सजाया गया था।

यहां भगवान भोलेनाथ का फोटो रखा हुआ था और इसे फूलों से भव्य तरीके से सजाया गया। ट्रेन में महाकाल दरबार को देखकर शहर में रेलवे के अफसरों के बीच यह चर्चा चली कि इस कोच में एक सीट बाबा महाकाल के लिए रिजर्व रहेगी। हालांकि आइआरसीटीसी के पीआरओ पिनाकिन मारवाला के मुताबिक, सिर्फ ट्रायल रन के लिए ही इसमें एक सीट पर बाबा महाकाल का दरबार सजाया था और सीट रिजर्व की गई थी। हमेशा सीट रिजर्व जैसी बात नहीं है।

▶ ट्रायल रन होने से ट्रेन में यात्री नहीं थे, 10 लोगों की मंडली भजन करते आई

▶ आइआरसीटीसी की सफाई, हमेशा के लिए नहीं है कोच में बनाया महाकाल का दरबार

20 फरवरी को वाराणसी से इंदौर के लिए रवाना होगी

21 फरवरी को इंदौर से वाराणसी के लिए शुरू होगा सफर

9 कोच हैं इस ट्रेन में, 550 यात्री कर सकेंगे सफर

मालवी पगड़ी में परोसा गया खाना

पहली बार आई इस ट्रेन में कैटरिंग स्टाफ ने खास ड्रेस कोड के रूप में कुर्ता-पायजामा और सिर पर मालवी पगड़ी पहन रखी थी। ट्रेन में आई भजन मंडली के सदस्यों, रेलवे अफसरों को उन्होंने खाना परोसा। रेलवे प्रबंधन के मुताबिक, ट्रेन के कैटरिंग स्टाफ का ड्रेस कोड अलग होगा, लेकिन पहली बार फेम रन में भक्तिमय माहौल के कारण उन्हें यह ड्रेस कोड दिया गया।

काशी-महाकाल एक्सप्रेस के कोच नंबर बी-4 की सीट नंबर 64 पर बाबा महाकाल का दरबार सजाया गया था। एएनआइ

पाकिस्तान में कटास राज मंदिरों के दर्शन के लिए भारतीय श्रद्धालुओं को वीजा जारी

नई दिल्ली, एजेंसियां : पाकिस्तानी उच्चायोग ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के चकवाल जिले में स्थित श्री कटास राज मंदिरों के दर्शन के लिए हिंदू श्रद्धालुओं के एक समूह को वीजा दिया है। पाकिस्तान उच्चायोग ने बयान जारी करके कहा है कि 19 से 25 फरवरी तक किला कटास या कटास मंदिर के परिसर के दर्शन के लिए हिंदू श्रद्धालुओं का एक जत्था जाएगा। पाकिस्तान में स्थित सबसे प्राचीन और अहम हिंदू मंदिरों का समूह कटास नाम के एक पवित्र सरोवर के किनारे स्थित है। पिछले साल 13 से 19 दिसंबर के बीच 88 भारतीय हिंदू श्रद्धालु श्री कटार राज मंदिरों का दर्शन करके आए थे। ये दोनों ही तीर्थ यात्राएं भारत-पाकिस्तान प्रोटोकाल, 1974 के तहत आयोजित की गईं। इसके जरिये दोनों देशों के श्रद्धालु दोनों देशों में स्थित अपने धर्मस्थलों में जा सकते हैं। इसीलिए पाकिस्तान सरकार समय-समय पर हिंदू और सिख श्रद्धालुओं को वीजा देती है।

अब केवल राम, शिव और हनुमान के मंदिर बचे हैं : कटास राज मंदिर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के चकवाल जिले में स्थित है। यह सात मंदिरों का समूह था, जिसमें से अब सिर्फ चार मंदिर बचे हैं। इनमें भगवान राम, शिव और हनुमान के मंदिर हैं। साथ ही यहां पर स्थित सरोवर के बारे में मान्यता है कि सती की अग्नि समाधि से दुखी भगवान शिव की आंखों से गिरे दो आंसुओं में से एक यहां पर गिरा था जिससे यह सरोवर बना। दूसरा आंसू राजस्थान के पुष्कर में गिरा। वहां भी पुष्कर सरोवर है। कटाक्ष से कटास राज की उत्पत्ति मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव को लेकर बहुत कटाक्ष किए थे। वहीं महाभारत काल में पांडव भी यहां पहुंचे थे। इसके अतिरिक्त यह कला और संस्कृति का भी कभी बड़ा केंद्र हुआ करता था। 11वीं सदी में महमूद गजनवी के आक्रमण के बाद इस मंदिर को क्षति पहुंची थी। कई ऐतिहासिक अभिलेख बताते हैं कि इनमें से कई मंदिर कश्मीरी वास्तुकला को प्रदर्शित करते हैं। कटास राज केवल हिंदू मंदिर नहीं है। मान्यता है कि गुरुनानक देव भी यहां पर आए थे। साथ ही यहां पर एक बौद्ध स्तूप के अवशेष भी मिले थे।

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित कटास राज मंदिर का फाइल फोटो।

ग्रेनो से धार्मिक स्थलों के लिए उड़ान भरेंगे हेलीकॉप्टर

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा : ग्रेटर नोएडा वासियों को हेलीकॉप्टर सेवा लेने के लिए अब दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के खैरपुर गुर्जर गांव में प्रभु हेली सर्विस कंपनी ने हेलीपैड बनाया है। कंपनी का दावा है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय व पुलिस से अनुमति मिल गई है। गौतमबुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह का कहना है कि कंपनी को सशर्त अनुमति दी गई है। अनुमति मिलने के बाद सोमवार को गांव में कंपनी का हेलीकॉप्टर भी उतारा गया। 25 फरवरी से वाराणसी के लिए पहली उड़ान शुरू होगी। लोग वृंदावन, जम्मू, हरिद्वार व चार धाम के लिए यहां से हेलीकॉप्टर से उड़ान भरेंगे। खैरपुर गुर्जर गांव में ही हेलीपैड के समीप एक टिकट काउंटर बनाया गया है।

शिअद ने कहा, संसद के सामने धरना दें सभी पार्टियां

▶ खेती संकट को लेकर किसान भवन में सभी पार्टियों के विधायक जुटे

▶ जाखड़ ने कहा, दविंदर शर्मा का विधानसभा में लेक्चर करवाने की कोशिश करेंगे

इन्द्रप्रीत सिंह, चंडीगढ़

शिरोमणि अकाली दल ने केंद्र में अपनी सहयोगी पार्टी भाजपा के लिए यह कहते हुए फिर से मुसीबत खड़ी कर दी है कि सभी पार्टियों को दो मार्च से शुरू होने वाले बजट सत्र के दौरान धरना देना चाहिए। शिअद के जनरल सेक्रेटरी व राज्यसभा सदस्य बलविंद सिंह भूंदड़ ने कहा कि असंगठित होने के कारण किसान अपने आप को लुटवा रहे हैं, जबकि दूसरी ओर अंबानी और अडानी जैसे लोगों ने सरकारें खरीद रखी हैं। उनका साथ आम आदमी पार्टी के विधायक कुलतार सिंह संधवां ने यह कहते हुए दिया कि पार्टियों की हालत 'जिसकी खाएं बाजरी, उसकी भरें हाजिरी' जैसी हो गई है। इसलिए जरूरत यह पता लगाने कि है किन-किन पॉलिटिकल पार्टियों को उद्योगपतियों की ओर से कितनी फंडिंग की जाती है।

राज्यसभा सदस्य बलविंदर सिंह भूंदड़ ने जब यह बयान दिया तो उस समय भाजपा किसान प्रकोष्ठ के हरजीत सिंह ग्रेवाल भी मौजूद थे। इस दौरान केंद्र सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य से पीछे हटने की बात चल रही थी। भारतीय किसान यूनियन ने सभी पार्टियों के अध्यक्षों, विधायकों व अन्य नेताओं को आमंत्रित किया। उन्होंने दबाव बनाया कि विधानसभा व संसद में इस पर विशेष बहस करवाई जाए। यह पहला मौका था, जब इतनी बड़ी संख्या में सभी पार्टियों के विधायक व नेताओं ने खेती व किसानी के संकट पर चर्चा की। प्रदेश में सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा कि वह मुख्यमंत्री व स्पीकर से बात करके दो दिन का विशेष सेशन खेती संकट पर ही करवाने की कोशिश करेंगे। इससे पहले भाकियू के प्रधान बलबीर सिंह राजेवाल ने न्यूनतम समर्थन मूल्य से पीछे हटने के बारे में प्रकाश डाला और बताया कि एमएसपी के कारण ही पंजाब, हरियाणा ने देश का अन्न भंडार सुरक्षित रखा हुआ है।

खेती नीतियों के विशेषज्ञ दविंदर शर्मा ने कहा कि जो लोग यह कहते हैं कि अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया में खेती बढ़िया है, उन्हें वहां की हालत देखनी चाहिए। अमेरिका में 87 फीसद किसान खेती छोड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जब अमेरिका में 65 हजार डॉलर की सब्सिडी दी जाती है, तब उनके किसानों का यह हाल है, तो भारत के किसानों का क्या होगा। यहां मात्र 250 डॉलर की सब्सिडी दी जाती है। अगर 1970 के सूचकांक को आधार बनाया जाए, तो कर्मचारियों की तनख्वाह में 300 गुणा वृद्धि हुई है, जबकि फसलों की कीमत 19 गुणा बढ़ी है। उन्होंने आशंका जताई कि एमएसपी को तोड़ने का मतलब सीधा खेती को कॉरपोरेट के हवाले करना है। भारत 76 हजार करोड़ रुपये के खाद्य तेल आयात करता है, क्या यह यहां के किसानों से नहीं करवाया जा सकता?

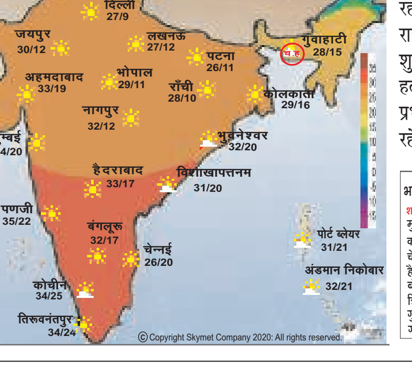

मौसम विशेष

जम्मू-कश्मीर में मुख्यतः आसमान साफ बना रहेगा। लद्दाख में आंशिक बादल छाए रहेंगे। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान व उत्तर प्रदेश का मौसम शुष्क बना रहेगा। दिन के समय हल्की से मध्यम गति की हवाएं प्रभावित करेंगी तथा दोपहर गर्म रहेगी। सुबह ठंडी बनी रहेगी।

भारत के मुख्य शहरों का तापमान:

शहर		शहर	
मुम्बई	33/21/सा	अहमदाबाद	36/16/सा
कोलकाता	30/16/सा	बड़ौदा	36/14/सा
चेन्नई	32/20/सा	नागपुर	33/13/सा
हैदराबाद	33/16/सा	इन्दौर	29/16/सा
बंगलूरू	31/16/सा	राँची	27/11/आंबा
त्रिवेन्द्रम	33/25/आंबा	पटना	25/12/सा
गुवाहाटी	29/17/सा	जमशेदपुर	29/13/सा
गंगटोक	13/06/सा	पुणे	34/19/सा

1911 में पहली बार विमान से भेजी गई थी डाक

आज ही के दिन 1911 में पहली बार विमान के जरिए डाक भेजी गई थी। इलाहाबाद से नैनी यह डाक भेजी गई थी। पूरे क्षेत्र के लोगों से डाक को ट्रिनिटी चर्च में इकट्ठा किया गया था। इस पहले वायुडाक विमान को फ्रांसीसी पायलट हेनरी पेक्वेट ने उड़ाया था। पांच मील की दूरी पर 6,500 पत्रों को लेकर उड़ान भरी गई।

लंदन में होमरूल सोसायटी की स्थापना की गई

आज ही के दिन 1905 में क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन होमरूल सोसायटी की स्थापना की थी। इस संस्था का लिखित संविधान था। भारत में स्वशासन और ब्रिटेन में भारत का प्रचार इसका मकसद था।

आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त करने वाले रामकृष्ण परमहंस

आज ही 836 में रामकृष्ण परमहंस का जन्म बंगाल प्रांत के हुगली जिले में हुआ था। शुरुआत में नाम गदाधर था। सात वर्ष की आयु में पिता का निधन हो गया। अच्छा गा सकते थे, चित्रकारी कर सकते थे। 1856 में दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुरोहित बने। तोतापुरी महाराज से अद्वैत वेदांत की शिक्षा पाई। आध्यात्मिक अनुभूतियों के कारण लोग पागल समझने लगे। 1859 में उनकी शादी सारदा मणि से कर दी गई। अपनी विरासत उन्होंने स्वामी विवेकानंद को सौंपी। 16 अगस्त 1886 को कलकत्ता के कोसिपोर में देह त्याग दी।

इधर-उधर की

रिसॉर्ट में हेलीकॉप्टर से गिराई बर्फ

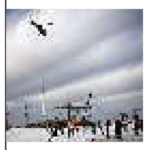

पेरिस, एजेंसी : बर्फ की कमी के चलते कई बार लोगों को पहाड़ों से निराश लौटना पड़ता है, लेकिन फ्रांस में बर्फ की कमी को दूर करने के लिए सबसे अलग रास्ता अपनाया गया है। फ्रांस में एक रिसॉर्ट ने स्की ढलानों को बंद होने से रोकने के लिए करीब 60 टन बर्फ गिराने के लिए दो हेलीकॉप्टरों की मदद ली। हालांकि लुचोन-सुपरबेगनेरेस के अधिकारियों के इस फैसले की काउंसिल और पर्यावरण प्रेमियों ने आलोचना की है। निदेशक हेरवे पनाऊ ने कहा कि हम बर्फ से पूरे स्की स्टेशन को ढकने नहीं जा रहे हैं। बर्फ की गैरमौजूदगी में हमें स्की क्षेत्र का बड़ा हिस्सा बंद करना होगा। रिसॉर्ट में बर्फ की कमी ने पहले से ही खुली ढलानों की संख्या 28 से छह कर दी थी। इस ऑपरेशन के बाद स्की केंद्रों की 15 दिनों की गतिविधि सुनिश्चित की जा सकेगी। हालांकि, एक पारिस्थितिकी विज्ञानी ने इस निर्णय को पागलपन बताया।

अब कुछ सेकेंड में कैंसर का चलेगा पता

तकनीक ▶ कोलकाता के शोधकर्ताओं ने शोध कर एक विशेष प्रकार की चिप विकसित की

जागरण ब्यूरो, कोलकाता

प्रतीकात्मक

- जादवपुर विवि के भौतिक विभाग के प्रोफेसर ने किया शोध
- वर्तमान में इंडोस्कोपी, बायोस्कोपी से की जाती है कैंसर की जांच

शरीर में कैंसर है कि नहीं अब इसका महज कुछ ही सेकेंड में पता चल सकेगा। जी हां, कोलकाता के जादवपुर विश्वविद्यालय के भौतिक विभाग के प्रोफेसर ने शोध कर एक विशेष प्रकार की चिप विकसित की है, जिसके जरिए तुरंत कैंसर का पता चल सकेगा। फिलहाल प्रोस्टेट व ब्रेस्ट कैंसर पर जादवपुर विश्वविद्यालय के भौतिक विभाग के प्रोफेसर जयदीप चौधरी व उनके शोधकर्ता छात्र सुमित कुमार दास ने शोध किया है। जीव विज्ञान के प्रोफेसर परिमल कर्मकार तथा शोधकर्ता छात्र कुणाल पाल ने उनकी सहायता की है। इसके अलावा बोस इंस्टीट्यूट के भौतिक विभाग के शोधकर्ता छात्र ताराशंकर भट्टाचार्य ने भी मदद की है। विशेषज्ञों का मानना है कि जादवपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर का शोध कैंसर की जांच के मामले में नई दिशा दिखाएगा।

प्रोफेसर जयदीप चौधरी के मुताबिक विश्वविद्यालय के जीव विज्ञान विभाग ने पुणे के नेशनल सेंटर फार सेल साइंस से एक सेल (कोषिका) की खरीदारी की। प्रयोगशाला में ही सेल को बड़ा किया गया। हालांकि, इसके लिए खास तापमान में विशेष तरह की पद्धति अपनाई गई। सेल के बड़े हो जाने पर उसे शोध के लिए भौतिक विभाग को दिया गया। इसके बाद सेल को लैंग्मूर ब्लजेट यंत्र की सहायता से तैयार किए गए चिप पर रखा गया जिससे यह पता चल सके कि यह टॉक्सिक हुआ है या नहीं। क्योंकि सेल के टॉक्सिक हो जाने पर उस पर शोध संभव नहीं था, लेकिन परीक्षण के बाद देखा गया कि इस तरह की खास कोई समस्या नहीं देखी गई। इसके बाद सरफेस इंहेस्ड रमन स्पेक्ट्रोस्केपिक की सहायता से सेल का परीक्षण किया गया। प्रोफेसर के मुताबिक सामान्य व कैंसर युक्त सेल को चिप पर रखा गया। इसके बाद सरफेस इंहेस्ड रमन स्पेक्ट्रोस्केपिक की मदद से दोनों सेलों में फर्क को देखा गया। देखा गया कुछ ही सेकेंड में कैंसर की जांच का पता चल गया। हाल में सेंसर्स एंड एक्टुएटर्सबी जर्नल में इस शोध से जुड़ा एक पेपर प्रकाशित हुआ है। प्रोफेसर का कहना है कि अगर आने वाले दिनों इस तरह की पद्धति को प्रयोगशालाओं या परीक्षण केंद्रों में अपनाया जाता है तो शीघ्र कैंसर की जांच मुमकिन होगी। जितनी जल्दी कैंसर का पता चलेगा उतनी जल्दी इलाज शुरू हो सकेगा। मौजूदा समय में कैंसर का पता लगाने के लिए इंडोस्कोपी, बायोस्कोपी आदि जांच की जाती है। लेकिन इसकी रिपोर्ट आने में कम से कम तीन से पांच दिन का समय लगता है। उन्होंने कहा कि अगर राज्य का स्वास्थ्य विभाग इस पद्धति को अपनाना चाहता है तो वह इस मामले में पूरी मदद करेंगे।

विशेषज्ञों का कहना है कि प्रति वर्ष लाखों लोग कैंसर का शिकार हो रहे हैं। इसमें पुरुषों में प्रोस्टेट तथा महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के मामले भी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं।

टिड्डियों के प्रकोप से निपटने को नया एप तैयार

संयुक्त राष्ट्र ने टिड्डियों से निपटने को तुरंत एक्शन लेने को कहा है। प्रतीकात्मक

लंदन, प्रेट्र : शोधकर्ताओं ने फसल को कीटों से बचाने के लिए एक नया स्मार्टफोन एप विकसित किया है। नए एप के माध्यम से किसान अपनी फसलों को टिड्डियों के प्रकोप से बचा सकेंगे। हाल ही में पाकिस्तान और भारत के राजस्थान और पंजाब में टिड्डियों का प्रकोप छाया हुआ है। संयुक्त राष्ट्र ने भी इस दिशा में तुरंत एक्शन लेने को कहा है।

साइंटिफिक रिपोर्ट जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में इस एप के बारे में जानकारी दी गई है। इस एप का नाम 'माइस्ट्रो' है। यह एप स्मार्टफोन के कैमरे के माध्यम से टिड्डियों और कीटों को पहचान सकता है और उनकी जीपीएस लोकेशन को भी रिकॉर्ड कर सकता है। ब्रिटेन की लिंकन यूनिवर्सिटी समेत शोधकर्ताओं की टीम ने बताया कि किसान इस एप के माध्यम से कीटों और टिड्डियों के स्थान और मात्रा का पता लगा सकते हैं। इसके बाद यह पता चल जाएगा कि कितनी मात्रा के कीटनाशक की जरूरत है, जिससे फसल पर भी कुप्रभाव न पड़े। शोधकर्ताओं ने बताया कि वे एक क्लाउड सर्वर विकसित करने की भी योजना बना रहे हैं, जिसमें एप के माध्यम से डाटा अपलोड किया सके ताकि टिड्डी दल की स्थिति का रियल टाइम पता लगाया जा सके। इस अध्ययन के सह लेखक बशिल अल-डेरी ने कहा कि हर साल लगभग 1.8 करोड़ हेक्टेयर भूमि टिड्डियों और कीटों की वजह से क्षतिग्रस्त हो जाती है। जिससे किसानों और उनकी उत्पादकता पर बहुत प्रभाव पड़ता है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में इसकी निगरानी तकनीक केवल सर्वेक्षण पर आधारित है। इस तकनीक से तुरंत के हमलों से नहीं बचा जा सकता।

1.8 करोड़ हेक्टेयर भूमि टिड्डियों और कीटों की वजह से क्षतिग्रस्त हो जाती है विश्व भर में सालाना

26 साल में यह टिड्डियों का सबसे बड़ा हमला है भारत में। गुजरात, राजस्थान और पंजाब प्रभावित

▶ 'माइस्ट्रो' नामक यह एप टिड्डियों और कीटों की आबादी के फैलाव के बारे में पहले ही देगा चेतावनी

वर्तमान में पाक, भारत में टिड्डी का प्रकोप

वर्तमान में पाकिस्तान और भारत के गुजरात, राजस्थान और पंजाब में टिड्डियों का प्रकोप छाया हुआ है। भारत में पिछले 26 वर्षों में यह टिड्डियों का सबसे बड़ा हमला है।

इस तरह तैयार किया एप

अध्ययन में कहा गया कि शोधकर्ताओं ने एप को विकसित करने के लिए टिड्डियों के 3500 से अधिक चित्रों को इकट्ठा किया। इस एप के माध्यम से विभिन्न प्रकार के इलाकों में पौधों की वृद्धि को भी पहचान सकते हैं।

शोधकर्ताओं ने बताया कि हमारा मकसद नए एप के माध्यम से टिड्डियों के प्रसार को पहचानने और रिकॉर्ड करना है, जिससे किसान समय रहते ही उचित कदम उठाकर कीटों के हमलों से फसल को बचा सकते हैं। इस एप के माध्यम से कीटों की आबादी के फैलाव के बारे में उन्हें पहले ही पता चल जाएगा।

अपने शरीर का तापमान खुद नियंत्रित रखते थे डायनासोर

- अपने मेटाबॉलिज्म से नियंत्रित करते थे शरीर का तापमान
- डायनासोर के अंडे में मौजूद यौगिक कैल्शियम कार्बोनेट का किया अध्ययन

यरूशलम, प्रेट्र: शोधकर्ताओं ने एक नए अध्ययन में दावा किया है कि डायनासोर का विकास तो छिपकली जैसे ठंडे खून वाले जानवर के रूप में हुआ, लेकिन बाद में वह गर्म खून वाले जानवरों में बदल गए। जिस तरह से छिपकली को अपने शरीर का तापमान नियंत्रित करने के लिए सूर्य की आवश्यकता पड़ती है उसके उलट डायनासोर अपने शरीर का तापमान अपने मेटाबॉलिज्म से नियंत्रित करते थे।

साइंस एडवांसेज जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में कैल्शियम कार्बोनेट के यौगिक में रासायनिक बांड का विश्लेषण किया गया। यह यौगिक डायनासोर के अंडे के छिलके में मौजूद था। शोधकर्ताओं ने गणना की किस तापमान पर इस यौगिक का निर्माण हुआ था और अंडे देने वाली डायनासोर के शरीर का तापमान क्या था।

शोधकर्ताओं ने जीवाश्मों का अध्ययन करने के बाद पाया कि डायनासोरों के शरीर का तापमान 35-40 डिग्री सेल्सियस तक रहा होगा, लेकिन डायनासोर युग में वैश्विक जलवायु आज की तुलना में काफी गर्म थी। इसके बावजूद डायनासोर अपने शरीर का तापमान नियंत्रित रखते थे।

शोधकर्ताओं के मुताबिक डायनासोर के शरीर का तापमान उसके मेटाबॉलिज्म से नियंत्रित होता था। इसी वजह से शरीर के तापमान से उनके आस-पास के वातावरण के तापमान के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है।

इस तरह की अध्ययन की पुष्टि: इजरायल के यरूशलम में हिब्रू यूनिवर्सिटी के हैगिट अफेक ने बताया कि इस अध्ययन की पुष्टि के लिए उन्होंने कनाडा के अल्बार्टा जैसे उच्च अक्षांशों में रहने वाले डायनासोरों का अध्ययन किया। इसके साथ ही उन्होंने डायनासोर के साथ रहने वाले घोंघो के खोल का भी विश्लेषण किया। इस दौरान पाया गया कि घोंघों के आवरण का निर्माण 26 डिग्री सेल्सियस में हुआ और डॉयनासोर के अंडे की परत का 35 डिग्री सेल्सियस में। इससे पता चलता है कि डायनासोर अपना तापमान खुद ही नियंत्रित रखते थे।

चेतना लाने वाला नया ब्रेन सर्किट खोजा

- शोधकर्ताओं ने बंदरों में अध्ययन कर प्रक्रिया को दर्शाया
- कोमा और असमान्य मस्तिष्क गतिविधि से जूझ रहे लोगों का हो सकेगा इलाज

वाशिंगटन, प्रेट्र : शोधकर्ताओं ने चेतना लाने वाले नए ब्रेन सर्किट की खोज की है। उन्होंने बताया कि मस्तिष्क के एक विशेष प्वाइंट पर बिजली का एक हल्का झटका गहरी से गहरी बेहोशी से बाहर निकाल सकता है। शोधकर्ताओं ने बंदर पर इसका प्रयोग कर दिखाया है। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया से मस्तिष्क विकारों का संभावित उपचार किया जा सकता है। इस अध्ययन को 'न्यूरान' जर्नल में प्रकाशित किया गया है।

अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने पहले एक मैकॉक बंदर को दवा देकर बेहोश कर दिया। इसके बाद उसके मस्तिष्क की गहराई के एक प्वाइंट जिसे सेंट्रल लेटरल थैलमस कहा जाता है, वहां करंट का हल्का सा झटका देकर मात्र दो से तीन सेकंड में फिर से होश में ला दिया। इस अध्ययन के सह लेखक यूरी साल्मन ने बताया कि जब तक मस्तिष्क के इस क्षेत्र में बिजली के झटके देते रहेंगे तो बंदर जाग्रत अवस्था में रहेगा। वह आंखे खोलेगा, आसपास की वस्तुओं को पहचानेगा, शरीर में हलचल होगी और चेहरे के भाव भी बदलेंगे। लेकिन जैसे ही बिजली के झटके बंद करेंगे वैसे ही बंदर फिर से बेहोश हो जाएगा। शोधकर्ताओं के अनुसार परिणामों से मस्तिष्क के सेंट्रल लेटरल थैलमस में तंत्रिका गतिविधि के एक विशेष लूप का पता चलता है।

प्रतीकात्मक

पुराने अध्ययनों में बताया गया है कि इसी जगह पर चोट लगने से व्यक्ति कोमा की स्थिति में पहुंच जाता है। हालांकि, शोधकर्ताओं ने बताया कि केवल यह स्थान ही चेतना लाने के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्होंने होश की अवस्था में सेंट्रल लेटरल थैलमस में तंत्रिका गतिविधि को मैच करने की कोशिश की। अध्ययन में बताया कि बेहोशी की स्थिति से निकालने के लिए सटीक जगह पर 50 हर्ट्ज की आवृत्ति से बिजली का संचारण करना होता है। अगर आप जगह से एक मिलीमीटर भी चूके तो इसका प्रभाव कम हो जाएगा और यदि बिजली संचरण की आवृत्ति कम हुई तो यह प्रक्रिया बेकार हो जाएगी। अध्ययन के सह लेखक मिशेल रेडिनबघ ने बताया कि यह प्रक्रिया सटीक स्थान पर सटीक प्रक्रिया के साथ होनी चाहिए।

कार्टेक्स भी निभाता है महत्वपूर्ण भूमिका

शोधकर्ताओं ने बताया कि मस्तिष्क की बाहरी तह जिसे कार्टेक्स कहा जाता है, यह भी चेतना लाने में शामिल होता है। उन्होंने देखा कि जब बंदर बेहोशी से सचेत अवस्था में आते थे तो उनके सेंट्रल लेटरल थैलमस कार्टेक्स के कुछ भागों को उत्तेजित करता था। इसके बदले में कार्टेक्स भी थैलमस को सक्रिय रहने में मदद करता था। शोधकर्ताओं ने बताया कि मस्तिष्क के इस क्षेत्र में नई प्रक्रिया के माध्यम से चेतना लाने में सफलता मिली है। भविष्य में इस प्रक्रिया से असमान्य मस्तिष्क गतिविधि से जूझ रहे लोगों का उपचार किया जा सकेगा।

फोटो न्यूज

सबसे बड़े ओपेरा बॉल से पहले अभ्यास

ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में होने वाले दुनिया के सबसे बड़े ओपेरा बॉल से पांच दिन पहले स्टेट ओपेरा हाउस माहलर-साल में करीब 11 देशों के 144 जोड़ों ने रिहर्सल किया। ये डेब्यूटेंट ओपेरा बाल में प्रस्तुति देंगे। 1814 में शुरू हुए इस ओपेरा बाल में हॉलीवुड के कलाकार भी प्रस्तुति देते हैं। दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों समेत हजारों प्रतिष्ठित शख्सियतों को आमंत्रित किया जाता है। इसे यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत में भी शामिल किया गया है। एएफपी

ब्लड टेस्ट से होगी गर्भाशय कैंसर की जांच

शोध अनुसंधान

वैज्ञानिकों ने ओवरियन यानी गर्भाशय कैंसर की जांच का नया तरीका ईजाद किया है। इसमें ब्लड टेस्ट के जरिये शरीर की प्रतिरक्षा को मापा जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि शरीर में कुछ इम्यून (प्रतिरक्षा) बायोमार्कर की जांच से यह जानना संभव हो सकता है कि गर्भाशय में बन रही गांठ कैंसर ग्रसित है या नहीं। इसमें किसी एमआरआइ या अल्ट्रासाउंड की जरूरत नहीं होती है। गर्भाशय का कैंसर महिलाओं में सबसे ज्यादा होने वाले कैंसर में शुमार है। इसमें जान जाने की दर भी सबसे ज्यादा रहती है। आंकड़ों के मुताबिक, हर साल गर्भाशय कैंसर के करीब तीन लाख नए मामले सामने आते हैं और जांच के पांच साल के भीतर ही ज्यादातर मरीजों की जान चली जाती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जांच का नया तरीका पारंपरिक ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड के संयुक्त नतीजों के बराबर ही कारगर पाया गया है। - आइएएनएस

बिना रोक-टोक के खेलने से बच्चों का बेहतर विकास

यह बात पहले से ज्ञात है कि आउटडोर यानी घर के बाहर शारीरिक गतिविधि वाले खेल से बच्चों का बेहतर विकास होता है। अब इस मामले में एक और जानकारी सामने आई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर आउटडोर खेलों के समय बच्चों पर कोई रोक-टोक नहीं हो, तो यह ज्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। अगर बड़ों की निगरानी के बिना बच्चों को स्वच्छंद रूप से खेलने का मौका मिले तो उनकी सोचने व समझने की शक्ति, सामाजिक सक्रियता और रचनात्मकता बढ़ जाती है। बच्चे जटिल स्थिति में सोचने में भी सक्षम बनते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया कि इस मामले में खेल का प्रकृति से संबंध होना ज्यादा फायदेमंद है। उदाहरण के तौर पर मिट्टी से खिलौने व तरह-तरह की आकृतियां बनाना, लकड़ी से घर बनाना और बेफिक्र होकर मिट्टी में खेलना बच्चों के विकास में अहम साबित हो सकता है। बच्चों की शारीरिक सेहत के लिए भी ऐसी गतिविधियां बेहतर होती हैं। - प्रेट्र

स्क्रीन शॉट

'मिस्टर इंडिया' की नई दुनिया रचेंगे अली अब्बास

वर्ष 1987 में रिलीज हुई हिंदी सिनेमा की सुपरहीरो वाली फिल्म 'मिस्टर इंडिया' के यादगार किरदारों पर फिल्म लिखने और उसका निर्देशन करने का जिम्मा अली अब्बास जफर को सौंपा गया है। जी स्टूडियो के सीईओ शारिक पटेल ने साफ कर दिया है कि यह फिल्म मूल 'मिस्टर इंडिया' की पार्ट 2 या रीमेक नहीं होगी, बल्कि उस क्लासिक फिल्म की कल्पनाओं में ले जाएगी। अली अब्बास स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। वह सुपरहीरो की दुनिया को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो नया और प्रासंगिक होगा। 'टाइगर जिंदा है' और 'भारत' जैसी फिल्मों का निर्देशन कर चुके अली का कहना है कि 'मिस्टर इंडिया' के यादगार किरदारों को आगे लेकर जाना बड़ी जिम्मेदारी है। इन किरदारों को भारतीय दर्शकों ने बहुत पसंद किया है। साथ ही उन्होंने बताया कि स्क्रिप्ट का पहला ड्राफ्ट तैयार होने के बाद कलाकारों को कास्ट करने की प्रक्रिया शुरू होगी। चूंकि प्रोडक्शन स्तर पर काफी काम करना होगा, इसलिए अगले साल की शुरुआत में शूटिंग शुरू होगी।

स्टूडियो की मानें तो यह केवल एक फिल्म नहीं, बल्कि ट्रायोलॉजी होगी।

डिजिटल पर डेब्यू करेंगे नीरज पांडे

अभिनेता से लेकर निर्देशक तक हर किसी को डिजिटल का मंच अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। 'ए वेडनेस डे', 'स्पेशल 26' व 'बेबी' जैसी फिल्मों के निर्देशक नीरज पांडे भी डिजिटल पर कदम रख रहे हैं। नीरज एक अंतरराष्ट्रीय जासूसी वाले थ्रिलर शो 'स्पेशल ऑप्स' का निर्माण करेंगे। इस शो का निर्देशन वह शिवम नायर ('नाम शबाना' के निर्देशक) के साथ मिलकर करेंगे। उन्होंने जाने-माने लेखकों दीपक किंग्रानी और बेनजीर अली फिदा के साथ मिलकर शो लिखा है। इसके लिए उन्होंने काफी रिसर्च भी की है। शो पिछले 19 वर्षों की महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटनाओं पर आधारित होगा। शो को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए इसकी शूटिंग अलग-अलग विदेशी लोकेशंस पर होगी, जिनमें भारत के अलावा तुर्की, जॉर्डन जैसे देश भी शामिल हैं। नीरज का कहना है कि जॉनर को परिभाषित करने वाला कंटेंट बनाना उनकी खासियत रही है। लेखन पर खास ध्यान दिया गया है।

जिनकी एकेडमी में सीखा डांस उनके साथ शो जज करेंगी मलाइका

स्टारडम हासिल करने के पीछे कड़ी मेहनत और संघर्ष होता है। डांस रियलिटी शो 'इंडियाज बेस्ट डांसर' के ऑडिशन के दौरान युवाओं का संघर्ष देखकर शो की जज मलाइका अरोड़ा को अपने संघर्ष के दिन याद आ गए। उन्होंने बताया कि जब वह ऑडिशन देने जाती थीं तो उनकी मां भी साथ जाती थीं। शुरुआत में कई जगहों पर मिली असफलता से उनके हौसले पस्त नहीं हुए और उन्होंने कोशिश करना जारी रखा। उन्होंने 17 साल की उम्र से ही मॉडलिंग करना शुरू कर दिया था। उसके बाद एक के बाद एक चीजें होती गईं। वर्तमान में वह शो को जज करने के मुकाम पर हैं। हालांकि यह आसान नहीं था। मलाइका ने बताया कि जब मैं 15-16 साल की थी, तब पता नहीं था कि मैं करना क्या चाहती हूं। आजकल ऑडिशन देने आने वाले बच्चों को पता होता है कि वे करना क्या चाहते हैं। मलाइका ने बताया कि वह लगभग 20 साल पहले टेरेंस लुईस से मिली थीं और वह उन्हीं की डांस एकेडमी में डांस सीख रही थीं। आज वह उनके साथ शो को जज कर रही हैं। इस शो का प्रसारण 29 फरवरी से सोनी चैनल पर होगा।

'तेजस' के फर्स्ट लुक में पायलट के अवतार में दिखीं कंगना

हिंदी सिनेमा का ध्यान इन दिनों युद्ध के नायकों की ओर आकर्षित हुआ है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना की जिंदगी पर आधारित फिल्म 'गुंजन सक्सेना : द कारगिल गर्ल' रिलीज होने को है। कारगिल युद्ध के दौरान गुंजन सक्सेना ने कई जवानों को सुरक्षित निकाला था। अब कंगना रनोट भी रॉनी स्क्रूवाला की फिल्म 'तेजस' में महिला पायलट के रूप में नजर आएंगी। सोमवार को कंगना की टीम ने सोशल मीडिया पर इस फिल्म से कंगना का फर्स्ट लुक जारी किया। इस पोस्टर में कंगना भारतीय वायुसेना की महिला पायलट की वर्दी में दिख रही हैं। उनके हाथ में एक हेलमेट है और पीछे एक लड़ाकू विमान भी खड़ा है। इस पोस्टर को साझा करते हुए कंगना की टीम ने लिखा, 'वर्दी में रहने वाली सभी बहादुर और दृढ़ इच्छाशक्ति वाली महिलाओं के नाम, जो दिन-रात हमारे देश के प्रति समर्पित रहती हैं। कंगना अपनी नई फिल्म तेजस में एयर फोर्स की पायलट का किरदार निभा रही हैं।' इस फिल्म को सर्वेश मेवाड़ा ने लिखा है और वह इस फिल्म से हिंदी सिनेमा में बतौर निर्देशक अपनी पारी का आगाज भी करेंगे। फिल्म में भारतीय वायुसेना में महिलाओं की बहादुरी, साहस और संघर्ष को दिखाया जाएगा।

अबू धाबी पहुंचे 'बंटी और बबली 2' के ठग

यशराज बैनर की फिल्मों की ज्यादातर शूटिंग विदेश में होती है। अब उसकी आगामी फिल्म 'बंटी और बबली 2' को अबू धाबी में फिल्माया जाएगा। 2005 में रिलीज हुई फिल्म 'बंटी और बबली' की सीक्वल में सिद्धांत चतुर्वेदी और शरवरी ठग बने हैं। ठगने वाले एक बड़े सीक्वेंस की शूटिंग के लिए दुबई के अबू धाबी शहर को चुना गया है। फिल्म की टीम दुबई के लिए रवाना हो चुकी है। निर्देशक वरुण शर्मा का कहना है कि टीम वहां 10 दिनों तक रुकेगी। ठगी वाले दृश्यों के साथ ही फिल्म के कुछ अन्य दृश्यों की भी शूटिंग वह करेंगे। उन्होंने आगे बताया कि भले ही यह सफल फिल्म की अगली कड़ी है, लेकिन इसे आज के समय में सेट किया गया है। फिल्म के ठगों को आज के दौर के मुताबिक तैयार किया गया है। फिल्म में सिद्धांत और शरवरी के अलावा सैफ अली खान और रानी मुखर्जी होंगे, जिन्हें असली बंटी और बबली के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। सैफ और रानी ने 'हम तुम' और 'ता रा रम पम' जैसी फिल्मों में साथ काम किया है। 'बंटी और बबली 2' से वरुण शर्मा अपने निर्देशन करियर की शुरुआत करेंगे। उन्होंने 'सुल्तान' और 'टाइगर जिंदा है' फिल्मों में बतौर सहायक निर्देशक काम किया था। फिल्म की रिलीज तारीख तो सामने नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि यह फिल्म इस वर्ष गर्मियों में रिलीज होगी।

13 मार्च को 'अंग्रेजी मीडियम', कई फिल्मों की रिलीज डेट में उलटफेर

कई फिल्मों की रिलीज डेट में फेरबदल हुआ है। इरफान अभिनीत 'अंग्रेजी मीडियम' की रिलीज डेट को 13 मार्च कर दिया गया है। पहले यह फिल्म 20 मार्च को रिलीज होने वाली थी। वहीं 13 मार्च को रिलीज होने वाली जाह्नवी कपूर अभिनीत फिल्म 'गुंजन सक्सेना : द कारगिल गर्ल' की रिलीज डेट अब 24 अप्रैल कर दी गई है। पहले 24 अप्रैल को जाह्नवी की ही फिल्म 'रूही आफजा' रिलीज होने वाली थी, लेकिन गुंजन सक्सेना' की वजह से अब वह पांच जून को रिलीज होगी। दूसरी तरफ अक्षय कुमार की फिल्म 'सूर्यवंशी' की रिलीज डेट में भी बदलाव की खबरें आ रही हैं। बताया जा रहा है कि 27 अप्रैल की जगह 25 अप्रैल को रिलीज करने की योजना है।